खण्ड–521, अंक–09
बुधवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1944
(01 मार्च, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2023)

(खण्ड 521 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-164
जनपद प्रयागराज में घटित घटना के दृष्टिगत सजायाफ्ता के पैरोल पर बाहर अभियुक्तों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	164-165
नियम-301, नियम-51 की सूचना को लॉटरी के माध्यम से लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	165
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	165-166
जनपद सन्तकबीरनगर के जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166
विवेक सक्सेना पुत्र स्व0 अवध बिहारी शरण सक्सेना के भवन संख्या-05, शंकर दयाल नगर, अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात में स्थित भवन पर कैलाश मिश्र द्वारा पिछले कई वर्षों से किये गये अवैध कब्जे को हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166-167
जनपद इटावा के तहसील इटावा के ग्राम लोहिया खुर्द पोस्ट-खेडाहेलू, विकास खण्ड बसरेहर में प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत स्थित पपौरा, अमलाई, प्रभुपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शरीफपुर तथा बांसखेड़ा का थाना स्थानान्तरित कर शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	167-168
जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम भैंसराव में गत कई वर्षों से निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेज का कार्य पूरा कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	168
जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ज्ञानसरोवर के सौन्दर्यीकरण व सीढ़ी की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168-169

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा के सदर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
जनपद फतेहपुर के खागा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किशनपुर नगर पंचायत से पहाड़पुर ग्राम तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169
विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत नियामताबाद ब्लाक के ग्राम सभा कुंडलियों में मिनी स्टेडियम बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	169-170
जनपद जौनपुर के जलालपुर में दर्ज मुकदमा के अन्तर्गत कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद बाँदा के नरैनी विधान सभा क्षेत्र में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	170-171
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम से बालागंज के आजाद नगर सी ब्लाक में स्थित नलकूप सही कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	171
जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर करन में कतिपय ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव द्वारा की जा रही अनियमितता तथा 06 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी स्थानान्तरण न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	171-172
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनिया में माहे पासी किला को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने तथा इसका विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	172
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत ग्राम बिलौआ से कल्यानपुर मार्ग पर गोहनिया नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172-173
नगरीय क्षेत्र में 24 मीटर सड़क पर व्यावसायिक भूमि बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विकास खण्ड गौर को नयी तहसील घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कन्नौज के छिबरामऊ नगर के बिजली विभाग में संविदा एवं ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बिजली की शिकायत करने पर बिना पैसे लिये उनकी समस्या का निराकरण नहीं करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173-174
समस्त कार्मिकों को एन0आर0एल0एम0 एच0आर0 पॉलिसी में अनुमन्य सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	174
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	175
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	175
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	175
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	175-176
उत्तर प्रदेश अटठारहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	176
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	176-180
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ...	180-255
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन में कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	255
औद्योगिक विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु समय का निर्धारण	255-256
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान की माँग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग	256-318
याचिकाओं का उपस्थापन	318
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	318
श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	318-319

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	319
श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	319
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	319-320
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	320
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	320-321
ईजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	321
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	321-322
डा0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	322
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	322-323
डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	323-324
डा0 मुकेश चंद्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	324
डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	324-325
श्री अमित सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	325
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	326
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	326-327

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	327
श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	327-328
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	328
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	328-329
श्री गणेश चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीर नगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	329
श्री गुरू प्रसाद मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	329-330
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)	330
श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	330-331
श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी) सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	331-332
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	332
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	332-333
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	333
श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयी) ...	334
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित दो व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	334-335

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	335
श्री जियाउदीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	335-336
याचिकाओं का उपास्थापन (क्रमागत)	336
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	336-337
श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	337
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	337-338
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	338
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	349
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	339-340
श्रीं प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	340
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	340-341
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)	341
श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	341-342
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	342
श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	342-343
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	343

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	343-344
श्री मूलचंद्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	344
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित चार तथा जनपद कन्नौज से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	344-345
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	345
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	346
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	346-347
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	347
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	347-348
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	348
श्री राजमणि कोल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)	348
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	348-349
श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	349
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं) ...	349-350
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	350-351

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)	351
श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	351
श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	351-352
श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	352-353
श्री विजयपाल आढती, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	353
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	353
श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	354
श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	354
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	354
श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	355
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	355-356
श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)	356
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत)	356-357
श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	357
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (उपस्थित की हुयी मानी गयीं)	357-358

विषय				पृष्ठ-संख्या
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)		...	...	358
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	...	...	...	358-360
नत्थियाँ	...	...	...	360-371

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 01 मार्च, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-366

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, श्री — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
15. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
16. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
18. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
19. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
20. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
21. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
22. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
25. अभिजीत सिंह साँगा, श्री — कानपुर नगर
26. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
27. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
28. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
29. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
30. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
31. अरमान खान, श्री — लखनऊ
32. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
35. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
36. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
37. अशरफ अली खान, श्री — शामली
38. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
41. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
42. आकाश सकसैना (हनी), श्री — रामपुर
43. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
44. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
46. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
47. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
48. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू — बदायूं
50. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
51. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी

53. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
54. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
55. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
56. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
57. एम0 पी0 आर्य, डा0 बरेली
58. ओमकुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
61. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
62. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
64. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
65. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
66. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
69. कैलाश, श्री चन्दौली
70. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
71. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
72. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
73. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
74. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
75. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
76. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
77. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
78. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
79. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
80. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
81. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
82. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
83. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट) श्री फतेहपुर
84. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
85. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
86. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
87. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
88. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
89. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
90. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
91. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
94. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
95. जाहीद, श्री भदोही
96. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
97. जियाउर्रहमान, श्री मुरादाबाद
98. जी0 एस0 धर्मेश, डा0 आगरा
99. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
100. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
101. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
102. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
103. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
104. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
105. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
107. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
108. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
109. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
110. दिनेश कुमार, श्री मेरठ
111. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
112. दीपक कुमार मिश्र "शाका", श्री देवरिया
113. दुधराम, श्री बस्ती
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
116. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
117. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
119. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
120. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा

121. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
122. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
123. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
124. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
125. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
126. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
127. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
129. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
130. नासिर कुरैसी, हाजी मुरादाबाद
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
134. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
135. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
136. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
137. पंकज, श्री जौनपुर
138. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
139. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
140. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
143. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
144. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
145. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
146. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
147. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
148. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
149. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
150. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
151. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
152. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
153. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
154. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
155. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
156. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
157. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
158. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
159. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
160. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
161. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
162. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
163. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
164. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
165. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
166. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
167. बाबूराम, श्री पीलीभीत
168. बाबूलाल, श्री आगरा
169. बावन सिंह, श्री गोण्डा
170. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
171. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
172. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
173. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
174. बेदी, श्री गाजीपुर
175. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
176. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
177. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
178. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
179. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
180. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
181. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
182. मदन भैया, श्री मुज्फ्फरनगर
183. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
184. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
185. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
186. मनीष रावत, श्री सीतापुर

187. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
188. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
189. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
190. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
191. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
192. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
193. महबूब अली, श्री अमरोहा
194. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
195. महेन्द्र, श्री अमरोहा
196. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
197. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
198. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
199. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
200. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
201. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
202. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
203. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
204. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
205. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
206. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
207. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
208. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
209. मेघश्याम, श्री मथुरा
210. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
211. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
212. मोहम्मद हसन "रूमी", श्री कानपुर नगर
213. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
214. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
215. योगेश धामा, श्री बागपत
216. योगेश वर्मा, श्री खीरी
217. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
218. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
219. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
220. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
221. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
222. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
223. रमेश, श्री जौनपुर
224. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
225. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
226. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
229. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
230. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
231. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
232. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
233. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
234. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
235. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
236. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
237. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
238. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
239. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
240. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
241. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
242. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
243. राजमणि, श्री प्रयागराज
244. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
245. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
246. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
247. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
248. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
249. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
250. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
251. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
252. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
253. राजेश चौधरी, श्री मथुरा

254. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
255. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
256. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
257. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
258. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
259. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
260. रामकेश निषाद, श्री बांदा
261. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
262. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
263. रामदुलार, श्री सोनभद्र
264. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
265. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
266. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
267. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
268. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
269. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
270. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
271. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
272. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
273. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
274. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
275. लकी यादव, श्री जौनपुर
276. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
277. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
278. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
279. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
280. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
281. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
282. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
283. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
284. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
285. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
286. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
287. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
288. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
289. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
290. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
291. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
292. विपुल दुबे, श्री भदोही
293. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
294. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
295. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
296. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
297. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
298. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
299. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
300. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
301. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
302. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
303. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
304. शशांक वर्मा, श्री खीरी
305. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
306. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
307. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
308. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
309. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
310. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
311. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
312. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
313. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
314. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
315. संग्राम सिंह, श्री बलिया
316. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
317. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
318. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
319. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र

320. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
321. सन्दीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
322. सन्दीप सिंह, श्री — प्रयागराज
323. सचिन यादव, श्री — फिरोजाबाद
324. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
325. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
326. सभाकुंवर, श्री — देवरिया
327. समरपाल सिंह, श्री — अमरोहा
328. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 — गोरखपुर
329. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
330. सरोज कुरील, श्रीमती — कानपुर नगर
331. सरोज सोनगर, श्रीमती — बहराइच
332. सर्वेश सिंह, श्री — फिरोजाबाद
333. सलोना कुशवाहा, श्रीमती — शाहजहांपुर
334. साकेन्द्र प्रताप, श्री — बाराबंकी
335. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — प्रयागराज
336. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
337. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
338. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
339. सुनील पटेल, डॉ0 — वाराणसी
340. सुभाष त्रिपाठी, श्री — बहराइच
341. सुरभी, डॉ0 — फर्रुखाबाद
342. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री — कुशीनगर
343. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री — देवरिया
344. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
345. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
346. सुरेश राही, श्री — सीतापुर
347. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
348. सुशांत सिंह, कुँवर — बिजनौर
349. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
350. सुशील सिंह, श्री — चन्दौली
351. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री — गाजीपुर
352. सैय्यदा खातून, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
353. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 — मेरठ
354. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
355. सौरभ सिंह सोनू, श्री — खीरी
356. स्वामी ओउमवेश, श्री — बिजनौर
357. हंसु राम, श्री — बलिया
358. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
359. हरिओम, श्री — कासगंज
360. हरिप्रकाश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
361. हरीश चन्द्र, श्री — बदायूं
362. हरेन्द्र सिंह, श्री — हापुड़
363. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री — प्रयागराज
364. हाकिम लाल बिन्द, श्री — प्रयागराज
365. हिमान्शु यादव, श्री — बदायूं
366. हदय नारायण सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़

नोटः- ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री(श्री दानिश आजाद अंसारी), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)(श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु'') सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतन्त्र देव सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न संख्या-1 श्री उमाशंकर सिंह का है, जो अस्पष्टता के आधार पर निरस्त है।

***1-श्री उमाशंकर सिंह-**

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उत्पादन व खरीद की जानकारी

***2-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत मांग के सापेक्ष कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन वर्तमान समय में हो रहा है तथा कितने मेगावाट बिजली की खरीद की जा रही है ? क्या सरकार प्रदेश के किसानों को विद्युत सप्लाई समयबद्ध तरीके से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

फरवरी,2023 में दिनांक 16-02-2023 तक अद्यतन 13491 मेगावाट औसतन मांग के सापेक्ष 13356 मेगावाट का उत्पादन रहा।

उत्पादन निगम व अन्य अनुबन्धों से क्रमशः औसतन 3380 मेगावाट तथा 9976 मेगावाट उत्पादन रहा।

सायं से प्रातः तक अनवरत् विद्युत आपूर्ति दिये जाने हेतु मांग एवं उपलब्धता के अन्तर को पूर्ण करने हेतु माह फरवरी, 2023 में दिनांक 16-02-2023 तक किसी-किसी दिन कुछ समय के लिए औसतन 244 मेगावाट (न्यूनतम 0 मेगावाट तथा अधिकतम 829 मेगावाट) विद्युत क्रय की गयी है।

वर्तमान में 2390 पोषकों को पृथक कर दिया गया है जिस पर 10 घण्टे दिन में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अन्य ग्रमीण पोषकों से सेवित किसानों को 18 घण्टे या उससे अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने जो लिखित जवाब दिया है वह मैंने पढ़ लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला

सवाल पूछना चाहता हूँ कि पहले बिजली की कितनी इकाइयाँ थीं और सरकार ने कितनी नई इकाइयाँ लगाई हैं और उन नई इकाइयों से उत्पादन कितना बढ़ा है। मेरा दूसरा सवाल इन्होंने कहा है कि हम किसानों को 10 घण्टे बिजली दे रहे हैं। किसान का अकेले का ट्यूबवेल नहीं होता है, बल्कि बीस-पच्चीस किसान मिलकर एक ट्यूबवेल से सिंचाई करने का काम करते हैं। चूंकि क्यारी लम्बी होती है और उसके लिए 10 घण्टे की बिजली पर्याप्त नहीं होती है, इसलिये क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सिंचाई के लिए 18 घण्टे बिजली दी जाये, क्योंकि आपने तो सिंचाई के लिए चुनावी वायदे भी किए थे। मेरा तीसरा प्रश्न है कि आपने घोषणा की है कि अप्रैल में बिजली मुफ्त कर देंगे तो किसान का जो पिछला बिजली बिल बकाया है क्या उसको भी माफ करने का काम करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ज्यादातर विषयों का जवाब दे दिया है। माननीय सदस्य का प्रश्न दो-तीन टुकड़ों में है। पहला तो यह है कि हम कितनी नई इकाइयाँ लगा रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि जवाहरपुर की जो यूनिट लग रही है उसका कार्य शुरू होने का काम योगी जी की सरकार में दिनांक 15 अप्रैल, 2017 से शुरू हुआ था। उसी प्रकार पनकी में जो नये प्लाण्ट लगाने के काम हुये हैं उनका भी काम 20 जून, 2018 को शुरू हुआ है और यह भी एक नया प्लाण्ट है। हमारे कुछ एक्सटेन्शन के प्लाण्ट हैं जैसे हम हरदुआगंज तापीय योजना का एक्सटेन्शन कर रहे हैं, घाटमपुर में जो नई यूनिट लग रही है यह सारी की सारी यूनिट इसी साल 31-05-2023, 31-10-2023 और 31-12-2023 को उत्पादन में आ जायेगी। किसानों के लिए जो बिजली दी जा रही है उससे सम्बन्धित माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न था जिसके जवाब में मैंने यह लिखा है दो प्रकार के किसानों के पोषक फीडर हैं। हमारे राज्य में जो कुल फीडर हैं उसमें से लगभग 20,000 के आस-पास हैं। उनमें से एग्रीकल्चर फीडर 5000 से ऊपर हैं। उनमें से 2390 फीडरों को अलग करके सम्पूर्ण रूप से कृषि के लिए कर दिया गया है। हमने कहा है कि जिन फीडरों को अलग कर दिया गया है उन फीडरों को 10 घण्टे बिजली सप्लाई दी जा रही है। बाकी जो फीडर हैं ग्रामीण से जुड़े हुये हैं उनमें आपको मालूम है कि जो ग्रामीण रोस्टर के हिसाब से जो बिजली घरों में जाती है वही बिजली किसानों के खेतों में भी जाती है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में किसानों के लिए सेप्रेट फीडर देने का काम शुरू किया गया था जिसके क्रम में आपने जो फीडर अलग किये हैं उनको आप 10 घण्टे बिजली दे रहे हैं, इस कारण किसान पर्याप्त रूप से सिंचाई नहीं कर पा रहा है। मैंने इसीलिए पूछा था कि क्या सरकार इस सप्लाई को बढ़ाकर 18 घण्टे करने का काम करेगी। सरकार किसानों के प्रति अपने भाषणों और बयानों में बहुत दयालु दिखती है, इसलिए मैं पूछना

चाहता हूँ कि जो पिछला बकाया है क्या उसको भी सरकार माफ करने का काम करेगी। किसान अन्न भी पैदा करता है और किसान का ही बेटा जवान के रूप में देश की सीमा की रक्षा करने का भी काम करता है, तो किसान जो घरेलू बिजली इस्तेमाल करता है क्या सरकार उसकी दर कम करने का काम करेगी।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार में और पहले की सरकारों में यही फर्क है कि यह सरकार जो कहती है वह करती है। हमने अपने संकल्प-पत्र में किसानों की बिजली मुफ्त करने की बात कही थी और मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को, मा0 वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बजट में उसका सम्पूर्ण प्राविधान कर दिया गया है। लगभग 25-26 सौ करोड़ रुपये, हमारे विभाग का 15 सौ और कृषि विभाग का 19 सौ करोड़ रुपये से ऊपर का जो प्राविधान किया गया है वह सम्पूर्ण किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए प्राविधान किया गया है। वर्तमान में भी लगभग 88.19 प्रतिशत छूट के साथ किसानों को बिजली दी जा रही थी। रही बात फीडरों के पृथकीकरण की आपने कहा कि मा0 अखिलेश जी की सरकार में सारे फीडर पृथक कर दिये गये थे। मैंने यह बात पहले भी कही है कि अभी जो फीडरों का काम चल रहा है उसमें पांच हजार फीडर एग्रीकल्चर के हैं जिनको पृथक करने का काम चल रहा है और उनको बहुत जल्द पृथक कर दिया जायेगा। रही बात कि आपके समय में 24 घण्टा बिजली जाती थी, लेकिन वह बिजली एक जिले में एक गाँव में जाती थी हम सभी जिलों को सभी गाँवों को, सभी किसानों को पर्याप्त बिजली दे रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न करना चाहता हूँ। एक तो मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमारा जो अद्यतन औसत उत्पादन है वह 13 हजार 491 मेगावाट है और मांग 13356 मेगावाट है। तो जब कम मांग है तो 24 घण्टा बिजली क्यों नहीं दी जा रही है। दूसरा, जो किसान का फीडर आपने अलग कर दिया तो केवल 10 घण्टा बिजली क्यों दे रहे हैं ? किसान को सिंचाई की आवश्यकता है, 10 घण्टा रात में देंगे तो उससे सिंचाई नहीं हो सकती। इसलिए क्या मा0 मंत्री जी किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये उनको सवेरे पांच बजे से कम से कम शाम को सात-आठ बजे तक बिजली देंगे। किसान को सुबह पांच बजे से कम से कम 16 घण्टा बिजली दें जिससे वह सिंचाई कर सके। क्या इसको करने पर विचार करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा कि किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें जितनी बिजली देने की आवश्यकता होगी उस पर अवश्य विचार किया जायेगा। किसानों की आवश्यकता की पूर्ति इस सरकार का परम कर्तव्य है हमारी प्रतिबद्धता है। रही बात औसत डिमाण्ड और प्रोडक्शन की। वैसे अगर मैं बीच की बात करूं तो हमारी डिमाण्ड 26590 तक

गयी थी, चूंकि आपने इसमें कोई महीना नहीं लिखा था इसलिए मैं आपको अन्तिम महीने फरवरी की बात करूं तो मेरे पास फीगर है। पहली फरवरी को हमारा औसत उत्पादन 13 हजार पांच मेगावाट था और मांग थोड़ी ज्यादा थी, तो उसमें हम बाजार से लेकर या अपने एक्सचेंज से लेकर देते हैं। उसी प्रकार से जो पीक डिमाण्ड होती है वह ज्यादा होती है। तो ऐसे समय में हम अपने एक्सचेंज से भी क्रय करके बिजली देते हैं।

***3-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु पात्रता मानक तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में पात्रों के चयन की जानकारी

***4-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन हेतु पात्रता मानक क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने हेतु चयनित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) में चयन हेतु पात्रता के मानक निम्नवत् हैं:-

लाभार्थी एवं उसके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय रु0 3.00 लाख से अधिक न हो।

लाभार्थी परिवार में पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र और अथवा अविवाहित पुत्रियाँ शामिल होंगे।

लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कहीं भी पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाइयां) नहीं होनी चाहिए।

किसी वयस्क कमाऊ सदस्य (वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग परिवार के रूप में समझा जा सकता है, बशर्ते कि उसके पास कहीं भी अपने नाम पर एक पक्का घर (सभी मौसम वाली रिहायशी ईकाई) नहीं हो।

किसी विवाहित दम्पत्ति के मामले में, पति/पत्नी में से कोई एक अथवा दोनों के संयुक्त स्वामित्व में केवल एक आवास पाने के पात्र होंगे, वह भी तब जब इस स्कीम के तहत परिवार की आय की पात्रता हो।

इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति जिसके पास 21 वर्ग मी0 से कम निर्मित क्षेत्र वाला पक्का मकान है, उसे मौजूदा रिहायशी ईकाई में 30 वर्ग मीटर तक सम्वर्धित करने हेतु शामिल किया जा सकता है।

विभिन्न घटकों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में स्वीकृत आवासों का विवरण निम्नवत् है:-		
वित्तीय वर्ष	घटक	स्वीकृत आवास
2021-22	बी0 एल0 स0	1,19,862
	ए0 एच0 पी0	799
	सी0 एल0 एस0 एस0	40,080
	योग	1,60,741
2022-23	बी0 एल0 सी0	1,17,225 (इनमें 40.839 ऐसे नये आवास भी सम्मिलित हैं, जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय समिति भारत सरकार की बैठक दिनांक 27-02-2023 में प्रदान की गयी है)
	ए0 एच0 पी0	
	सी0 एल0 एस0 एस0	37,465
	योग	1,54,690

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी क्षेत्र में पात्रता से जुड़ा है। उपलब्ध जवाब से पता चला कि प्रधानमंत्री आवास की पात्रता हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा फर्क किया गया है।

मान्यवर, शहरी क्षेत्र में वर्ष 2011 के आर्थिक सर्वे को आधार नहीं बनाया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पहले केवल वर्ष 2011 के आर्थिक सर्वे के पात्र लोग ही इसके पात्र माने गये। इसका फायदा बहुत से अपात्रों एवं बहुत से गलत लोगों ने उठाया। जिस कारण अभी भी बहुत से पात्र लोग आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं मा0 मंत्री जी से पहला अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी गलत तरीके से आवास प्राप्त लोगों

की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने तथा अवशेष पात्रों को भी लाभान्वित कराने का आश्वासन देंगे ? मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों की तुलना में दोगुने से अधिक अनुदान धनराशि देना ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के साथ वर्तमान सरकार के पक्षपात एवं अन्याय की पराकाष्ठा है। जबकि पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के पात्र लोगों को शहरी क्षेत्र की धनराशि से भी ज्यादा धनराशि मुहैया कराकर इस पक्षपात को समाप्त करने का काम किया था।

श्री अध्यक्ष-

शहरी मंत्री जी से शहरी आवास की बात पूछ लीजिए। आपने प्रश्न शहरी आवास पर लगाया है और भाषण गांव पर दे रहे हैं। मा0 मंत्री जी तो शहरी आवासों के बारे में बतायेंगे।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या मा0 मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब के साथ इस सरकारी पक्षपात एवं अन्याय का कारण बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका जो प्रश्न है, आप प्रश्न से सन्दर्भित कुछ भी अनुपूरक पूछ लीजिए।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गलत तरीके से आवास प्राप्त लोगों की जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने तथा अवशेष पात्रों को लाभान्वित कराने का आश्वासन इस सदन में देंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, यह गरीबों के लिए आवास की योजना है। दण्डित करने के लिए मा0 सदस्य बार-बार बोल रहे हैं। आपकी जानकारी में यह बात होनी चाहिए कि जिनके सर पर छत नहीं है, मकान नहीं है, झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, गली-चौराहों पर सोते हैं, पगडण्डियों पर सोते हैं, उनको कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। कई बार ऐसा संज्ञान में आता है कि एक ही व्यक्ति दो जगह अप्लाई कर देता है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, जिनके कारण से कई लोगों के मकान हमें बाद में जब छानबीन होती है तब रद्द करने पड़ते हैं। लेकिन उन सभी को दण्डित करना यह बात मुझे रास नहीं आती है कि मा0 सदस्य किस तरह के दण्ड को देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब-लाचार पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है, कई घरों में केवल गरीब गृहिणी होती हैं, उसको न तो कानून की जानकारी है और न ही उसको कोर्ट-कचहरी के बारे में जानकारी है। इसलिए हम दण्डित करने में नहीं पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पांच श्रेणियां हैं जिसके चलते हम कई बार पात्र लोगों की सूची घोषित कर देने के बाद भी हम उन्हें अपात्र घोषित करते हैं अगर छानबीन में ऐसा कोई मामला प्रकाश

में आता है। जैसे हम इसी वर्ष 2022-23 की बात करें तो कई अन्य घटकों के लिए वह पात्र पाए गये या अन्य घटकों में उन लोगों ने मकान ले लिया था, इस तरह के 806 लोग पाये गये, भूमि विवाद या भूमि स्वामित्व का कोई विवाद था ऐसे 15,271 लोग थे और कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं से गलत आय लिखवा लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पात्रता की आय तीन लाख है, लेकिन उनकी आय पात्रता की आय से ज्यादा है। उसके चलते भी हमने बड़ी संख्या में मकान रद्द किये हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अप्लाई करने के बाद कहीं चले जाते हैं, मकान लेने के इच्छुक नहीं होते हैं, शहर बदल देते हैं, ऐसे लोग भी होते है। ऐसे 23,358 लोगों के मकान को रद्द किया गया है। हमने इस वर्ष 2022-23 में 01 लाख 56 हजार 378 लोगों का मकान रद्द किया है। लेकिन उन गरीबों के सामने कोर्ट-कचहरी करना, केस करना एवं उनको दण्डित करना, यह मुझे आवश्यक नहीं लगता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आपकी बात शत्-प्रतिशत सही है, आपने जो भी जवाब दिया है वह सही है। इसमें बहुत सारे लोग अपने नाम पर मकान आवंटित करा लेते हैं, लेकिन उस मकान को किराये पर दे देते हैं। वह मकान पात्र व्यक्ति के रहने के लिए है, उसको किराये पर देने के लिए मकान नहीं दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात की जांच करा लें कि पात्र व्यक्ति कोई भी हो, वह उसमें रह रहा है, तो वह उसका अधिकार है। हम अपात्र उसको मानेंगे कि किसी को किराये पर देने के लिए मकान आवंटित न हो। इसकी जांच करा लेंगे और जो लोग भी उसमें होंगे उनको खाली कराकर पात्र लोगों को देंगे। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

***5-श्री अतुल प्रधान-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्धारित शिड्यूल के अनुसार करने के सम्बन्ध में

***6-श्री तुफानी सरोज (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां। वर्तमान में शिड्यूल और औसतन वास्तविक आपूर्ति वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक) का विवरण निम्नवत् है :-

श्रेणी	शिड्यूल के अनुसार (घण्टों में)	वास्तविक आपूर्ति (घण्टों में)
जनपद मुख्यालय	24	23.30
तहसील	21.30	21

बुन्देलखण्ड	20	18.39
ग्रामीण	18	17.34

उपरोक्त के अनुसार (स्थानीय/आकस्मिक व्यवधानों को छोड़कर) विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री तुफानी सरोज जी उपस्थित हैं या नहीं ?

प्रदेश में सरकारी/निजी बिजली उत्पादन कारखानों में जलवायु प्रदूषण की रोकथाम में लगी इकाइयों को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

***7-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी अथवा निजी रूप से लगाई गई बिजली उत्पादन कारखाना में कितनी इकाइयां पर्यावरण को दूषित होने की जांच नियमित रूप से कर रही हैं ? क्या सरकार जांच में कुछ इकाइयों द्वारा एनजीटी व प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी इकाइयां हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 अरुण कुमार)-

जी हाँ।

प्रदेश में सरकारी एवं निजी तापीय विद्युत परियोजनाओं को मिलाकर कुल 24 विद्युत उत्पादन परियोजनायें स्थापित/संचालित हैं। उक्त समस्त तापीय विद्युत परियोजनाओं में जलवायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित जलवायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित/संचालित हैं। इन सभी इकाइयों द्वारा समय-समय पर नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरीज (एन0ए0बी0एल0) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से जांच कराकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी समय-समय पर स्वयं जांच करायी जाती है। मानकों का पालन न करने वाली निम्न दो तापीय विद्युत इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	इकाई का नाम	कार्यवाही का विवरण
1	मैसर्स बजाज एनर्जी लि0 (90 मेगावाट), खम्भारखेड़ा, लखीमपुर खीरी।	प्रश्नगत इकाई के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण की संयुक्त निरीक्षण

क्र0सं0	इकाई का नाम	कार्यवाही का विवरण
		आख्या दिनांक 21-12-2022 एवं 22-12-2022 में पाई गई कमियों के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत धनराशि रुपये 3,50,000/-(रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड के पत्र दिनांक 10-02-2023 द्वारा अधिरोपित की गई है।
2	मैसर्स उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (यूनिट अ एवं यूनिट-ब), ओबरा, जनपद-सोनभद्र।	प्रश्नगत इकाई के निरीक्षण आख्या दिनांक 16-11-2022 में पाई गई कमियों के दृष्टिगत इकाई विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि मानव जीवन एवं मानव स्वास्थ्य के इस बहुत आवश्यक प्रश्न पर आपने अनुपूरक पूछने का अवसर दिया है। मान्यवर, हमारा प्रश्न था कि एन0टी0पी0सी0 संयंत्र के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है...

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न तो आप कई बार पूछ चुके हैं और पहले भी हाउस में आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले भी तो इसी पर बात हो रही थी।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, उस दिन मैंने प्रश्न किया था वह एयर (पॉल्यूशन) से सम्बन्धित था, यह दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, वह दूसरा प्रश्न था, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कन्फ्यूज हो गया था। मनोज जी, आप पूछिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमारा प्रश्न था कि एन0टी0पी0सी0 संयंत्र द्वारा जो प्रदूषण एवं मानव जीवन पर खतरा पैदा हो रहा है उस पर सरकार कोई जांच कराएगी या कार्यवाही करेगी ? मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं भी इससे प्रभावित हूं। मेरी

विधान सभा ऊंचाहार में एन0टी0पी0सी0 ऊंचाहार है। आज स्थिति यह है कि 27 ग्राम पंचायत चाहे गंगेरा हो, रायपुर, मतरमपुर, इटैली, उमरन, रसूलपुर, सराय, निगोहां, सुकरुल्लापुर, ऊधनपुर, सराय सहिजन, गनसरी, मुरारमऊ आदि क्षेत्रों की स्थिति यह है कि जब एन0टी0पी0सी0 की ऐश वहां से निकलती है और उतनी दूर का वातावरण और आसमान एकदम ब्लैक हो जाता है। ऐश लोगों के सांस द्वारा अन्दर जाती है। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य कमेटी ने उस इलाके में एक सर्वे कराया था उसमें सबसे ज्यादा 07 जिलों में कैंसर के मरीज उसी रोहनिया ब्लाक और ऊंचाहार के आंशिक क्षेत्र में मिले। अगर वहां पर कोई व्यक्ति सुबह लोगों की छतों पर चला जाए तो एक इंच ऐश लोगों की छतों पर इकट्ठा रहेगी और यही नहीं, इनके तीन ऐश डैम भी बने हैं एक कोटरा बहादुरगंज और एक रायपुर में बना हुआ है, किलोमीटरों में बने हुए हैं। कालान्तर में उनकी फर्श बनवायी गयी, जब वह पक्की थी और फिर टूट गयी, उसमें पानी भरा जाता है कि ऐश उड़े न, ऐश के साथ वह पानी भू-जल में जा रहा है। भूजल की स्थिति सरकारी रिपोर्ट में भी है और पिछले हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि आर्सेनिक और फ्लोराइड की सबसे ज्यादा मात्रा रोहनिया ब्लाक ऊंचाहार में है। स्थिति यह है कि वहां पर विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके हाथ-पैर टेढ़े हो रहे हैं और इस महत्वपूर्ण विषय में हम आपके संरक्षण से यह कहना चाहते हैं कि जहां टी0बी0 एवं अन्य संक्रामक रोग, श्वास रोग, गले के रोग, कैंसर बड़ी संख्या में हो रहे हैं, तो क्या सरकार और माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि एन0टी0पी0सी0 ऊंचाहार के द्वारा हो रहे इस प्रदूषण से, जहां ऐश के कारण प्रदूषण, फ्लोराइड आर्सेनिक की मात्रा भूजल में जा रही है, वही एन0टी0पी0सी0 का गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है, क्या इसकी कोई जांच अलग से कराई है और उसकी रिपोर्ट है ? दूसरा, क्या सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का जो सर्वे है उसको संज्ञान में लिया है ? वहां का जो भू-जल खराब हुआ है उसका कोई सर्वे कराकर उसको संज्ञान में लिया है और तीसरा, मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि अगर इसको गम्भीरता से नहीं लिया गया तो सीधे मानव जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

डॉ0 अरूण कुमार-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने बताया कि ऊंचाहार में 27 ग्राम पंचायतें हैं इसके लिए मैं यह कहूंगा कि समय-समय पर वहां जांच की जाती है और कोई ऐसी कमी जहां पाई जाती है उसके खिलाफ तुरन्त कार्रवाई होती है। ऊंचाहार के बारे में मैं दोबारा फिर से दिखा लूंगा और आपने जो बताया कि ऐश उड़ रही है, इसकी भी जांच करा लेंगे और जहां तक सी0एम0ओ0 से हेल्थ सर्वे का सवाल है उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, हम उसको भी मालूम करेंगे, अगर कुछ ऐसा है तो उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक संरक्षण चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष-

बताइए, प्लीज।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बन जाए, हम भी साथ लेकर चले जाए, मैं केवल इतना चाहता हूं कि इसकी सही जांच हो जाए। मैं सरकार का कोई दोष नहीं दे रहा हूं मान्यवर, इसमें एक कमेटी बन जाए, जीवन का सवाल है, वह जाँच कर ले, यही हम आपसे निवेदन करते हैं।

डा0 अरूण कुमार-

मान्यवर, हम इसको पहले दिखवाते हैं और हम आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो बात माननीय मनोज पाण्डेय जी ने कही है कि एनटीपीसी द्वारा जो फ्लाई ऐश निकलती है, वह काफी बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। जो बातें माननीय सदस्य ने बतायीं हैं, वह गम्भीर हैं कि रात भर में छतों के ऊपर इतनी फ्लाई ऐश इकट्ठी हो जाती है और स्वाभाविक रूप से जब पानी इकट्ठा होता है, जैसा माननीय सदस्य ने इससे ग्राउण्ड वाटर भी पलूटेड होने की बात कही है, लेकिन फैक्ट क्या है, यह जाँच से पता चलेगा। इसमें प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एक उच्च अधिकारी लखनऊ से वहाँ जायें, उसमें आप स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी लें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक टीम बना लें और माननीय मनोज पाण्डेय जी को साथ लेकर उसका सर्वेक्षण करा लें और जो भी इसमें आवश्यक कार्यवाही हो वह करें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, उसमें जल वालों को भी सम्मिलित कर लें।

श्री अध्यक्ष-

उनको भी शामिल कर लेंगे और प्रयास करें कि 15 दिन के अन्दर उसकी जाँच कराकर मेरे कार्यालय में उसकी जानकारी दें।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, दादरी वाले में भी माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता और सम्भव भी नहीं है और अपेक्षित भी नहीं है। दादरी नहीं, जिस विषय के ऊपर प्रश्न है, उसका उत्तर आया है, पूरे प्रदेश की जानकारी उनके

पास नहीं है। उस दिन जो आपने पूछा था, उसका जवाब मिला था, आज माननीय मनोज पाण्डेय जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह उससे सन्तुष्ट हैं। उसके ऊपर अब कुछ पूछने को बाकी नहीं है। आज जो प्रश्न था, माननीय मंत्री जी के पास उसी की जानकारी होगी।

प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

***8-डॉ0 रागिनी-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मुख्य मार्ग से जोड़गी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य किया जाता है। प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय सड़कों पर अथवा सड़कों के समीप स्थित हैं। जो विद्यालय लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर स्थित हैं, उन सड़कों के रख-रखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग करता है, लेकिन जो विद्यालय सड़कों से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, उन्हें मार्गों से जोड़ने का कार्य पंचायतों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

डॉ0 रागिनी-

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से था कि जितने भी हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं और जो मुख्य सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हुए हैं, क्या उनको मुख्य मार्गों से जोड़ने की कोई योजना सरकार के द्वारा है ? मान्यवर, जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। अध्यक्ष जी, कल हमारे बेसिक शिक्षा के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो हमारे इनरोलमेंट रेट्स हैं, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के, वह कम हैं और यह इनरोलमेंट्स कम होने का कारण है कि आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं, वह जब सरकारी स्कूल की ड्रेस में रहते हैं, तो वह कहीं न कहीं हिचकिचाते हैं। वह एक परिवार के आय प्रमाण-पत्र की तरह काम करता है। अध्यक्ष जी, यह एक बड़ी विडम्बना है कि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम एक गवर्नमेण्ट मेडिकल कालेज से पढ़ रहे हैं, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज से, आईआईटी से

पढ़ रहे हैं, एनआईटी से पढ़ रहे है, हम एमबीए कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन से कर रहे हैं, हम गवर्नमेण्ट इन्स्टीट्यूशन से लॉ की पढ़ाई को कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है, हमारे स्कूल्स की तो हमें कहीं न कहीं हिचकिचाहट होती है, परिवार अपने आपको यह बताने से छिपाता है कि मैं प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करा रहा हूँ और इन संस्थानों की जिनकी मैंने बातें कीं, इनकी गुणवत्ता जो है, वह सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्कूल के टीचर्स, वहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है, वह सबसे अच्छी है। एजुकेशन क्वालिटी के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर और सबसे मोस्ट इम्पारटेंट है, किसी भी एजूकेशन डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए वहाँ की रोड कनेक्टिविटी और जितने भी संस्थानों की मैंने बात की है, वहाँ की कनेक्टिविटी जो है, वह बहुत अच्छी है। लेकिन आज जब हम गाँव के स्कूल की बात करते हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं, वह टूटे हुए हैं, बच्चे पगडंडियों से स्कूल जा रहे हैं। बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे स्कूल ही न पहुँच पायें।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई योजना है नहीं, क्या सरकार इस पर मंथन करेगी और कोई ऐसी योजना बनायेगी, ताकि जितने भी हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जा सके और योजना बनायेगी तो उसे कब तक करेगी ? साथ ही साथ मैं सरकार से यह भी पूछना चाहूँगी कि आपके द्वारा ही कहा गया था कि जहाँ-जहाँ पर जो भी स्टूडेंट टॉप करेंगे, अच्छे अंक लायेंगे, उन स्कूलों को प्राथमिकता देते हुए, उन स्कूलों की जो रोड्स हैं, उनको बनवाया जायेगा या मरम्मत करायी जायेगी। तो आपके 06 वर्षों के कार्यकाल में उन बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा चिन्हित कितने स्कूल हैं, जिनके मार्गों को बनवाया गया है ? साथ ही में यह स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो हैं ही साथ ही साथ यहां पर एक बहुत ही बड़ा जो हमारा कांस्टीट्यूशन में हमें मतदान का अधिकार मिला है और हमारी जो जनता है वहां पर मतदान के लिए आती है, लेकिन जब वह उन रास्तों को टूटा-फूटा देखती है तो कई बार तो हमारे जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर जाने के लिए जगह भी नहीं होती है और वह निराश होकर वापस चली जाती हैं। मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि हमारी शिक्षा और साथ ही साथ यह जितने पोलिंग बूथ हैं क्या सरकार उनको प्राथमिकता पर लेते हुए काम करेगी। मैं एक और बात कहूंगी कि जो जवाब आया है उसमें यह भी बोला गया है कि ज्यादातर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वह या तो मेन रोड पर हैं और जो कुछ अन्दर हैं उनको हमारा लोक निर्माण विभाग कवर नहीं करता है और उसे पंचायत के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहां पर शिक्षा के साथ-साथ मतदान भी होता है और पोलिंग बूथे स्कूल को न बनाया जाए।

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, जहां तक मा0 सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह सही है कि जो विद्यालय हैं वह प्राथमिक विद्यालय अधिकतर ग्राम पंचायत की परिधि में आते हैं और जहां तक लोक

निर्माण विभाग का सवाल है और लोक निर्माण विभाग की जो योजनाएं हैं वह जनसंख्या और बसावटों के ऊपर आधारित हैं और उसको दृष्टिकोण में रखते हुए अभी जो योजनाएं चल रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी आबादी ढाई सौ है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना जो है, उन बसावटों को हम जोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। और जो पांच सौ मीटर से कम की सड़कें हैं उन्हें जैसा कि सदस्य ने बताया और उनको मालूम है कि वह अभी लोक निर्माण विभाग नहीं करता है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के द्वारा होता है। स्कूल का जहां तक सवाल है वह अधिकतर सड़कों पर ही हैं और जहां आगे की योजना का सवाल उठाया है मैं यह बताना चाहता हूं और आगे अनेक सदस्यों ने भी पहले यह सवाल उठाया था कि जो हमारी विलेज रोड हैं यू0पी0 में बहुत ज्यादा हैं दो लाख किलोमीटर विलेज रोड ग्रामीण सड़कें और समय के साथ ट्रैफिक बढ़ गया है, लोगों का आवागमन गन्ना ट्रॉली तमाम ऐसी चीजें आ गई है और सरकार ने आगे के लिए यह योजना बनाई है कि जो विलेज रोड हैं उन्हें हम ओ0डी0आर0 में कनवर्ट करें और जब ओ0डी0आर0 में सड़क कनवर्ट होती है तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के मानक उसमें चौड़ी भी होंगी, मजबूत भी होंगी और प्राथमिकता भी जारी है। हमारी जो सदस्य हैं वह इस बात से प्रसन्न होंगी, क्योंकि वह डॉक्टर हैं यह जितने मेडिकल कॉलेज हैं, ट्रॉमा सेण्टर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनको प्राथमिकता पर लिया जाएगा जहां यह सड़कें हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है डिग्री कालेज हैं, महिला इण्टर कालेज हैं उनको भी जहां ग्रामीण सड़कें हैं वहां ओ0डी0आर0 में कनवर्ट किया जाएगा। तमाम ऐसी मण्डियां हैं ब्लॉक मुख्यालय हैं इसमें मेरा पूरा प्रयास भी है और पूरा ध्यान भी है और जहां तक मतदान का सवाल है मा0 सदस्य ने उठाया मतदान केंद्र अधिकतर स्कूल होते हैं और यह मुझे बताने में प्रसन्नता होगी कि पिछले छः वर्षों में जबसे हमारी सरकार आई है मतदान प्रतिशत इतना बढ़ा है कि आजादी के बाद कभी बढ़ा नहीं होगा। मतदान में यह भी देखा गया है कि सबसे कम रिपोल हुए हैं तो जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ही यह किया गया है और जहां तक मा0 सदस्य की चिंता है, तो उसका पूरा ध्यान है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि किसी तरह की खासतौर से शिक्षा और महिला शिक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी दी जाएगी।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतदान बढ़ा है, मैं अगर अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे पास लिस्ट है कि कितने स्कूल बूथ हैं। मेरे पास लिस्ट है। अध्यक्ष जी, मेरे पास उसकी लिस्ट है कि कितने स्कूल्स हैं, बूथ्स हैं जहाँ पर लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बूथ हैं, अगर उसी पर रास्ता नहीं है, तो हम कैसे जाएँगे ? मंगरा, बूसा, आलम नगर, जरौटा, चतुर्भुजपुर, मनीपुर, आरजापुर, अनारी, चिगराऊँ, अमारा, परौरा, बामी ये सारे गाँव हैं जहाँ पर रास्ते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, स्कूल के बारे में पूछिए, टीचर्स और बच्चों के बारे में पूछिए। यह इलेक्शन का विषय नहीं है।

डॉ0 रागिनी-

जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा, कुछ रोड हैं जो उनके अन्तर्गत आती हैं, कुछ पंचायत के अन्तर्गत आती हैं। अध्यक्ष जी, यह जो जिम्मेदारी है, एक मतदान और शिक्षा प्रोवाइड कराने की तो ये क्यूमिलेटिव जिम्मेदारी पूरी सरकार की है। मुझे लगता है कि इस विषय को सिर्फ एक विभाग को नहीं, बल्कि पूरी सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर से आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ से आप वोट्स गेदर कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी मुहैया कराएँ, यह पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था। हम ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने का प्रयास कर रहे हैं और लोक निर्माण विभाग जनहित के लिए सड़कों का निर्माण करता है। यह जनहित के लिए है। जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसे विद्यालय प्रदेश में जितने भी हों, उनको देखा जाए। मान्यवर, हम गाँवों की कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं, ऐसे में जैसे आपने विद्यालयों में 250 का लक्ष्य रखा तो विद्यालयों में भी 250 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उसको एक इकाई मानकर सारे विद्यालयों को, प्राइमरी विद्यालयों को आप सड़क से जोड़ें, इससे बड़ा जनहित का काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि अगर अभी तक नीति नहीं रही है, तो क्या मा0 मंत्री जी पुनः नीति बनाकर सारे प्राइमरी विद्यालयों को सड़क से जोड़ने का काम करेंगे ?

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि लोक निर्माण विभाग जनसंख्या के आधार पर सड़कों का चयन करता है और 250 की आबादी वाली जितनी बसावटें हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से उन सबको कनेक्टिविटी दे दी गई है। जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ, वह अब हो गया है। मैं इसका दावा कर सकता हूँ। जहाँ ये विद्यालयों की बात कर रहे हैं तो वे अधिकतर ग्राम पंचायत की परिधि के अन्दर आते हैं। लोक निर्माण विभाग पहले उन बसावटों को उस जनसंख्या का ध्यान रख रहा है जहाँ 500 मीटर से ऊपर की सड़क बननी है। जब हम 500 मीटर को पूर्ण कर लेंगे, एक किलोमीटर वाली पूर्ण कर लेंगे, जब ऐसी कोई सड़क नहीं बचेगी तो हम उन छोटी सड़कों पर जिनकी 500 मीटर से कम की कनेक्टिविटी है, उस पर आएँगे। विद्यालयों के लिए अन्य संस्थाएँ भी हैं, जो छोटी सड़कें हैं, वह जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, सांसद निधि, विधायक निधि जैसी तमाम इकाइयाँ हैं, जिनसे वे कनेक्ट हो सकती हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा ध्यान है और हम अपने ग्रामीण

क्षेत्र की सड़कों को अपग्रेड भी कर रहे हैं और जो उसमें आएँगे, मैंने उन्हें पढ़कर बताया भी था कि उसमें अस्पताल भी हैं, उसमें इण्टर कॉलेज भी हैं, उसमें मण्डियाँ भी हैं, उसमें ब्लॉक मुख्यालय हैं, तमाम श्रेणियाँ हैं। धन्यवाद।

***9-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सरकारी विभागों का बकाया विद्युत बिल वसूलने की कार्यवाही का विवरण

***10-श्री महबूब अली-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी विभागों पर विगत 3 वर्षों का कितना बिजली बिल बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाए विद्युत बिल को वसूलने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22) में शासकीय विभागों पर बकाया बिजली के बिल की शुद्ध धनराशि रु0 1764.53 करोड़ है।

जी हाँ, सरकारी विभागों से बकाये के भुगतान हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है। बकाये के भुगतान हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ विभिन्न वार्तायें सम्पन्न की गयी हैं। उ0प्र0पा0का0लि0 स्तर पर भी इन विभागों से भुगतान हेतु वार्तायें की गयी हैं।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश पत्रांक सं0-1/2022/ई-10-162757-दस-2022-10-10099-22-2022, दिनांक 05-05-2022 एवं सं0-2/2022/ई-10-1-197718/दस-2022-10-10099-22, दिनांक 03-08-2022 के अनुसार उ0प्र0 के समस्त सरकारी विभागों के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्रीकृत रूप में उ0प्र0पा0का0लि0 को किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। तत्क्रम में सरकारी विभागों द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे द्वारा रखे गए प्रश्न पर बल देने और सप्लीमेण्टरी क्वेश्चन करने का मुझे मौका दिया। यह प्रश्न इसलिए किया गया है, मंत्री जी का जवाब मेरे सामने है। बिजली लगभग हर व्यक्ति, हर कारखाने, हर विभाग में इस्तेमाल होती है, लेकिन मेरा सीधा सा प्रश्न था कि क्या अगर किसी किसान के, गरीब के या किसी आम व्यक्ति के घर में बिजली का बिल बकाया हो जाता है, तो उसे सात दिन का मौका दिया जाता है, इसके बाद में सात दिन और दिए जाते हैं, उसके बाद उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, विजिलेंस की टीम पहुँच जाती है, बिजली के थानों का इस्तेमाल होता है, बिजली

विभाग के अधिकारी पूरा ताण्डव करते हैं। मंत्री जी ने यह तो मान लिया कि आम जनता के लिए विभाग की कितनी रुचि है, यह तो अच्छी तरह से महसूस हो गया। उन्होंने कहा है कि करीब 1200-1300 करोड़ रुपया हमारा अभी विभागों पर बाकी है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, उसमें भी कुछ छुपाया गया है। मंत्री जी, आप इसे निश्चित रूप से देख लें और हो सके तो इसकी विभागवार रिपोर्ट रख दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, क्या आपके पास कोई सूचना है कि जो चीज छुपाई गई है, तो उसे आप प्रस्तुत करें।

श्री महबूब अली-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप कह रहे हैं कि जो मंत्री जी ने बोला है उसमें कुछ छिपाया गया है, तो उसको प्रस्तुत करें, नहीं तो नहीं बोलें।

श्री महबूब अली-

यह ठीक है, मान्यवर, शुक्रिया मेहरबानी।

श्री अध्यक्ष-

जो उन्होंने दिया है उसके विपरीत यदि आपके पास कोई तथ्य है, तो तथ्य के साथ दीजिए, अन्यथा नहीं।

श्री महबूब अली-

मेरे अपने संज्ञान में है कि मा0 मंत्री जी के पास एक विभाग है और दूसरे विभाग, नगर विकास विभाग के मंत्री भी आप ही हैं। 4261 करोड़ रुपया जो नगर विकास पर आपका बाकी है, जो जलकल का है वह 2577 करोड़ है, लाइट का है वह 1683 करोड़ आपने छिपा लिया अपने विभाग के विषय में ही नहीं बताया। घर का काट नहीं रहे हैं और पूरे प्रदेश के कनेक्शन काटते फिर रहे हैं। इसलिए इससे स्पष्ट और कुछ नहीं, आपने मेरी भावनाओं का और प्रदेश की जनता की भावनाओं का, कहीं न कहीं एहसास करते हुए मान्यवर, आपने खुद मेरी बात पर बल दिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने बल नहीं दिया, मैंने कहा कि अपना पक्ष सदन को बताइये।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, इसलिए सीधा मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूँ कि आप विभागवार रिपोर्ट दे दीजिए, जो देनी भी चाहिए थी। मैं प्रश्न से हटकर आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा,

विभागवार रिपोर्ट दे दीजिए। जहाँ तक मेरी जानकारी में है यह पूरा 1200 करोड़ से अधिक का बिल अभी बाकी है और आज तक जिस तरह से गरीब पर ताण्डव होता है, मैं आप से प्रश्न कर रहा हूँ कि आप सीधा बता दीजिए, मेरा सवाल सीधा है कि तीन सालों में कितने सरकारी विभागों पर विद्युत विभाग की रेड पड़ी है, विजिलेन्स का छापा पड़ा है, एफ0आई0आर0 हुई है या आर0सी0 जारी हुई है ? मंत्री जी, इतना बता दें एक प्रश्न बाद में कर लूँगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री महबूब अली जी का इस विभाग के मंत्री के रूप में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने उठाया है, तो महबूब भाई आप तो मेरे महबूब निकले।

(सदन में हँसी) स्वाभाविक बात है कि हमारे विभाग के बिलों का पेमेण्ट होगा तो सबसे खुश व्यक्ति मैं ही हूँगा। 1200 करोड़ का आंकड़ा आप पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं मैंने जो लिखा है 1764.53 करोड़ रुपये लिखा हुआ है। दूसरी बात एक चीज आप और नहीं पढ़ पाये, हमने लिखा है कि बिल की शुद्ध धनराशि, शुद्ध धनराशि जो मूल धन होता है उसको कहते हैं उसके बाद सरचार्ज लगता है, ब्याज लगता है उसके बाद वह बढ़ते-बढ़ते आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो जाती है। हमने शुद्ध धनराशि लिखी हुई है इसलिए आंकड़ों में कहीं कोई समस्या नहीं है। रही बात उसके भुगतान की मा0 अध्यक्ष जी, तो इन्होंने हमारे विभाग की बात की है। इसलिए मैं नगर विकास विभाग की बात पहले कर लेता हूँ। वर्ष 2022-2023 में मा0 अध्यक्ष जी, हमने 1607 करोड़ रुपया बिजली विभाग को नगर विकास विभाग ने दिया है, 1299 करोड़ लगभग 1300 करोड़ रुपया चालू बिल का था और तीन-चार सौ करोड़ रुपया पिछले का एरियर भी था तो इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं। दो बहुत अच्छे काम हुये हैं जो कि इस सदन की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो यह कि मैंने इस पूरी व्यवस्था को मई महीने में वित्त विभाग के साथ बैठकर, मा0 वित्त मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, हमने इसको केन्द्रीकृत करा दिया है।

केन्द्रीकृत का मतलब यह है कि एक-एक स्कूल, एक-एक पुलिस थाने से पैसा वसूलने की बजाय उस विभाग के विभागाध्यक्ष के पक्ष में हमने एक हेड बना दिया है और वित्त विभाग से एक शासनादेश कर दिया है कि सभी विभागाध्यक्ष बिजली विभाग को सीधे-सीधे पैसा दे देंगे। 5 मई, 2022 का यह शासनादेश है, जिसमें हमने ई0-कुबेर नाम की एक व्यवस्था खड़ी की है, जिसमें बैंक का एकाउण्ट नम्बर भी सभी विभागों को लिखा है और आई0एफ0एस0सी0 नम्बर भी हमने दिया हुआ है कि आप एक-एक पुलिस स्टेशन या एक-एक स्कूल का पैसा न भेजकर आप सेन्ट्रलाइज्ड करके आप इतना पैसा पॉवर कारपोरेशन को दे दीजिए। उसके अच्छे परिणाम आने शुरू हुए हैं। यह मैं एक अच्छी खबर मा0 सदन से शेयर करना चाहूँगा, दूसरी बात मा0 अध्यक्ष जी यह हुई है कि सरकारी विभागों की बात तो हमारे रिकर्ड पर थी, लेकिन बहुत से

हमारे ऐसे प्राइवेट उपभोक्ता थे जिनको, जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा, इसलिए मैं यह बात बता रहा हूँ। मा0 सदस्य ने कहा कि सामान्य व्यक्ति का या किसान का छोटा सा बिजली का बिल बाकी होता है, उसका कनेक्शन बिजली विभाग वहाँ जाकर काट आता है। मैंने ऐसा पूछा कि हमारे जो 3 करोड़ 23 लाख उपभोक्ता हैं। उनमें से कितने का हमारे पास टेलीफोन नम्बर या ई-मेल नम्बर उपलब्ध है। पिछले साल 5 महीने पहले तक बहुत ही कम लोगों का नम्बर हमारे पास उपलब्ध था। पिछले 15 दिन, इसी महीने फरवरी में हमने एक बहुत बड़ा अभियान के0वाई0सी0 (नो योर कस्टमर) का चलाया। उसमें हमने सबके टेलीफोन नम्बर, सबके सम्पर्क नम्बर ले करके अब हम आगे से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास जो मोबाइल का प्री-पेड सिम होता है तो जैसे-जैसे उसका बैलेन्स कम होने लगता है, वैसे-वैसे कम्पनी का आपके पास रिमाइण्डर आने लगता है कि आप कृपया अपना रीचार्ज करा लें। जब बैलेन्स एकदम खत्म होता है तो आपकी आउटगोइंग बंद करते हैं फिर उससे भी आगे बढ़ते हैं, तब जाकर इनकमिंग बंद करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मैं बिजली विभाग में बहुत दिनों से लाना चाहता था, लेकिन हमारी एक मर्यादा यह थी कि 3 करोड़ 23 लाख लोगों में से मात्र लगभग 1 करोड़ लोगों का ही डेटा हमारे पास उपलब्ध था। उसको इस बार फरवरी महीने में के0वाई0सी0 का अभियान चलाकर लगभग 3 करोड़ तक हमने वह अपडेशन करके अधिकृत कर दिया है। यह बहुत बड़ा काम हुआ है और बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके बाद अब हम बहुत जल्दी ही यह व्यवस्था करने वाले हैं कि जैसे ही आपका बिल बनेगा, बिल जेनरेट होगा, वह आपके मोबाइल पर इतने रुपये का, इस महीने का, इस तारीख को जेनरेट हो गया है। उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी तो उसके 3 दिन पहले से 3 बार रिमाइण्डर देने की हम व्यवस्था दे रहे। यह व्यवस्था साफ्टवेयर करेगा, एक-एक आदमी का कोई मंत्री या अध्यक्ष नहीं करेगा, साफ्टवेयर यह काम करेगा, कम्प्यूटर यह काम करेगा लेकिन 3 बार आपको ड्यू डेट नजदीक आने के 3 दिन तक रिमाइण्ड कराया जायेगा। उसके बाद जब ड्यू डेट बीत जाएगी फिर भी अगर आपने जमा नहीं किया है तो उसके बाद भी हमने कहा है कि 3 बार फिर से आप उपभोक्ता को रिमाइण्ड कराइये कि भई देखिए, आपने बिल अपना जमा नहीं किया है, कृपा करके जमा कर दीजिए। दूसरे दिन देखिए आपका बिल जमा नहीं हुआ है, आपका कनेक्शन कट सकता है। तीसरी बार उनको सावधान कर दिया जाये कि अब आपका कनेक्शन किसी भी समय काटा जा सकता है। हमारे हाथ में जो मोबाइल होता है, उसमें जो व्यवस्था है, उस प्रकार की व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी, हम बिजली में भी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसका आनन्द आपको मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महबूब जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, यह तो बात स्पष्ट हो गयी कि कुछ छिपाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, कहां हुई साफ ! वह तो उन्होंने बता दिया और जो नहीं पता था, वह भी बता दिया।

श्री महबूब अली-

अब मैं पढ़ देता हूँ फिर इसे जो आपने जवाब भेजा है, जवाब, 17 सौ 64 हजार रुपये का आपने बताया कि बकाया बिल बाकी है। 17 सौ 64 हजार तो इन्होंने अपने विभाग पर ही मान लिया।

श्री अध्यक्ष-

17 सौ 64 है, हजार नहीं।

श्री महबूब अली-

जी मान्यवर, 17 सौ 64 हजार इन्होंने अपने ही विभाग पर मान लिया कि हां 12 सौ हजार मेरा बिल है, शुद्ध बिल है और लगभग 400-500 और है। मैं कहूंगा कि हर विभाग का बता दीजिए, इन्होंने सिर्फ अपने विभाग का बताया है।

श्री अध्यक्ष-

सब विभागों का उपलब्ध नहीं है।

श्री महबूब अली-

दूसरी बात, इनके पास कोई भी मीटर चेक करने जाता है, तो कोई प्रशिक्षित आदमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, इतना डिटेल में बताया है, दो-दो तीन-तीन बार मैसेज जा रहा है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोगों को पता चलेगा।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न से हटना नहीं चाह रहा हूँ।

(श्री जियाउद्दीन रिजवी अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप रिजवी साहब, क्यों उँगली कर रहे हैं। अरे, आप जबरदस्ती सवाल कर रहे हैं। उनका पूछना जरूरी है जिन्होंने प्रश्न लगाया है। महबूब जी।

(श्री अवधेश प्रसाद यादव जी के अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अवधेश जी, उनका प्रश्न आ रहा है, आपको इनके बाद बुलाऊँगा, आप बैठिए।

श्री महबूब अली-

अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब स्पष्ट नहीं आया है, उसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। उसकी रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं नहीं पूछ रहा। मैं विभागवार रिपोर्ट मा0 सदस्य को उपलब्ध करा दूँगा, यह प्रश्न था सीधा-सीधा, जिसका जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अवधेश जी को बुला लिया है।

(श्री महबूब अली जी के अपने स्थान से अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका तो प्रश्न आ गया है न।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, अभी मेरा प्रश्न नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

तो पूरा प्रश्न आए बिना ही प्रवर समिति को भेज रहे हैं।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, जब यह जवाब सही नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रवर समिति को जाने का अनुरोध मैं कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अलग-अलग कौन-सा जायेगा, कौन-सा नहीं जायेगा, इसके ऊपर भी निर्भर होगा।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, इसका जो यह अंश है, यह प्रवर समिति को जायेगा, मेरे दूसरे प्रश्न का हो सकता है कि वह जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय महबूब जी यह लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए।

(श्री अवधेश प्रसाद यादव जी के अपने स्थान से अपनी बात कहने पर)

अवधेश जी वह मूल प्रश्नकर्ता उनको पूछ लेने दीजिए, उसके बाद आप पूछ लीजियेगा।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, लगातार आज भी हमने अखबार में पढ़ा है कि बिना नियामक आयोग में जाए 23 रुपये फिर बिल में बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न का हिस्सा नहीं है।

श्री महबूब अली-

जी मान्यवर, यह मूल प्रश्न का हिस्सा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप खुद कह रहे हैं कि मैं प्रश्न पर रहूंगा फिर कह रहे हैं कि मूल प्रश्न का हिस्सा नहीं है।

श्री महबूब अली-

मैं प्रश्न पर आ रहा हूं, थोड़ा-सा बल तो दे लूं, मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया है।

श्री अध्यक्ष-

आपको पूरा अवसर दिया गया। आपने जितना पूछा आज तक किसी ने नहीं पूछा।

श्री महबूब अली-

दूसरा-मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आम जनता जिसके प्रतिनिधि खुद ऊर्जा मंत्री जी भी हैं, वह जिस तरह से सरकारी विभागों से वसूली कर रहे हैं वैसी बिल वसूली से आपको हमको और जनता को भी राहत देंगे।

श्री अध्यक्ष-

विभागों के बारे में आपने बकाया पूछा था।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, सीधा विभागों की ही तो बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं आप सीधा विभागों के प्रश्न पढ़िये, ये गलत बात है।

श्री महबूब अली-

सीधा सवाल यही है कि जिस तरह से बिजली बिल के भुगतान की सहूलियत विभागों को दी जा रही है, क्या आम जनता को बिजली कनेक्शन, विजिलेन्स, थाने आना-जाना इत्यादि में भी सहूलियतें दी जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष-

वह अलग-अलग परिस्थितियों में निर्भर करता है। अगर जल संस्थान वालों की टंकी की बत्ती काट देंगे तो पानी नहीं मिलेगा। उसका उस हिसाब से निर्णय किया जाता है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मेरा अनुरोध स्वीकार कर प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

बाकी दूसरा उत्तर भी आने दीजिये। आपके हिसाब से नहीं आया, लेकिन मंत्री जी का जवाब आ गया है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हमारे साथी ने उठाया है। श्रीमन्, यूं तो सरकारी बिजली अदायगी के सम्बन्ध में है, लेकिन आज बिजली के बिल के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अरे सरकारी बिल के ऊपर आप कहां से क्वेश्चन कर रहे हैं ? ओम प्रकाश जी अगर कोई रेलेवेन्ट बात हो तो पूछिये नहीं तो बैठ जाइये। मैं डिबेट थोड़े ही करा रहा हूं।

श्री अवधेश प्रसाद-

हिलौली गांव में सारे गांव का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

वह अलग से बताइयेगा। इससे उसका कोई मतलब नहीं है। कौन-कौन से गांव का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया इसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। आप अनावश्यक उसको क्यों पूछ रहे हैं ? अवधेश प्रसाद जी आप बैठ जाइये, आप बहुत सीनियर हैं, आपको तो बैठने को कहते हुए मुझे संकोच लगता है। माननीय अवधेश जी, प्लीज बैठ जाइये। ओम प्रकाश जी विषय पर आइये, ये बस लास्ट प्रश्न है आपका।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और सिंचाई का बिजली से बहुत गहरा रिश्ता है और सिंचाई विभाग पर बिजली विभाग का कितना बिल अभी बकाया है और क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं ? ये कृपया माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपको जानकारी हो तो बताइये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जैसा कि महबूब जी ने पूछा विभागवार, बाकी बिल का जो एमाउण्ट है, वो मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

वो लिस्ट बहुत लम्बी होगी आपको दे देंगे। माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग की जानकारी अगर उपलब्ध हो तो बता दीजिये नहीं तो दे दीजियेगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इसमें कुल धनराशि बताई गयी है और मैंने जो जवाब दिया है वह शुद्ध धनराशि का दिया है, उसको अलग करके मैं माननीय महबूब जी को दिखा दूंगा। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक सिंचाई विभाग की बात है, तो सिंचाई विभाग का हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें 34.49 करोड़ रुपया बकाया है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिसको 24 घण्टा बिजली चाहिए, जिसको फ्री बिजली चाहिए, जिसको विजिलेंस नहीं चाहिए, इन्क्वाइरी नहीं चाहिए, वह जाकर इटावा का एक गाँव है, वहीं रहने लगे।

***11-श्री जय प्रकाश अंचल-**

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में छोटे कॉलोनाइजर द्वारा विकसित कालोनियों में नवनिर्मित मकानों में विद्युत कनेक्शन कराने के सम्बन्ध में

***12-श्री मनोज कुमार पारस (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छोटे-छोटे कॉलोनाइजर द्वारा विकसित कॉलोनियों में बिना विद्युत कनेक्शन के रह रहे लोगों के लिए या नवनिर्मित मकानों में सरकार विद्युत कनेक्शन कराने हेतु कोई योजना लाएगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में छोट-छोटे कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित कालोनियों में विद्युत आपूर्ति हेतु तंत्र की स्थापना/व्यवस्था का दायित्व विकासकर्ता का है। विकासकर्ता द्वारा विद्युतीकरण का सम्पूर्ण व्यय वहन करने पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। यदि विकासकर्ता विद्युत संयोजन हेतु विद्युत

तंत्र का निर्माण कराये बिना ही प्लाटों/आवासों का आवंटन करते हैं, तो उस अवस्था में मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 21-09-2016 के प्रावधान के अनुसार उपभोक्ताओं से धनराशि जमा कराकर उनको विद्युत संयोजन जारी करने सम्बन्धी योजना विद्यमान है।

10 प्रतिशत प्लाट/आवास के मालिक आवेदन करने पर वितरण लाइसेन्सी द्वारा प्राक्कलन तैयार कर सम्बन्धित प्लाट/आवास के मालिकों अथवा आवेदनकर्ता को प्रेषित की जायेगी।

वितरण लाइसेन्सी द्वारा कार्य तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब 50 प्रतिशत प्लाट/आवास के मालिकों द्वारा रु0 35 प्रति वर्ग फुट के अनुसार तैयार की गयी प्राक्कलन धनराशि जमा कर दी गयी हो।

उपरोक्त योजना अविकसित प्लाटिंग क्षेत्रों में लागू है जिनमें न्यूनतम 25 प्रतिशत भवनों का निर्माण हो चुका है। (प्रति संलग्न)†

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***13-श्री राजेन्द्र कुमार-**

[03-गुरुवार के तारांकित प्र0सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के नगरों एवं नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में हो रहे अनियमित विकास को रोकने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

***14-श्री पंकज-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों एवं नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में हो रहे अनियमित विकास को रोकने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की संगत धाराओं-26, 27, 28 व 28क में महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में किये गये निर्माण, विकास रोकने की शक्ति एवं अनधिकृत विकास के ध्वस्तीकरण, विकास (निर्माण) को रोकने तथा सील करने की व्यवस्था है, जिसके अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

---

† देखिये नत्थी (क) का उत्तर आगे पृष्ठ सं0 .361-362... पर।

यह भी उल्लेख करना है कि अनियमित विकास/अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियन्त्रण/रोक-थाम हेतु शासनादेश संख्या-3805/8-3-2008-194 काम्प/2001, दिनांक 05-08-2008 व शासनादेश संख्या-1428/आठ-8-2018-194 काम्प/2001, दिनांक 09-08-2018 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त अभिकरणों को दिशा-निर्देश भी निर्गत किए गए हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पंकज-

अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वर्तमान में लखनऊ के साथ ही अन्य नगरों से सटे नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में हो रहे अनियमित विकास पर रोक लगाते हुए, अब तक हुए अनियमित विकास पर कोई नगरीय शुल्क लगाकर नियमित विकास कराने पर सरकार विचार करेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में नियमित विकास कराते हुए समस्त मूलभूत सुविधाएँ जैसे नाली, सड़क, बिजली तथा स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ?

पशुपालन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेन्शन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ ,हज एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1973 की धारा-26, 27, 28 व 28-क के अन्तर्गत अनियमित विकास को ध्वस्त कराना, जुर्माने का प्रावधान करना, अनियमित विकास रोकने की शक्ति एवं अनधिकृत विकास को सील करना, यह सरकार की प्राथमिकता में भी है। मान्यवर, नगरों और नगरीय क्षेत्र के समीपवर्ती हिस्सों में जो अनियमित विकास है, उसको विभिन्न धाराओं में रोकने का जुर्माना करने का प्रावधान भी है। मान्यवर, इन्हें पूछना यह चाहिए था-'अनियमित विकास को नियमित विकास करने के सम्बन्ध में मान्यवर, नगरीय क्षेत्र और नगरों के पास कुछ लोग अपनी जमीनों पर विकास का काम करते हैं। उन अनियमित विकास को भी नियमित करने की सरकार की प्राथमिकता है, जैसे माननीय सदस्य ने माँग की है, उसको नियमित करने पर सरकार विचार कर लेगी।

श्री पंकज-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सवाल था, नगरीय क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में नियमित विकास कराते हुए समस्त मूलभूत सुविधाओं जैसे नाली, सड़क, बिजली तथा स्ट्रीट लाइट की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी या नहीं ?

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, हमने आपके माध्यम से बता दिया है कि जो अनियमित विकास है, योगी सरकार की प्राथमिकता है, गरीबों को मकान बनाकर देना, अनियमित विकास को नियमित करना तथा सड़क, पानी, खड़ंजा, लाइट, इन सबकी व्यवस्था सरकार प्राथमिकता से करेगी, यह हमने आपको बताया।

***15-श्री अखिलेश**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण से आच्छादित गांवों की संख्या की जानकारी

***16-श्री जगदीश नारायण-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को आच्छादित कर दिया गया है तथा कितनों को किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष ग्रामों को उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सभी आबाद राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है। वर्ष 2018 के उपरान्त अब कोई भी राजस्व ग्राम विद्युतीकरण हेतु अवशेष नहीं हैं। पिछले 5 वर्षों में 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है, किन्तु संज्ञान में आया है कि कुछ मजरे अवशेष हैं इसके सम्बन्ध में भारत सरकार को आर0 डी0 एस0 एम0 योजना में विद्युतीकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा और मेरा बड़ा सीधा प्रश्न था कि प्रदेश में कितने ग्रामीण गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? जवाब में आया है कि प्रदेश की जनगणना के अनुसार सभी आबाद राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है, कुछ मजरे बाकी हैं और उसके लिए भारत सरकार से पैसा माँगा गया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कुछ मजरे, मतलब कितने मजरे प्रदेश में बाकी हैं, क्या इसकी कोई संख्या है और जो आपने पैसा माँगा है, आर0डी0एस0एस0 योजना के तहत् भारत सरकार से, वह माँग कब गई है और कितनी गई है ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है, आपके उत्तर

के अनुसार अगर सभी गाँव आच्छादित हो चुके हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण दूँगा, उसे आप नोट कर लें और बाद में हमको जानकारी दे दीजिएगा। जौनपुर जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गाँव डाड़ीडीह है, उस गाँव का विद्युतीकरण हुआ कि नहीं, इसको आप देख लीजिए, वहाँ खम्भे खड़े हैं, तार नहीं है, लोगों को बिल जा रहा है। हम लोग बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिएगा।

श्री जगदीश नारायण-

मान्यवर, हमने पूछ लिया है, यह बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लिख कर दे दीजिएगा तो पूरी जानकारी आ जायेगी।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो भाग हैं, एक तो गाँव का विद्युतीकरण और दूसरा है, राजस्व गाँवों के मजरों का विद्युतीकरण, मैंने यह कहा है कि राजस्व गाँवों का जो विद्युतीकरण का काम है वह पूर्ण हो गया है। माननीय सदस्य जो नाम ले रहे हैं, क्या वह गाँव, मजरा है, आप उसका थोड़ा डिटेल दे दीजिए तो हम दिखवा करके उसको करवाने का आवश्यक कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की जानकारी के लिए बता दूँ, आपको मालूम है कि जैसा कि हमारे सामने के मित्र लोग बार-बार यह बात कह रहे हैं कि माननीय फलॉ जी के टाइम पर सारा विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया।

मान्यवर, सारे गाँव विद्युतीकृत हो गये, सारे खम्भे ठीक हो गये, सारे ट्रांसफार्मर ठीक हो गये। माननीय शिवपाल जी भी बैठे हैं उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि इनके समय में बहुत कुछ काम बाकी था और उन्हीं में से यह भी एक गाँव होगा, यह भी मजरा होगा जो बाकी रह गया था। इस प्रकार के बाकी रह गये मजरों के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है और माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में भी कहा है। माननीय योगी जी की सरकार में कुल 1 लाख 21 हजार 324 मजरों का विद्युतीकरण हुआ है और यह प्रक्रिया निरन्तर चालू है। हजारों गाँवों की मुझे जानकारी है कि इन गाँवों का विद्युतीकरण अभी बाकी है। हमने माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी को 18 अक्टूबर, 2022 को एक पत्र लिखा है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है अगर चाहिए तो प्रस्तुत भी कर सकते है। जिसमें हमने कहा है कि पूर्वांचल के लगभग 18 हजार 818 मजरे, मध्यांचल के लगभग 12 हजार 372 मजरे, दक्षिणांचल के 5 हजार 710 मजरे। इस प्रकार कुल मिला करके 36 हजार 900 मजरे बाकी होने का एक अन्दाजा हम लोगों ने लगाया है। एक लाख 21 हजार

होने के बाद का यह आँकड़ा है। इसमें आपने खर्च भी प्रस्तावित पूछा था। जो पूर्वांचल के हैं उसमें 758 करोड़, मध्यांचल का आँकड़ा थोड़ा धूमिल हो गया है। इसमें कुल आँकड़ा 1958 करोड़ रुपये का हमने भेजा है। दक्षिणांचल का 516 है, मध्यांचल का फीगर्स थोड़ा धूमिल लगता है 683 हो सकता है या 583 हो सकता है। इस प्रकार से सम्पूर्ण दरखास्त भेजी है। भारत सरकार की टीम आई थी जिसमें उनके बीच और हमारे बीच आंकड़ों में थोड़ा फर्क है। उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला करके हमारी प्लानिंग है मैं स्वयं यह कहना चाहता हूँ कि जो आर0डी0एस0एस0 योजना चल रही है उसी में हमने दरखास्त भी किया है कि आर0डी0एस0एस0 योजना में अभी तक मजरों के या गाँव के विद्युतीकरण का कम्पोनेंट नहीं था। हमने विशेष रूप से माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह करके कहा है कि साहब अगर यह काम इस बार नहीं होगा तो हमेशा-हमेशा के लिए रह जायेगा। इसलिए मेहरबानी करके आर0डी0एस0एस0 में ले लीजिये। तो उन्होंने सहमति दी। उसका फायदा मात्र उत्तर प्रदेश को ही नहीं मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश को हुआ होगा, क्योंकि सभी जगह यह मजरे रह गये होंगे, उनको अच्छादित कर लिया जायेगा। इस प्रकार यह काम हमारे हाथ में है जो बाकी है उनका विद्युतीकरण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जो बाकी है उनको लिख कर दे दीजियेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो भारत सरकार से पैसा मांगा है, यह पैसा कब तक आ जायेगा और इन मजरों में कब तक विद्युतीकरण का काम पूरा हो जायेगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, हमने 18 अक्टूबर, 2022 को लिखा है। इसमें बात-चीत चल रही है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इसमें कब तक बात-चीत चलेगी।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मेरा प्रयास है कि यह बहुत जल्दी हो जायेगा।

विद्युत विभाग में कार्यरत पति/पत्नी कर्मियों की एक ही जनपद में स्थानान्तरण/आमेलन नीति लागू किये जाने विषयक

***17-डा0 पल्लवी पटेल-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग में कार्यरत पति/पत्नी कर्मचारियों की अलग-अलग जनपदों में तैनाती से उन्हें हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते

हुये पति/पत्नी को एक ही जनपद में तैनात किये जाने एवं अपने परिवारों/निवास स्थानों से दूर कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण/आमेलन नीति लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

पति/पत्नी दोनों के सरकारी/कारपोरेशन की सेवा में होने पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-430-ज0स0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2019-100 (01) प्र0सु0/92, दि0 03-06-2019 द्वारा निर्धारित अद्यतन लागू स्थानान्तरण नीति में विद्यमान प्राविधान के अनुसार कॉमन कैडर के कर्मियों को यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर में तैनात करने पर विचार किया जाता है।

परन्तु विभिन्न निगमों में से किसी एक निगम में आमेलित कार्मिकों का दूसरे निगम में स्थानान्तरण नियमानुकूल नहीं है। ऐसे कर्मचारियों का उसी निगम के परिधि के अन्दर स्थानान्तरण किये जाने का विचार किया जाता है।

कार्यालय-ज्ञाप सं0-2662/24-पी-2-2008-61एम0ई0/2000 टी0सी0-3, दिनांक 11-12-2008 द्वारा ऊर्जा निगमों में अन्तिम किये गये आमेलन के उपरान्त कारपोरेशन द्वारा कार्मिकों के अन्तर्निगमीय स्थानान्तरण/आमेलन के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की गयी :-

(i) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में कारपोरेशन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-696-ज0श0 एवं प्र0सु0 (01)/पाकालि/09-21-प्र0सु0/2001 टी0सी0-3, दिनांक 23-10-2009 द्वारा 'अन्तर्निगमीय स्थानान्तरण नीति' निर्गत की गयी, जो कि आदेश निर्गमन की तिथि से 02 माह तक प्रभावी रही।

(ii) उक्त के उपरान्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय-ज्ञाप सं0-66-ज0श0 एवं प्र0सु0 (01)/पाकालि/10-21-प्र0सु0/2001 टी0सी0-3, दिनांक 25-01-2010 द्वारा उक्त अवधि को 01 माह तक बढ़ाया गया।

(iii) पुनः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय-ज्ञाप सं0 395-ज0श0 एवं प्र0सु0 (01)/पाकालि/10-21-प्र0सु0/2001 टी0सी0-3, दिनांक-17-05-2010 द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 31-05-2010 तक बढ़ाया गया।

इस प्रकार आमेलित कार्मिकों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अन्तर्निगमीय स्थानान्तरण/आमेलन हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जा चुका है। अतः ऐसे कार्मिकों को एक निगम से दूसरे में स्थानान्तरण किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। तथापि ऐसे आमेलित कार्मिकों को निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत यथासम्भव एक ही जनपद/नगर में तैनात किये जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

डा0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, एक प्रदेश विकसित तब होता है जब उसकी विधायिका और कार्यपालिका आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं। आपसी सामंजस्य में कार्य करने के लिए विधायिका हो या कार्यपालिका उसके विभिन्न विभागों में पर्दे के पीछे से कार्य कर रहे हमारे सपोर्ट हैंड कहलाये जाने वाले उन विभागों में काम वाले हर कैडर के कर्मचारी होते हैं। आज उन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये मेरा प्रश्न था जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा अपने उत्तर में लिखा है कि विभिन्न निगमों में से एक निगम में आमेलित कार्मिकों का दूसरे विभाग में स्थानान्तरण नियमानुकूल नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि यदि एक दूसरे निगम में स्थानान्तरण नियमानुकूल नहीं है, तो दिनांक 23-10-2009 को अन्तर्निगमीय स्थानान्तरण नीति जोकि 2 माह के लिए प्रभावी थी क्या वह नियम के प्रतिकूल या अनुकूल थी। माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूँ कि यदि पति/पत्नी में से एक कॉरपोरेशन में हो तथा दूसरा किसी अन्य सरकारी अथवा प्राइवेट संस्थान में हो, तो उनके लिए क्या अलग-अलग रह पाना सम्भव होगा ? या यू0पी0पी0सी0एल0 इस तरह की समस्या को देखते हुए कुछ नियम बनायेगा? संविधान के अनुच्छेद-161 के अनुसार राज्य अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। इसका भी उल्लंघन हो रहा है, यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं। क्योंकि जूनियर इंजीनियर एवं कार्यकारी सहायक दोनों का कैडर समान है। परन्तु प्रमोशन्स के उपरान्त जूनियर इंजीनियर का स्थानान्तरण किसी भी जनपद में हो सकता है परन्तु किसी कार्यकारी सहायक का नहीं हो सकता है। क्या ऐसी विसंगतिया आपकी जानकारी में हैं, यदि हां तो आपने क्या कार्यवाही की, कृपया टेबल करें, यदि न तो डेडलाइन समेत क्या कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, इसको भी टेबल करें। धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जो प्रश्न है वह हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसका जवाब हमने दिया है। पहली बात तो यह कि हमारा समग्र ऊर्जा विभाग हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी अधिकारी, हमारे ऊर्जा परिवार के भाग हैं। उनकी सुख-सुविधा, उनकी व्यक्तिगत अनुकूलता का ध्यान रखना, जितनी आप चिंतित हैं उससे ज्यादा हम चिंतित रहते हैं और उसके लिए हम हर सम्भव प्रयास करते हैं कि उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना हो, उनके परिवार का हो, अच्छे ढंग से पालन हो, अच्छी मानसिकता से, अच्छी शारीरिक क्षमता से वे काम करें और उनका भविष्य सुखमय हो। लेकिन हर चीज में प्रशासन में कोई न कोई नीति बनानी पड़ती है, नीति यह है कि, जूनियर इंजीनियर और उनके ऊपर के कैडर को हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड कैडर जैसा मानते हैं या ऊपर का कैडर मानते हैं। उनके लिए तो जैसे हमारे 5 निगम हैं, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और आपका कानपुर, तो इनमें आपस में भी ट्रांसफर होता है, वरिष्ठ लोगों का और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, जब यह

बिजली विभाग का पुनर्गठन हुआ था नए-नए निगम बनाये गये थे, उस समय यह बात बड़ी सक्रिय रूप से चर्चा में आयी थी। यूनियन के साथ वार्तालाप भी किया गया और सभी कर्मचारियों को विकल्प दिया गया था कि आप इस निगम में रहना चाहेंगे या उस निगम में रहना चाहेंगे, जिसने जहां कहा उसको वहां कर दिया गया और इसको हम आमेलन कहते हैं, आमेलन हो गया उनका उस निगम में वह हमेशा के लिए उस निगम के कर्मचारी मान लिये गये और ऐसा जो उनको विकल्प दिया गया वह मा0 अध्यक्ष जी, एक बार नहीं मा0 सदस्या ने जो दिनांक 23-10-2009 का उल्लेख किया वह 23-10-2009 को भी दिया गया उसके बाद भी इस योजना को खुला रखते हुए वर्ष 17-05-2010 तक चलाया गया। मैंने आपको जवाब भी दिया उसके बाद भी उस योजना को अन्तिम रूप से दिनांक 31-05-2010 तक उस योजना को बढ़ाया गया, तो इस प्रकार हमारा यह कहना है कि इन कर्मचारियों को हमेशा के लिए वह किस निगम का भाग बने रहना चाहते हैं उसके लिए सम्पूर्ण विकल्प, सम्पूर्ण छूट दी जा चुकी है। जिसने जो विकल्प बताया था उस विकल्प के अनुसार उसको उस निगम में आमेलित कर लिया गया है। अब उनको एक निगम से दूसरे निगम में ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमने साथ में यह भी कहा है कि अन्य लोगों को या जहां ऐसी कोई परिस्थितयां आती हैं हम उनको नजदीक के जिलों में जैसे एक निगम का का भाग अब पूरा हो रहा है, दूसरे का भाग अब शुरू हो रहा है। यह सब जो मानवीय सुविधा करने की जो व्यवस्था होती है उसके प्रति भी हम सजग हैं और उस तरह की कोई व्यवस्था अगर करनी पड़ती है, तो हम करते हैं। वर्तमान में अब निगमों से एक निगम से दूसरे निगम में जाने की छूट देना, मुझे लगता है इसमें बहुत समय व्यतीत हो चुका है, काफी पानी बह चुका है नदी में, इसलिए इस व्यवस्था की पुनरावृति करना ठीक नहीं होगा, लेकिन व्यक्तिगत सुविधा में हम परिवार की सुख-सुविधा का ध्यान रखते हुए हम अवश्य उन बातों पर ध्यान देंगे।

डा0 पल्लवी पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मेरा सवाल यह है कि प्रमोशन के बाद जो विसंगतियां आ रही हैं, सेम कैडर के ट्रांसफर्स के लिए तो उस पर अगर आपने कार्यवाही की है, तो उसकी जानकारी चाहिए और यदि कार्यवाही नहीं की है, तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 सदस्या को बताना चाहूँगा कि प्रमोशन के बाद जो व्यक्ति मान लीजिए कि नीचे के कैडर का सहायक है, वह बाद में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर बन जाता है, तो स्वभाविक रूप से मैंने कहा कि यह जो व्यवस्था है वह लागू होगी। वह जे0 ई0 के नीचे के कैडर के लिए बाध्यता है जैसे ही वह ऊपर जायेगा उस पर ऊपर वाले कैडर का नियम लागू हो जायेगा। निगम के अन्दर रहने की,

वह जे0ई0 के नीचे के कैडर के लिए बाध्यता है जैसे ही वह ऊपर जायेगा उस पर ऊपर वाले कैडर का नियम लागू हो जायेगा।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, विधान सभा में आज भी कई प्रश्न विद्युत विभाग के लगे और पहले भी लगे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य इस प्रश्न पर सवाल पूछिये।

श्री इकबाल महमूद-

इन प्रश्नों पर जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उससे लगा कि मा0 मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा इन्वाल्व हैं। यह बहुत अच्छी बात है, परन्तु मेरा एक सवाल उनसे यह है कि अक्सर देखा गया है कि जब भी विद्युत विभाग के कर्मचारी की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह उसकी पत्नी को लगा दिया जाता है। मगर प्रैक्टिकल में अगर देखा जाये तो रात में कोई बिजली की खराबी आ जाती है, तो पोल पर चढ़ कर उसे ठीक कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि ठीक कौन करेगा, तो जो दूसरा आदमी होगा, उसको ठीक करेगा। यह संवेदनशील विभाग है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मंत्री जी को जवाब देने देंगे, तो सबको आसानी होगी। यह बहुत बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष-

यह इससे सम्बन्धित नहीं है, अगर कोई समस्या है, तो उसको अलग से बताओ। यह प्रश्न ट्रांसफर-पोस्टिंग और प्रमोशन से सम्बन्धित है। अगला प्रश्न श्री विनोद चतुर्वेदी जी।

***18-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन के कारण हटाया गया]

प्रदेश में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उपभोग से अत्यधिक विद्युत बिल भेजे जाने के सम्बन्ध में

***19-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उपभोग से अत्यधिक धनराशि के विद्युत बिल भेजे जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर बढ़ी धनराशि के बिलों को ठीक कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उपभोग से अत्यधिक धनराशि के विद्युत बिल भेजे जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

उपभोक्ताओं को अत्यधिक धनराशि के बिल भेजे जाने के प्रकरण संज्ञान में आते ही जांच कराकर त्रुटिपूर्ण बिलों को सम्बन्धित खण्ड द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसके लिए अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) अधिकृत है। त्रुटिपूर्ण बिलों के सृजन में लिप्त कार्मिक मीटर रीडर बिलिंग एजेन्सी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है।

त्रुटिपूर्ण बिलों का संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उपभोग से अत्यधिक धनराशि के विद्युत बिल भेजे जाने की जानकारी है ? उसका जवाब आया है कि जी हाँ। जो भी बिल त्रुटिपूर्ण होता है उसको संशोधित करने के लिए अधिशाषी अभियंता (वितरण) को अधिकृत किया गया है। यह ऐसा प्रश्न है कि कनेक्शन हमने लिया और कनेक्शन विद्युत वितरण से कर दिया गया, लेकिन मीटर नहीं लगाया। मीटर का खण्ड अलग है, मीटर लगाते नहीं हैं उसके बाद छापा पड़ता है और छापा पड़ने के बाद वह इतना लम्बा बिल देते हैं कि उपभोक्ता देने में सक्षम ही नहीं रहता। फिर उसकी तहसील में आर0सी0 भेज देते हैं। यह गलती मीटर न लगाने वालों की हैं इस पर उपभोक्ता को दण्ड क्यों मिले ? दूसरा, मेरा यह प्रश्न है कि 15 दिन की एक नोटिस देनी चाहिए। ये लोग तब तक नोटिस नहीं देते हैं जब तक 15 दिन गुजर नहीं जाते हैं। 15 दिन के बाद नोटिस देंगे, ताकि उपभोक्ता कहीं जा भी न सके। तीसरा, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरी खुद की विधान सभा क्षेत्र में तस्लीम पत्नी जाकिर, मोहल्ला-राजेपुरा, कालपी में उनका सिर्फ बिजली का कनेक्शन है, कोई पॉवर कनेक्शन नहीं है, उस पर 4284 किलोवाट निकाला और 4 लाख 79 हजार 712 रुपये का बिल 28-01-2023 में भेजा। दूसरा रु0 5,31,008 का बिल श्रीमती अख्तरी पत्नी श्री दौलत को 03-10-2022 को भेजा है। आप सोचिये कि क्या गरीब लोग यह बिल दे पायेंगे ? अगर नहीं देंगे तो आर0सी0 काट देंगे, आर0सी0 काट देंगे तो तहसील वाले पकड़ ले जायेंगे। अगर मीटर नहीं लगाया तो क्या उपभोक्ता की गलती है ? मीटर लगाने वाले कहो सालों तक मीटर न लगायें।..

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं मा0 मंत्री जी से एक तो जो यह चार लाख और पांच लाख का बिल है कम से कम यह इसको पूछें कि यह किस रूप में भेजा गया और दूसरा इनको

दण्डित किया जाए जो यह इस तरह टेरर पैदा कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन यह भी है कि कम से कम हम उपभोक्ताओं के लिए तो आपने टीमें बनाई हैं, विजिलेन्स बनाई है, जो इनके लोग ए0ई0, जे0ई0, सुबह उठते ही एक लाख रुपये पैदा करते हैं इनकी क्या व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

इसका कोई प्रमाण हो तो बताइए।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम एक टीम गठित करें यह रोज जो चोरी कर रहे हैं इनको भी दंड दिया जाए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति हो, तो जरा वह नाम मैं फिर से सुनना चाहूंगा जो आपने नाम बोला है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, तसलीम पत्नी जाकिर मोहन लाल राजेपुरा 28-01-2023 को दिया है चार लाख नवासी हजार सात सौ बारह रुपये और दूसरा है अख्तरी वाइफ ऑफ दौलत पांच लाख इकतीस हजार आठ रु0 03-10-2022 को दिया है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, तो यह मान लिया जाए कि इनके अलावा बाकी का बिल ठीक-ठाक जा रहा है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 मंत्री जी और भी बहुत से बिल हैं।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ जाने दीजिए फिर पूछ लीजिएगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैंने जवाब दिया है और मैंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि बिल बनाने की प्रक्रिया में कई बार त्रुटि होने की शिकायतें आती हैं और उन शिकायतों को दूर करने के लिए एक पूरा व्यवस्था तंत्र है और यह किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कहीं कम कहीं ज्यादा होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मा0 सदस्य ने जो दो नाम लिए उनका अगर हमको नाम, पता मिल जाए तो मैं उसके व्यक्तिगत केसों को दिखवा लूंगा, लेकिन मैं यह मान रहा हूं कि आपके क्षेत्र में बाकी सब सलामत है, केवल दो ही लोग परेशान हैं।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, दो लोग यह तो मैंने उदाहरण के रूप में बताए हैं वैसे बहुत लोग अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरे जिलें की लिस्ट दें दूंगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, इस प्रकार की जो शिकायतें आती हैं उसमें पिछले कई महीनों से कई काम हम लोगों ने किए हैं जिनका मैं थोड़ा वर्णन करना चाहूंगा सबसे पहला काम यह था कि गर्मी के दिनों में हमने विद्युत समाधान सप्ताह चलाया था, पूरे तंत्र को हमने लगभग बारह घण्टे चौदह घण्टे इसी काम पर पूरा पन्द्रह दिन लगाया हुआ था और मैं स्वयं एक-एक सब-स्टेशन पर जाकर के बैठता था देखने के लिए कि क्या यह शिकायतें वाजिब हैं। कहीं मीटर नहीं लगाने का जैसा आपने कहा, मीटर लगाए बिना बिल दे देना, बिल ज्यादा दे देना, ज्यादा दे करके फिर कम कर देना, यह सारी शिकायतें आती थीं उसका काफी अच्छा परिणाम निकला था। एक लाख तिहत्तर हजार लोगों की ऐसी शिकायतों का समाधान किया गया था। साथ ही हमने यह भी कहा है कि हमने एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू किया है सम्भव नाम की और यह भी कहा है कि हमारे सभी क्षेत्रीय अधिकारी हर सप्ताह एक्सीएन के लेवल पर सोमवार को दस बजे एस0ई0 के लेवल पर सोमवार को एक बजे और चीफ इंजीनियर के लेवल पर सोमवार को ही चार बजे से पांच बजे तक से जन सुनवाई करेंगे। जिसमें ऐसी शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाएगा। साथ ही हमने कहा है कि मंगलवार को डिस्कॉम के एम0डी0 के स्तर पर जन शिकायतों के निपटारे के लिए सुनवाई होनी चाहिए और वह भी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद हमने सम्भव नाम का एक बहुत अच्छा बहुत महत्वाकांक्षी पोर्टल शुरू किया है जिसमें आपकी जानकारी एवं मा0 सदन के जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि न सिर्फ मा0 विधायकगण की तरफ से आने वाली शिकायतें, न सिर्फ मा0 सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि की तरफ से, मा0 मंत्री जी लोगों की तरफ से आने वाली शिकायतें, बल्कि मा0 मुख्य मंत्री जी के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर जो शिकायतें आती हैं उसको भी हम स्कैन करते है मा0 प्रधानमंत्री जी के पोर्टल पर जो शिकायतें आती हैं उसको भी हम स्कैन करते हैं और हमारे खुद के वेबसाइट पर हमारा खुद का अपना तेज नाम का पोर्टल है उस पर जो शिकायतें आती हैं उसको भी हम देखते हैं सोशल मीडिया के जरिये जो शिकायतें हमारे संज्ञान में आती हैं उसको भी हम लेते हैं। हमें कोई ई-मेल करके बताता है उसको भी हम संज्ञान में लेते हैं हमारे घर पर या प्रवास के दरमियान या अन्य मंत्रीगण के प्रयास के दरमियान जो शिकायतें मिलती थी।

हर महीने इन सारी शिकायतों को इकट्ठा करके नीचे के स्तर पर अगर उनका निस्तारण नहीं होता है, तो हम उसको अपने स्तर पर ले करके एक बड़ी ही सुन्दर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक मल्टी मॉडल अरेन्जमेंट के अन्तर्गत हम सैटेलाईट से फोटो भी मंगा कर वहाँ

की वर्तमान स्थिति भी जान लेते हैं। हर महीने के एक बुधवार को मैं यह बैठक करता हूँ जिसमें एक तरफ हमारे अधिकारीगण तथा दूसरी तरफ शिकायतकर्ता भी उपस्थित रहता है। ज्यादातर शिकायतकर्ताओं की शिकायतें 'सम्भव पोर्टल' पर डालते ही उनका निस्तारण हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो शिकायतें रह जाती हैं, मेरे मार्गदर्शन के बाद उनका भी निस्तारण किया जाता है। जहाँ तक कर्मचारियों के आचरण तथा उनकी कार्यशैली की बात हैं तो मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूँ कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जायेगा, लेकिन यह मानना या यह कहना कि बिजली विभाग के सभी कर्मचारी दोषी हैं या सभी कर्मचारी बदमाश और भ्रष्ट हैं, यह कहना शायद ज्यादा होगा।

(इसी मध्य सदस्य श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा अपने स्थान से अनुपूरक पूछे जाने हेतु अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी की तरफ से पूरा डिटेल में उत्तर आ गया है। अब इसमें कुछ और पूछे जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जहाँ भी इस तरह के गलत बिल की, बिना मीटर लगाये बिल देने की शिकायतें आती हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लाखों ऐसे कस्टमर थे जो हमारी शब्दावली में अनमीटर्ड कहे जाते थे। ऐसे अनमीटर्ड, लेकिन बिजली का उपभोग कर रहे तमाम उपभोक्ताओं को हम लोगों ने मीटर दे करके उनको मीटर की परिधि और मीटर की व्यवस्था में लाने का प्रयास किया है। यह सारी व्यवस्थाएं काफी चुस्त-दुरुस्त हुयी हैं, फिर भी अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक शिकायत हो तो मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य की अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत होगी तो वह आपको दे देंगे।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 विनोद जी, इससे ज्यादा डिटेल में तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। इतना डिटेल में उत्तर आने के बाद अब छोटा-सा प्रश्न कहाँ बचता है। मा0 मंत्री जी ने पूरा डिटेल दिया है और बहुत विस्तृत जानकारी दी है।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर आपने कनेक्शन दे दिया तो उसके बाद कितने दिन में मीटर लग जायेगा, इस पर क्या सरकार कोई कानून बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 विनोद जी, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मा0 मंत्री जी के जवाब में आ गया है। अब अगला प्रश्न मा0 नफीस अहमद जी का है।

प्रदेश के जिला अधिष्ठान के लिपिकीय संवर्ग में उच्च ग्रेड-पे में पदोन्नति के पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में

***20-श्री नफीस अहमद-**

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभागीय पुनर्गठन में जिला अधिष्ठान के कार्मिकों को मात्र 2800 ग्रेड पे में पदोन्नति के लिये 69 पद सृजित किये गये व उसके ऊपर के वेतन बैण्ड में पदोन्नति के अवसर नहीं दिये गये है ? क्या सरकार मुख्यालय संवर्ग व अन्य विभागों के लिये संवर्ग की भाँति जिला अधिष्ठान के लिपिकीय संवर्ग में भी उच्च ग्रेड-पे 4200, 4600 या 4800 में पदोन्नति के लिए पद सृजित करने एवं पुनर्गठन की विभागीय कार्य योजना प्रस्तावित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-5/2016/635/94-1-2016-312 (54)/2013, दिनांक 20-07-2016 वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के सन्दर्भ में निर्गत किया गया है। इस शासनादेश में जिला अधिष्ठान हेतु सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायकों को 2000 ग्रेड-पे अनुमन्य है तथा पदोन्नति के 68 पद वरिष्ठ सहायक के ग्रेड-पे 2800 में दिए जाने की व्यवस्था है।

उपर्युक्त शासनादेश सं0-5/2016/635/94-1-2016-312 (54)/2013, दिनांक 20-07-2016 द्वारा लिपिकीय संवर्ग पुनर्गठन किया जा चुका है। सम्प्रति उक्त व्यवस्था विभाग में प्रचलित/लागू है। अन्य कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या विभाग द्वारा किये गये जिला अधिष्ठान कैडर के पुनर्गठन में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08-03-2011 लिपिकीय सेवा नियमावली में दिये गये पद और वेतन बैण्ड इस कैडर को दिये गये ? दूसरा, जबकि मुख्यालय कैडर का पुनर्गठन उक्त शासनादेश के अनुरूप किया गया। प्रदेश के सभी विभागों में उक्त लिपिकीय सेवा नियमावली के अनुरूप 2000 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड-पे में पद सृजित हैं। वित्त विभाग के जी0ओ0, लिपिकीय सेवा

नियमावली व भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 व 16 की मंशा के विपरीत किये गये उक्त पुनर्गठन को संशोधित करते हुये जिला अधिष्ठान के कर्मियों को भी 4200, 4600, 4800 ग्रेड-पे या उच्च पे लेवल में पद और वेतन प्रदान करने का काम क्या यह सरकार करेगी ? मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि सदन में त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक उत्तर देने के लिये क्या सरकार विभागीय अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में वर्ष 2016 में जो नियम बनाये गये थे उसी के अनुसार पदोन्नति हो रही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है और न ही कोई भ्रामक उत्तर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहे हैं।

(इसी मध्य सदस्य श्री समरपाल सिंह द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने हेतु अनुरोध करने पर)

मा0 सदस्य, पहले मूल प्रश्नकर्ता अनुपूरक प्रश्न पूछ लें, उसके बाद आप पूछ लीजियेगा।

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने मा0 मंत्री जी से पूछा है कि वित्त विभाग के जी0ओ0 व लिपिकीय सेवा नियमावली तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 व 16 की मंशा के विपरीत किये गये पुनर्गठन को संशोधित करते हुये जिला अधिष्ठान के कर्मियों को 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे अथवा उच्च पे लेवल पर पद और वेतन प्रदान करने का काम क्या यह सरकार करेगी? मा0 मंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नफीस जी, यह तो आप पूछ चुके हैं। श्री समरपाल जी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री समरपाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं। कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नौगवां में तहसील बना दी गयी है किन्तु वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस नहीं है, जो है वह अमरोहा के अन्तर्गत दूसरी तहसील में आता है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न से क्या मतलब है ?

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस कब तक खुल जायेगा जबकि जमीन और मकान मैंने एस0डी0एम0 को बिना किराये के उपलब्ध करा दिया है। अब वहां के जिलाधिकारी कहते है कि मा0 मंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं जिसके कारण रजिस्ट्री ऑफिस का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी समय दे दें जिससे कि रजिस्ट्री ऑफिस का उद्घाटन हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, समय दे दीजिए।

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

ठीक है मा0 अध्यक्ष जी, समय दे देंगे।

अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है और आज सारे 20 प्रश्न ले लिए गये हैं। आज कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा है जो न लिया गया हो।†

अतारांकित प्रश्न

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट स्थित सिद्धपीठ माता शाकुम्भरी देवी से सहारनपुर तक जाने वाली मार्ग को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में

1-श्री उमर अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद सहारनपुर में विधान सभा क्षेत्र बेहट स्थित सिद्धपीठ माता शाकुम्भरी देवी से सहारनपुर तक जाने वाली सड़क को फोर लेन करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश)-

सहारनपुर से बेहट (एस0एच0-57) मार्ग के चैनेज किमी0 162.00 से 166.00 तक मार्ग पूर्व से ही 4 लेन से सन्तृप्त है। बेहट से भूरादेव मन्दिर तक आरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण 4 लेन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। भूरादेव मन्दिर से माँ शाकुम्भरी देवी मुख्य मन्दिर तक 4 लेन एलिवेटेड सेतु का निर्माण मल्टीलेवल पार्किंग के बिना फिजिबिल नहीं है, जिसकी

---

† नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न सं0-20 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

कार्यवाही पर्यटन विभाग द्वारा की जानी है। उक्त के अतिरिक्त एलिवेटेड सेतु के निर्माण हेतु वन विभाग की अनापत्ति एवं मंदिर के न्यास की पूर्वानुमति की आवश्यकता है।

अतएव सहारनपुर से बेहट मार्ग के चैनेज 167.00 किमी0 से 207 किमी0 (लम्बाई 40.00 किमी0) तक 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य, बेहट से भूरादेवी मन्दिर तक 2 लेन मार्ग का पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण कार्य एवं भूरा देवी मन्दिर से माँ शाकुम्भरी देवी मुख्य मन्दिर तक 4 लेन एलिवेटेड सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण की स्वीकृति वन विभाग और मन्दिर के न्यास की अनापत्ति/पूर्वानुमति प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सहारनपुर के शिवालिक वन क्षेत्रों में रहने वाले वन गुर्जरों के पुनर्वास के सम्बन्ध में

2-श्री उमर अली खान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वनों में रहने वाली आबादी के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेहट विधान सभा क्षेत्र जनपद सहारनपुर की शिवालिक वन क्षेत्रों में रहने वाले वन गुर्जरों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा विज्ञापित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के प्राविधानों एवं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत कोर/क्रिटिकल बाघ क्षेत्र से पुनर्वास की योजना वर्तमान में है। प्रश्नगत क्षेत्र उक्त श्रेणी में नहीं आता है।

3-श्री अमिताभ बाजपेई-

(02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण में स्थानीय विधायक को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में

4-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण में स्थानीय विधायक को आमंत्रित करना व शिलालेख में नाम लिखने के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पत्र दिनांक 14-02-2023 एवं दिनांक 25-02-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण में स्थानीय मा0 विधायकों को आमंत्रित किया जाता है एवं शिलापट्ट पर मा0 विधायकों के नाम लिखे जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-399/नौ-5-2016-265 सा/2015, दिनांक 24-02-2016 एवं शासनादेश संख्या-6711/नौ-5-2018-524 सा/2018, दिनांक 20-01-2021 द्वारा नगर विकास विभाग के समस्त विकास कार्य जिनमें नगर विकास विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत की जाती है, उनमें विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलालेख/पट्टिका में मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में गौरा बाजार स्थित लेबर कालोनी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री जै किशन साहू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र में लेबर कालोनी, गौरा बाजार का निर्माण कार्य रुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार लेबर कालोनी, गौरा बाजार का शेष निर्माण कार्य को जनहित में प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

उक्त कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या-210ईजी/23-5-08-50 (139) ईजी/07, दिनांक 20-03-2008 के द्वारा रु0 632.21 लाख की प्रदान की गयी थी, जिसके अन्तर्गत श्रेणी-4 के 9 आवास, श्रेणी-3 के 6 आवास व श्रेणी-2 के 47 आवास पूल्ड हाउसिंग कैम्पस में एवं श्रेणी-1 के 50 आवासों का निर्माण लेबर कालोनी गौरा बाजार कैम्पस में कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के अन्तर्गत गौरा बाजार स्थित लेबर कालोनी में प्रस्तावित श्रेणी-1 के 50 आवासों में 24 आवास निर्माणाधीन हैं एवं 26 आवासों हेतु परिसर में भूमि उपलब्ध नहीं है।

उक्त कार्य एस0आई0टी0 जांच से आच्छादित होने के कारण विगत वर्षों से बन्द था। वित्तीय अनियमितता/एस0आई0टी0 जांच से आच्छादित होने के दृष्टिगत लोक निर्माण अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-1692/23-8-2022-9सीबी/2020, दिनांक-10-11-2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कार्य को पुनः प्रारम्भ कराये जाने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

6-श्री सचिन यादव-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांवों में जर्जर हो चुकी विद्युत लाइनों को बदलवाने के सम्बन्ध में

7-श्री सचिन यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विभिन्न गांवों में पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी विद्युत लाइनों से विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है एवं जर्जर तार के टूटने से दुर्घटना होने की स्थिति में जान-माल की भी हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को बदलवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-फिरोजाबाद में तहसील जसराना के क्षेत्रान्तर्गत विद्युत लाइन पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में नहीं है। वर्तमान में रोस्टर के अनुरूप ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है और जर्जर तार से दुर्घटना का कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में अतिभारित ट्रांसफार्मर की संख्या एवं उनकी क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

8-डॉ0 रागिनी -

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में कितने ट्रांसफार्मर अतिभारित हैं ? क्या सरकार सर्वे कराकर निश्चित समय-सीमा में उक्त अतिभारित ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कोई नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली कनेक्शन हेतु तय दर से अधिक वसूल की गई धनराशि को वापस किये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के लिए तय दर से अधिक वसूल की गई 2.27 करोड़ रुपये की धनराशि वापस करने का आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

ऐसे संयोजनों को चिन्हित कर कॉस्ट डाटा बुक की दरों से भिन्न जमा अतिरिक्त धनराशि को उपभोक्ताओं को वापस किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

	पूर्वान्चल	मध्यान्चल	पश्चिमांचल	दक्षिणांचल	केरको	योग
उपभोक्ता की संख्या	98	2203	197	118	13	2629
वापस की गयी धनराशि (लाख में)	16.22	272.33	25.56	24.43	0.60	399.14

प्रश्न नहीं उठता।

10-प्रश्न हटाया गया।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर0ई0सी0) की कन्ज्यूमर सर्विस रेटिंग में प्रदेश की कंपनियों के खराब प्रदर्शन की जानकारी एवं उसे सुधारे जाने के सम्बन्ध में

11-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर वर्ष 2020-21 हेतु जारी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आर0ई0सी0) की कन्ज्यूमर

सर्विस रेटिंग में प्रदेश की कंपनियों का प्रदर्शन खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ता हित में कंपनियों के प्रदर्शन को सुधारने हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रदेश की कम्पनियों की कन्ज्यूमर सर्विस रेटिंग का प्रदर्शन निम्नवत् है :-

डिस्कॉम	कुल ग्रेड
दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, आगरा	D
केस्को, कानपुर	A
मध्यान्चल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ	D
पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, मेरठ	C
पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी	C

कन्ज्यूमर सर्विस रेटिंग में सुधार के लिए सरकार ने कई प्राविधान किए हैं। नया विद्युत संयोजन घर बैठे झटपट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नए औद्योगिक संयोजन निवेश मित्र पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं कृषक अपने निजी नलकूप का संयोजन पी0टी0डब्ल्यू0 पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। उपभोक्ताओं की विभिन्न बिल सम्बन्धी शिकायतों को समाधान हेतु पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। उपभोक्ता अपने विद्युत भार में परिवर्तन पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति एवं मीटर सम्बन्धी या अन्य किसी समस्या के लिए कस्टमर केयर सेंटर 1912 (24x7) कार्यरत है।

विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार की जाती है एवं विद्युत आपूर्ति का अनुश्रवण 24x7 किया जाता है। उपभोक्ताओं को त्रुटि रहित बिल बनाने हेतु मीटर की रीडिंग प्रो0 एवं एम0आर0आई0 के माध्यम से की जाती है, जिससे कि उपभोक्ताओं को त्रुटि रहित बिल मिल सके।

विद्युत बिल जमा करने हेतु उपभोक्ताओं के पास अनेक विकल्प हैं जैसे-ऑनलाइन, मीटर रीडर के माध्यम से सी0एस0सी0 सेंटर, विद्युत सखी एवं राशन की दुकानों पर बिल जमा किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-चित्रकूट के ग्राम पंचायत संग्रामपुर में मुनगी तिराहा से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश बॉर्डर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने विषयक

12-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत संग्रामपुर में खोही शिवरामपुर मार्ग में मुनगी तिराहा से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश बॉर्डर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत ग्राम संग्रामपुर एवं मुनगी तिराहा तथा मध्य प्रदेश बार्डर पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुड़े हुए हैं। प्रश्नगत मार्ग मुनगी तिराहा को मध्य प्रदेश बार्डर से जोड़ने से सम्बन्धित है। जो डबल कनेक्टिविटी का प्रकरण है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-चित्रकूट में खोह के पास बन रहे रेलवे उपरिगामी सेतु का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में खोह के पास बन रहे रेलवे उपरिगामी सेतु का कार्य विगत 3 वर्षों से बंद है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेतु का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

रा0मा0-76 (नया रा0मा0-35) पर स्थित खोह आर0ओ0बी0 का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में प्रारम्भ हुआ, कार्य की जी0ए0डी0 उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज से अनुमोदित थी, परन्तु निर्माण कार्य के दौरान रेलवे द्वारा अनुमोदित जी0ए0डी0 पर आपत्ति व्यक्त करने के कारण कार्य को स्थगित करना पड़ा।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज द्वारा रिवाइज्ड जी0ए0डी0 अनुमोदित कर दी गयी है। तदनुसार सृजित सी0ओ0एस0 (चेंज ऑफ स्कोप) मंत्रालय से अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रिया में है। उक्त रेलवे उपरिगामी ब्रिज का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के जनपद अधिष्ठान के कनिष्ठ सहायक कर्मिकों के नियम विरुद्ध पदोन्नति होने का प्रकरण

14-श्री अभय सिंह-

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद अधिष्ठान के 1122 कनिष्ठ सहायक कार्मिक जो 100 से अधिक कार्यालयों में उप निबन्धक के पदीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, की पदोन्नति बिना किसी विहित विधि व्यवस्था के नियम विरुद्ध करने

सम्बन्धी प्रकरण सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर उप निबन्धक सेवा नियमावली, 1983 व जिला अधिष्ठानों के कैडर की समीक्षा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

जी नहीं।

प्रभारी उप निबन्धक के पदीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले कनिष्ठ सहायक, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा-12 एवं महानिरीक्षक निबन्धक के परिपत्र संख्या-2901, दिनांक 30-07-2013 के अनुसार जनपदीय ज्येष्ठता (वरिष्ठता) के आधार पर कार्य कर रहे हैं। नियम विरुद्ध किसी की पदोन्नति नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के बांकेगंज क्षेत्र में नेपाल के शुक्ला फाटा नेशनल पार्क के जंगल में 40 हाथियों के लापता होने के सम्बन्ध में

15-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के बांकेगंज क्षेत्र में नेपाल के शुक्ला फाटा नेशनल पार्क से जंगल में पहुंचे 63 हाथियों में से 40 हाथियों के लापता होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में दिनांक 30-11-22 तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ है तथा इस क्षेत्र में नेपाल से हाथियों का आवागमन होता रहता है, जिसकी सतत् निगरानी वन विभाग द्वारा की जाती है।

अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारी समितियां के वेतनमान उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में

16-श्री पंकज मलिक-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारी समितियां, उ0प्र0 का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक : ग-7 न0-07920, दिनांक 28-12-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जे0पी0एस0 राठौर)-

जी हां।

श्री धर्मवीर मलिक, सेवानिवृत्त सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 अपर जिला सहकारी अधिकारी को शासनादेश संख्या-1847, दिनांक 07-08-2006 द्वारा उच्चीकृत वेतनमान के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण का लाभ वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1251/दस-2012-308/97 टी0सी0, दिनांक 21-12-2012 में निहित व्यवस्थानुरूप देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली में (झाल-सल्फा लिंक रोड पर जर्जर नाला का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

17-श्री पंकज मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में झाल-सल्फा लिंक रोड पर जर्जर नाला का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-घ-6 नं0 403225 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पी0आई0यू0 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग शामली के अन्तर्गत निर्मित किया गया है। मार्ग दिनांक 30-06-2027 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 के अनुरक्षणाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की अनियोजित कॉलोनियों को नियोजित करने की सरकार की योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

18-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अनियोजित कॉलोनियों को नियोजित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001, दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गई थी। शासनादेश

संख्या-5438/9-आ-3-2001, दिनांक 02-12-2003 एवं शासनादेश संख्या- 3805/8-3-2008-194 काम्प/2001, दिनांक 05-08-2008 द्वारा उक्त गाइडलाइन्स में कतिपय संशोधन किए गए हैं। शासनादेश संख्या-1428/आठ-8-2018-194 काम्प/2001, दिनांक 09-08-2018 द्वारा अनधिकृत कालोनियों पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मेरठ में विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017 के उपरान्त स्वीकृत हुए मानचित्रों की संख्या, आय एवं बिना नक्शा पास भवन निर्माण करने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

19-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017 के उपरान्त कितने भवन स्वामियों के मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं कितने विचाराधीन हैं तथा उक्त से कितनी आय हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि बिना नक्शा पास भवन निर्माण करने पर कितने लोगों को नोटिस जारी कर कितना कम्पाउन्ड शुल्क वसूला गया है ? क्या सरकार भवन मानचित्र की समयवद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जनपद मेरठ में विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 के उपरान्त दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक कुल 5852 भवन स्वामियों के मानचित्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृत किये गये हैं तथा 454 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं जिनका निस्तारण आवेदकों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त किया जायेगा। मानचित्र स्वीकृति से मेरठ विकास प्राधिकरण को 9472 लाख रुपये की आय हुई है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अवधि में बिना मानचित्र पास कराये भवन निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 7315 नोटिस जारी किये गये हैं तथा शमन शुल्क के मद में 3317.40 लाख रुपये वसूल किये गये हैं। प्रदेश में भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु लागू ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा शुल्क जमा कराये जाने पर भवन मानचित्र निर्गत किये जाते हैं। मानचित्र स्वीकृति में आने वाली कठिनाइयों के निस्तारण हेतु विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में प्रत्येक बृहस्पतिवार को मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आवेदकों की कठिनाइयों/आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में खुन्दनपुर रोड से जाफरपुर बार्डर तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

20-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में खुन्दनपुर पिच रोड से भरसारी चौहान बस्ती होते हुए चन्द्रभानपुर, जाफरपुर बार्डर तक 06 किमी0 की सड़क जर्जर गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कम्हरिया बिन्द्रा बाजार मार्ग से भदसारी चौहान बस्ती लम्बाई 1.500 किमी0 एवं बिन्द्रा बाजार मेहनगर मार्ग से दूबे के पुरा के पास मंगरावां ग्राम में घुरहुआ मंगरवां खुन्दनपुर मार्ग लम्बाई 0.700 किमी0 जिला पंचायत आजमगढ़ के अधीन है।

गोमाडीह मेहनगर नहर की पटरी से चन्द्रभानपुर सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसकी सामान्य मरम्मत/नवीनीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-7 नं0 226956, दिनांक 27-12-2022 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

21-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़क मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-7 नं0 226956, दिनांक 27-12-2022 को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

पत्र में अंकित कुल 29 मार्गों में से क्रमांक-1, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 26 व 29 पर अंकित कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

क्रमांक-2, 9, 13, 17, 20, 22 व 25 पर अंकित मार्ग गड्ढामुक्त एवं यातायात हेतु पैच रहित है। क्रमांक-3 व 15 पर अंकित मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधीन है तथा क्रमांक-4 पर अंकित मार्ग की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत प्रदान की गयी है।

क्रमांक-6, 7, 14, 21 पर अंकित मार्ग के मरम्मत का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

क्रमांक-19, 27 व 28 पर अंकित मार्ग के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-7 नं0 226960, 27-12-2022 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22-श्री बेचई सरोज

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़क मार्गों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-7 नं0 226960, दिनांक 27-12-2022 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ

पत्र में उल्लिखित मार्गों की विशेष मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में चेवार पूरब गांगी नदी पुल से गोवर्धनपुर तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

23-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में चेवार पूरब गांगी नदी पुल से गोवर्धनपुर तक 500 मीटर जर्जर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-7 नं0 226959, दिनांक 27-12-2022 को प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग चेवार पूरब गांगी नदी के पुल से गोवर्धनपुर सम्पर्क मार्ग जो कि लोक निर्माण विभाग के रिकार्ड में गोवर्धनपुर सम्पर्क मार्ग के नाम से दर्ज है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है। विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत रु0 25.80 लाख की

स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मार्ग की मरम्मत का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के तहसील मुख्यालय हाटा में रजिस्ट्री भवन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24-श्री मोहन वर्मा-

क्या स्टाप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के तहसील मुख्यालय हाटा में खाली पड़े जमीन पर रजिस्ट्री भवन के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सख्या-ख-7 नं0 130536 दिनांक 22-09-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

जी हाँ।

महानिरीक्षक कार्यालय के पत्र संख्या-2271, दिनांक 23-11-2022 द्वारा जिलाधिकारी, कुशीनगर को आवश्यक कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम गुजरपार में डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति से प्राथमिक विद्यालय तक की क्षतिग्रस्त रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

25-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम गुजरपार में डा0 भीमराव अम्बेडकर मूर्ति से प्राथमिक विद्यालय तक की रोड क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में शोहरतगढ़-मुबारकपुर मेन रोड से मुहब्बत रौजा सम्पर्क मार्ग तक जर्जर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

26-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में शोहरतगढ़-मुबारकपुर मेन रोड से मुहब्बत रौजा सम्पर्क मार्ग तक मार्ग जर्जर

एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग रौजा यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.700 किमी0 की विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य की वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लागत रु0 21.18 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत सिकंदरपुर बागिहवा का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री अखिलेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत ग्राम सिकंदरपुर बागिहवा का विद्युतीकरण कराये जाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ, विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत ग्राम सिंकदरपुर बागिहवा का विद्युतीकरण सौभाग्य योजना के अन्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में मोहम्मदाबाद मेन रोड से मोईनाबाद सम्पर्क मार्ग की जर्जर सड़क के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

28-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में मोहम्मदाबाद मेन रोड से मोईनाबाद सम्पर्क मार्ग की जर्जर सड़क का मरम्मत कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुहम्मदाबाद मुबारकपुर से मुईनाबाद ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसके विशेष मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में सठियावं मुबारकपुर मेन रोड से यूनिवर्सिटी के सामने अशरफ से ग्राम देवली एवं आदमपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में सठियावं मुबारकपुर मेन रोड से यूनिवर्सिटी के सामने अशरफ से ग्राम देवली एवं आदमपुर सम्पर्क मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुबारकपुर यूनिवर्सिटी से आदमपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.750 किमी0 की विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत लागत रु0 29.12 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मार्ग की मरम्मत का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात में नई सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री समरपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात में विगत 1 वर्ष से किसी भी नई सड़क का निर्माण किये जाने से कच्चे रास्तों पर आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कच्चे मार्गों को पक्का/नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के समस्त ग्राम सिंगल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत पूर्व से सम्पर्क मार्ग से सन्तृप्त हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्प्रभाव तथा कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी के रोकथाम हेतु कार्य योजना की जानकारी

31-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्प्रभाव तथा कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी को रोकने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हां।

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्प्रभाव तथा कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी को रोकने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन कराते हुये उ0प्र0 राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना निरूपित की गई है। उक्त कार्य योजना में 08 मिशन यथा सतत् कृषि, जल, हरितिमा, सतत् आवास, हरित ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य, आपदा प्रबन्धन तथा सामरिक ज्ञान मिशन के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन एवं शमन हेतु 39 रणनीतियों के तहत 179 कार्यवाही के बिन्दु निहित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी विभागों में बकाया राज्य कर एवं उसकी वसूली हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी

32-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में किस सरकारी विभाग पर कितना राज्य कर बकाया है ? क्या उक्त बकाए की वसूली हेतु किए गए प्रयासों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्तमान में सरकारी विभागों पर रु0 14041.22 लाख बकाया है, जिसका विभागवार विवरण संलग्न† है।

उक्त मद में रु0 105.95 लाख की वसूली की गयी है। जिसका विभागवार विवरण संलग्न है।

---

† देखिए नत्थी (ख) का उत्तर आगे पृष्ठ संख्या 361 पर।

आयुक्त राज्य कर द्वारा सम्बन्धित सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को बकाए की वसूली हेतु अर्द्धशासकीय पत्र भेजे गये हैं। वसूली हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में रिंग रोड फरीदीपुर मोड़ से सरकारी स्कूल तक जर्जर सड़क के नव निर्माण के सम्बन्ध में

33-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में रिंग रोड फरीदीपुर मोड़ से दुबग्गा चौराहे होते हुए सरकारी स्कूल से आगे तक सड़क जर्जर होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित रूप से प्राइवेट सोसाइटी कालोनाईजर द्वारा बसायी गई है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है, ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सोसाइटी कालोनाईजर का है, फिर भी नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत स्थल क्षतिग्रस्त है। नागरिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थल पर सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य निगम के पास धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

34-श्री अरमान खान-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-212 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् में जर्जर सामुदायिक केन्द्र के कायाकल्प कराये जाने के सम्बन्ध में

35-श्री अरमान खान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् के ई ब्लाक में स्थित सामुदायिक केन्द्र जर्जर होने से क्षेत्र के निवासियों को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सुचारु रूप से नहीं हो पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक केन्द्र का कायाकल्प कराकर नागरिक सुविधाओं का विस्तार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् के ई ब्लाक में स्थित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित सामुदायिक केन्द्र क्रियाशील है तथा क्षेत्र के इच्छुक निवासियों द्वारा इसका आरक्षण कराकर कार्यक्रमों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा सामुदायिक केन्द्र का समय-समय पर आवश्यकतानुसार अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् क्षेत्र स्थित काला पहाड़ शमशान घाट के पास बनी आवासीय कालोनी की जर्जर सड़क के निर्माण कराये जाने विषयक

36-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् क्षेत्र के पास स्थित काला पहाड़ शमशान घाट के पास बनी आवासीय कालोनी से हबीबपुर मोड़ तक सड़क जर्जर होने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित रूप से प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा बसायी गई है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है, ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सोसाइटी कालोनाईजर का है, फिर भी नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाते है, प्रश्नगत स्थल क्षतिग्रस्त है। नागरिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थल पर सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य निगम के पास धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ स्थित विजय खण्ड-2, गोमती नगर के उजरियाँव में ट्यूबवेल में पानी के साथ बालू निकलने से पेयजल की आपूर्ति न हो पाने के सम्बन्ध में

37-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित विजय खण्ड-2, गोमती नगर के उजरियाँव को वाटर सप्लाई दरगाह स्थित ट्यूबवेल द्वारा की जा रही है ? यदि

हाँ, तो क्या ट्यूबवेल मैं पानी के साथ बालू निकलने से पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त ट्यूबवेल को रि-बोर करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्तमान में ट्यूबवेल में पानी के साथ बालू की मात्रा नगण्य है एवं ट्यूबवेल से पानी का डिस्चार्ज भरपूर है, इसलिए पेयजल की सप्लाई इस ट्यूबवेल से सुचारुपूर्वक जारी है।

उक्त ट्यूबवेल लगभग 10 वर्ष पुराना है, परन्तु उसका डिस्चार्ज वर्तमान में भी क्षमता के अनुरूप है। इसलिए उक्त ट्यूबवेल को रि-बोर कराने की आवश्यकता नहीं है

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका मंझरपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में सम्पर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक

38-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में राजेन्द्र खरे की बाग से शिवालय तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

शासनादेश संख्या-1989/नौ-6-2019-6 सी0वी0/07 लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 के द्वारा तत्कालीन नगर पंचायत मंझनपुर का सीमा विस्तार कर नगर पालिका परिषद् मंझनपुर, कौशाम्बी के गठन के क्रम में राजस्व ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी सम्मिलित किया गया है। असकरनपुर मंगरोहनी में राजेन्द्र खरे की बाग से शिवालय तक की पक्की सी0सी0 सड़क लम्बाई लगभग 300 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। असकरनपुर मंगरोहनी मुख्य मार्ग से श्री राजेन्द्र खरे की बाग होते हुए श्रीनाथ के घर तक 136 मीटर पक्की सी0सी0 सड़क का भाग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के द्वारा नवनिर्मित कराया गया है तथा शेष सड़क, लगभग 15 वर्ष पूर्व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा निर्मित कराया गया है, जिसका आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

उपरोक्त क्षतिग्रस्त सी0 सी0 सड़क के किनारे पटरी के भाग पर मिट्टी भराई का कार्य नगर पालिका परिषद्, मंझनपुर द्वारा करा दिया गया है। नगर पालिका परिषद् की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर धन उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के कतिपय क्षेत्रों में सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने विषयक

39-श्री चन्दन चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के पारा, गोविन्द नगर के हैदरगंज तृतीय, वार्ड नं0-20 में सीवर लाइन न होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में गोविन्द नगर, पारा में सीवर लाइन की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लखनऊ नगर के अन्य क्षेत्रों के साथ पारा गोविन्द नगर के हैदरगंज तृतीय, वार्ड-20 में सीवर लाइन डालने हेतु अमृत-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज योजना का सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार के अमृत-2.0 पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उक्त सिटी वाटर एक्शन प्लान की स्वीकृति के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर धनराशि का आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तनुसार।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

40-[प्रश्न हटाया गया]

जनपद अमरोहा में वर्ष 2016 में संचालित जल निकासी योजना को पूर्ण कराये जाने विषयक

41-श्री महबूब अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के अमरोहा की जल निकासी योजना (त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत) वर्ष 2016 में शुरू की गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना किन कारणों से अपूर्ण है ? क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण कराने की कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अमरोहा नगर की जल निकासी व्यवस्था हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 11-12-2014 द्वारा रु0 3007.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रु0 1203.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त के उपरान्त शासनादेश दिनांक 13-04-2016 द्वारा रु0 1203.14 लाख, शासनादेश दिनांक 17-09-2019 द्वारा रु0 300.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 11-09-2020 द्वारा रु0 301.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत लागत रु0 3007.86 लाख के सापेक्ष समस्त धनराशि अवमुक्त की

जा चुकी है। इसके उपरान्त सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा रु0 4407.05 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है।

नाले के सेक्शन में परिवर्तन, आबादी क्षेत्र में आर0सी0सी0 स्लेब से नाले को कवर करने, सड़क के किनारे वाली दीवार की ऊंचाई बढ़ाये जाने आदि कारणों से परियोजना का पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति न होने के कारण परियोजना अपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत परियोजना के पुनरीक्षण पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के वलीपुरा फीडर के कतिपय गांवों की बिजली को शहरी रोस्टर से जोड़ने के सम्बन्ध में

42-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के वलीपुरा फीडर के गांव हरतौली नैथला गंगेरुआ सुनहरा में वर्ष 1980 से शहरी रोस्टर के अनुसार बिजली आती थी, जबकि अब बिजली को ग्रामीण रोस्टर के अनुसार कर दिया है। जबकि बिल अभी भी शहरी रोस्टर के हिसाब से आता है ? क्या सरकार इसे शहरी रोस्टर से जोड़गी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

विधान सभा क्षेत्र सदर बुलन्दशहर के क्षेत्राधीन गांव हरतौली, नैथला, गंगेरुआ, सुनहरा इत्यादि को विद्युत आपूर्ति वर्तमान में नगरीय वितरण खण्ड के क्षेत्राधीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र वलीपुरा से पोषित 11 के0वी0 नैथला पोषक से शहरी रोस्टर के अनुसार की जा रही है तथा विद्युत बिल भी शहरी रोस्टर के अनुसार बनाये जा रहे हैं। उपरोक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की स्थिति में वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के हरि एन्क्लेव कालोनी में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के मकान से बृजमोहन शर्मा के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने विषयक

43-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के हरि एनक्लेव कालोनी में वीरेन्द्र सिंह सिरोही के मकान सं0-211 से बृजमोहन शर्मा भवन से 215 तक

आर0सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें नाली निर्माण एवं सड़क के रेस्टोरेशन का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया गया है। वर्णित मार्ग वर्तमान में आवागमन के लिए बिल्कुल ठीक पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम भगीरथपुर में 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में

44-डा0 रागिनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम भगीरथपुर में यादव बस्ती में 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर व विद्युत पोल लगवाये जाने हेतु कोई योजना सरकार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-जौनपुर के मछलीशहर के ग्राम भगीरथपुर में यादव बस्ती में 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित करने का कार्य रिवैम्प्ड योजना में आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि टूटे या जर्जर विद्युत पोल को बदलने का कार्य रिवैम्प्ड योजना में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ किये जाने पर टूटे या जर्जर विद्युत पोलों को बदलने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जिले में बायोफ्यूल यूनिट स्थापित कराये जाने की कार्य योजना की जानकारी

45-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में बायोफ्यूल यूनिट स्थापित करने की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022' का प्रख्यापन किया गया है, जिसमें फसलों के अपशिष्ट यथा-पराली, भूसी, भूसा, खोई, पत्ती आदि से जैविक ईंधन बनाने की योजना है। प्रख्यापित नीति यूपीनेडा की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

http://www.upneda.in/wp-content/uploads/
2022/10/BIOENERGYPOLICY2022.PDF

नीति के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक तहसील में विभिन्न जैव ऊर्जा उद्यमों यथा-बायो-सी0बी0ज0, बायो-कोल तथा बायो-डीजल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर निम्नानुसार प्रोत्साहन एवं उपादान का प्राविधान है :-

प्रोत्साहन

विद्युत शुल्क में छूट

जैव ऊर्जा इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट।

स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत छूट

जैव ऊर्जा उद्यमों/संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि क्रय अथवा लीज पर देय स्टाम्प ड्यूटी की शत-प्रतिशत छूट।

विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्जेज से शत-प्रतिशत छूट।

उपादान

कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र-रु0 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ तक,

बायो कोल संयंत्र-रु0 75,000 प्रति टन की दर से अधिकतम रु0 20 करोड़ तक,

बायो डीजल/बायो-एथेनॉल संयंत्र-रु0 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम 20 करोड़।

यदि किसी उद्यमी द्वारा बायोप्लान्ट में 50 करोड़ या उससे अधिक का निवेश किया जाता है, तो उसे इकाई से अधिकतम 05 किमी0 तक एप्रोच रोड की सुविधा मुख्य मार्ग तक दी जायेगी।

इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित एग्रीगेटर्स (एफपीओ, को-आपरेटिव सोसाईटी एवं गन्ना समिति) को बेलर, रेकर और ट्रोलर्स की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (अधिकतम रु0 20 लाख) देय होगा, जो भारत सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व से दिये जा रहे 50 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रेलवे अण्डरपासों में जलभराव और कीचड़ की समस्या से उत्पन्न स्थिति के समाधान के सम्बन्ध में

46-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रेलवे अण्डरपासों में जलभराव और कीचड़ की समस्या से आम जनता को हो रही परेशानी से सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

रेलवे अण्डरपासों का निर्माण एवं रख-रखाव रेल मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा किया जाता है। रेलवे अण्डरपास रेलवे के स्वामित्व में होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कानपुर नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत परमट मंदिर के प्रस्तावित कार्य को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में

47-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत परमट मंदिर के पास क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पत्र दिनांक 14-02-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की'परमट में आनन्देश्वर मंदिर के पास सरकारी एवं सार्वजनिक स्थानों का विकास' परियोजना का कार्य कुल धनांक रु0 06.00 करोड़ से कराया जा रहा है, जिसमें मार्ग के चौड़ीकरण, नाले को ढक कर पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग के साथ बागवानी, भूमिगत विद्युत लाइन, पी0ए0 सिस्टम व सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना, कण्ट्रोल रूम, स्ट्रीट लाइटें तथा कॉरिडोर सुन्दरीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के नवीन मार्केट से जुड़ी मल्टीलेवल पार्किंग होते हुए भी पार्किंग स्टैण्ड संचालित किये जाने का प्रकरण

48-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के नवीन मार्केट से जुड़ी मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराके मार्केट को नो पार्किंग जोन घोषित करने के पश्चात्

भी उक्त मार्केट में पार्किंग स्टैण्ड संचालित है ? यदि हां तो किस नियम के अन्तर्गत उक्त स्टैण्ड संचालित है ? क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है, जो नवीन मार्केट से हटकर है। वर्तमान में मेट्रो परियोजना के कारण नवीन मार्केट के सामने स्थित नगर निगम की पार्किंग निरस्त होने के कारण नवीन मार्केट क्षेत्र में नवीन मार्केट व्यापारी संगठन के अनुरोध पर फ्री पार्किंग जोन घोषित किया गया है, जिसका संचालन व्यापारी संगठन द्वारा किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा पार्किंग संचालित नहीं की जा रही है। वर्तमान में मेट्रो का कार्य होने के कारण व्यापारियों की मांग पर नवीन मार्केट प्रांगण में फ्री पार्किंग हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर नगर निगम में 15वां वित्त आयोग से होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित न किये जाने का प्रकरण

49-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 15वाँ वित्त आयोग के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास में क्षेत्र के विधायक को बुलाने एवं शिलालेख में नाम उल्लेख करने हेतु सरकार के निर्देश हैं ? यदि हां, तो क्या कानपुर नगर निगम में 15वां वित्त आयोग से होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण में क्षेत्रीय विधायक को सूचित एवं आमंत्रित न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

शासन द्वारा आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास सम्बन्धी शिलालेख में मा0 विधायक जी का नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-399/नौ-5-2016-265सा/2015, दिनांक 24 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-6711/नौ-5-18-524सा/2018, दिनांक 20-01-2021 एवं शासनादेश संख्या-1217/नौ-5-2023-524सा/2018, दिनांक 28-02-2023 के माध्यम से निर्गत किया गया है, जिसके अनुपालन में शिलालेख में मा0 विधायक जी का नाम अंकित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र गराठा में कतिपय क्षेत्रों में 33/11 के0वी0ए0 के नये उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

50-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली की समस्या के निराकरण हेतु गरसराय चौथामील बड़वार तथा बकुवाँ में 33/11 के0वी0ए0 के नये उपकेन्द्र स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-झाँसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरसराय चौथामील क्षेत्र की विद्युत समस्या के निराकरण हेतु रिवैम्प्ड स्कीम के अन्तर्गत भदरवा में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

बड़वार क्षेत्र की विद्युत समस्या को दूर करने हेतु रिवैम्प्ड स्कीम के अन्तर्गत बड़वार में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

बकवां क्षेत्र की विद्युत समस्या को दूर करने हेतु रिवैम्प्ड स्कीम के अन्तर्गत धमनाखुर्द में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त तीनों उपकेन्द्रों की स्थापना हो जाने पर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा।

उपरोक्तानुसार।

उप परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम की भ्रष्ट कार्य प्रणाली एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायतों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में

51-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक-1057/वि0क0/फा0अ0/2022, दिनांक-02-11-2022 जो जनपद आगरा में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम विभाग में उप परियोजना प्रबन्धक की भ्रष्ट कार्य प्रणाली एवं क्षेत्र के कार्यों की रिपोर्ट से जनप्रतिनिधियों को अवगत न कराते हुए जनप्रतिनिधियों की शिकायतों की अवहेलना की जाँच कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के वि0स0क्षे0 चरथावल में कतिय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52-श्री पंकज मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में बघरा, अमीरनगर से खुशरोपुर होते हुए चरथावल थाने तक लुहारी फीडर से ग्राम सांझक आदि मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-7 न0-75294 व क-7 न0-75293 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्रों में उल्लिखित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 05 मार्गों में से 03 मार्गों (क्रमांक-2, 4 एवं 5) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन तथा शेष 02 मार्गों जनपद मुजफ्फरनगर में बघरा-अमीरनगर से खुसरोपुर होते हुए चरथावल थाने तक एवं मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उक्त पत्रों में उल्लिखित विशेष मरम्मत के 11 कार्यों में से 9 कार्यों (क्रमांक-1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 एवं 11) के विशेष मरम्मत/पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और निविदा आमंत्रण/अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा बरवाला से कल्याण इण्टर कालेज मार्ग एवं नसीरपुर मार्ग से लडवा मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधीन है।

उक्त पत्रों में उल्लिखित नव निर्माण के 21 कार्य डबल कनेक्टिविटी की प्रकृति का होने के कारण वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं हैं।

उक्त पत्रों में उल्लिखित 03 लघु सेतुओं हरसौली सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 में 2x5 मी0 स्थान के लघु सेतु, दघेडू से मलीरा मार्ग के किमी0 5 पर 4x5 मी0 स्पान के लघु सेतु एवं बघरा हरसौली माण्डी मार्ग के किमी0 10 में 2x5 मी0 स्पान के लघु सेतु के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा में मुआर-आधारगंज सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

53-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा में मुआर-आधारगंज सम्पर्क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। यह मार्ग दो भागों में विभक्त है, जिसकी कुल लम्बाई 3.00 किमी0 है। मार्ग के विशेष मरम्मत के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में पत्थर डालकर यातायात योग्य कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की समस्त जिला/तहसील मार्गों को गड्ढामुक्त कराये जाने की जानकारी

54-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त जिला/तहसील मार्गों को गड्ढामुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो प्रदेश में वर्तमान में कितनी सड़कें जर्जर व गड्ढायुक्त हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि पूर्वांचल के आजमगढ़ व अन्य जनपदों की जर्जर व गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने सम्बन्धी स्टीमेट शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त समस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में मार्गों पर पैच मरम्मत का कार्य किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। पैच मरम्मत का कार्य एक अभियान के रूप में किया गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश के 60397 किमी0 लम्बाई में मार्गों पर पैच मरम्मत का कार्य किया गया है। पूर्वांचल के आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत 2699 किमी0 लम्बाई में मार्गों पर पैच मरम्मत किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त आजमगढ़ मण्डल में 548 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण एवं 820 किमी0 लम्बाई में विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत है। समस्त मार्गों की मरम्मत किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ठेकमा बाजार से केदलीपुर सरहद तक जर्जर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ठेकमा बाजार में श्री मुन्ना राय के घर से जगदीशपुर मिर्जापुर होते

हुए केदलीपुर सरहद तक लगभग 01 किमी0 तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण/पिच रोड का कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-7 नं0 226954, दिनांक 27-12-2022 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज में प्रश्नगत ठेकमा बाजार, आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग (रा0मा0 सं0-66ए) के किमी0 33 में स्थित है। उक्त राज्य मार्ग के किमी0 33 से निकले मिर्जा जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग पर मिर्जापुर, जगदीशपुर एवं केदलीपुर ग्राम स्थित है। मार्ग की लम्बाई 0.700 किमी0 है, जो खडन्जा स्तर का है। उक्त मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरायमोहन में जर्जर भैंसकुर पिच रोड के नव निर्माण के सम्बन्ध में

56-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सरायमोहन में उसरे पासी बस्ती से भैंसकुर पिच रोड लगभग 02 किमी0 जर्जर होने के कारण क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग नव निर्माण पिच रोड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग आजमगढ़ सरायरानी जौनपुर मार्ग से सरायमोहन सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की लालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सरायमोहन में श्री रामजग यादव से हेडवरिया तक जर्जर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

57-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सरायमोहन में बादिलबाबा से श्री रामजग यादव के घर से हेडवरिया

पिच जर्जर व गड्ढायुक्त के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ढडिया दक्षिणी पासी बस्ती सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 1350 किमी0 है। यह मार्ग बेसों नदी के तराई भाग में होने के कारण मार्ग का आंशिक भाग वर्षा ऋतु में जलमग्न होने से मार्ग की सतह 0.700 किमी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गयी है। मार्ग के मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में छोइया नदी बहली क्षेत्र में फैक्टरियों से निकले गन्दे पानी पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में

58-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में छोइया नदी बहली क्षेत्र में स्थापित फैक्टरियों के गन्दे पानी से किसानों की फसलों को हानि हो रही है तथा उक्त क्षेत्र में अधिष्ठापित हैडपम्पों का पानी भी दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सराकार उक्त फैक्टरियों के गन्दे पानी पर रोक लगायेगी ? यदि हॉ, कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर छोइया नाले के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित इकाइयों का निरीक्षण किया जा रहा है। अद्यतन किये गये निरीक्षणों में उक्त उद्योगों में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा छोइया नाले का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2022 एवं माह जनवरी, 2023 में छोइया नाले में साप्ताहिक निरीक्षणों में नाले की जल गुणता सामान्य पायी गयी है।

जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर के पत्र दिनांक 15-02-2023 द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में खड़ी फसलों पर हैण्डपम्प के पानी से कोई भी कुप्रभाव नहीं पाया गया है।

उक्त क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों का पानी दूषित होने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा दिनांक 22-02-2023 को उक्त क्षेत्र में विभिन्न स्थलों से हैण्डपम्प के जल गुणवत्ता जाँचने हेतु नमूने एकत्र किये गये, जिसमें समस्त प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये।

जनपद बिजनौर में चाँदपुर से फीना-अमरोहा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

59-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में चांदपुर से फीना-नूरपुर-अमरोहा मार्ग तक मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जनपद बिजनौर में चाँदपुर से फीना नूरपुर-अमरोहा मार्ग की लम्बाई 10.500 किमी0 तथा लेपित चौड़ाई 3.75/3.00 मी0 है। उक्त मार्ग बालावाली किरतपुर नहटौर चाँदपुर फीना मार्ग (एम0डी0आर0-170 डब्लू) के चैनेज 77.000 से 87.500 तक का भाग है। मार्ग को 2 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में बन्दरों द्वारा क्षेत्रवासियों को घायल किये जाने विषयक

60-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में बन्दरों द्वारा वर्तमान में क्षेत्र वासियों को घायल किये जाने के आकड़े इकटठे कराये गये है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बन्दरों द्वारा नागरिकों को घायल किये जाने की समस्या से निजात दिलाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उत्पाती बन्दरों को पकड़ने की अनुमति देने हेतु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1464/14-4-2006-854/92, दिनांक

31-07-2008 द्वारा वन विभाग के समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक एवं राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। इन बन्दरों को सुरक्षित रूप से पकड़े जाने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। बन्दरों की शिकायतों से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन-पत्रों/सूचनाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में भैसा से ग्राम जुझैला मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

61-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चॉदपुर में भैसा से ग्राम जुझेला मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित कर सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बिजनौर में चांदपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम भैसा एवं ग्राम जुझेला पूर्व में ही पक्के मार्ग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नगर निगम, लखनऊ अन्तर्गत पुराने हनुमान मन्दिर के नाम पर बजरंगबली वार्ड का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में

62-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत ऐतिहासिक पुराने हनुमान मन्दिर के नाम पर बजरंगबली वार्ड का नामकरण हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि वार्डों के नये परिसीमन 2022 में बजरंग बली वार्ड को समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या नये परिसीमन में जिस क्षेत्र में प्रश्नगत मन्दिर स्थित है, उक्त वार्ड का नामकरण बजरंग बली वार्ड करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां। परन्तु वर्ष 2017 में परिसीमन के समय जोन-3 स्थित बजरंगबली वार्ड को समाप्त कर बेगम हजरतमहल वार्ड के साथ सम्मिलित करते हुए संयुक्त रूप से बेगम हजरतमहल-बजरंगबली वार्ड बना दिया गया था।

वर्तमान में नये परिसीमन वर्ष 2022 के अनुसार बेगम हजरतमहल-बजरंगबली वार्ड की जनसंख्या कम होने के कारण तथा भौगोलिक दृष्टि से दो विधान सभा क्षेत्र में पड़ने के कारण उक्त वार्ड को तीन भागों में विभाजित कर प्राकृतिक सीमा को दृष्टिगत रखते हुए विवेकानन्दपुरी वार्ड, महानगर वार्ड एवं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार पुराना हनुमान मंदिर कुर्सी रोड के बायें तरफ स्थित होने के कारण बेगम हजरत महल-बजरंग बली वार्ड से काटकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड में नियमानुसार सम्मिलित कर दिया गया है।

नगर निगम, लखनऊ के कक्ष/वार्ड निर्धारण एवं परिसीमन की अनन्तिम अधिसूचना दिनांक 12-07-2022 के क्रम में निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कराने के उपरान्त अन्तिम अधिसूचना दिनांक 31-10-2022 निर्गत कर दी गयी है। इस प्रकार अन्तिम अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत कक्ष/वार्ड के नाम परिवर्तन का अवसर नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ महानगर में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किये जाने की योजना की जानकारी

63-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार किये जाने की योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो प्रस्तावित मार्ग का विवरण क्या है ? क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के नये परिसर, इंजीनियरिंग कालेज, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के साथ ही चौक आदि क्षेत्रों को भी उक्त मार्ग में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हाँ।

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ महानगर में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) प्रस्तुत की गयी है, जिसमें चारबाग से बसन्त कुंज तक लगभग 11 किमी0 लम्बा कॉरिडोर प्रस्तावित है। इस डी0पी0आर0 का परीक्षण किया जा रहा है।

लखनऊ शहर में मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार से सम्बन्धित विभिन्न ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्टेशन सर्वेक्षण तथा अन्य अध्ययन के अनुसार टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है। इस टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट में अन्य रूट के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के नये परिसर, इंजीनियरिंग कालेज, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय रूट भी सम्मिलित है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न रूट का अनुमोदन देने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

64-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमृत योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज सहित लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में अमृत-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फैजुल्लागंज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अयोध्यादास कदम रसूल एवं त्रिवेणी नगर वार्ड की प्रस्तावित पेयजल योजना का सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

उक्त सिटी वाटर एक्शन प्लान की स्वीकृति होने के पश्चात् उक्त योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत सेक्टर एम, अलीगंज के कतिपय पार्क में कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में

65-डा0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत सेक्टर एम अलीगंज के कतिपय पार्क में जहां निगम के कुछ कर्मचारी भी अस्थायी रूप से रहते हैं, वहां भू-माफियाओं द्वारा कथित आश्रम बनाकर पूरे पार्क पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत पार्क को खाली करा कर भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर निगम, लखनऊ अन्तर्गत अलीगंज सेक्टर एम में स्थित प्रश्नगत पार्क में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण/कब्जा नहीं है। पार्क के बाहर उत्तर दिशा में नगर निगम के

अभियंत्रण विभाग का स्टोर बना हुआ है। उक्त स्टोर से उत्तर दिशा में साई सेवा का आश्रम स्थापित है। अतः पार्क में कोई अवैध कब्जा नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्नगत पार्क में बाउण्ड्रीवाल, गेट, रेलिंग, पाथ-वे, झूले एवं पेड़-पौधे लगे हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

66-श्री सन्दीप सिंह-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-209 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

प्रदेश के नलकूप उपभोक्ता किसानों के विद्युत कनेक्शन की बकाया धनराशि की जानकारी के सम्बन्ध में

67-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2022 में कितने नलकूप उपभोक्ता किसानों के विद्युत कनेक्शन का विद्युत बिल बकाया होने के कारण विच्छेदन किया गया है तथा उन किसानों पर विद्युत बिल की कितनी धनराशि बकाया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्ष 2022 में प्रदेश में कुल 1,22,796 नलकूप उपभोक्ता किसानों के विद्युत कनेक्शन का विद्युत विल बकाया होने के कारण विच्छेदन किया गया था, जिन पर विद्युत बिल की धनराशि रु0 1930.62 करोड़ बकाया था, इनमें से भुगतान के उपरान्त 51,563 संयोजन जोड़ दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के भीतर न कराये जाने पर मिल मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी

68-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान हेतु निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन करने पर वर्ष 2022 में कितने मिल मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चौदह दिन की समय-सीमा के अन्दर भुगतान कराने हेतु कोई उपाय किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

गन्ना मूल्य भुगतान विलम्बित करने के सम्बन्ध में वर्ष 2022 में निजी क्षेत्र की चीनी मिल न्यौली (कासगंज) के प्रबन्ध निदेशक सहित 06 अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक चीनी मिल के लिए एस्क्रो एकाउन्ट अनिवार्य रूप से खुलवाये जा चुके हैं जो सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल अध्यासी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित हैं। चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी शीरा प्रेसमडॉ बगास एवं एथेनॉल की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का नियत प्रतिशत अंश सीधे एस्क्रो एकाउन्ट में स्थानान्तरित कराया जाता है। इस व्यवस्था से चीनी मिलों की तरलता में सुधार हुआ है तथा गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी आई है।

प्रश्न नहीं उठता।

69-[प्रश्न हटाया गया|

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम टोला में किशवाही में जर्जर सड़क के पुन निर्माण हेतु

70-डा0 मनोज कुमार प्रजापति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम टोला से किशवाही में ओवर लोड बालू के ट्रकों के आवागमन के कारण मार्ग जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 25.50 किमी0 एवं लेपित चौड़ाई 3.00 से 3.75 मीटर है। मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में 4जी स्मार्ट विद्युत मीटर के पुराने स्मार्ट मीटर से तेज चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

71-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 4जी स्मार्ट मीटर पुराने स्मार्ट मीटर से तेज चलने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में अब तक 4जी स्मार्ट मीटर के तेज चलने की कोई भी शिकायत स्मार्ट मीटर हेल्पडेस्क को प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश में दिनांक 31-01-2023 तक कुल 11,77,835 स्मार्ट मीटर (3जी एवं 4जी तकनीक पर आधारित) स्थापित किये गये हैं। 01 सितम्बर, 2022 से प्रदेश में 4जी तकनीक पर आधारित स्मार्ट मीटरों की स्थापना आरम्भ हुई है। अब तक 4जी तकनीक पर आधारित कुल 29,606 स्मार्ट मीटर स्थापित किये जा चुके हैं।

यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर सन्देह होता है तो उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर चेक मीटर लगाकर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच की जाती है। किसी कमी के परिलक्षित होने पर मीटर को 15 दिनों के भीतर नये मीटर से बदलते हुए उस माह के जिसमें शिकायत प्राप्त हुई है, पूर्व तीन माह का बिल अंतिम परिणाम के अनुसार पश्चात्वर्ती बिल में समायोजित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बिजली विभाग केस्को, कानपुर में फर्जी मीटर पकड़े जाने का प्रकरण एवं सर्वोदय नगर डिवीजन में फर्जी बिजली मीटर लगाने के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

72-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली विभाग केस्को, कानपुर में जो फर्जी बिजली मीटर पकड़े गए हैं वो मीटर कहाँ से आ रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि सन् 2020 में कानपुर के सर्वोदय नगर डिवीजन में फर्जी बिजली मीटर लगाने के दोषसिद्ध बिजली कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

पूर्व में 2022 में भारी मात्रा में कबाड़ की दुकानों पर पुराने चोरी के मीटर मिले थे, जिस पर विभाग द्वारा एफ0आई0आर0 संख्या-0244, दिनांक 07-04-2022 कल्यानपुर थाने में दर्ज करायी गयी है, जिसकी विवेचना प्रक्रियाधीन है।

विषयगत प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी पाये गये मीटर रीडर श्री अखिलेश त्रिपाठी, मे0 काम्पिटेन्ट सिनर्जीस प्रा0लि0, चण्डीगढ़ के अधीनस्थ कार्यरत थे एवं श्री अरविन्द कमाल, मे0 काइया एसोसिएट्स, कानपुर के अधीनस्थ कार्यरत थे। उक्त दोनों कार्मिक वर्तमान में अनुबन्धित एजेंसी मे0 के0एन0डी0 इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंट (इण्डिया), गोरखपुर के अन्तर्गत कार्य नहीं कर रहे हैं। साथ ही प्रकरण में दोषी पाये गये संविदाकर्मी श्री शम्भू सिंह वर्तमान में केस्को के अन्तर्गत किसी भी अनुबन्धित एजेंसी के अधीनस्थ कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रकरण में

आंशिक रूप से दोषी पाये गये श्री गणेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता केस्को को परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र घोषित किये गये गांवों में किये गये विकास कार्यों की जानकारी

73-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र घोषित किए गए हेतु अधिसूचित 221 गांव (नगर निगम सीमा के बाहर) में क्या-क्या विकास कार्य दिनांक 07-09-22 तक कराये गये है तथा कौन-कौन सी आवासीय योजनाएं उपरोक्त गांव में बनाई गई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र घोषित किए गए हेतु अधिसूचित 221 गांव (नगर निगम सीमा के बाहर) में दिनांक 07-09-2022 तक निम्न विवरण के अनुसार विकास कार्य कराये गये हैं :-

क्र0 सं0	अधिसूचित गांव (नगर निगम सीमा के बाहर)	कृत विकास कार्य/आवासीय योजना
1	2	3
1.	ग्राम सिंहपुर	के0डी0ए0 ग्रीन्स बहुमंजिली आवासीय योजना
2.	ग्राम सिंहपुर	कल्याणपुर सिंहपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य
3.	ग्राम कटरी कोहना एवं ग्राम शंकरपुर सराय	लवकुश गंगा बैराज पर थीम लाइट का कार्य
4.	ग्राम कटरी ज्योरा नवाबगंज एवं ग्राम शंकरपुर सराय	बोटेनिकल गार्डेन
5.	ग्राम मकसूदाबाद	सड़क का निर्माण एवं डिस्ट्रिक्ट पार्क के चैन लिंक्ड फेंसिंग का कार्य
6.	ग्राम उजियारा	कैटिल कालोनी
7.	ग्राम नगंवा	भागीरथी एवं जान्हवी प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वर्ण जयन्ती विहार आवास योजना

8.	ग्राम सम्भरपुर, ग्राम हिन्दुपुर, ग्राम गंगपुर चकबदा एवं ग्राम सिंहपुर कछार	लगभग 153.0 हे0 भूमि पर न्यू कानपुर सिटी आवासीय योजना नियोजित करने का कार्य प्रस्तावित किया गया है।

हाँ/उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में भैरो घाट पंम्पिंग स्टेशन के सामने बनी पानी की टंकी को गंगा बैराज की फीडर मेंन से जुड़वाये जाने के सम्बन्ध में

74-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में भैरो घाट पंम्पिंग स्टेशन के सामने बनी पानी की टंकी को गंगा बैराज की फीडर मैन से जुड़वाने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

कानपुर नगर में भैरो घाट पंम्पिंग स्टेशन के सामने 700 कि0ली0 क्षमता के ओवर हेड टैंक का निर्माण वर्ष 2014-15 में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है, जिसे भरने हेतु नलकूप की व्यवस्था भी की गयी है। वर्तमान में नलकूप के माध्यम से उक्त ओवर हेड टैंक को भरकर ग्वाल टोली क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम कानपुर द्वारा 5 वर्षों से अनुबन्ध पर रखी गयी गाड़ियों की संख्या एवं अन्य विवरण

75-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम कानपुर में विगत 5 वर्षों में कितनी गाड़ियाँ, किस कंपनी से, किन शर्तों पर अनुबन्ध की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर निगम कानपुर द्वारा विगत पाँच वर्षों में 40 हल्की गाड़ियाँ मेसर्स ज्योति ट्रैवेल से अनुबन्ध पर ली गयी हैं। अनुबन्ध की शर्तें संलग्न हैं।

अनुबन्ध की शर्तों का विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता है।

विद्युत विभाग की लापरवाही से नागरिकों की मृत्यु हो जाने पर वर्ष 2019 से दिनाँक 30-12-2022 तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान किये जाने की जानकारी

76-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग की लापरवाही से नागरिकों की मृत्यु हो जाने पर दावा किये जाने के पश्चात् दिये जाने वाले मुआवजा भुगतान की कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 में दिनांक 30-12-2022 तक कितने ऐसे प्रकरण में निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय के पश्चात् पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी तथा कितने ऐसे प्रकरण वर्तमान तक लम्बित हैं ? क्या सरकार इन प्रकरणों का निस्तारण कर पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के आदेश सं0-2828-औस/2021-19(125)-ए0एस0/01 दिनांक, 25 सितम्बर, 2021 के द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गयी है।

प्राप्त सूचना के अनुसार विवरण निम्नवत् है :-

विलम्ब से किये गये भुगतान के प्रकरणों की संख्या वर्षवार					वर्तमान में कुल लम्बित प्रकरण
2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल	
379	299	322	61	1061	220

विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में विद्युत वितरण निगमों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाये परन्तु पीड़ित परिवार द्वारा वांछित अभिलेख यथा मृत्यु की अवस्था में पीड़ित परिवार के स्तर से प्रत्यावेदन, उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, एफ0आई0आर0 की प्रति, पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाता विवरण, अपंगता की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी अपंगता प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त न होने के कारण कतिपय प्रकरणों में विलम्ब होता है।

77-श्री अनिल प्रधान-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-65 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

---

† देखिए नत्थी (ग) का उत्तर आगे पृष्ठ सं0 364-366 पर।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत खुटहा में प्रयागराज झांसी मार्ग से खुटहा होते हुए सीतापुर-शिवरामपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

78-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत खुटहा में प्रयागराज-झांसी मार्ग से खुटहा होते हुए सीतापुर-शिवरामपुर मार्ग जोड़ते हुए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग कच्चा स्तर का है, जिसकी लम्बाई 2.000 किमी0 एवं आंकलित लागत रु0 159.93 लाख है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

79-श्री अनिल प्रधान-

[03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-206 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर स्थित पुरऊपुर-सोहासा मार्ग से गुलरा पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग के मरम्मतीकरण कराये जाने विषयक

80-श्री पंकज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर स्थिति पुरऊपुर-सोहासा मार्ग से गुलरा पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग लम्बाई 400 मीटर जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में पुरऊपुर-सोहासा मार्ग से गुलरा पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 370 मी0 है, जिसकी मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के नीभापुर-कबीरपुर मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

81-श्री पंकज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के नीभापुर-कबीरपुर मार्ग प्रयागराज बार्डर तक लम्बाई लगभग 3 किमी0 जर्जर

है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में अचौरा-नीभापुर-कबीरपुर मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 8.900 किमी0 है। उक्त मार्ग के नीभापुर से कबीरपुर प्रयागराज बार्डर तक लम्बाई लगभग 3.00 किमी0 क्षतिग्रस्त था जिसकी मरम्मत/ नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के मुँगराबादशाहपुर कस्बे में ट्रांसफार्मर एवं जर्जर तार बदले जाने विषयक

82-श्री पंकज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 915095, दिनांक 29-07-2022 जो जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के मुंगराबादशाहपुर कस्बे में ट्रांसफार्मर एवं जर्जर तार को बदले जाने के सम्बन्ध में उक्त पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के मुंगराबादशाहपुर कस्बे में जर्जर तार को बदले जाने की व्यवस्था रिवैम्पड योजना में है। वर्तमान में कार्यदायी संस्था द्वारा रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

परिवर्तक बदलने का कार्य रिवैम्पड योजना में द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों की योजना में आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के तहसील-सोराँव के ग्राम फाफामऊ स्थित भूमि आराजी संख्या-992 के प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाये जाने के बाद बैनामा निरस्त किये जाने विषयक

83-श्री सन्दीप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज, ग्राम फाफामऊ तहसील सोराँव में स्थित भूमि आराजी संख्या-992 अनाध्याप्त क्षे0 1140 वर्ग मीटर में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लिए गए क्षे0 957 वर्ग मीटर के सापेक्ष आराजी संख्या-293 स्थित

मौजा फाफामऊ में समतुल्य क्षेत्र 574.20 वर्ग मीटर विनिमय के माध्यम से समायोजन के बाद उभयपक्षों की सहमति से दिनांक 07/06/2013 व 11/06/2013 को उप निबन्धन कार्यालय सोराँव प्रयागराज में बैनामा किया गया ? जिसमें लिखा गया की प्राधिकरण द्वारा 957 वर्ग मीटर भूमि का उपयोग कर लिया गया है ? परन्तु 02 वर्ष बाद प्राधिकरण द्वारा बैनामा निरस्त कर दिया गया ? क्या सरकार उक्त भूमि का परीक्षण करा कर भूमि की भरपाई कराएगी यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

आराजी संख्या-293 क्षेत्र 564.52 वर्गमी0 भूमि, जो कि प्राधिकरण की अध्याप्ति भूमि है, श्री कुन्दन सिंह के पक्ष में विक्रय विलेख के माध्यम से अन्तरित की गयी थी। श्री कुन्दन सिंह द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में विक्रीत की गयी भूमि के मौके पर कम एवं विवादित होने तथा प्राधिकरण द्वारा श्री कुन्दन सिंह के पक्ष में आन्तरित की जाने वाली भूमि में स्थलीय भिन्नता होने के कारण विनियम अविधिक, अनियमित एवं प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण होने के कारण उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 28- 05-2014 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख निरस्त किये जाने हेतु मा0 सिविल न्यायालय में वाद संख्या-96/15 दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है। वाद निस्तारित होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डंडिया नगला पुलिया से ग्राम भोगपुर तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

84-श्री अताउर रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम डंडिया नगला पुलिया से ग्राम भोगपुर तक मार्ग का लेपन कार्य न कराये जाने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में ग्राम डंडिया नगला एवं ग्राम भोगपुर पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुड़े हुए है। प्रश्नगत मार्ग डंडिया नगला एवं भोगपुर ग्रामों को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत आपस में जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सकरस से ग्राम जसाईनगर तक मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

85-श्री अताउर रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम सकरस से ग्राम जसईनगर तक मार्ग का मरम्मत कार्य न होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत सकरस से जसईनगर ग्रामीण श्रेणी का मार्ग हैं, जिसकी लम्बाई 3.780 किमी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बरेली के बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हाफिजगंज नहर की पुलिया से ग्राम बसूपुरा तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री अताउर रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम हाफिजगंज नहर की पुलिया से ग्राम बसूपुरा तक मार्ग का लेपन कार्य न होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में ग्राम हाफिजगंज एवं ग्राम बसूपुरा पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत मार्ग ग्राम हाफिजगंज एवं ग्राम बसूपुरा को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत आपस में जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के नैनीताल बरेली मार्ग से ग्राम भिलोर तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने विषयक

87-अताउर रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के नैनीताल बरेली-मार्ग से ग्राम भिलोर तक मार्ग का लेपन कार्य न होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिजेश-

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत बरेली-नैनीताल मार्ग (राज्य राजमार्ग-37) से परौडी नजरगंज मार्ग के चौनेज 0.00 किमी0 से चौनेज 2.00 किमी0 में पैच मरम्मत का कार्य कराया गया है। वर्तमान से मार्ग की दशा सन्तोषजनक है मार्ग के शेष चौनेज 2.00 किमी0 से 5.700 किमी0 तक के भाग की विशेष मरम्मत के अन्तर्गत लम्बाई 4.700 किमी0 की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

बरेली-नैनीताल मार्ग (राज्य राजमार्ग सं0-37) से परोही-नजरगंज मार्ग के किमी0 07 में स्थित ग्राम पृथ्वीपुर से बिल्लौर (भिलोर) सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग की दशा सन्तोषजनक है

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली में बिजली से वंचित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

88-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में बिजली से वंचित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-03MLA/2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही कि गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

अवगत कराना है कि शामली शहर की अटल विहार कॉलोनी, सलेक विहार रेलपार आदि कॉलोनी अविद्युतीकृत कॉलोनी हैं। जिसमें अभी तक कॉलोनी में विकासकर्ता द्वारा बाह्य विद्युतीकरण नहीं कराया गया है। नियमानुसार कॉलोनी में विकासकर्ता द्वारा बाह्य विद्युतीकरण

कराने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत किये जा सकते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमानुसार 40 मीटर की दूरी तक केबिल सर्विस एवं 40 मीटर से अधिक दूरी होने पर प्राक्कलन बनाकर धनराशि जमा होने के उपरान्त नये संयोजन निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम सुकटिया से ग्राम चका तक मार्ग के लेपन कार्य कराये जाने विषयक

89-अताउर रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम सुकटिया से ग्राम चका तक मार्ग का लेपन कार्य न होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बरेली में विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में ग्राम सुकटिया एवं ग्राम चका पूर्व में पक्के मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत मार्ग ग्राम सुकटिया एवं ग्राम चका को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित है, जो डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाई-वे के निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हुये अन्य मार्गों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

90-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद शामली में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाई-वे के निर्माण के चलते जनपद में अनेक पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्या उक्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद शामली में राष्ट्रीय राजमार्ग हाई-वे के निर्माण कार्य के चलते लो0नि0वि0 के क्षतिग्रस्त मार्गों हेतु एन0एच0ए0आई0 बागपत से मार्गों की मरम्मत कराये जाने हेतु निरन्तर पत्राचार एवं दूरभाष पर अनुरोध किया जा रहा है।

स्टेट हाई-वे पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है एवं स्टेट हाई-वे से कोई भी मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त लिंक ग्रामीण मार्ग निम्नवत् हैं:-

1-कादरगढ़ से भैंसानी मार्ग।

2-बाबरी रायपुर पंवार खेड़ा तितारसी मार्ग के कि0मी0 02 से कैडी पुल।

3-बन्तीखेड़ा से बाबरी मुस्लिम बस्ती मार्ग।

4-बनत से डीऊवाई मार्ग।

5-शामली आदमपुर भौराकला मार्ग के किमी0 06 से 10 तक।

6-बनत से सहारनपुर मार्ग।

7-कुडाना आर्य समाज बस स्टैण्ड से काबडौत मार्ग।

8-मंसूरा मार्ग के किमी0 02 से पावटी खुर्द।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर निगम द्वारा विज्ञापन नियमावली के विपरीत 01 ही कंपनी को 10 वर्षों के लिए टेन्डर दिये जाने का प्रकरण

91-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम द्वारा घोषित विज्ञापन नियमावली का उल्लंघन कर एवं उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर पूरे शहर का अधिकार एक ही कंपनी को 10 वर्षों के लिए टेन्डर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम द्वारा विगत 5 वर्षों में जब्त प्लास्टिक एवं उसके निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

92-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम द्वारा विगत 5 वर्षों में कितना प्लास्टिक जब्त किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जब्त प्लास्टिक का किस प्रकार निस्तारण किया गया तथा प्लास्टिक के निस्तारण से कितनी आय हुई ? क्या सरकार उक्त का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर निगम, कानपुर द्वारा विगत 05 वर्षों में कुल 2,19,534 कि0ग्रा0 सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लाण्ट के माध्यम से जब्त प्लास्टिक को नष्ट कराया गया है। प्लास्टिक के निस्तारण से विगत 05 वर्षों में रु0 17.50 लाख की आय हुयी है।

जब्त की गयी पॉलीथीन एवं जुर्माना से प्राप्त आय का वर्षवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता है।

93-श्री अमिताभ बाजपेई-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कानपुर नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत नाना राव पार्क में कराये गये कार्यों की जानकारी

94-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत नाना राव पार्क में क्या-क्या काम कितने धन से कराए गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्यों के प्रस्ताव कब दिये गये तथा उक्त कार्यों से पार्क की उपयोगिता में क्या सुधार हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पत्र दिनांक-14-02-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कुल रु0 11.24 करोड़ से कानपुर नगर की ऐतिहासिक धरोहर नाना राव पार्क में विभिन्न कार्य कराये गये हैं-

बाहरी बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।

शहीद स्थल एवं मेमोरियल वेल को संयुक्त करते हुए बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य।

562 मी0 सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य।

716 मी0 साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य।

455 मी0 वाकिंग ट्रैक का निर्माण कार्य।

पूरे पार्क में लाइट की व्यवस्था का कार्य।

बैठने हेतु बेंचेज का निर्माण कार्य।

---

† देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ सं0 367 पर।

पूरे पार्क में सिंचाई हेतु बोरिंग के साथ पाइप लाइन बिछाने का कार्य।

पार्क में घूमने आने वाले पर्यटकों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।

पार्क के अन्दर पूर्व में बने क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार कार्य।

वाहनों हेतु पार्किंग की व्यवस्था।

नाना राव पार्क कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा चिन्हित ए0बी0डी0 क्षेत्र का सबसे बड़ा (क्षेत्रफल में) पार्क है एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण हेरिटेज कन्जर्वेशन थीम के तहत कराया गया है। नाना राव पार्क भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित पार्क है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दिये गये निर्देश एवं सुझावों पर उक्त कार्यों का प्रस्ताव एवं स्वीकृति दिनांक 05-07-2018 को आहूत कानपुर स्मार्ट सिटी की 5वीं बोर्ड बैठक द्वारा प्रदान की गयी।

उपरोक्त कार्यों से नाना राव पार्क में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या में तीन से चार गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम अन्तर्गत वार्डवार पार्कों की संख्या की जानकारी एवं उक्त पार्कों को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

95-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत कितने पार्क किस वार्ड में हैं ? क्या सरकार उक्त पार्क की वार्डवार सूची उपलब्ध कराएगी ? क्या सरकार की जानकारी है कि कतिपय पार्कों पर अवैध कब्जा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्कों को अतिक्रमण से मुक्त करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत वार्डवार पार्कों की कुल संख्या-792 है।

सूची संलग्न† है।

समय-समय पर प्राप्त सूचना एवं विभागीय निरीक्षण के दौरान कतिपय पार्कों में अवैध अतिक्रमण होने पर हटाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

---

† नोट :- छापी नहीं गयी।

प्रदेश के महानगरों को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने सम्बन्धी

96-श्री अतुल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में मानक के अनुसार वर्तमान में कितने घण्टे विद्युत कटौती की जा रही है ? क्या सरकार की महानगरों में विद्युत कटौती से मुक्त करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

महानगरों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रति गाँव सोलर लाइट उपलब्ध कराने विषयक

97-श्री अतुल प्रधान-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रति गाँव 5-5 सोलर लाइट सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में प्रति गांव 5-5 सोलर लाइट लगाये जाने की राज्य सरकार की कोई योजना संचालित नहीं है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में संचालित बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में 20 ग्राम पंचायतों को सन्तृप्त करने के लिए प्रत्येक विधान सभा में बराबर-बराबर ग्राम पंचायतों को चयनित कर 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइटों (कुल 200 अदद लाइटों) की स्थापना करायी जानी लक्षित है। इस योजनान्तर्गत जनपद मेरठ में कुल 200 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की गयी है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र सरधना के ग्राम ज्वालागढ़, झिंझाड़पुर चकबन्दी एवं बातनौर प्रत्येक में 10-10 नग सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य करा दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र सरधना के ग्राम सकौती में 30 एवं ग्राम धन्जू में 16 ग्राम जमालपुर में 15 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना शासन द्वारा संचालित क्रमशः मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना एवं पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से पूर्व में करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अति गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े किसानों को निःशुल्क विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने विषयक

98-श्री अतुल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अति गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़े किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु निःशुल्क विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने के साथ ही निःशुल्क बिजली सरकार मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्रदेश के नलकूप धारक किसानों को विद्युत दर में 88.19 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते समय अब यह राहत 100 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी गयी है

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अमरोहा में जलभराव से निजात हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि की जानकारी

99-श्री अतुल प्रधान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के शहर अमरोहा में जलभराव से निजात हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत योजना कब शुरू हुई तथा उक्त योजना अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार योजना पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित कर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अमरोहा नगर की जलनिकासी व्यवस्था हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 11-12-2014 द्वारा रु0 3007.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रु0 1203.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त के उपरान्त शासनादेश दिनांक 13-04-2016 द्वारा रु0 1203.14 लाख, शासनादेश दिनांक 17-09-2019 द्वारा रु0 300.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 11-09-2020 द्वारा रु0 301.58 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत लागत रु0 3007.86 लाख के सापेक्ष समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

नाले के सेक्शन में परिवर्तन आबादी क्षेत्र में आर0आर0सी0 स्लेब से नाले को कवर करने सड़क के किनारे वाली दीवार की ऊंचाई बढ़ाये जाने आदि कारणों से परियोजना का पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति न होने के कारण परियोजना अपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत परियोजना के पुनरीक्षण पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ नगर निगम के फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड में सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित किये जाने विषयक

100-डा0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड में सरकारी भूमि की पैमाइश करायी थी तथा वहां भूमि व नाले पर अतिक्रमण पाया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि नगर निगम के कतिपय अधिकारियों व कर्मचारियों के संरक्षण में आज भी भू-माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

ग्राम गाजीपुर बलराम वार्ड फैजुल्लागंज द्वितीय में खसरा संख्या-184 निजी स्वामित्व की भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालित है। उक्त पेट्रोल पम्प के सामने स्थित मुख्य मार्ग एवं पेट्रोल पम्प के मध्य दक्षिणी-पूर्वी कोने पर खसरा संख्या-256 नाले की 675 वर्ग फुट भूमि पर अवैध कब्जा कर इण्टरलॉकिंग टाइल्स लगाकर आवागमन में प्रयुक्त किया जा रहा था, जिसे दिनांक 04-07-2022 को हटा दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के पुरनिया चौराहे के निकट एल0डी0ए0 द्वारा विकसित कॉलोनी के अन्तर्गत अवैध तरीके से रेस्टोरेण्ट एवं मांसाहारी व्यंजन संचालित किये जाने विषयक

101-डा0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के अलीगंज में पुरनिया चौराहा के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी के एक कोने पर अवैध तरीके से बनी दुकानों में रेस्टोरेण्ट एवं मांसाहारी व्यंजन का व्यवसाय किया जा रहा है जिससे उक्त क्षेत्र में ट्रैफिक जाम रहता है ? यदि हां, तो क्या ऐसी दुकानों को चिन्हित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए जनसामान्य को ट्रैफिक जाम से सरकार निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सभी दुकानें प्राधिकरण द्वारा मासिक किराये पर आवंटित हैं।

लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत टेढ़ीपुलिया चौराहे के निकट सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते हुए व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

102-डा0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत टेढ़ीपुलिया चौराहा के पास बीच सड़क पर सरकारी भूमि का अवैध अतिक्रमण करते हुए फैजी जूस कार्नर नामक दुकान व अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं तथा इन्हीं कारणों से चौराहे पर यातायात संचालन में प्रायः बाधा उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उक्त अतिक्रमण कुर्सी रोड पर है। कुर्सी रोड लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है। उक्त सड़क के आर0 ओ0 डब्ल्यू0 की सीमाओं का विवरण एवं चिन्हांकन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सड़क की सीमा में कोई अतिक्रमण आता है तो उसका चिन्हांकन एवं अतिक्रमण हटाने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित है, जिसमें नगर निगम द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा अधिशाषी

अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को पत्रांक डी-236 (क)/ई0 ई0-03, दिनांक 27-02-2023 द्वारा संसूचित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ स्थित विधान भवन के परिधि में आने वाले व्यावसायिक अनुष्ठानों के भवनों के नवीनीकरण हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

103-डा0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद लखनऊ स्थित विधान भवन के चारों ओर हाई सिक्योरिटी जोन है, जिसकी परिधि में आने वाले कतिपय भवन जहां व्यावसायिक गतिविधियां वर्षों से संचालित हैं, के भवन जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त भवनों के पुनः नवीनीकरण के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-331 (1) (2) के अन्तर्गत जर्जर/खण्डहर भवनों को ध्वस्त कराने/हटवाने/पुनः निर्माण कराने एवं अन्य खतरों से सुरक्षित कराने हेतु अध्यासियों/भवन स्वामी को नोटिस प्रेषित की जाती है तथा साथ ही जर्जर भवनों के सन्निकट से आने-जाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत बैरीकेटिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय किये जाते हैं। लखनऊ विधान सभा के चारों ओर के हाई सिक्योरिटी जोन और आस-पास क्षेत्र में वर्ष 2022 में कुल 10 चिन्हित जर्जर भवनों को नोटिस निर्गत की जा चुकी है। व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन/पुनर्निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति आदि की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बांदा में बिसण्डा रोड रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बाईपास रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

104-डा0 संग्राम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में मुख्य चौराहे तथा बिसण्डा रोड रेलवे क्रासिंग पर हमेशा ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जाम से निजात दिलाने हेतु बांदा रोड नहर पटरी से बिसण्डा रोड नहर की पटरी तक लम्बाई लगभग 2 किमी0 (बाईपास रोड) सड़क बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में मुख्य चौराहे पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं0-35 एवं राज्य मार्ग सं0-71 क्रास करता है। उक्त चौराहे पर राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं0-35 की लेपित चौड़ाई 10.00 मी0 एवं राज्य मार्ग सं0-71 की लेपित चौड़ाई 7.00 मी0 है। अन्तर्रा कस्बा में पटरी पर अस्थाई अतिक्रमण एवं बिसण्डा रोड पर रेलवे क्रासिंग पर रेलवे फाटक होने के कारण यदा-कदा जाम की समस्या हो जाती है। समय-समय पर जिला प्रशासन के सहयोग से अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाता है। सामान्यतः स्थाई जाम की समस्या नहीं है।

जनपद बांदा में कस्बा-ओरन से कस्बा-अतर्रा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

105-डा0 संग्राम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा अन्तर्गत कस्बा ओरन से कस्बा अतर्रा तक लगभग 03 किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराते हुये निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश--

जनपद बांदा में अतर्रा ओरन-बौसड़ (तहसील अतर्रा से ओरन कस्बे तक) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है। निर्माण के दौरान मार्ग को मोटरेबल रखा जा रहा है। मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से चालू है। कार्य पूर्ण करने हेतु लक्षित माह मार्च, 2023 है।

106-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

ट्रांजिट हॉस्टल, डालीबाग, लखनऊ में लगाये गये प्रीपेड विद्युत मीटर को अध्यासियों के अवासों के सामने लगाये जाने के सम्बन्ध में

107-श्री अखिलेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जय देवी, सदस्य विधान सभा का पत्र संख्या-क-6 नं0 120739, दिनांक 28-08-2022 जो ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, लखनऊ में लगाये गये प्री-पेड विद्युत इलेक्ट्रानिक मीटर को पूर्व की भांति अध्यासियों के आवासों के सामने ही लगाये जाने सम्बन्धित है, मुख्य मंत्री तथा प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, लखनऊ में लोक निर्माण विभाग, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, लखनऊ द्वारा एक कक्ष प्रीपेड मीटर स्थापित किये जाने हेतु नियत किया गया है, जहाँ से प्रत्येक आवास को आपूर्ति हेतु वायरिंग की गयी है। प्रत्येक आवास के सामने प्रीपेड मीटर स्थापित किये जाने से पहले लोक निर्माण विभाग, विद्युत अनुरक्षण खंड द्वारा वायरिंग में बदलाव किया जाना आवश्यक है। वायरिंग में आवश्यक परिवर्तन के लिए अधिशाषी अभियंता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-द्वितीय, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-769-वी0न0वि0खं0/रा0भ0, दिनांक 15-02-2023 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

अधिशाषी अभियंता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-द्वितीय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ कार्यालय पत्रांक 352/प्रा0-2/23, दिनांक 21-02-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि डालीबाग ट्रांजिट हास्टल, लखनऊ में प्रत्येक आवास के परिसर के सामने प्रीपेड मीटर स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक वायरिंग में परिवर्तन सम्बन्धी आगणन/प्रस्ताव शासन में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है। स्वीकृति के उपरान्त अविलम्ब कार्य सम्पादित करा दिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा वायरिंग में आवश्यक परिवर्तन कराने के उपरान्त प्रीपेड मीटर प्रत्येक आवास के सामने विभाग द्वारा स्थापित कराया जाना सम्भव है

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण में आस-पास के गांवों को बाउण्ड्री के अन्दर जोड़ लिये जाने विषयक

108-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण में आस पास के दर्जनों गांव के सम्पर्क मार्गों को कार्यदायी संस्था द्वारा बाउण्ड्री बनाकर अन्दर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के सम्पर्क मार्गों को मुख्य मार्ग से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विश्वविद्यालय के आस-पास के राजस्व ग्राम आजमबांध, असपालपुर, बुन्दा, बसगित एवं मित्तूपुर के लिये लेपित सम्पर्क मार्ग निर्मित है, जो कि मुख्य मार्गों से जुड़े हैं। विश्वविद्यालय बाउण्ड्रीवाल के अन्दर 0.500 किमी0 लेपित भाग एवं 0.500 किमी0 खड़न्जा भाग यूनिवर्सिटी कैम्पस में जाकर समाप्त होते हैं जिसमें कोई आबादी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विद्युत विभाग में तैनात सहायक/लिपिकों का कतिपय विद्युत निगमों से दूसरे विद्युत निगम में स्थानान्तरण नीति बनाये जाने विषयक

109-श्री अखिलेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युत विभाग में तैनात कार्यकारी सहायकों/लिपिकों का विद्युत वितरण, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा केस्को निगम लिमिटेड से दूसरे विद्युत निगम लिमिटेड में स्थानान्तरण नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति के अनुपालन में कार्यकारी सहायकों के स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

इस सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है :-

(1) अधिसूचना संख्या-149/पी-1/2000-24, दिनांक 14-01-2000 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम-2000 के ''कार्मिकों का स्थानान्तरण'' शीर्षक प्रस्तर-6 के प्राविधानानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-60-प्र0सं0-10/पा0का0लि0/2001, दि0 09-01-2001 द्वारा कार्मिकों का स्थायी रूप से उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में स्थानान्तरण एवं आमेलन किया गया।

(2) तदोपरान्त अधिसूचना संख्या-2740/पी-1-2003-24-14पी-2003, दिनांक 12-08-2003 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपक्रमों का अन्तरण) स्कीम-2003 के कार्मिकों का अन्तरण शीर्षक प्रस्तर-4 के प्राविधानानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में स्थायी रूप से कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं आमेलन उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2662/24-पी-2-2008-61 एम0ई0/2000-टी0सी0-3, दिनांक 11-12-2008 द्वारा अन्तिम रूप से किया गया।

अग्रेतर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यक्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में निम्नवत् विवरणानुसार स्थानान्तरण आमेलन हेतु समुचित अवसर भी प्रदान किया गया है :-

(i) कारपोरेशन के का0 ज्ञा0सं0-696 ज0श एवं प्र0सु0 (01) पाकालि/09-21 प्र0सु0/2001 टी0सी0-3, दि0 23-10-2009 द्वारा अन्तर्निगमीय स्थानान्तरण नीति निर्गत की गयी जो कि आदेश निर्गमन की तिथि से 02 माह तक प्रभावी रही।

(ii) उक्त के उपरान्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के का0 ज्ञा0सं0-66-ज0श0 एवं प्र0सु0 (01)/पाकालि/10-21-प्र0सु0/2001 टी0सी0-3, दिनांक 25-01-2010 द्वारा उक्त

अवधि को 01 माह एवं पुनः उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के का0 ज्ञा0सं0-395-ज0श0 एवं प्र0सु0 (01)/पाकालि/10-21-प्र0सु0/2001 टी0सी0-3, दिनांक 17-05-2010 द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 31-05-2010 तक बढ़ाया गया।

(3) तदोपरान्त उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-2974/24-पी-2-2010, दिनांक 23-12-2010 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड में अन्तरण) स्कीम, 2010 के प्रस्तर-3 के प्राविधानानुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3104/24-पी-2-12-4 (04)/09, दि0 22-12-2015 द्वारा आमेलन/स्थानान्तरण किया गया।

कार्यकारी सहायकों के पदों का आमेलन विद्युत वितरण, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा केस्को में चूंकि अन्तिम रूप से कर दिया गया है, अतएव इन कार्मिकों का एक निगम से दूसरे निगम में स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के किसान सहाकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सठियांव में चीनी मिल निर्माण से छोड़ी गयी भूमि को किसानों के नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में

110-श्री अखिलेश-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड सठियांव से सम्बन्धित चीनी मिल आयुक्त के अ0शा0 पत्र संख्या 3954 ए0 सी0/18 (6) 775/73, दिनांक 6 अगस्त, 1974 के अनुपालन के क्रम में भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा चीनी मिल निर्माण से छोड़ी गई जमीनों को प्रतिकर न दिए जाने के बावजूद भी किसानों की भूमि उनके नाम दर्ज नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को किसानों के नाम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

प्रकरण वर्ष 1974 में हुई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से सम्बन्धित है। अधिग्रहीत भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियांव के नाम दर्ज है। दर्ज भूमि में से किसी अंश को अधिग्रहण की कार्यवाही में अन्तिम रूप से छोड़े जाने का उपलब्ध अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं है। अतः भूमि वापस किये जाने का कोई कारण एवं आधार विद्यमान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण हेतु कार्य योजना की जानकारी

111-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बस्ती में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 02 नवम्बर, 2022 द्वारा प्रदेश में ई-कचरे के प्रबन्धन के लिये ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022 प्रख्यापित किया गया है, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

प्रदेश में ई-कचरे के निस्तारण हेतु कार्यवाही ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022 में प्रावधानित है तथा इसी नियम के प्रावधानों के अनुसार विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) के रूप में इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उत्पादकर्ताओं द्वारा कार्यवाही कराये जाने की सरकार की कार्य योजना है। ऐसे उत्पादनकर्ता जिनसे ई-वेस्ट जनित होगा उन्हें उक्त के प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना एवं किसी भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में विनिर्माण के दौरान अथवा पुराने हिस्से से नया उत्पाद बनाने वाली इकाइयों से उत्पन्न ई-कचरा और अपशिष्ट को एकत्र करना और उसके पुनर्चक्रण या निपटान एवं परिशोधन को सुनिश्चित करना तथा इसका रिकॉर्ड मेन्टेन करना भी अनिवार्य किया गया है।

इस हेतु निम्न विभागों का पृथक-पृथक उत्तरदायित्व ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022 की अनुसूची-5 में वर्णित है।

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ,

3. स्थानीय निकायों (शहरी व ग्रामीण) का उत्तरदायित्व,

4. भारतीय बन्दरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के तहत बन्दरगाह प्राधिकरण की जिम्मेदारी और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमाशुल्क प्राधिकरण,

5. भारत मानक ब्यूरो/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारियाँ।

उक्त नियम के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ई-अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत कुल-135 इकाइयों (विनिर्माता-76

नवीनीकरणकर्ता 23 व पुनर्चक्रणकर्ता-36) को प्राधिकार-पत्र निर्गत किया गया है, जिनकी कुल अधिकृत क्षमता 3.65 लाख टन प्रति वर्ष है।

जनपद बस्ती में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण के दृष्टिकोण से ई-अपशिष्ट के संग्रह भण्डारण और निराकरण/पुनर्चक्रण हेतु मै0 एल0एस0ई0 वेस्ट रिसाईक्लिंग यूनिट, ग्राम-नव्वागाँव टप्पा छपिया तहसील-भानपुर, जिला-बस्ती को क्षमता 2.0 टन प्रति दिन हेतु दिनांक 09-02-2022 को संचालन हेतु प्राधिकार राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 08-02-2026 तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 250 से ऊपर आबादी वाले राजस्व ग्राम/मजरों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

112-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 250 से ऊपर आबादी वाले राजस्व ग्रामों/मजरों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के उक्त श्रेणी के सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है ? यदि हाँ तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

2011 की जनगणना के अनुसार जनपद बस्ती के बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र में मात्र राजस्व ग्राम उदयपुर के अन्तर्गत बिगहिया मजरे को छोड़कर 250 या उससे अधिक जनसंख्या वाले समस्त राजस्व ग्राम/मजरे पूर्व से ही पक्के मार्ग से सन्तृप्त हैं। उक्त मजरे को लेपित मार्ग से जोड़ने हेतु 3.15 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग (लागत रु0 244.43 लाख) की स्वीकृति की कार्यवाही नाबार्ड योजनान्तर्गत प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड सं0 09 स्थित श्मशान घाट के निर्माण कार्य/सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

113-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा सदर के वार्ड नं0 9 शिकारपुर रोड स्थित श्मशान घाट के निर्माण कार्य व सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि से उक्त कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर को अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 42.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्समय आवंटित भूमि विवादित होने के कारण निकाय द्वारा कार्य नहीं कराया जा सका। वर्तमान में नयी भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराकर प्रश्नगत स्थल पर निर्माण कार्य करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के खेड़ा सांधन मार्ग का सी0सी0 निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में

114-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम सांधन में खेड़ा सांधन मार्ग के शुरुआत में लगभग 250 मीटर मार्ग में पानी और कीचड़ से आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 1.500 किमी0 है। मार्ग के चैनेज 0.000 से 0.525 कि0मी0 में सी0सी0 मार्ग पूर्व से निर्मित है। मार्ग के दोनों ओर आबादी के घरों के पानी की समुचित निकासी न होने के कारण उक्त भाग में जलभराव हो रहा है। जल निकासी के समाधान हेतु ग्राम सांधन के आबादी भाग में 100 मीटर लम्बाई में मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा में ग्राम रसूलपुर से सकतपुर तक सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 निर्माण एवं जल निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में

115-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम रसूलपुर से सकतपुर मार्ग पर रसूलपुर ग्राम के पास लगभग 300 मीटर मार्ग में पानी ओर कीचड़ से आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का न होने के कारण मार्ग निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीतियों के अन्तर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला अन्तर्गत ग्राम सोनिगा में जल निकासी की व्यवस्था एवं सी0सी0 मार्ग के सम्बन्ध में

116-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के ग्राम सोनिगा के आबादी भाग में पानी और कीचड़ से आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम भिलावटी के सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

117-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम भिलावटी का आबादी भाग के मार्ग जर्जर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम भिलावटी के आबादी भाग में सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 1.600 किमी0 है। उक्त मार्ग पर भिलावटी आबादी भाग की लम्बाई लगभग 100 मीटर में सी0सी0 मार्ग बना हुआ है, जिसकी दशा अच्छी है। वर्तमान में मार्ग के किनारे आबादी विकसित होने के कारण भिलावटी आबादी भाग में 100 मीटर अतिरिक्त सी0सी0 एवं नाली निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम रायभा रेलवे फाटक से बिचपुरी रोड तक मार्ग के मरम्मत कराये जाने विषयक

118-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम रायभा रेलवे फाटक से बिचपुरी रोड तक आबादी भाग का मार्ग जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार रायभा रेलवे फाटक से बिचपुरी रोड तक आबादी भाग में सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर निगम फिरोजाबाद में कुतुबपुर चनौरा में निर्माणाधीन सॉलिड वेस्ट प्लाण्ट हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

119-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में कुतुबपुर चनौरा में निर्माणाधीन 250 टी0डी0पी0 के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट के पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि सरकार जारी करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद-फिरोजाबाद के कुतुबपुर चनौरा में 250 टी0पी0डी0 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान्ट के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 24-11-2021 द्वारा रु0 1710.98 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 427.745 लाख एवं शासनादेश दिनांक 27-09-2022 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में 427.745 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है एवं तृतीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में अपराध रोकने की दृष्टि से मुख्य सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0टी0वी0 लगवाये जाने विषयक

120-श्री अनिल प्रधान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में ओवरलोडिंग एवं अपराधों को रोकने के दृष्टिगत मुख्य सम्पर्क मार्गों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाए जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पालिका परिषद् चित्रकूटधाम के सार्वजनिक स्थानों यथा रामघाट एवं कामदगिरि परिक्रमा परिक्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत 100 नग सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अधिष्ठापन कराया गया है।

जनपद चित्रकूट में ओवरलोडिंग एवं अपराधों को रोकने के दृष्टिगत मुख्य सम्पर्क मार्गों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बिहारा में सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

121-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बिहारा में पंचायत भवन के पास से बरगदहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट के ग्राम बिहारा एवं ग्राम बरगदहा पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। प्रश्नगत मार्ग कच्चा स्तर का है, जिस पर मार्ग निर्माण चाहा गया है, जो ग्राम बिहारा एवं ग्राम बरगदहा को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित डबल कनेक्टिविटी का प्रकरण है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

ग्राम पंचायत भगनपुर में कोडियार नाला हनुमान मंदिर से भगनपुर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

122-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत भगनपुर में कोडियार नाला हनुमान मंदिर के पास से भगनपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट का ग्राम भगनपुर पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है। प्रश्नगत मार्ग कच्चा स्तर का है, जिस पर मार्ग निर्माण चाहा गया है, जो कोडियार नाला हनुमान मंदिर

के पास से ग्राम भगनपुर को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत देवकली से कुई नहर पटरी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

123-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत देवकली में देवकली से दरिया पुरवा होते हुए कुई नहर पटरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग कच्चा स्तर का है, जिसकी लम्बाई 3.00 किमी0 एवं आंकलित लागत रु0 246.58 लाख है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों हेतु विद्युत लाइन हटवाये जाने के लिए होने वाले व्यय के नियम में बदलाव किये जाने के सम्बन्ध में

124-श्री सचिन यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घरों के ऊपर से जा रही विधुत लाइन को हटवाने हेतु होने वाले व्यय को घर मालिक द्वारा वहन किये जाने के नियम हैं ? यदि हां, तो उक्त विवरण क्या है ? क्या सरकार कतिपय ग्रामीण परिवारों द्वारा इस खर्च को वहन नहीं करने की स्थिति के दृष्टिगत उक्त नियम में बदलाव पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम संख्या-82 के अनुसार यदि विद्युत तार भवन निर्माण के पूर्व हटाने में आने वाले खर्च का वहन जमा योजना के अन्तर्गत घर के मालिक द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है।

इस मद में अधिक धन की आवश्यकता होती है। इस हेतु विभाग की कोई योजना नहीं है। दुर्घटना की सम्भावना को देखते हुए विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार गार्डिंग की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज में वित्तीय वर्ष 2022-23 में को-ऑपरेटिव एवं एग्रीजंक्शन में खाद के आवंटन की जानकारी के सम्बन्ध में

125-डा0 सुरभी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में समस्त को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं एग्रीजंक्शन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाद का कितना आवंटन हुआ तथा इन सोसायटियों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितनी आमद हुई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जे0पी0एस0 राठौर)-

जी हाँ।

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज में समस्त को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं एग्रीजंक्शन में वित्तीय वर्ष 2022-23 (दि0 20-09-2022 से 31-01-2023 तक) में कुल 3461.750 मी0टन खाद का आवंटन हुआ तथा इन सोसाइटियों एवं एग्रीजंक्शन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 01-04-2022 से 31-01-2023 तक) में कुल 5855.125 मी0टन खाद की आमद/प्रेषण हुई।

जी हाँ। समितियों/उर्वरक बिक्री केन्द्रों को किये गये आवंटन और प्रेषित उर्वरक का विवरण/सूची संलग्न हैं।†

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में संचालित ईंट भट्ठों की संख्या एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जानकारी के सम्बन्ध में

126-डा0 सुरभी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में संचालित ईंट भट्ठों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि संचालित सभी ईंट भट्ठों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखानुसार जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में स्थापित कुल 53 ईंट भट्ठों में से 44 ईंट भट्ठे संचालित हैं।

जी नहीं।

---

† छापी नहीं गयी।

उक्त स्थापित 53 ईंट भट्ठों में से 44 संचालित ईंट भट्ठों द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त की गई है, शेष 09 ईंट भट्ठों के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किये गये हैं।

जी हां। विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम व पता	अनापत्ति/सहमति का विवरण
1	सुग्रीव सिंह बिजेन्द्र सिंह एण्ड कं0 ईंट भट्ठा, गाटा नं0 540, 555, ग्राम-चिलौली, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
2	गंगवार बद्रर्स ईंट भट्ठा, मझनां, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
3	अग्रवाल ब्रिक फील्ड (पुराना नाम ग्रामीण ब्रिक फील्ड) खसरा नं0 595, 596, 597, ग्राम-लखनपुर, परगना कम्पिल, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
4	शान्ती देवी एण्ड कम्पनी ईंट भट्ठा, खसरा नं0 121, ग्राम-बिराहिमपुर जागीर, पोस्ट पैथान, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
5	लखनपुर ईंट भट्ठा, गाटा नं0 723, 724, 725, ग्राम-लखनपुर, पोस्ट कायमगंज, तहसील कायमगंज फर्रुखाबाद	स्वीकृत
6	कास्तकार ईंट भट्ठा, गाटा नं0 1874 ज, 2056ए, ग्राम-चिलसरा, शमशाबाद, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
7	राम किशन रस्तोगी एण्ड कम्पनी ईंट भट्ठा, गाटा नं0 417, 419, ग्राम-खानपुर, शमशाबाद, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
8	गन्धर्व सिंह देवेन्द्र सिंह ईंट भट्ठा, ग्राम-खानपुर, शमशाबाद, कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
9	किसान ईंट भट्ठा, गाटा नं0 00167, ग्राम चन्दुइया, पोस्ट सिलसाण्डा, नवाबगंज, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
10	प्रभात गंगवार ईंट भट्ठा (पुराना नाम किसान ईंट भट्ठा), गाटा नं0 268 ग्राम-खिनमिनी, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
11	अभय प्रदीप ईंट भट्ठा, खसरा नं0 278, 279, ग्राम-खुन्दीना धमगवां, पोस्ट-लहरा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम व पता	अनापत्ति/सहमति का विवरण
12	न्यू सिंह ईंट भट्ठा, खसरा नं0 436, ग्राम-मोती नगर, बघौना, पोस्ट उखरा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
13	कृष्णा ईंट भट्ठा, गाटा नं0 1568 ग्राम बरतल नवाबगंज, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
14	महेश चन्द्र गंगवार ईंट भट्ठा, गाटा नं0 855, 856, ग्राम-सिकन्दरापुर महमूद शमशाबाद, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
15	एम0एन0 ब्रिक फील्ड (पुराना नाम जयमातादी ब्रिक फील्ड) गाटा नं0 1690, ग्राम-चिलसरा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
16	छल्लू गंगवार ईंट भट्ठा, गाटा नं0 202, ग्राम-चिलौली, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
17	कुमार ईंट भट्ठा ग्राम-कटरा रहमत खान, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
18	न्यू रुदायन ईंट भट्ठा, गाटा नं0 1108 ग्राम रुदायन कम्पिल, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
19	भारत ब्रिक फील्ड, गाटा नं0 794, ग्राम रुदायन कम्पिल, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
20	माँ वैष्णों ईंट भट्ठा, गाटा नं0 228, ग्राम नगला समाधान, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
21	पाल ईंट भट्ठा, ग्राम व पोस्ट चिलसरा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
22	न्यू किसान ईंट भट्ठा, गाटा नं0 371, ग्राम-सिकन्दरपुर महमूद शमशाबाद, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
23	गौतम ईंट उद्योग (पुराना नाम मुन्डौल ब्रिक फील्ड), गाटा नं0 465, ग्राम-मुडौल, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
24	कोकीला देवी ईंट उद्योग, गाटा नं0 203/2, नौगांव, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम व पता	अनापत्ति/सहमति का विवरण
25	श्यामलाल गुप्ता ईंट उद्योग (पुराना नाम गौतम ईंट उद्योग), गाटा नं0 821, ग्राम-दमदमा पोस्ट एवं तहसील कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
26	जय माँ दुर्गे ईंट भट्ठा, ग्राम-बिचौली, पोस्ट पिलखना, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
27	मारुती ईंट उद्योग (पुराना नाम जय ईंट भट्ठा), गाटा नं0 53, ग्राम-कासीमपुर सैनी, पोस्ट-शुकरूलपुर, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
28	प्रभात गंगवार ईंट भट्ठा, गाटा नं0 734, ग्राम व पोस्ट खिनमिनी, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
29	जय माँ वैष्णों ब्रिक फील्ड, गाटा नं0 197, 198, ग्राम बरई, विकास खण्ड, शमशाबाद, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
30	किसान ईंट उद्योग, गाटा नं0 68, ग्राम-नौगांव, पिलखना, तहसील- कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
31	जय माँ दुर्गे ईंट उद्योग, खसरा नं0 36/5 ग्राम नौगांव पोस्ट पिलखना, तहसील- कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
32	सुपर ईंट भट्ठा, गाटा नं0 959, 960 ग्राम रुदायन पोस्ट रुदायन, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
33	जे0के0 ईंट भट्ठा, गाटा नं0 24, ग्राम दलेलगंज, परगना शमशाबाद पश्चिम, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
34	हरिओम ब्रिक फील्ड (पुराना नाम पाल ईंट भट्ठा), ग्राम-चिलसरा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
35	कृष्णा ईंट उद्योग, गाटा नं0 109 ग्राम समाचीपुर, औरैया, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
36	किसान ईंट भट्ठा, गाटा नं0 1269, ग्राम-गनीपुर, जोगपुर, नवाबगंज, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
37	एन0पी0 ईंट उद्योग, गाटा नं0 154, ग्राम-विराहीमपुर जागीर, तहसील- कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम व पता	अनापत्ति/सहमति का विवरण
38	याम सिंह ईंट भट्ठा, गाटा नं0 261, ग्राम-हुसैनपुर बांगर, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
39	न्यू एच0एम0 ईंट उद्योग, गाटा नं0 567, 569, 571, ग्राम पोस्ट चिलसरा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
40	किसान ईंट भट्ठा, गाटा नं0 574, 576, ग्राम-जौरा, विकास खण्ड व तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
41	प्रभात गंगवार ईंट भट्ठा (पुराना नाम पूर्णागिरी ईंट भट्ठा), आराजी नं0 357, ग्राम अलादादपुर, तहसील- कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
42	आर0एस0 ब्रिक्स (पुराना नाम एम0आर0 ब्रिक फील्ड), खसरा नं0 295/1, ग्राम-उगरपुर, सुल्तान पट्टी, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
43	आर0पी0 ब्रिक उद्योग, गाटा नं0 4197, ग्राम-पिलखना, शमशाबाद पश्चिम, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
44	बालाजी ईंट उद्योग, खसरा नं0 163, ग्राम-शाहपुर धासू, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	स्वीकृत
45	ममता ईंट भट्ठा उद्योग, पिलखना, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत
46	बजरंग ईंट भट्ठा, गाटा नं0 3214. पिलखना, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत
47	गनेश ब्रिक फील्ड ग्राम व पोस्ट पिलखना, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत
48	गंगा ब्रिक फील्ड, ग्राम-चिलौली, गंगा दरवाजा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत
49	कुंवर ब्रिक फील्ड, कुंवर खास कम्पिल, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत
50	अशोक कुमार जितेन्द्र कुमार ईंट उद्योग दलेलगंज, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत

क्रमांक	ईंट भट्ठे का नाम व पता	अनापत्ति/सहमति का विवरण
51	विरप्रताप ईंट भट्ठा, बिरहिमपुर जागिर, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत
52	एच0एम0 ईंट भट्ठा, ग्राम-चिलसरा, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत
53	टॉप ईंट भट्ठा, गाटा नं0 632, ग्राम-मानीकपुर, पोस्ट रुदायन, तहसील-कायमगंज, फर्रुखाबाद	बन्दी आदेश निर्गत

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निबन्धन विभाग में वर्ष 2014 से कार्मिकों को लिपिक संवर्ग से उपनिबन्धक के पद पर की गयी पदोन्नति के सम्बन्ध में

127-श्री पंकज-

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निबन्धन विभाग में वर्ष 2014 से वर्तमान तक कितने कार्मिक को लिपिक संवर्ग से उपनिबन्धक के पद पर पदोन्नति दी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रविन्द्र जायसवाल-

वर्ष 2014 से लिपिक संवर्ग से उपनिबन्धक के पद पर वर्तमान तक कोई पदोन्नति नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर अन्तर्गत बादशाहपुर बेलवार मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

128-श्री पंकज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगरा बादशाहपुर में बादशाहपुर बेलवार मार्ग की लम्बाई लगभग 9 कि0मी0 को उखाड़े जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मतीकरण जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

मुँगराबादशाहपुर बेलवार मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसके प्रारम्भ के 9.00 किमी0 का भाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) द्वारा स्क्रैप किया गया

था, किन्तु उनके द्वारा प्रारम्भ के 7.00 किमी0 में ही निर्माण करते हुए लेपन स्तर तक अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया है। शेष कार्य कि0मी0 8 व 9 के लेपन करने हेतु विशेष मरम्मत मद में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसे मार्च 2023 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में करनौली से बाबूरामपुर प्रतापगढ़ तक जर्जर मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

129-श्री पंकज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में करनौली से सोरजा का पुरा होते हुए बाबूरामपुर प्रतापगढ़ बार्डर तक लम्बाई लगभग 6 कि0मी0 जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर में करनौली से सूरजा का पुरा होते हुए बाबूरामपुर प्रतापगढ़ बार्डर तक कुल लम्बाई 4.35 किमी0 है, जिसमें करनौली से सूरजा का पुरा कुल 3.00 किमी0 लम्बाई में मार्ग गड्ढामुक्त है तथा सूरजा के पुरा से बाबूरामपुर प्रतापगढ़ बार्डर तक कुल लम्बाई 1.35 किमी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में कुंवरपुर से मधुपुर मार्ग तक मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

130-श्री पंकज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबाद शाहपुर में कुवरपुर से लम्बाई लगभग 8 कि0मी0 जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुँगराबादशाहपुर के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 8.50 किमी0 एवं लागत रु0 158.61 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य मई, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र में अदारी-ऊंचडीह मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

131-श्री पंकज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में अदारी-ऊंचडीह मार्ग कि0मी0 10 से कि0मी0 20 तक जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत प्रश्नगत अदारी-ऊंचडीह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसके कि0मी0 10 से 14 एवं कि0मी0 20 में गड्ढामुक्ति योजना के अन्तर्गत पक्का पैच बनवा दिया गया है तथा इस मार्ग के कि0मी0 15 से 19 (लम्बाई 9.80 किमी0) में मरम्मत/नवीनीकरण कार्य की लागत रु0 103.89 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य मई, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर नगर पालिका अन्तर्गत असकरनपुर मंगरोहनी में जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

132-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के असकरनपुर मंगरोहनी में पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन द्वारा नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार असकरनपुर मंगरोहनी में पानी टंकी बनवा कर पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एवं अस्थायी रूप से पाइप लाइन के माध्यम से नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के असकरनपुर, मंगरोहनी में जलापूर्ति की जा रही है।

अमृत-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् मंझनपुर का सिटी वाटर एक्शन प्लान अनुमानित लागत रु0 81.54 करोड़ तैयार कर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त सिटी वाटर एक्शन प्लान की स्वीकृति होने के पश्चात् उक्त योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कल्याणपुर पश्चिम के कन्हैया नगर में नाली का स्तर ऊंचा होने से जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में

133-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कल्याणपुर पश्चिम में स्थित मकान संख्या-ए/65, निकट रेनबो पब्लिक स्कूल, कन्हैयानगर के सामने से जाने वाली नाली का स्तर ऊंचा होने के कारण उक्त मकान के सामने मार्ग पर व उसके अगल-बगल प्रायः नाली का गन्दा पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर नाली की मरम्मत कराकर जलभराव की समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर निगम द्वारा प्रश्नगत स्थल पर नाली की मरम्मत एवं सड़क सुधार का कार्य सतही ढाल के अनुसार कराने हेतु आगणन तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य निगम के पास धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

134-डा0 अमित सिंह चौहान-

[मा0 न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त]

रौजा गांव चीनी मिल, अयोध्या में गन्ना किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में

135-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-12-2022 को मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्रांक सं0 क-6 नं0 632908 व अपर मुख्य सचिव गन्ना 22-12-22 पत्रांक सं0 क-6 नं0 632914 तथा विशेष सचिव, गन्ना को पत्र दिनांक 22-12-2022 पत्रांक सं0 क-6 नं0 632917 रौजा गांव चीनी मिल अयोध्या में गन्ना

किसानों की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी हाँ, किन्तु पत्र सं0-क-6 नं0 632908 दिनांक 22-12-2022 अप्राप्त है।

सन्दर्भित पत्रों को आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ0प्र0 के कार्यालय के पत्र संख्या-2255/सांख्यिकीय (चीनी) दिनांक 05-01-2023 एवं पत्र संख्या-618/समिति/पर्ची, दिनांक 16-01-2023 द्वारा उप गन्ना आयुक्त, अयोध्या को रौजागांव चीनी मिल के किसानों को गन्ने की आपूर्ति में आ रही समस्त समस्याओं की जांच कर शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में उप गन्ना आयुक्त, अयोध्या ने कृषकों की बिन्दुवार समस्याओं की जांच कर उनका निराकरण कराते हुए पत्र संख्या-2051-53, दिनांक 24-01-2023 द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है तथा वस्तुस्थिति से मा0 सदस्य को भी अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या की विधान सभा क्षेत्र बीकापुर अन्तर्गत जलालपुर पहुपी कुचेरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

136-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-06-22 पत्रांक सं0-क 6 नं0 797326 व पत्र दिनांक 13-12-2022 पत्रांक सं0-6 नं0 632763, जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था एवं पत्र दिनांक 08-06-22 व पत्र दिनांक 17-07-22 जो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को सम्बोधित था तथा अयोध्या जनपद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर अन्तर्गत मार्ग जलालपुर पहुपी शाहगंज कुचेरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य में अनियमितता की जांच किये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत जलालपुर पहुपी शाहगंज कुचेरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की उच्च स्तरीय टी0ए0सी0 जांच कराये जाने विषयक मा0 सदस्य के उल्लिखित पत्रों में से 17-07-2022 कार्यालय अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु उक्त विषयक पत्र दिनांक 07-06-2022 पत्रांक सं0-क-6 नं0 797326 एवं पत्र दिनांक 13-12-2022 पत्रांक सं0 क-6 नं0 632763, जो कि मा0 मुख्य मंत्री जी को

सम्बोधित तथा पत्र दिनांक 08-06-2022 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं।

उक्त मार्ग की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के माध्यम से करायी गयी है। कोष्ठ की प्राप्त जांच आख्या दिनांक 21-10-2022 पर शासन के पत्र दिनांक 21-11-2022 एवं पत्र दिनांक 10-01-2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/समिति की संस्तुति सहित आख्या मांगी गयी है। प्रकरण में वांछित आख्यानुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर अन्तर्गत रेल विहार कॉलोनी (प्रथम) की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में

137-श्री पंकज मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में रेल विहार कालोनी फेज (प्रथम) की सड़कें क्षतिग्रस्त व जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद गोरखपुर नगर निगम सीमान्तर्गत वार्ड संख्या-06 चरगाँवा स्थित रेल विहार कालोनी (फेज प्रथम) का नगर निगम को दिनांक 02-05-2022 को हस्तान्तरण इस शर्त के साथ किया गया है कि वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण वर्तमान में नगर निगम द्वारा उक्त कालोनी में अगले 01 वर्ष तक विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

उक्त अवधि के उपरांत स्थल का सर्वे कराकर प्रश्नगत कार्य निगम के पास तत्समय धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर स्थित रेल विहार कॉलोनी फेज (प्रथम) में जल निकासी एवं पार्क के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

138-श्री पंकज मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में रेल विहार कालोनी फेज (प्रथम) स्थित पार्क में बरसात के समय में पानी भर जाने से आम जनमानस को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

पार्क में जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए पार्क का सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अत्यधिक वर्षा होने पर जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में रेल विहार कालोनी फेज (प्रथम) स्थित पार्क में कुछ समय के लिए जलभराव होता है, परन्तु थोड़े समय बाद जल निकासी स्वतः हो जाती है।

जनपद-गोरखपुर नगर निगम सीमान्तर्गत वार्ड संख्या-06 चरगाँवा स्थित रेल विहार कालोनी फेज प्रथम को अध्यक्ष, रेल विहार कालोनी के अनुरोध पर दिनांक 02-05-2022 को नगर निगम, गोरखपुर द्वारा हस्तगत कर लिया गया है। जलनिकासी की व्यवस्था कराते हुए उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में लखनऊ-कानपुर वी0आई0पी0 मार्ग के सौन्दर्यीकरण, डिवाइडर निर्माण एवं विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

139-श्री मोहम्मद हसन रूमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के प्रवेश मार्ग लखनऊ से कानपुर वी0आई0पी0 रोड जो सर्किट हाउस तक जाता है का सौन्दर्यीकरण, डिवाइडर निर्माण और विद्युतीकरण कार्य हेतु उक्त प्रमुख प्रवेश द्वार को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत समायोजित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पत्र दिनांक-14-02-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार सम्बन्धित क्षेत्र स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत एरिया बेस्ड डेवलपमेन्ट (ए0बी0डी0) क्षेत्र से आच्छादित नहीं है, कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन जून, 2023 तक विस्तारित है। उक्त समयावधि में स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं को फ्रीज कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की कतिपय नगर पंचायतों में विकास कार्यों के शिलान्यास हेतु मार्गदर्शी के सिद्धांत का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में

140-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराए गए विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धांत

बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज, सुवंसा और पृथ्वीगंज नगर पंचायतों में उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

शासन द्वारा आवंटित धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास सम्बन्धी शिलालेख के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-399/नौ-5-2016-265-2015, दिनांक 24 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-6711/नौ-5-18-524-2018, दिनांक 20-01-2021 एवं शासनादेश संख्या-1217/नौ-5-2023-524-2018, दिनांक 28-02-2023 के माध्यम से निर्गत किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में राजकीय गुलिस्ता कॉलोनी में निर्मित पार्क के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

141-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में राजकीय गुलिस्ता कॉलोनी में निर्मित पार्क के जीर्णोद्धार, रख-रखाव व सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद लखनऊ में राजकीय गुलिस्ता कॉलोनी का स्वामित्व राज्य सम्पत्ति विभाग में निहित है, जिसका अनुरक्षण एवं विकास का मूल दायित्व राज्य सम्पत्ति विभाग का है तथापि जन साधारण की सुविधा के दृष्टिगत पार्क के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य निगम के पास धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत छितपालगढ़ मार्ग से खालिसपुर पाल बस्ती में सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

142-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत छितपालगढ़ मार्ग से खालिसपुर पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग रामफल इनारी मान्धाता मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-2 में स्थित छितपालगढ़ बाजार से पाल बस्ती तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.60 कि0मी0 है, जिसमें छितपालगढ़ से खालिसपुर मार्ग जिसकी लम्बाई 0.300 कि0मी0 है, लेपित सतह है। खालिसपुर से पाल बस्ती तक कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.300 कि0मी0 है। पाल बस्ती की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 95 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से कम आबादी की बसावटों/मजरों को लेपित मार्ग से जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत रानीगंज विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

143-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में लखनऊ-वाराणसी मार्ग से प्राइमरी विद्यालय व प्रजापति बस्ती होते हुए नौडेरा स्वरूपपुर में ननकू यादव के घर तक जामताली वीरापुर मार्ग से जगदीशपुर होते हुए छानापार तथा डी0आर0पी0के0 मार्ग से बुढौरा मुस्लिम बस्ती सम्पर्क मार्गों का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्न तीन मार्गों (1) लखनऊ-वाराणसी मार्ग से प्राइमरी विद्यालय व प्रजापति बस्ती होते हुए नोडेरा स्वरूपपुर में ननकू यादव के घर तक सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 2.00 कि0मी0) (2) जामताली वीरापुर मार्ग से जगदीशपुर होते हुए छानापार सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 2.00 कि0मी0), (3) डी0आर0पी0के0 मार्ग से बुढौरा मुस्लिम बस्ती सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 2.00 कि0मी0) की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लालगंज से शिवपुर कपूर मार्ग को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

144-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत लालगंज से शिवपुर कपूर दियर (सिनपुर धारी) मार्ग का जीर्णोद्धार एवं उच्चीकरण कराने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग विभागीय अभिलेखानुसार लालगंज बाजार सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी (लम्बाई 3.00 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर) का मार्ग है, जिसकी विशेष मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एन0एच0-31 बेलहरी ग्रामीण मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

145-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के एन0एच0-31 के बेलहरी ग्रामीण मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं लेपन कार्य कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग विभागीय अभिलेखानुसार 'दुधैला से बेलहरी मार्ग' है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 2.90 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर है। मार्ग निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत बी0एम0टी0 बांध से बिहार बार्डर तक जाने वाले मार्ग का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

146-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत बी0एम0टी0 बांध से रामपुर कोड़रहा होकर बिहार बार्डर तक जाने वाले मार्ग का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग विभागीय अभिलेखानुसार बिहार बार्डर सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त है, जिसकी कुल लम्बाई 1.30 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के कतिपय विकास खण्डों की सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

147-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के ब्लाक बामौर, मोंठ, चिरगांव एवं गुरसराय की कतिपय सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-7 सं0 174064, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद झॉसी के ब्लॉक बामौर, मोंठ, चिरगांव एवं गुरसराय क्षेत्र के पत्र में वर्णित मार्गों के स्थलीय आवश्यकतानुसार मरम्मत/पुनःनिर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ की पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत योगीपुरम डिप्टी खेड़ा में कतिपय सड़कों एवं नाली के निर्माण कार्य विषयक

148-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के योगीपुरम् डिप्टी खेड़ा बुद्धेश्वर पारा लखनऊ क्षेत्र की योगीपुरम् डिप्टी खेड़ा में विशाल श्रीवास्तव के घर से विवेक के घर तक तथा दीपक राजवानी के घर से पंकज पाल के घर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित रूप से प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा बसायी गई हैं, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सोसाइटी/कालोनाईजर का है फिर भी नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाते है प्रश्नगत स्थल क्षतिग्रस्त है। नागरिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थल पर सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य निगम के पास धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद तथा आगरा में संचालित छोटे-बड़े उद्योगों से उत्सर्जित गैस से प्रदूषण की रोक थाम हेतु कठोर कार्रवाई किये जाने विषयक

149-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद तथा आगरा में संचालित सभी छोटे-बड़े उद्योगों में से कितनों को नियंत्रित प्रदूषण का प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त उद्योगों से उत्सर्जित जहरीली गैसें स्थानीय वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अनियंत्रित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनपद-फिरोजाबाद एवं आगरा में स्थापित एवं संचालित लाल श्रेणी के अन्तर्गत 38 , नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत 362 एवं हरी श्रेणी के अन्तर्गत 444 उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति जल एवं वायु प्रदान की गई है।

जी नहीं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13381/84 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 30-12-1996 एवं तदोपरान्त समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में जनपद-आगरा तथा फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्रान्तर्गत समस्त उद्योगों में ईंधन के रूप में सी0एन0जी0 गैस अथवा विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

150-डा0 मुकेश चंद्र वर्मा-

[03-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-205 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर निगम को पिछले 02 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवस्थापना मद में आवंटित धनराशि के विवरण की जानकारी

151-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में अवस्थापना मद में आवंटित धनराशि का विवरण क्या है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि अवस्थापना मद की राशि समय से आवंटित नहीं होने के

कारण विकास कार्य बाधित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अवस्थापना मद की धनराशि ससमय आवंटित करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा--

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवस्थापना मद की कुल आवंटित धनराशि रु0 175.00 करोड़ नगरीय निकायों की विद्युत देयताओं के सापेक्ष भुगतान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त मद में रु0 34.00 करोड़ की धनराशि नगर निगम, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना मद में नगर निगम, लखनऊ को रु0 40.13 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

जी नहीं, नगर निगम, लखनऊ को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अवस्थापना सहित विकास कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत नगर निगम, लखनऊ को रु0 196.00 करोड़, मुख्य मंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत इण्टरलाकिंग, रोड निर्माण, नाला-नाली निर्माण आदि के लिए रु0 11.85 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत रु0 155.43 करोड़, जी0आई0एस0 के अन्तर्गत रु0 24.80 करोड़, जी-20 के अन्तर्गत रू0 05.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशियों से सौन्दर्यीकरण, लाइटिंग, पौधरोपण, सेनीटाइजेशन, फागिंग, एण्टीलार्वा छिड़काव, मार्ग प्रकाश, सड़कों के सुदृढ़ीकरण, डिवाइडर पेंन्टिंग, नाला-नाली निर्माण, चौराहों के सौन्दर्यीकरण आदि कार्य कराये गये हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की उत्तरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना के अन्तर्गत सोलर लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में

152-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सौरपुंज योजना के अन्तर्गत लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सोलर लाइट लगाये जाने का प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए सोलर लाइटों को लगाने का कार्य सुनिश्चित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौरपुंज योजना के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सोलर लाइट लगाये जाने विषयक सक्षम स्तर से अनुमोदित कोई कार्य योजना/डी0पी0आर0 विभाग में लम्बित नहीं है।

यह भी उल्लेख करना है कि डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना के अन्तर्गत नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा नेडा के माध्यम से तैयार कराकर उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना डी0पी0आर0 पर उच्चानुमोदन प्राप्त करते हुए

धनराशि निर्गत किये जाने की नियमों में व्यवस्था है। उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्य योजना डी0पी0आर0 पर सम्यक् विचारोपरान्त नगर निगम, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 18 जनवरी, 2019 द्वारा रु0 67.02 लाख, दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा रु0 155.96 लाख एवं दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा रु0 20.96 लाख (कुल धनराशि रु0 243.94 लाख) की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज तथा जानकीपुरम क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाइन भूमिगत कराये जाने के सम्बन्ध में

153-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज तथा जानकीपुरम क्षेत्र में घनी आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों की चपेट में आकर जन-धन हानि होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त हाईटेंशन बिजली लाइनों को भूमिगत किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं। ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार हाईटेंशन लाइन की गार्डिंग करायी जाती है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम आवासीय योजना में श्मशान क्षेत्र की भूमि आवंटित किये जाने का प्रकरण

154-डा0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्रधिकरण की जानकीपुरम आवासीय योजना में सम्मिलित गांवो के समीप श्मशान क्षेत्र को उक्त आवासीय योजना की सम्पत्ति विक्रय में आवंटियों को श्मशान क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट/पार्क दर्शया गया था तथा वर्तमान में वहाँ अन्त्येष्टि संस्कार किये जाने से आवंटियों को समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त श्मशान से उत्पन्न समस्या का स्थायी समाधान करते हुए उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जानकीपुरम् आवासीय योजना में गांवों के समीप श्मशान क्षेत्र को उक्त आवासीय योजना की सम्पत्ति विक्रय में आवंटियों के पक्ष में जो डीड निष्पादित की गयी है, उसके साथ संलग्न लीज प्लान में भी दर्शाया गया है।

चूँकि ले-आउट में पूर्व से ही श्मशान दर्शित है तथा आवंटियों को निष्पादित डीड में भी लीज प्लान में श्मशान को दर्शाया गया है। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राज्य कर विभाग अन्तर्गत जनपद में 03 वर्ष एवं मण्डल में 07 वर्ष सेवा देने पर उनके परिजनों को गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु पात्रता के आधार पर स्थानान्तरण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

155-श्री सचिन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य कर विभाग में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत एक जनपद में 03 वर्ष अथवा एक मण्डल मैं 07 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके अधिकारियों को उनके परिजनों की गम्भीर बीमारी के इलाज कराने के अनुरोध पर पात्रता के अधार पर स्थानांतरित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 15-06-2022 द्वारा जारी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 के प्रस्तर-5 (iii) में निम्न व्यवस्था है :-

किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

उक्त के क्रम में राज्य कर विभाग द्वारा स्थानान्तरण सत्र में ऐसे प्रकरणों पर विचार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में फरिहा से एटा मार्ग को फोर लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में

156-श्री सचिन यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद से फरिहा, एका होते हुये एटा तक एकल मार्ग होने के कारण उक्त मार्ग पर दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को फोर लेन बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग का पी0सी0यू0 चार लेन चौड़ीकरण हेतु अपेक्षित पी0सी0यू0 से कम है। अतः उक्त मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण निर्धारित मानकों से आच्छादित नहीं है।

जनपद कानपुर में कुलीबाजार गुलियाना बादशाहीनाका में कतिपय चट्टा मालिक द्वारा भैंस का चट्टा न हटाये जाने विषयक

157-डा0 संग्राम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में मकान नं0 76/228, कुलीबाजार गुलियाना बादशाहीनाका में कतिपय चट्टा मालिक द्वारा भैंस के चट्टे न हटाये जाने के कारण कानपुर नगर निगम द्वारा दिनांक 24 जून, 2019 को रु0 2,86,000/- का दण्डात्मक जुर्माना किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त जुर्माना कानपुर नगर निगम कोष में जमा कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जुर्माना की वसूली करते हुये उक्त भैंस के चट्टा को उक्त स्थान से पूर्ण रूप से हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर निगम, कैंटिल कैंचिंग विभाग, कानपुर द्वारा दिनांक 24-06-2019 को मकान नं0 76/228, कुलीबाजार, गुलियाना, बादशाहीनाका में कतिपय चट्टा मालिकों पर रु0 2,86,000/- का दण्डात्मक जुर्माना नहीं किया गया था।

वर्तमान में उक्त स्थल पर कोई भैंस का चट्टा नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ की पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत न्यू हैदरगंज वार्ड-03 में कतिपय खड़न्जा मार्ग को पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

158-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के न्यू हैदरगंज वार्ड-3 में ग्राम मुन्नू खेड़ा से डाक्टर खेड़ा तिकोनिया पुल तक आवागमन के लिये खडण्जा मार्ग लगभग 02 किमी0 जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पक्का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत कालोनी अनियोजित रूप से प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा बसायी गई है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है, ऐसी कालोनियों में विकास का प्रथम दायित्व सोसाइटी/कालोनाईजर का है फिर भी नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष विकास कार्य कराये जाते है। प्रश्नगत स्थल क्षतिग्रस्त है। नागरिक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थल पर सड़क

निर्माण हेतु आगणन तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य निगम के पास धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अमरोहा के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूलों के ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत लाइन शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में

159-श्री समरपाल सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अमरोहा के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूलों के ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत लाइनें शिफ्ट करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद अमरोहा के 43 नं0 जूनियर/प्राइमरी स्कूलों के ऊपर से हाई वोल्टेज लाइनें शिफ्ट करने का कार्य पूर्व में कराया जा चुका है एवं वर्तमान में 55 नं0 जूनियर/प्राइमरी स्कूलों के ऊपर से हाई वोल्टेज विद्युत लाइनें शिफ्ट करने का कार्य नवीन जिला विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है तथा कार्य प्रगति पर है।

कार्य शीघ्र पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ऋण जमा के अनुपात एवं देश के ऋण जमा अनुपात की जानकारी के सम्बन्ध में

160-श्री जगदीश नरायण-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऋण जमा का अनुपात क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि देश के ऋण जमा अनुपात में प्रदेश का कौन सा स्थान है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

प्रदेश का ऋण जमा अनुपात माह दिसम्बर, 2022 में 54.67 प्रतिशत था।

देश के ऋण जमा अनुपात में प्रदेश का कौन सा स्थान है, से सम्बन्धित सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

जनपद हाथरस की नगर पंचायत सादाबाद में आगरा से मथुरा को जोड़ने वाली जर्जर सड़क के डामरीकरण के सम्बन्ध में

161-श्री जगदीश नारायण-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस की नगर पंचायत सादाबाद में आगरा रोड से ईदगाह होते हुए मथुरा रोड को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है व

दोनों ओर नालियां भी टूटी हुयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पंचायत सादाबाद में आगरा रोड से ईदगाह होते हुए मथुरा रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराया गया था। उसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त डामर सड़क के दोनों तरफ पटरी पर राज्य वित्त आयोग की धनराशि से इण्टरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण कराया गया है। डामर सड़क कतिपय स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका पुनर्निर्माण एवं नाली का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में लखनऊ माझीघाट मार्ग पर स्थित गोमती नदी पर जर्जर पुल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में

162-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में लखनऊ माझीघाट मार्ग पर स्थित गोमती नदी का पुल जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर में लखनऊ-मांझीघाट मार्ग के कि0मी0 259 में गोमती नदी पर स्थित सेतु के एक्पेंशन ज्वाइंट, बियरिंग, रेलिंग एवं फुटपाथ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

जी हां, प्रश्नगत सेतु के आंशिक क्षतिग्रस्त भाग हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य करा दिया गया है एवं द्वितीय चरण हेतु अपेक्षित धनराशि की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

163-श्री तुफानी सरोज-

[बहुत अधिक ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर अन्तर्गत कतिपय कस्बों में पुरानी विद्युत लाइन हटवाते हुए केबल के तार द्वारा विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

164-श्री कैलाश नाथ-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत स्थित ग्रामीण स्तर के कस्बों मथुरा बाजार, शिवपुरा, हरैया बाजार में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिये पुराने जर्जर तारों को बदलवाकर केबल के द्वारा विद्युत आपूर्ति कराया जाना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड हरैया सतघरवा के ग्राम हरैया सतारवा मजरा हरैया सतधरवा, ग्राम शिवपुरा के मजरा शिवपुरा और ग्राम मथुरा बाजार के मजरा मथुरा बाजार में जर्जर तार को ए0बी0सी0 केबिल द्वारा बदलने का कार्य जनवरी, 2022 में पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर अन्तर्गत ग्राम-ठाकुरजोत में विद्युत उपकेन्द्र को पुनः संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में

165-श्री कैलाश नाथ-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम ठाकुरजोत (शिवपुरा) में पूर्व निर्मित 33/11 विद्युत उपकेन्द्र को पुनः संचालित करवाने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम ठाकुरजोत (शिवपुरा) में पूर्व में दिनांक 11-11-98 को पूर्वाचल विकास निधि से स्वीकृत एवं निर्मित परन्तु सम्प्रति बाढ़ में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र को पुनः पूर्ण क्षमता पर संचालित करवाने का कार्य रिवैम्प्ड योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

योजना में आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उप्लब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत कतिपय विद्युत उपकेन्द्रों पर मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

166-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी, दिघार, रेवती, बैरिया नगरीय व ग्रामीण चाँद दियर (लोकधाम

ठेकहा) व जय प्रकाश नगर फीडरों पर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न होने के कारण आम जनमानस को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त फीडरों से मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी, दिघार, रेवती, बैरिया नगरीय व ग्रामीण चांद दियर (लोकधाम ठेकहा) व जय प्रकाश नगर फीडरों पर विद्युत आपूर्ति निर्धारित रोस्टर (ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे एवं तहसील मुख्यालय पर 21.30 घण्टे) के सापेक्ष उपरोक्त क्षेत्रों में (ब्रेकडाउन व शटडाउन एवं आपातकालीन की जाने वाली कटौती छोड़कर) वर्ष 2022-23 में अभी तक औसतन 17.47 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में एवं तहसील क्षेत्र में 19.46 घण्टे औसतन आपूर्ति की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत अधूरे पचरूखिया दिघार रेवती मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

167-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में पचरूखिया दिधार रेवती मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग विभागीय अभिलेखों में दीघार पिरौटा से रेवती है, जो अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का है, जिसकी कुल लम्बाई 8.33 है, जिसके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 1819.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है। कार्य जून, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की बदलापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जर्जर सहकारी केन्द्रों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में

168-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत सभी जर्जर सहकारी केन्द्रों को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार सरकार करवायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जे0 पी0 एस0 राठौर-

जनपद जौनपुर के बदलापुर विधान सभा क्षेत्र में सहकारिता विभाग की 24 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां न्याय पंचायत स्तर पर अवस्थित है, जिनमें से 07 समितियां जर्जर के रूप में चिन्हित हैं। जर्जर समितियों के पुनर्निर्माण/नवनिर्माण कराये जाने हेतु वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर की कतिपय विकास खण्डों को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में

169-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत सिगरामऊ तथा विकास खण्ड महराजगंज को नगर पंचायत का दर्जा सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426 सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है। जिसमें निर्धारित मुख्य मानक-प्रस्तावित क्षेत्र की जनसंख्या-20,000 या उससे अधिक होना 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना, शहरी गुण होना आदि निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 20-10-2022 एवं पत्र दिनांक 18-01-2023 द्वारा क्रमशः जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सिंगरामऊ तथा महराजगंज को नगर पंचायत बनाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उक्त आख्यानुसार उक्त क्षेत्रों के 65 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि तथा जनसंख्या 20,000 से कम है। अतः उक्त आख्या के आधार पर मानकों की पूर्ति न किये जाने के दृष्टिगत जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत सिंगरामऊ तथा विकास खण्ड महराजगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा अन्तर्गत अयोध्या-डुमरियागंज, बहराइच-गोण्डा मार्ग को फोरलेन किये जाने के सम्बन्ध में

170-श्री प्रभात कुमार वर्मा -

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अयोध्या से गौरा डुमरियागंज-सिद्धार्थनगर मार्ग तथा बहराइच-गोण्डा से अयोध्या को फोरलेन मार्ग सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

अयोध्या से गौरा डुमरियागंज-सिद्धार्थनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बहराइच गोण्डा मार्ग (राज्य मार्ग सं0-30) वर्तमान पी0सी0यू0 के आधार पर 4 लेन हेतु अर्ह नहीं है।

गोण्डा से अयोध्या मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 330 है। उक्त मार्ग फोरलेन किये जाने की स्वीकृति सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती है।

जनपद गोण्डा व बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी पर सरयू नदी पर फोरलेन पुल बनाये जाने हेतु दूसरे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

171-श्री प्रभात कुमार वर्मा -

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा व बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी व सरयू नदी पर सिंगल लेन पुल के अतिरिक्त उक्त प्रमुख मार्ग जो लखनऊ को जोड़ता है, फोरलेन पर दूसरा पुल बनाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-927 बाराबंकी से रूपैडिहा मार्ग है जो वर्तमान में दो लेन पेव्ड शोल्डर मार्ग है जिसे फोर लेन चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्ग की डी0पी0आर0 कार्य प्रगति पर है जिसके अन्तर्गत बाराबंकी से रूपैडिहा मार्ग पर घाघरा पुल समाहित है।

जनपद गोण्डा को लखनऊ से जोड़ने हेतु गोण्डा-जरवल मार्ग (एस0एच0-1ए) के किमी0 221 में सरयू नदी पर पुल स्थित है। प्रश्नगत मार्ग भारत सरकार के राजपत्र संख्या-1128 जीआई/2015, दिनांक 10-03-2015 द्वारा राष्ट्रीय मार्ग 330बी के रूप में घोषित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रश्नगत मार्ग को हस्तान्तरित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद गोण्डा के गौरा चौकी-बभनान मार्ग पर रेलवे क्रासिंग के ऊपर रेलवे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

172-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के गौरा चौकी बभनान मार्ग पर बभनान कस्बा में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज न होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बे में रेलवे पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के दोनों तरफ पक्के मकान, दुकान घनी बस्ती एवं अतिक्रमण है, जिनको हटाने/विस्थापित करने के उपरान्त ही प्रस्तावित सेतु का निर्माण कार्य फिजबिल होगा। उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी अन्तर्गत रिछा कस्बे में विद्युत ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में

173-श्री अताउर रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के कस्बा रिछा में सब स्टेशन 33 के0वी0 ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि 05 के0वी0ए0, 10के0वी0ए0 जनहित में सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बरेली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के कस्बा रिछा में स्थापित 33/11 के0वी0 रिछा उपकेन्द्र की क्षमता 05 के0वी0ए0 से बढ़ाकर 10 के0वी0ए0 करने का कार्य बिजनेस प्लान वर्ष 2023-2024 में स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में

174-श्री अताउर रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-बहेड़ी के कस्बा रिछा-जहानाबाद रोड से शारदा नहर पुलिया से चुरैली डाम तक मार्ग का लेपन कार्य न होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य को समय-सीमा निर्धारित कर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में ग्राम चुरेली डाम पूर्व में ही लेपित मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत मार्ग खडन्जा स्तर का है, जो ग्राम चुरैली डाम को एक अन्य संरेखण के द्वारा पक्के मार्ग से जोड़ने से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में ई-कचरे के निस्तारण हेतु नियमों को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु

175-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ई-कचरा पैदा करने वाली उत्पादन इकाइयों को ई-कचरे के प्रबन्धन हेतु कौन से नए नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है ? क्या सरकार उक्त नियमों तथा उक्त के उल्लंघन करने पर प्रवाधानित कार्रवाई का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02-11-2022 द्वारा प्रदेश में ई-कचरे के प्रबन्धन के लिए ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम 2022 प्रख्यापित किया गया है, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

प्रदेश में ई-कचरे के निस्तारण हेतु कार्यवाही ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022 में प्रावधानित है तथा इसी नियम के प्रावधानों के अनुसार विस्तारित निर्माता उत्तरदात्यिव (ईपीआर) के रूप में इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल उत्पादककर्ताओं द्वारा जमा की गई कार्य योजना के अनुसार कार्यवाही कराये जाने की सरकार की कार्य योजना है। ऐसे उत्पादनकर्ता जिनसे ई-वेस्ट जनित होगा उन्हें उक्त के प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना एवं किसी भी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में विनिर्माण के दौरान अथवा पुराने हिस्से से नया उत्पाद बनाने वाली इकाइयों से उत्पन्न ई-कचरा और अपशिष्ट को एकत्र करना और उसके पुनर्चक्रण या निपटान एवं परिशोधन को सुनिश्चित करना तथा इसका रिकॉर्ड मेन्टेन करना भी अनिवार्य किया गया है।

इस हेतु निम्न विभागों का पृथक-पृथक उत्तरदायित्व ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022 की अनुसूची-5 में वर्णित है।

1-केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

2-राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ।

3-स्थानीय निकायों (शहरी व ग्रामीण) का उत्तरदायित्व।

4-भारतीय बन्दरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के तहत बन्दरगाह प्राधिकरण की जिम्मेदारी और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमाशुल्क प्राधिकरण।

5-भारत मानक ब्यूरो, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारियाँ।

6-ई-अपशिष्ट इकाइयों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही ई-अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2022 के क्रमांक 22 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति व क्रमांक 23 में अभियोजन कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना खरीद मूल्य में वृद्धि की जानकारी एवं गन्ना मूल्य विलम्ब से घोषित किये जाने के कारण के सम्बन्ध में

176-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ना खरीद मूल्य में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है ? क्या सरकार गन्ना मूल्य देर से घोषित करने के प्रमुख कारण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण -

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पेराई सत्र 2021-22 में घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य को यथावत रखते हुए पेराई सत्र 2022-23 के लिए विज्ञप्ति संख्या 01/2023/210/46-3-23-3/(48) 98-99, दिनांक 17 फरवरी 2023 के माध्यम से गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) निम्नवत् घोषित किया गया है:-

अगेती प्रजाति रु0350.00 प्रति कुन्तल

सामान्य प्रजाति रु0340-00 प्रति कुन्तल

अनुपयुक्त प्रजाति रु0335 00 प्रति कुन्तल

उक्त के दृष्टिगत इसे सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है

उपरोक्तानुसार।

जनपद अयोध्या की विधान सभा क्षेत्र बीकापुर अन्तर्गत निरीक्षण गृह के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता की जाँच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

177-श्री अमित सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-07-22 पत्रांक सं0- क-6 नं0 797494 व पत्र दिनांक 13-12-22 पत्रांक सं0- क-6 नं0 632146 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था व पत्र दिनांक 19-07-22 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को सम्बोधित था जिसमे अयोध्या जनपद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत राजकीय राजमार्ग के किनारे स्थित निरीक्षण गृह के निर्माण कार्य में किये गये अनियमितता की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा पुनः प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में साक्ष्य लेकर जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित निरीक्षण गृह के निर्माण कार्य में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक मा0 सदस्य, विधान सभा के उल्लिखित पत्रों में से पत्र दिनांक 13-12-2022 पत्रांक सं0-क-6 नं0 632146 कार्यालय अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु उक्त विषयक पत्र दिनांक 19-07-22 पत्रांक सं0 क-6 नं0 797494, जो कि मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तथा पत्र दिनांक 19-07-22 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं।

उक्त मार्ग की जाँच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के माध्यम से करायी गयी है। कोष्ठ की प्राप्त जाँच आख्या दिनांक 21-10-2022 पर शासन के पत्र दिनांक 21-11-2022 एवं पत्र दिनांक 17-01-2023 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष समिति की संस्तुति सहित आख्या मांगी गयी है। प्रकरण में वांछित आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या की बीकापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के अनुबन्ध न गठित होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

178-श्री अमित सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-12-22 पत्रांक सं0-6 न0 632352, जो मुख्य मंत्री को प्रेषित था तथा विधान सभा क्षेत्र बीकापुर,

अयोध्या की दो सड़क के अनुबन्ध न गठित होने विषयक तथा सड़क निर्माण नहीं होने के सम्बन्ध में है. पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

मा0 सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र में उल्लिखित दोनों मार्गों के सम्बन्ध में अनुबन्ध संख्या-274/एस0ई0-अयो0-अम्बे0 वृत्त/23, दिनांक 27-01-2023 एवं अनुबन्ध संख्या-273/एस0ई0-अयो0-अम्बे0 वृत्त/23, दिनांक 27-01-2023 द्वारा अनुबन्ध का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में दोनों मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में कतिपय आरामशीन द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क न जमा करने के सम्बन्ध में

179-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी पत्रांकः स्टा0 अ0 953/41, लखनऊ दिनांक 24 दिसम्बर, 2018, जो कि प्रदेश में आरामशीन के लाइसेंस के नवीनीकरण के सम्बन्ध में है, के आदेशानुसार जनपद प्रयागराज में सामिल विद वरटिकल बैंड सॉ अपटू 10 एच0पी0 हॉरीजेन्टल बैंड सॉ आरा मशीन के लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु रु0 17000/-के स्थान पर 2000/-रु0 जमा किया जा रहा है जिससे राजस्व की क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व बढ़ाने हेतु जनपद प्रयागराज में आरामशीन के लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु निर्धारित धनराशि रु0 17000/-जमा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरूण कुमार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

आरामशीनों का नवीनीकरण हेतु निम्न प्रकार दरें निर्धारित की गयी हैं

क्र0 सं0	आरामशीन का प्रकार	वार्षिक लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क दर (रु0 में)
1	उर्ध्व बैंड आरी के साथ 10 हार्सपावर तक की आरामिल	2000/-

क्र0 सं0	आरामशीन का प्रकार	वार्षिक लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क दर (रु0 में)
2	उर्ध्व बैंड आरी के साथ 10 हार्सपावर से अधिक की आरामिल	15,000/-
3	उर्ध्व एवं क्षैतिज बैंड आरी के साथ 10 हार्सपावर तक की आरामिल	17,000/-
4	उर्ध्व एवं क्षैतिज बैंड आरी के साथ 10 हार्सपावर से अधिक की आरामिल	30,000/-

उपरोक्तानुसार प्रत्येक आरा मशीन का मूल लाइसेंस में दर्ज प्रकार व क्षमता के अनुरूप ही निर्धारित शुल्क आरा मशीन स्वामी द्वारा ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त वार्षिक नवीनीकरण, प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

जनपद लखनऊ के विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 लो0नि0वि0 में 35 वर्षों से स्थानान्तरण नीति के विपरीत कतिपय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की तैनाती के सम्बन्ध में

180-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम अचल राजभर, स0वि0स0 का पत्र सं0-क-7 नं0 64070, दिनांक 07 जुलाई, 2022 जो जनपद लखनऊ के विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2 लो0नि0वि0 लखनऊ में स्थानान्तरण नीति के विपरीत लगभग 35 वर्षों से तैनात कतिपय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण विषयक है, प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

वर्ष 2022-23 का स्थानांतरण सत्र दिनांक 10-07-2022 को समाप्त हो गया था। उक्त स्थानांतरण सत्र समाप्त हो जाने के उपरांत पत्र प्राप्त होने के कारण तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्ष 2023-24 का स्थानांतरण सत्र प्रारम्भ होने पर निर्गत स्थानांतरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर अन्तर्गत स्थित ग्राम इटैली पाण्डेय में विद्युत आपूर्ति हेतु बांस-बल्ली के स्थान पर विद्युत खंभे लगवाये जाने के सम्बन्ध में

181-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खंड बस्ती सदर के अन्तर्गत स्थित ग्राम इटैली पाण्डेय में निवासीगणों को

बिजली की आपूर्ति बांस-बल्ली पर विद्युत तार खींच कर की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युत खम्भा लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत ग्राम इटैली पाण्डेय में विद्युत पोल व तार लगाये जाने का कार्य रिवैम्प्ड योजना में सम्मिलित है। कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रूपपुर में लो0नि0वि0 की जर्जर सड़क की मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

182-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रूपपुर में लोक निर्माण विभाग की मेन सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

रूपपुर से कुर्रीकूपा मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 3.00 किमी0 है, जिसके नवीनीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में

183-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी के अनथुवा-देवरार मार्ग से पौण्डरा-दुबरी (लगभग 2 किमी0) सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बांदा में तहसील नरैनी के अन्तर्गत अनथुवा-देवरार मार्ग से पौण्डरा दुबरी ग्रामीण मार्ग पर विशेष मरम्मत हेतु लम्बाई 2.00 किमी0 एवं लागत रु0 22.20 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है। मार्ग पर मरम्मत का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा अन्तर्गत क्षतिग्रस्त स्टेशन रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

184-श्री अखिलेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में स्टेशन रोड क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

जी हां।

नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित स्टेशन रोड लगभग 400 मीटर है, जो नगर पालिका परिषद् अतर्रा के स्वामित्व में है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर विकास योजनान्तर्गत निर्माण प्रस्तावित है जिसका आगणन तैयार करा लिया गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3268000.00 रु0 है। नगर पालिका की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर धन उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 26-08-2023 तक सड़कों के निर्माण/गड्ढामुक्त कराये जाने की जानकारी के सम्बन्ध में

185-श्री अतुल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 26-08-2022 तक कितनी व कौन कौन सी सड़कों का निर्माण व कितनी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है, तथा

कितनी सड़कों का निर्माण और गड्ढामुक्त कराया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष सड़कों का निर्माण अथवा गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 26-08-2022 तक निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य एवं गड्ढामुक्ति के कार्यों को पूर्ण कराया गया है :-

क्र0 सं0	कार्य का प्रकार	कुल कार्य	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0 में)	माह 02/22 तक पूर्ण लम्बाई (कि0मी0 में)	माह 08/22 तक पूर्ण लम्बाई (कि0मी0 में)	अवशेष (कि0मी0 में)
1	निर्माण	8	55.560	0.810	21.086	33.664
2	गड्ढामुक्त	30	81.850	9.950	38.650	21.250

अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा गड्ढामुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। (कार्यों की सूची संलग्न है।)†

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में वृक्षारोपण कार्य में जिलेवार व्यय की गयी धनराशि की जानकारी के सम्बन्ध में

186-श्री अतुल प्रधान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में वृक्षारोपण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या सरकार उक्त कार्य हेतु खर्च धनराशि का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

प्रदेश में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में वृक्षारोपण कार्य पर क्रमशः रु0 6120349 लाख एवं रु0 61811.62 लाख की धनराशि व्यय की गयी है, जिसका वर्षवार/जनपदवार/प्रभागवार विवरण निम्न प्रकार है :-

---

† देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ सं0 368-371 पर।

वित्तीय वर्ष (रु0 लाख में)

क्र0सं0	वृत्त नाम	जनपद/प्रभाग का नाम	2020-21	2021-22
1	आगरा वृत	आगरा	641.10	672.18
		मैनपुरी	535.39	528.96
		मथुरा	315.36	559.97
		फिरोजाबाद	472.24	510.35
		योग	1964.09	2271.45
2	अलीगढ़ वृत	अलीगढ़	364.62	495.37
		हाथरस	349.63	368.68
		एटा	315.31	272.04
		कासगंज	358.12	372.77
		योग	1387.68	1508.86
3	बरेली वृत्त	बरेली	512.02	444.55
		बदायूं	532.36	485.96
		शाहजहांपुर	866.81	784.30
		योग	1911.19	1714.82
4	पीलीभीत टाईगर रिजर्व	पीलीभीत सा0वा0प्रभाग	171.79	180.90
		पीलीभीत टाइगर	0.42	0.28
		योग	172.21	181.18
5	बुन्देलखण्ड वृत्त	झांसी	837.34	650.69
		ललितपुर	867.83	668.29
		जालौन (उरई)	829.11	803.94
		योग	2534.28	2122.92
6	चित्रकूटधाम वृत्त	बांदा	626.36	538.70
		हमीरपुर	1021.87	973.63
		महोबा	1246.71	911.43

क्र0सं0	वृत्त नाम	जनपद/प्रभाग का नाम	2020-21	2021-22
		चित्रकूट	1274.82	852.83
		योग	4169.76	3276.58
7	कानपुर मण्डल	कानपुर	909.15	857.50
		कानपुर देहात	1138.38	945.02
		फर्रुखाबाद	592.50	425.15
		कन्नौज	590.90	649.98
		इटावा	790.45	570.24
		औरैया	475.94	359.71
		योग	4497.32	3807.60
8	लखनऊ मण्डल	लखनऊ	476.25	461.02
		रायबरेली	780.83	880.13
		हरदोई	879.24	915.29
		उन्नाव	889.07	824.21
		सीतापुर	865.59	877.44
		द0खीरी	791.13	750.33
		उ0 खीरी	268.54	254.32
		योग	4950.65	4962.74
9	सरयू वृत्त, अयोध्या	अयोध्या	855.05	770.14
		अम्बेडकरनगर	689.73	612.73
		सुल्तानपुर	842.96	958.68
		बाराबंकी	991.77	898.54
		अमेठी	1099.48	980.73
		योग	4478.99	4220.82
10	देवीपाटन वृत्त, गोण्डा	गोन्डा	928.66	867.45
		बलरामपुर गोन्डा	506.94	473.00

क्र0सं0	वृत्त नाम	जनपद/प्रभाग का नाम	2020-21	2021-22
		श्रावस्ती	1486.33	1476.92
		बहराइच	1332.68	1078.27
		योग	4254.61	3895.64
11	मेरठ वृत्त	मेरठ	247.36	162.93
		बागपत	127.64	108.97
		गाजियाबाद	57.44	48.05
		हापुड	182.98	143.38
		गौतमबुद्धनगर	83.62	85.62
		बुलन्दशहर	434.05	435.04
		योग	1133.09	983.99
12	सहारनपुर वृत्त	सहारनपुर	252.52	202.55
		शिवालिक	376.85	436.34
		मुजपफरनगर	236.66	215.92
		शामली प्रबुद्ध नगर	128.61	158.19
		योग	994.64	1012.99
13	मुरादाबाद वृत्त	मुरादाबाद	202.20	197.82
		सम्भल भीमनगर	166.91	187.18
		अमरोहा ज्योतिबाफूलेनगर	493.11	512.20
		रामपुर	289.00	283.93
		बिजनौर	571.52	593.88
		नजीबाबाद	601.73	554.70
		योग	2324.47	2329.71
14	वाराणसी वृत	वाराणसी	370.33	353.58
		गाजीपुर	586.65	571.26

क्र0सं0	वृत्त नाम	जनपद/प्रभाग का नाम	2020-21	2021-22
		जौनपुर	852.15	755.45
		योग	1809.13	1680.29
15	मिर्जापुर मण्डल	सन्तरविदास नगर	238.78	227.45
		मिर्जापुर + कैमूर	1168.57	827.03
		सोनभद्र + कैमूर	727.58	522.17
		रेनुकूट	450.19	458.41
		ओबरा	386.25	317.51
		योग	2971.37	2352.57
16	प्रयागराज वृत्त	प्रयागराज	908.26	741.55
		कौशाम्बी	358.34	410.19
		फतेहपुर	389.43	547.30
		प्रतापगढ़	630.44	703.39
		योग	2286.47	2402.43
17	गोरखपुर मंडल	गोरखपुर	828.63	800.14
		महराजगंज पार्ट	251.01	219.36
		देवरिया	658.91	553.74
		पडरौना (कुशीनगर)	511.63	557.68
		योग	2250.18	2130.92
18	बस्ती वृत्त	बस्ती	614.54	591.62
		सन्तकबीरनगर	679.72	621.31
		सिद्धार्थनगर	573.45	588.01
		योग	1867.71	1800.94
19	आजमगढ़ वृत्त	आजमगढ़	665.58	737.97
		मऊ	343.34	440.94

क्र0सं0	वृत्त नाम	जनपद/प्रभाग का नाम	2020-21	2021-22
		बलिया	731.87	754.94
		योग	1740.79	1933.86
20	मु0 वन संर0 व0जी0 पूर्वी गोण्डा	सोहगीबरवा	113.06	91.93
		सोहेलवा	56.36	69.87
		योग	169.42	161.80
21	मु0व0सं0व0जी0, प0 कानपुर	काशी वन्य जीव प्रभाग	1155.43	760.52
		योग	1155.43	760.52
		कुल योग	49023.49	45512.62
	कैम्पा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु व्यय धनराशि		12180.00	16299.00
		महायोग	61203.49	61811.62

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

187-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[दिनांक 23-02-2023 को उत्तरित।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम आवासीय योजना में रिक्त प्लॉटों के विक्रय हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

188-डा0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम आवासीय योजना में कतिपय प्लाट रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त प्लाटों का विवरण क्या है ? क्या सरकार विभाग द्वारा रिक्त प्लाटों के विक्रय हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित जानकीपुरम् आवासीय योजना में कोई आवासीय प्लाट रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत फैजुल्लागंज तथा जानकीपुरम क्षेत्र में बांस-बल्ली के स्थान पर विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में

189-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फैजुल्लागंज तथा जानकीपुरम क्षेत्र में बांस-बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत क्षेत्र में बांस-बल्ली हटाकर स्थायी विद्युत पोल लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्तमान में बांस-बल्ली वाले स्थानों को चिन्हित किया जा चुका है। उक्त कार्य नवीन जिला विद्युत विकास निधि अथवा धन की उपलब्धता पर कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जानकीपुरम द्वितीय वार्ड में सहारा स्टेट के अन्दर नगर निगम के तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

190-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के जानकीपुरम द्वितीय वार्ड स्थित सहारा स्टेट के अन्दर नगरीय झील/तालाब (पोखर) संरक्षण योजनान्तर्गत नगर निगम के तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष 2019 से शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के जानकीपुरम द्वितीय वार्ड स्थित सहारा स्टेट के अन्दर नगरीय झील/तालाब (पोखर) संरक्षण योजनान्तर्गत नगर निगम के तालाब का सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 436.96 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत दिनांक 01-01-2023 तक पात्र लाभार्थियों के शेष भुगतान की जानकारी के सम्बन्ध में

191-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में दिनांक 01-01-2023 तक कितने पात्र लाभार्थियों की पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त का भुगतान शेष है ? क्या सरकार उक्त लंबित किस्तों को लाभार्थियों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2023 तक प्रथम किस्त हेतु 380, द्वितीय किस्त हेतु 895 तथा तृतीय किस्त हेतु 9774 लाभार्थियों को भुगतान किया जाना शेष है।

जी हाँ।

अवशेष किस्तों के भुगतान हेतु अवशेष धनराशि भारत सरकार द्वारा शीघ्र अवमुक्त किया जाना सम्भावित है, जिसके प्राप्त होने पर यथास्थिति आवश्यक धनराशि जनपद को उपलब्ध करा दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों को निजी ट्यूबवेल लगाये जाने हेतु प्रदान की गयी सुविधा की जानकारी के सम्बन्ध में

192-श्री जगदीश नारायण-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को निजी ट्यूबवेल लगाने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा क्या-क्या सुविधा प्रदान की जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्रदेश के नलकूप धारक किसानों को विद्युत दर में 88.19 प्रतिशत का राहत दी जा रही है। मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते समय अब यह राहत 100 प्रतिशत करने की घोषणा कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में रिंग रोड बनाये जाने की कार्य योजना के सम्बन्ध में

193-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में रिंग रोड बनाने की कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद जौनपुर में रिंग रोड बनाने की कोई कार्य योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अधिशाषी अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, पी0आई0यू0, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जौनपुर रिंग रोड/फेज-1 के बाईपास कार्य हेतु डी0पी0आर0 कन्सल्टेण्ट की नियुक्ति कर दी गयी है एवं इस कार्य की स्वीकृति मई, 2023 तक अनुमानित है। स्वीकृति के उपरान्त टेन्डर प्रक्रिया का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

जनपद अयोध्या से वाराणसी तक हाई-वे बनाये जाने के सम्बन्ध में

194-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या से वाराणसी तक हाई-वे बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

जनपद अयोध्या से वाराणसी पूर्व से ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है।

जनपद लखनऊ मांझीघाट मार्ग पर स्थित पुल की मरम्मत कार्य के आगणन को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

195-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ मांझीघाट मार्ग पर जनपद जौनपुर के मार्ग 259 कि0मी0 पर गोमती नदी पर स्थित पुल की मरम्मत कार्य का आगणन निगम मुख्यालय में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

प्रश्नगत सेतु के प्रथम चरण के अन्तर्गत मरम्मत का कार्य करा दिया गया है एवं द्वितीय चरण हेतु अपेक्षित धनराशि की स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है, जिसके सापेक्ष निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में मडियाहूँ से वाराणसी सीमा तक निर्मित मार्ग निर्माण में की गयी अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में

196-श्री जगदीश नरायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में मडियाहूँ से इटायें होते हुये वाराणसी सरहद तक निर्मित मार्ग निर्माण में की गई अनियमितता की जानकारी सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर में मडियाहूँ से इटायें होते हुए वाराणसी सरहद तक मार्ग, विभागीय अभिलेखों में पिण्डरा कठिराव इटायें-मडियाहूँ अन्य जिला मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 13.425 कि0मी0 है। इस मार्ग पर चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 28-10-2021 द्वारा लागत रु0 1569.57 लाख की प्राप्त है। मार्ग का चौड़ीकरण मूल लेपित चौड़ाई 3.75 मी0 से 5.50 मी0 में प्रस्तावित है जिसमें जी0एस0वी0 से 21.0 सेमी0 मोटाई में लगभग 12.00 कि0मी0 लम्बाई ने मात्र चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है। कराये गये कार्य की चेकिंग की गयी है, जो सन्तोषजनक है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के भड़रिया से बढ़नी माफी तक जर्जर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

197-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के भड़रिया से बढ़नी चाफा मार्ग जर्जर होने के कारण आम जनमानस को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को उच्चीकृत/चौड़ीकरण कराकर नव निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग भड़रिया से बढ़नी चाफा मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसके चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर की नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नूरपुर नगर के प्राथमिक विद्यालय में सामुदायिक शौचालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में

198-श्री राम अवतार सिंह सैनी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नूरपुर नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सामुदायिक शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 18-05-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नूरपुर नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सामुदायिक शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 10-05-2022 प्राप्त हुआ है।

शासन के पत्र दिनांक 15-09-2022 एवं 15-02-2023 द्वारा उक्त पत्र दिनांक 10-05-2022 की प्रति राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। राज्य मिशन निदेशक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों की चाहरदीवारी के अन्दर सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु धनांवटन का प्रावधान नहीं है।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद, नूरपुर में राज्य मिशन निदेशालय के पत्र दिनांक 13-10-2017 द्वारा 18 सीट सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु रु0 7.056 लाख पत्र दिनांक 22-12-2017 द्वारा 20 सीट सामुदायिक शौचालय हेतु रु0 15.68 एवं 05 सीट सार्वजनिक शौचालय महिलाओं हेतु रु0 3.92 लाख, पत्र दिनांक 01-07-2019 द्वारा 06 सीट सार्वजनिक शौचालय हेतु रु0 4.704 लाख एवं 04 यूरिनल हेतु रु0 0.85336 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के नगर पंचायत सुच्चितागंज में सड़क पर लगे बिजली के खम्भे हटवाये जाने के सम्बन्ध में

199-श्री अमित सिंह चौहान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के नगर पंचायत सुच्चितागंज (खिरौनी) के सुच्चितागंज बाजार में रोड पर बिजली के खम्भे होने से जनता को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड से बिजली के खम्भों को हटवाने का कार्य करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद अयोध्या के नगर पंचायत सुच्चितागंज (खिरौनी) के सुच्चितागंज बाजार में सड़क चौड़ीकरण के कारण बिजली के खम्भों को शिफ्ट करने का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चयनित स्मार्ट सिटी की संख्या एवं उनमें किये गये कार्यों की जानकारी

200-श्री तुफानी सरोज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है तथा उनमें से कितने स्मार्ट सिटी में किन-किन कार्यों को कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद जौनपुर को भी स्मार्ट सिटी मैं शामिल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों व राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत 07 नगर निगमों का चयन किया गया है। इन शहरों में योजनान्तर्गत स्वच्छता, जलापूर्ति, पथ-प्रकाश, सीवरेज आदि जैसी बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ स्मार्ट मार्ग, स्मार्ट पार्किंग, पार्कों एवं वाटर बॉडीज के विकास सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में तैनात कार्मिकों को केन्द्र सरकार की तैनाती के दौरान लिये गये अर्जित अवकाश को प्रदेश सेवा अवकाश के साथ जोड़े जाने के प्रावधान के सम्बन्ध में जानकारी

201-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार की सेवा में तैनात कार्मिकों को उनकी केन्द्र सरकार की सेवा अवधि के अर्जित अवकाश को प्रदेश सेवा अवकाश के साथ जोड़े जाने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ?

---

† छापा नहीं गया।

यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश में सेवारत ऐसे कार्मिकों हेतु कोई नियम बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रेव मॉल की जमीन की नीलामी दर की प्रकृति एवं उक्त मॉल को पार्वती बंगला रोड से जोड़ने वाली सड़क के सम्बन्ध में जानकारी

202-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रेव 3 मॉल की जमीन की नीलामी दर आवासीय अथवा व्यावसायिक है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त मॉल को पार्वती बंगला रोड से जोड़ने वाली रोड किस प्राधिकरण अथवा मॉल की है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आवास विभाग के शासनादेश संख्या 3236/9-आ-4-99-375-एन/99, दिनांक 18-11-1999 द्वारा नजूल भूखण्ड सं0-11, ब्लाक संख्या-6 के क्षेत्रफल लगभग 12334.52 वर्ग मी0 भूमि मल्टीप्लेक्स केन्द्र हेतु इस शर्त के अधीन कानपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित/हस्तान्तरित की गयी थी कि ''प्रश्नगत भूमि को मल्टीप्लेक्स निर्माण हेतु निजी उद्यमियों को दिये जाने हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे एवं इस प्रकार प्राधिकरण को जो मूल्य प्राप्त होगा उसमें से इस भूमि को विकसित करने के लिए जो आवश्यक धनराशि प्राधिकरण द्वारा व्यय की जाय, उसे घटाते हुए अवशेष धनराशि ही प्राधिकरण द्वारा शासन को देय मूल्य के रूप में निर्धारित की जाय। इस धनराशि को प्राधिकरण द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि में जमा करा दिया जायेगा जिसका उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर मद में ही किया जायेगा।''

उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित फिल्म नीति 1999 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :-

नवीन छविगृहों को अपने आच्छादित क्षेत्रफल के 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु करने की छूट होगी।

मल्टीप्लैक्सेज तथा छविगृहों के भावी विकास के लिए प्रमुख स्थलों पर भूमि का आवंटन स्थानीय नागर प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा। मल्टीप्लैक्सेज/छविगृहों हेतु भूमि, आवासीय दर को न्यूनतम मानकर नीलामी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित व्यक्ति

द्वारा पहले मल्टीप्लैक्सेज/छविगृहों का निर्माण कराया जायेगा तथा इसके उपरान्त ही वाणिज्यिक निर्माण किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

नजूल भूखण्ड संख्या-11, ब्लाक सं0-06 पर स्थित कानपुर हाट एवं मल्टीप्लेक्स हेतु निर्धारित भूखण्ड को एप्रोच रोड के माध्यम से पार्वती बंगला रोड को जोड़ने वाले मार्ग की भूमि नजूल भूमि है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

रायल होटल, विधायक निवास-04 लखनऊ में बंदरों के आतंक से छुटकारा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

203-श्री माधवेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायल होटल विधायक निवास-4 लखनऊ में बंदरों का आतंक बहुत अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार बंदरों के आतंक से छुटकार दिलाने हेतु कोई व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरूण कुमार-

जी हाँ।

रायल होटल विधायक निवास-4 लखनऊ में बंदरों के आतंक की शिकायत प्राप्त हुई थी।

जी हाँ।

उक्त शिकायत के क्रम में समय-समय पर वन विभाग द्वारा आतंकी बंदरों को पिंजड़ा लगाकर पकड़ा गया और उन्हें सुरक्षित कुकरैल वन क्षेत्र में छोड़ा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कुआनो नदी के तट पर स्थित बस्ती-गणेशपुर मार्ग पर वन विहार का सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में

204-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कुआनो नदी के तट पर स्थित बस्ती गणेशपुर मार्ग पर वन विहार का सुंदरीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरूण कुमार-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में कुआनो नदी के तट पर स्थित बस्ती-गणेशपुर मार्ग पर वन विहार के सुंदरीकरण की सरकार की कोई योजना अभी तक प्रस्तावित नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में गंगा बैराज स्थित हैदरपुर वैटलैण्ड को बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में

205-श्री चंदन चौहान-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में गंगा बैराज स्थित हैदरपुर वैटलैंड में विदेशी प्रवासी पक्षी काफी संख्या में आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को पंक्षी विहार (बर्ड सेंचुरी) के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

यह क्षेत्र वर्तमान में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत एक संरक्षित क्षेत्र है तथा इसका प्रबन्धन प्रचलित प्रबन्ध योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में

206-श्री अभय सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मैं सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को चिकित्सा विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के समान प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन0पी0ए0) दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रैक्टिस बन्दी भत्ता उस दशा में देय होता है जब राज्य सरकार द्वारा सम्बंधित चिकित्साधिकारियों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई गयी हो। इस प्रकार की रोक केवल

एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के लिए The UP Government Doctors (Allopathic) Restriction on Private Practice Rules, 1983 से प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर लगाई गयी है। इस नियमावली 1983 का नियम-4 यह प्राविधान करता है कि ऐसे चिकित्साधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के एवज में भुगतान किया जाएगा और यही प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के अलावा अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों की प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक नहीं लगायी गयी है इसलिए इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस भत्ता देय नहीं है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि किन चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाया जाना औचित्यपूर्ण है इसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा राज्य सरकार ने अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया है।

आगामी महाकुम्भ 2024-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में कतिपय क्षेत्रों में विकास कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में

207-श्री पीयूष रंजन निषाद

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी महाकुंभ 2024-2025 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के यमुनापार क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कैम्प स्थापना, नैनी क्षेत्र की तरफ लगभग 500 मीटर पक्का घाट एवं गंगा बांध का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

गत कुम्भ मेला 2019 में पर्यटन विभाग द्वारा 1300 टेण्ट्स के साथ टेण्ट सिटी का निर्माण किया गया था। महाकुंभ 2025 में भी यमुनापार (नैनी) क्षेत्र में अस्थाई टेण्ट सिटी की कार्य योजना प्रस्तावित की जा रही है।

महाकुम्भ 2025 की कार्य योजना में बाढ़ कार्य खण्ड (सिंचाई) द्वारा यमुना नदी के दायें किनारे पर स्थित महेवा (नैनी क्षेत्र) में भैरव मन्दिर के सामने 30 मीटर लम्बाई में पक्के घाट के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

नैनी क्षेत्र में गंगा तट पर सिंचाई विभाग का ऐसा कोई बांध नहीं है, जिसका चौड़ीकरण किया जाना है। अरैल क्षेत्र में यमुना/गंगा नदी के दांये तट पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ऊंचाई बढ़ाकर सड़क बनायी गयी है। महाकुम्भ 2025 की कार्य योजना में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में आगामी महाकुम्भ 2024-2025 के दृष्टिगत गंगा के पूरब एवं पश्चिमी घाट पर पक्का घाट एवं बांध का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

208-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में आगामी महाकुंभ 2024-2025 के दृष्टिगत गंगा घाट के पूरब एवं पश्चिम के तरफ 500 मीटर पक्का घाट एवं गंगा बांध का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

महाकुम्भ 2025 की कार्य योजना में प्रयागराज में गंगा नदी के पूरब एवं पश्चिम में निम्नवत् घाट बनाये जाने का कार्य प्रस्तावित है :-

1-गंगा नदी के पूरब स्थित छतनाग घाट के डाउन स्ट्रीम में ज्ञान गंगा आश्रम के सामने 30 मीटर लम्बाई में पक्के घाट के निर्माण का कार्य।

2-गंगा नदी के पश्चिम स्थित दशाश्वमेध घाट पर 110 मीटर लम्बाई में पक्के घाट के निर्माण का कार्य।

3-गंगा नदी के पश्चिम स्थित रसूलाबाद में 30 मीटर लम्बाई में पक्के घाट के निर्माण का कार्य।

इसके अतिरिक्त गंगा तट पर सिंचाई विभाग का ऐसा कोई बंधा नहीं है, जिसका चौड़ीकरण किया जाना है। महाकुम्भ 2025 की कार्य योजना में गंगा नदी के पूरब एवं पश्चिम में बाढ़ कार्य खण्ड (सिंचाई विभाग) द्वारा सड़क निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में पूर्वी यमुना नहर के किनारे निर्मित शामली-गंदेवड़ा मार्ग के मध्य में स्थित पेड़ों को हटाये जाने के सम्बन्ध में

209-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के किनारे निर्मित मार्गों के मध्य में स्थित पेड़ों को हटाये जाने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो जनपद शामली में पूर्वी यमुना नहर के किनारे निर्मित शामली से गंदेवड़ा संगम मार्ग के मध्य में स्थित पेड़ों को हटाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरूण कुमार-

जी हाँ।

शामली वन प्रभाग, शामली के अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर पटरी की भूमि पर संरक्षित वन भूमि है, जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू हैं। इसलिए उक्त नहर के किनारे निर्मित शामली से गंदेवड़ा संगम मार्ग के मध्य में स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना होता है।

इस हेतु अभी तक किसी भी कार्यदायी संस्था के स्तर से कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के नादरगंज में शूटिंग रेंज संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

210-श्री अरमान खान

क्या नगर विकास बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के नादरगंज सरोजनीनगर में उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शूटिंग रेंज को संचालित कराने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नादरगंज इन्डस्ट्रियल एरिया, सरोजनीनगर लखनऊ में स्थित शूटिंग रेंज में नगर निगम, लखनऊ द्वारा 50 मी0, 25 मी0 एवं 10 मी0 की रेंज का निर्माण तथा ट्रैप स्कीड रेंज का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में शूटिंग रेंज पुलिस बल, ए0टी0एस0 सिक्योरिटी सर्विसेज को फायरिंग अभ्यास हेतु वट आवंटन किया जाता है।

शूटिंग रेंज के विकास अनुरक्षण एवं संचालन पी0पी0पी0 माडल पर कराये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम, लखनऊ को सहमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना नगर निगम सदन के निर्णय/सहमति पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अमौसी स्थित नादरगंज शूटिंग रेंज का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में

211-डा0 सुरभी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अमौसी में स्थित नादरगंज शूटिंग रेंज बदहाल होने के कारण प्रदेश के निशानेबाजों को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार खेलो इण्डिया के अन्तर्गत लखनऊ स्थित नादरगंज शूटिंग रेंज के जीर्णोद्धार करने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

खेल विभाग द्वारा प्रदेश के 06 जनपदों-बिजनौर, अलीगढ़, आगरा, बलिया, बड़ौत (बागपत), कानपुर में शूटिंग रेज का निर्माण कराया जा चुका है, जो क्रियाशील है। उक्त के अतिरिक्त खेल विभाग द्वारा 02 जनपदों मेरठ व वाराणसी में शूटिंग रेंज का निर्माण कराया जा रहा है।

नादरगंज इन्डस्ट्रियल एरिया, सरोजनीनगर लखनऊ में स्थित शूटिंग रेंज में नगर निगम, लखनऊ द्वारा 50 मी0, 25 मी0 एवं 10 मी0 की रेंज का निर्माण तथा ट्रैप स्कीड रेंज का निर्माण कराया गया है। उक्त के दृष्टिगत शूटिंग रेंज के विकास अनुरक्षण एवं संचालन पी0पी0पी0 माडल पर कराये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा नगर निगम, लखनऊ को सहमति प्रदान की जा चुकी है। उक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना नगर निगम सदन के निर्णय सहमति पर निर्भर है।

वर्तमान में शूटिंग रेंज पुलिस बल, ए0टी0एस0 सिक्योरिटी सर्विसेज को फायरिंग अभ्यास हेतु आवंटन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में घटित घटना के दृष्टिगत सजायाफ्ता के पैरोल पर बाहर अभियुक्तों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सन्दीप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी हमारे यहां जनपद प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना घटी और उस घटना में जिन लोगों का नाम सामने आया है, चूँकि हम लोग उसी जनपद से चलकर आते हैं जिस विधान सभा से मैं चुनाव जीतकर आया जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा और जीता वह लोग सजायाफ्ता हैं आज वह पैरोल पर बाहर हैं लेकिन जिन लोगों का इसमें लगातार नाम आ रहा है, अभी कल वहां के पेपर में भी छपा है और कई दिनों से लगातार मीडिया में छप रहा है। उन लोगों की हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले लोगों के साथ लगातार फोटो वायरल हो रही है, उनके निजी सम्बन्ध बतायें जा रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनका हमारे क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों में लगातार योगदान रहता है, वह हमारे क्षेत्र में अक्सर देखे जाते हैं। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता था कि हमको सुरक्षा की दृष्टि से।

श्री अध्यक्ष-

आप हमें अलग से पूरा विषय लिखकर दे दीजिए वह सरकार को निर्णय करना है। आप पूरा विषय लिखकर दे दीजिए मैं सरकार के पास भेज दूँगा। मैं इसके लिए आपको यहां पर आश्वस्त नहीं कर सकता हूँ। आपने जो कहा हैं मैंने उसका संज्ञान ले लिया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्य के द्वारा बीच में टीका-टिप्पणी करने पर)

मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ विषय आया है इसलिए उस पर सरकार का संज्ञान दे रहा हूँ। इस पर मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ। अरे आप तो सरकार में हैं जाकर मिल लीजिएगा। आप बैठिए, हर बारे में हर व्यक्ति का बोलना आवश्यक नहीं है।

नियम-301, नियम-51 की सूचना को लॉटरी के माध्यम से लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

***श्री कमाल अख्तर-**

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न था हम यहां पर 403 विधायक हैं और निश्चित तौर पर जो आपने व्यवस्थायें की हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि हर चीज में आपने बहुत अच्छी तरह से सुधार किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सब यहां पर अपनी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि नियम-301, नियम-51 की जो सूचनायें है वह इतनी अधिक आ जाती हैं जिससे सभी लोगों की सूचनायें लग नहीं पाती हैं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए रोज यह सूचनायें लगाते हैं लेकिन लग नहीं पाती हैं। एक तो मेरा अनुरोध है कि इनकी संख्या बढ़ा दी जाय। इसके अलावा मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की सारी सूचनायें रोज आ जाती हैं। इसे अगर आप लॉटरी के माध्यम से पार्लियामेंट की तरह कर देंगे तो बड़ी कृपा हो जायेगी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बात तो नियम-300 में आनी नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, नियम-300 में नहीं है किसी भी नियम में नहीं है। उन्होंने खड़े होकर बोला है मैंने उनको सुना नहीं है। आपने सुन लिया मंत्री जी (सदन में हंसी) मा0 मंत्री जी अभी नियम-300 लिया नहीं है।

[12:22] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 की कुल 78 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार जी आपकी सूचना इसके पहले कब ली गयी थी ?

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, इसके पहले नहीं ली गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना पहली बार आई है। कमाल अख्तर साहब इनकी सूचना पहली बार आई है और आप कह रहे हैं कि बार-बार इनकी सूचना ली जाती है। श्रीमती पिंकी यादव यह भी उपस्थित है और इनकी भी फर्स्ट टाइम ली गयी है। श्रीमती सरिता भदौरिया, इनकी भी फर्स्ट टाइम ली गयी है। जिन सदस्यों की सूचनाएं न आई हों और मैं जिस समय बैठता हूं मेरा प्रयास होता है कि जिनकी सूचना फर्स्ट टाइम आई हैं पहले उनकी सूचना ले लें। फिर बाद में किसी की पुनरावृत्ति हो सकती है। एक हफ्ते में एक सूचना देने का ही नियम है।

जनपद सन्तकबीरनगर के जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय में तैनात वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[महोदय, सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद सन्त कबीरनगर में जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय पर तैनात वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा0 चन्द्रशेखर जो बिना अनुमति के लगातार जनपद मुख्यालय से बाहर रहते हैं, एवं अस्पताल पर सप्ताह में मात्र एक दिन आते है, और मरीजों के साथ अभद्र व्यहार करतें हैं एवं दवा के नाम पर धन उगाही का भी काम करते हैं। जिससे प्रदेश के अन्दर ये सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

विवेक सक्सेना पुत्र स्व0 अवध बिहारी शरण सक्सेना के भवन संख्या-5, शंकर दयाल नगर, अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात में स्थित भवन पर कैलाश मिश्र द्वारा पिछले कई वर्षों से किये गये अवैध कब्जे को हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

[महोदय, सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि विवेक सक्सेना पुत्र स्व0 अवध बिहारी शरण सक्सेना का भवन संख्या-5 शंकर दयाल नगर अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात में स्थित है जिस पर कैलाश मिश्रा ने कई वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ है। नगर पंचायत अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात के पारिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र संख्या-मेमो/एन0पी0ए0/2018-19, दिनांक 14-08-2019 में श्री विवेक सक्सेना पुत्र स्व0 अवध बिहारी शरण सक्सेना अंकित है।

श्री कैलाश मिश्रा द्वारा उसमें तोड़फोड़ कर निर्माण कार्य भी कराया गया है अपने नाम बिजली कनेक्शन भी ले लिया है। विवेक सक्सेना द्वारा जब भी मकान खाली करने के लिए कहा जाता है तो डराते, धमकाते हैं तथा दबंगई करते हैं और जान-माल की धमकी देते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद इटावा के तहसील इटावा के ग्राम लोहिया खुर्द, पोस्ट-खेडाहेलू, विकास खण्ड बसरेहर में प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरिता भदौरिया-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-इटावा विधान सभा क्षेत्र इटावा, तहसील-इटावा के अन्तर्गत ग्राम लोहिया खुर्द पोस्ट खेडाहेलू, विकास खण्ड बसरेहर में प्राइमरी स्कूल का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यहां बच्चों को शिक्षा के लिए 03 किमी0 दूर पास के ग्राम बहादुरपुर लोहिया में जाना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के एवं जनहित के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

जनपद चंदौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत स्थित पपौरा, अमलाई, प्रभुपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद चन्दौली के अन्तर्गत पपौरा, अमलाई-प्रभुपुर मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 6-7 किमी0 है जो लगभग 8 साल पूर्व उक्त सम्पर्क मार्ग का कार्य किया गया था। वर्तमान समय में उक्त सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुका है। आम जनमानस को आने-जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है किसान हेतु जनहित में उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शरीफपुर तथा बांसखेड़ा का थाना स्थानान्तरित कर शमशाबाद, जनपद फर्रुखाबाद किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सुरभी-

[महोदय, जनहित एवं लोकमहत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कायमगंज में ग्राम पंचायत शरीफपुर छिछनी, गुटैटी दक्षिण, भगवानपुर वसोला तथा बांसखेड़ा इन ग्राम पंचायतों का राजस्वकार एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र तथा संसदीय क्षेत्र कायमगंज, फर्रुखाबाद में आता है लेकिन इनका थाना क्षेत्र मिर्जापुर एवं कलान जनपद शाहजहांपुर है अतएव ग्राम पंचायत शरीफपुर छिछनी, गुटैटी दक्षिण, भगवानपुर वसोला तथा बांसखेड़ा इन ग्राम पंचायतों का थाना क्षेत्र मिर्जापुर एवं कलान, जनपद शाहजहांपुर से स्थानान्तरित कर शमसाबाद, जनपद फर्रुखाबाद समृद्ध कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शरीफपुर छिछनी, गुटैटी दक्षिण, भगवानपुर वसोला तथा बांसखेड़ा का थाना क्षेत्र स्थानान्तरित कर शमशाबाद, जनपद फर्रुखाबाद समृद्ध किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खण्ड मुजफ्फराबाद के ग्राम भैंसराव में गत कई वर्षों से निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेज का कार्य पूरा कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमर अली खान-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विकास खंड मुजफ्फराबाद के ग्राम भैंसराव में गत कई वर्षों से निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण करा कर सुचारु रूप के दिलाने के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उक्त ग्राम में पिछले कई वर्षों से एक राजकीय इंटर कॉलेज निर्माणाधीन है जिसका निर्माण कार्य अधूरा है तथा स्थानीय छात्र-छात्राओं को इंटर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है जिससे स्थानीय छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः समस्या का निराकरण नियम-301 के माध्यम से कराना चाहता हूँ।]

जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ज्ञान सरोवर के सौन्दर्यीकरण व सीढ़ी की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपुल दुबे-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर नगर में स्थित ज्ञानसरोवर के सौन्दर्यीकरण व सीढ़ी की मरम्मत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है यह सरोवर अति प्राचीन है तथा कई धार्मिक तिथियों पर यहां मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों भक्तगण आते हैं। नगर के बीच में सरोवर होने के कारण प्रायः लोग इसके आस-पास विश्राम भी करते हैं। सरोवर का सौन्दर्यीकरण और सीढ़ियों की मरम्मत नहीं होने से यहां दुर्घटना भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होती रहती है। यदि पर्यटन विभाग का इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी मिल जाए तो यह जनपद वासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय होगा।

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र अमरोहा के सदर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा के खादर क्षेत्र में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण खादर क्षेत्र के गरीब एवं निर्बल तथा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। काफी समय से इस खादर क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्र की जनता में निराशा एवं आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के खागा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किशनपुर नगर पंचायत से पहाड़पुर ग्राम तक सड़क का चौड़ीकरण कराने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के 243 खागा विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग यमुना नदी के तट पर स्थित है जहां पर मौरंग-बालू एवं मत्स्य आखेट के अनेकों भण्डार हैं जिससे सरकार को प्रतिवर्ष अरबों रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है लेकिन समुचित चौड़े मार्ग न होने से वाहनों के आवागमन सुगम न होने के कारण राजस्व वृद्धि में बाधक है। साथ ही मार्ग कम चौड़े व गड्ढेयुक्त होने से हमेशा जाम व दुर्घटनाओं से क्षेत्र में जनाक्रोश व्याप्त रहता है। इसके समाधान हेतु किशनपुर नगर पंचायत से पहाड़पुर ग्राम तक 7 मीटर चौड़ी व 01 फुट थिकनेस सी0सी0 रोड का नव निर्माण व मौरंग खदान मार्गों का उपरोक्तानुसार पुनर्निर्माण आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुय कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत नियामताबाद ब्लाक के ग्राम सभा कुंडलियों में मिनी स्टेडियम बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश जायसवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में बहुत दिनों से जिले के खिलाड़ियों द्वारा 'मिनी स्टेडियम' की मांग की जा रही है। शासन के मंशा के अनुरूप

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय मुख्य मंत्री जी भी प्रत्येक गाँव में खेल मैदान की स्थापना पर जोर दे रहे हैं। हमें भी खिलाड़ियों की भावनाओं का ख्याल रखना है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मेरे विधान सभा क्षेत्र नियामताबाद ब्लाक के ग्राम सभा कुण्डलियों में नजूल की पाँच बिघा जमीन उपलब्ध है अगर जिला प्रशासन उस जमीन की राजस्व विभाग से सर्वे कराकर जमीन उपलब्ध करा दें, तो चन्दौली जनपद के खिलाड़ियों की 'मिनी स्टेडियम' की मांग पूर्ण हो सकती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के जलालपुर में दर्ज मुकदमा के अन्तर्गत कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ कि ब्लाक प्रमुख के चुनाव के समय मेरे बेटे एवं भतीजे का अपहरण करके जान से मारने की नीयत से बर्बरता पूर्वक मारा-पीटा गया था। जिसमें थाना जलालपुर जिला जौनपुर में उपरोक्त धाराओं में मुकादमा दर्ज है। क्षेत्राधिकारी केराकत द्वारा जाँच करके सभी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

कई बार गैर जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है और न ही माल बरामद किया जा रहा है। सभी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए तथा माल बरामद कराया जाए।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सदन में वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

जनपद बाँदा के नरैनी विधान सभा क्षेत्र में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ओममणि वर्मा-

[महोदय, मैं, आपके माध्यम से जनपद-बांदा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-234, नरैनी में सबसे प्राचीन तहसील नरैनी जो वर्ष 1915 से संचालित हैं जिसमें 187 राजस्व ग्राम सम्बद्ध हैं, तहसील नरैनी के अधिकांश राजस्व ग्रामों से जिला मुख्यालय की दूरी 50-60 किमी0 है, जिससे वादियों को समय से पहुंचने में परेशानी होती है। विगत कई वर्षों से तहसील मुख्यालय नरैनी में मुंसिफ न्यायालय सृजित किये जाने की मांग स्थानीय निवासियों व अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही है। विगत वर्ष मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तहसील मुख्यालय नरैनी में मुंसिफ कोर्ट बनाये जाने हेतु स्थलीय निरीक्षण करके वित्तीय व अन्य स्वीकृतियां किये जाने हेतु शासन स्तर पर रिपोर्ट प्रेषित की गयी है, किन्तु अभी तक इस पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोई प्रगति नहीं हुई। लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार कृत संकल्पित है। तहसील मुख्यालय नरैनी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराया जाना जनहित में अविलम्ब आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए तहसील नरैनी जनपद बांदा में मुंसिफ न्यायालय स्वीकृत किये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम में बालागंज के आजाद नगर सी ब्लाक में स्थित नलकूप सही कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरमान खान-

[महोदय, अवगत कराना है कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के बालांगज के आजाद नगर सी-ब्लॉक में स्थित नलकूप पिछले कई महीनों से खराब होने के कारण सम्बद्ध क्षेत्र में जलापूर्ति अनियमित होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नलकूप को यथाशीघ्र ठीक कराकर जलापूर्ति को नियमित किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर करन में कतिपय ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव द्वारा की जा रही अनियमितता तथा 06 वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी स्थानान्तरण न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[महोदय, मैं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि कार्मिक अनुभाग-4 के समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरांत पटल/क्षेत्र परिवर्तन किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैंतालिस-4-2022- (1/3/96), दिनांक 13 मई, 2022 में उल्लिखित उपबन्धों के विरुद्ध जनपद उन्नाव में वर्तमान में कुछ ग्राम पंचायत सचिव 6 से 7 वर्षों से ब्लाक सिकन्दरपुर करन में तैनात हैं। जिनमें श्री शिवदत्त तिवारी 2017-2023 (2017 से 2020 व 2020 में निलम्बित होने के बाद बिछिया ब्लाक 2 माह की कार्यावधि के पश्चात् 2020 में पुनः सिकन्दरपुर करन ब्लाक में कार्यरत हो गये), श्री चन्द्रकान्त अवस्थी 2016-2023 (2016 से 2020 तक जबकि वे 2020 में निलम्बित होने के बाद बिछिया ब्लाक 2 माह की कार्यावधि के पश्चात् 2020 में पुनः सिकन्दरपुर करन ब्लाक में कार्यरत हो गये), श्री प्रताप नारायण द्विवेदी (1998 से 2023 जबकि 2021 में स्थानान्तरण बीघापुर ब्लाक में होने के बाद 2 माह के पश्चात् पुनः सिकन्दरपुर करन ब्लाक में कार्यरत हो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गये थे। जिनका स्थानान्तरण नीति के अनुसार नहीं किया जा रहा है। कई वर्षों से एक ही ब्लाक में तैनात होने से इनकी मनमानी चल रही है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं में भारी अनिमिततायें की जा रही हैं और सरकार द्वारा लाभकारी योजनाओ का लाभ सही रूप से जमीनी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। कई बार शासन में एवं विधान सभा की नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत सूचना देने पर जिले से इन भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव करते हुए सूचना का गलत जबाब आला अधिकारियों कि तरफ से दिया जाता है। जनहित में उक्त ब्लाक में कई वर्षों से तैनात ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानान्तरण जनपद के किसी अन्य ब्लाक में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः उक्त प्रकरण पर सदन से कार्यवाही कर ग्राम पंचायत सचिवों को जनपद के किसी अन्य ब्लाक में स्थानान्तरण करने का कष्ट करें।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनिया में माहे पासी किला को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने तथा इसका विकास कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां में माहे पासी किला स्थापित है, लगान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई माहे पासी ने लड़ने का काम किया था, हर वर्ष जनपद रायबरेली, कौशाम्बी, इलाहाबाद, अमेठी आदि क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु माहे पासी किले पर आते हैं, लोगों के आस्था का जहां केन्द्र है वहीं लगान आन्दोलन व अन्य कई आन्दोलनों के अगुवा रहे, यह सांस्कृतिक, दार्शनिक व ऐतिहासिक केन्द्र है। इसे पर्यटक स्थल में चयनित कर विकास कार्य कराया जाना आवश्यक होगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 में वक्तव्य स्वीकार करने की कृपा करें।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत ग्राम बिलौआ से कल्यानपुर मार्ग पर गोहनिया नदी पर पुल का निर्माण कराने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर, जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम बिलौआ से कल्यानपुर मार्ग पर गोहनिया नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इस पुल से 01 दर्जन गाँवों के लोगों का आवागमन सुगम हो जायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नगरीय क्षेत्र में 24 मीटर सड़क पर व्यावसायिक भूमि बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, नगरीय आवासीय क्षेत्र में चौबीस मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर व्यवसायिक भू-उपयोग सम्बन्धित आदेश का पालन किया जाना था। आवास विभाग में कार्यवाही लम्बित थी। इस पर क्या कार्यवाही हुई, इसकी सूचना नहीं है। भू-उपयोग बदलने वाले इस कार्यवाही के लम्बित होने से सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विकास खण्ड गौर को नई तहसील घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कविन्द्र चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के विकास खण्ड गौर को नयी तहसील बनवाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इस विकास खण्ड में कुल 1535 राजस्व गाँव हैं। जनता की समस्याओं का तुरन्त निस्तारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं हो पाता है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद कन्नौज के छिबरामऊ नगर के बिजली विभाग में संविदा एवं ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बिजली की शिकायत करने पर बिना पैसे लिए उनकी समस्या का निराकरण नहीं करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम खिलाड़ी सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद कन्नौज के छिबरामऊ नगर के बिजली विभाग में जो प्राइवेट ठेकेदार के कर्मचारी हैं वह लोकल के ही हैं, इसलिए वह लोंगो से अवैध धन वसूली करते हैं और

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर्मचारियों से मिलकर फर्जी तरीके से पैसे वसूलते हैं। वह आये दिन लोगों द्वारा बिजली की शिकायत करने पर बिना पैसे के उनकी समस्या का निराकरण नहीं करते हैं। इसलिए लोकल के लोगों के हटाकर दूसरे जनपदों के लोगों को उनकी जगह नियुक्त किया जाय।

अतः जनपद कन्नौज के छिबरामऊ नगर के बिजली विभाग में संविदा एवं ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बिजली की शिकायत करने पर बिना पैसे के उनकी समस्या का निराकरण नहीं करने की जांच कराये जाने हेतु मांग करता हूँ।]

समस्त कार्मिकों को एन0 आर0 एल0 एम0 एच0 आर0 पॉलिसी में अनुमन्य सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि प्रदेश में 12वीं एवं 18वीं शासकीय निकाय बैठक में एन0आर0एल0एम0एच0आर0 पॉलिसी में अनुमन्य सुविधाओं को प्रदान किया जाए, जिसमें मुख्यतः समस्त कार्मिकों को एच0आर0 पॉलिसी के तहत 07 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा, कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता, लैपटाप भत्ता, मोबाइल भत्ता एवं सेल्फ लर्निंग भत्ता दिया जाए।

2-समस्त एन0आर0एल0एम0 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग समाप्त कर उनको विनियमितीकरण (विभागीय संविदा) किया जाय। जिससे आउटसोर्सिंग कम्पनियों को सुविधा शुल्क के नाम पर दिये जा रहे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की बचत कर राजकोषीय घाटा की प्रतिपूर्ति की जा सके।

3-कर्मचारियों को उनके मूल निवास के नजदीक तैनाती किये जाने हेतु ट्रान्सफर पॉलिसी तैयार किया जाय।

4-सभी कर्मचारियों को उनके बेहतर भविष्य के लिए ई0पी0एफ0 की सुविधा प्रदान की जाय।

उपरोक्त सभी सुविधाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का अन्य प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार आदि में दिया जा रहा है, उ0प्र0 में अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए एन0आर0एल0एम0 के कर्मचारियों की समस्या के निस्तारण हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[12:25] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुईं। एक सूचना पर श्री कमाल अख्तर साहब ने अभी बिना सूचना के बोला था, क्योंकि यह विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 1958 प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आती है, उसकी चर्चा विधान सभा में नहीं हो सकती, इसलिए अग्राह्य की जाती है। दूसरी श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की है यह भी नहीं सुनी जायेगी। दोनों अग्राह्य की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक 2023†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को पारित किया गया तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किये जाने के पश्चात् दिनांक 27 फरवरी, 2023 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 फरवरी, 2023 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 फरवरी, 2023 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-04 में कुछ नहीं है। अब मद सं-05।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सभापति प्रतिनिहित विधायन समिति, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2022-2023) का प्रथम

---

† छापा नहीं गया।

प्रतिवेदन, जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग (राज्य कर विभाग) से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, मैं सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

[12:27] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर सुना जायेगा। श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सचिन यादव, श्री पंकज पटेल, श्री हिमांशु, श्री रविदास महरोत्रा। एक कोई भी माननीय सदस्य बोल लें।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जबसे यह सरकार आयी है वर्ष 2017 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं करायी हैं उनमें से 85 प्रतिशत परीक्षाएं या तो निरस्त हुई हैं या पेपर लीक हुआ हैं इसलिए कोई भी परीक्षा पूर्ण नहीं हो पायी है। उसी सन्दर्भ में मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से दरोगा की भर्ती प्रक्रिया चालू की गयी और उसमें ऐसी एजेंसी को परीक्षा कराने के लिए दे दिया गया जिसको उत्तरांचल व मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट द्वारा इस एजेंसी पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और कोई भी नियुक्ति की प्रक्रिया इस एजेंसी द्वारा न की जाए। इस एजेंसी द्वारा दरोगा की भर्ती कराने की प्रक्रिया की गयी और उसमें लखनऊ, आगरा और कई जगह एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है और इसमें एक सज्जन ने तो यहां तक कहा है कि ये मेरे बोर्ड से परीक्षा देकर मेरी कोचिंग में पास हुआ है अंकित भाटी और जिसमें 3500 छात्र दरोगा बने हैं। उसमें ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं कि 2 मिनट में और 4 मिनट 32 सेकेण्ड में 40 प्रश्नों में 29 प्रश्नों के सही उत्तर पाये हैं और वह गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं फलां व्यक्ति को 15 लाख रुपये चेक के माध्यम से व व्यक्तिगत माध्यम से दिये हैं। यही नहीं आगरा में अजय चौहान का 15 लाख रुपया पकड़ा भी गया है और इसके बाद कल जो बात हो रही थी, तो आपने कहा कि यह वर्ष 2020-21 की हैं लेकिन नियुक्ति-पत्र परसों से देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी बिलिंग हुई कि 59 सेकेण्ड में 60 प्रश्न हो गये हों यह पूरा का पूरा पहले बता दिया जाता तो यह नियुक्ति-पत्र आंवटन ही नहीं किया जाता। इसमें हमारी जो बात है मैं इसमें बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बग्लिंग होने के बाद भी इसमें 70 लोग गिरफ्तार हुए और यह

हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसके बाद भी जल्दबाजी में बिना जाने, बिना कुछ सत्यापन कराये नियुक्ति-पत्र दिये जा रहे हैं। यह कहीं न कहीं से अपने आप में अवैध हैं इसका कोई औचित्य नहीं बनता है और ऐसे समय में अध्यक्ष जी आपसे जरूर कहूंगा कि जो आपने कल कहा है कि मैं ध्यान आकर्षण कर रहा हूं यह बहुत ही गम्भीर सवाल है मान्यवर यह 3500 दरोगा बनकर जायेंगे तो उनसे कौन से न्याय की अपेक्षा करेंगे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार वह भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो तो क्या न्याय की उम्मीद इनसे जनता करेगी। मान्यवर, इस पर कड़ा विचार किया जाए इसमें एक-दो नहीं हैं इसमें 4 मिनट में 48 प्रश्न हल किये गये हैं जिनके ऐसे हल किये गये हैं वह सब पास हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस भंयकर भ्रष्टाचार पर और इन दरोगा की भर्ती को अवैध घोषित करवाने व इनको रुकवाने व पुनः परीक्षा कराने का काम करें तभी यह समझ में आयेगा कि यह सरकार निष्पक्ष होकर भर्ती कराना चाह रही है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इनती बड़ी भर्ती का टेंडर देना भ्रष्टाचार की सरकार की पोल खोलता है। जिसे उत्तरांचल और मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इस कंपनी से परीक्षा नहीं करायी जा सकती है और उत्तरांचल में विपक्ष के नेता ने बैठ कर इस एजेंसी के खिलाफ आमरण अनशन किया और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस एजेंसी से आप परीक्षा न करायें और दोषी पाये जाने के कारण मध्य प्रदेश व उत्तरांचल ने इस कंपनी को बैन कर रखा है।

श्री ओम प्रकाश-

यही नहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस एजेन्सी से आप परीक्षा न करायें इसके बाद भी इस एजेन्सी को परीक्षा कराने का काम दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की मिलीभगत के बिना यह हेराफेरी हो ही नहीं सकती थी। जब देश और प्रदेश में बहुत सारी परीक्षा एजेन्सियाँ हैं तो फिर इस प्रकार की दागी एजेन्सी से परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं बनता था। दागी परीक्षा से सफल किए गए चयनित अभ्यर्थियों को परसों नियुक्ति-पत्र भी बांट दिये गये हैं। कल इसीलिये मैंने इस विषय को उठाया था कि किसी तरह से इसको तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाये, लेकिन कल हमें नहीं सुना गया। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि स्वतंत्र एजेन्सी की जांच में बड़े पैमाने पर परीक्षा में धांधली पाई गई है इसलिये पूरी परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नियुक्तियों को तत्काल रोका जाये और दोषियों को दण्डित किया जाये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम प्रकाश जी ने जो बात यहाँ पर कही है मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। इन्होंने जो बातें कही हैं वह दरोगा सही है। दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को आनलाइन दरोगा भर्ती की परीक्षा कराई गई। हाई कोर्ट ने जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था उसको परीक्षा कराने का काम दिया गया। इस भर्ती में जिन

अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में हुई धांधली के कारण उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर मामले पर दो घण्टे की चर्चा कराई जाये।

श्री सचिन यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आनलाइन परीक्षा हुई है उसमें स्क्रीन शेयरिंग से नकल पाई गई है और इसका कई एफ0आई0आर0 में उल्लेख भी है। एक डी0एल0सी0 साफ्टवेयर होता है उसकी मदद से एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर लागिन करके यह फर्जीवाड़ा किया गया है। इसको पुलिस ने पकड़ा है। हमारा कहना यह है कि जो कैण्डीडेट आनलाइन एक्जाम देता है तो उसका वैकेण्ट में कैण्डीडेट रिस्पान्स लॉग दर्ज होता है कि उसने पूरी परीक्षा को साल्व करने में कितना टाइम लिया और हरेक प्रश्न को साल्व करने में कितना टाइम लिया है। हम लोगों अथवा पब्लिक ने जो प्रूफ इकट्ठे किए उस पर तो पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज कर ली, लेकिन इसमें गड़बड़ी इससे कहीं ज्यादा है। सात लाख लोगों ने इसमें एक्जाम दिया जिसमें से नौ हजार से ज्यादा लोग सलेक्ट हुये हैं। इसमें जो 9534 लोग सलेक्ट हुये हैं उनका कैण्डीडेट रिस्पान्स लॉग देख लिया जाये तो पता चल जायेगा कि 70 लोगों में कितने लोग ऐसे है जिन्होंने बहुत कम समय में क्वेश्चन्स को साल्व किया है। यह बहुत गम्भीर विषय है और यह लोग दरोगा बनने जा रहे हैं जिन पर कानून-व्यवस्था को सम्भालने की जिम्मेदारी होगी। मेरा अनुरोध है कि इस परीक्षा में सफल हुये सभी अभ्यर्थियों के कैण्डीडेट रिस्पान्स लॉग की जाँच कराकर पता किया जाये कि ऐसे कौन-कौन अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नकल करके परीक्षा को पास किया है।

*** संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओम प्रकाश जी और दो अन्य माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाया है उसमें कही गई एक-एक बात के बारे में मैं जवाब दूँगा। मान्यवर, एजेन्सी के चयन की जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से पालन किया गया। वर्ष 2020-2021 में आनलाइन लिखित परीक्षा भारत सरकार के उपक्रम नेशनल स्टाक एक्सचेंज के सहयोगी संगठन एन0एस0ई0आई0टी0 द्वारा सम्पन्न कराई गई है। यह संस्था ब्लैक लिस्टेड नहीं है जिस वक्त इसका चयन किया गया। पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही इसका तीन बार टेण्डर हुआ, इसमें तीन बार टेण्डर हुआ और तीन बार टेण्डर होने के बाद दो कम्पनियों ने एप्लाई किया और न्यूनतम आधार पर इनका चयन किया गया। इसमें पूरी प्रकिया का पालन किया गया। जब इस कम्पनी का चयन किया गया तब यह कम्पनी ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। मान्यवर, यह बड़ी संस्था है। इसमें ऑनलाइन परीक्षा करायी गयी। परीक्षा में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। यह परीक्षा 18 दिनों में 54 पालियों में आयोजित की गयी थी। प्रत्येक स्तर पर उपर्युक्त अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने हेतु बायोमेट्रिक मैचिंग का प्रयोग भी किया गया। मान्यवर, जितनी सावधानी बरतने की आवश्यकता थी उसका पूरा पालन किया गया। इसके बाद जो आप बता रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण से अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले 350 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया जिसमें 161 अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा के अगले चरण में अनुपस्थित होने पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो गये। चयन प्रक्रिया में 189 अभ्यर्थियों को डिलिस्ट किया गया। 169 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया। मान्यवर, इसमें 169 एफ0आई0आर0 हुयीं, उनको जेल भेजा गया। मान्यवर, अगर कहीं पर भी अनियमितता पायी गयी तो सरकार ने स्वयं कार्रवाई की है। आप मिली भगत की बात करते हैं। कम से कम एक जिम्मेदार सदस्य को इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बहरहाल सरकार ने इस मामले में पूरी सावधानी बरती है और 169 लोग जेल गये हैं जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने किसी प्रकार की गड़बड़ी की है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

इतने लोग जेल गये हैं तो इसका मतलब है कि परीक्षा में धांधली हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 रविदास जी आपको बोलने की इजाजत नहीं है। रविदास मेहरोत्रा जी का कुछ नहीं लिखा जायेगा। बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वैसे तो सामान्यतः एक ही लोग बोलते हैं, इसमें तो तीन लोग बोले। हमने तो बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। मान्यवर, जितने बिन्दु उठाये गये उन सबका मैंने जवाब दिया। एक बात और है कि इसमें जो लोग हाई कोर्ट गये थे हाई कोर्ट में जो रिटें दाखिल की गयी थीं मेरी सूचना के हिसाब से उन रिटों को डिसमिस किया जा चुका है। मान्यवर, 2017 के बाद से 22429 महिलाओं का चयन भी किया गया है। कुल मिलाकर जितनी सावधानी बरतनी थी उतनी सावधानी सरकार ने बरती है और हर तरह से इस बात की कोशिश की है हम पारदर्शी तरीके से लोगों को रोजगार दें। मान्यवर, एक सामान्य सा चयन चल गया है कि अगर हम किसी भी परीक्षा में सफल न हो पायें तो कहीं न कहीं परीक्षा वालों को किसी न किसी संस्था को जिम्मेदार ठहरा दें। तो जो लोग असफल हुये जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया अगर वह लोग किसी प्रकार की बात करते हैं तो उसको तो नजरअन्दाज किया जाना चाहिए। सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा करायी और पूरी सावधानी बरती गयी। एजेंसी के चयन से लेकर रिजल्ट आउट होने तक हर प्रकार से सावधानी बरती गयी। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि यह नियम-56 में नहीं आता है इसको अग्राह्य किया जाये। यह सरकार हर परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कराना चाहती है जो सही मायने में योग्य हों उसी का चयन हो और इसमें पूरी सावधानी बरती गयी है। मान्यवर, इसको अग्राह्य किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसमें मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और मा0 सदस्य को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है अतः इस सूचना को अग्रह्य करता हूँ। दो सूचनायें श्री प्रभु नारायण सिंह यादव इंजी0 सचिन, एक जानकारी दे दें। अगर कोई भी एक मा0 सदस्य दो सूचनाओं के ऊपर नियम-56 में हस्ताक्षर करता है तो दोनों सूचनाएं अग्राह्य हो जाती हैं। आगे से इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए और आपकी एक सूचना पर और हस्ताक्षर है। यह फर्स्ट टाइम गलती है उसको ठीक कर लीजिए। उसे ध्यानाकर्षण के लिए दे दिया है।

[12:45] वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्यय पर साधारण चर्चा†

श्री अध्यक्ष-

तीन बजे मा0 मुख्य मंत्री जी बजट भाषण की जनरल चर्चा पर जवाब देंगे। अभी से लेकर तीन बजे तक लगभग सवा दो घण्टे मेरा सभी विधान मण्डल दलों के नेताओं से एक निवेदन है कि जो मा0 सदस्यों की नाम की सूची भेजें फिर उसको चेंज न करें, क्योंकि सूची चेंज होने के बाद मा0 सदस्य शिकायत करते हैं कि हमारा नाम चेंज हो गया है। इसलिए जो भी फाइनल सूची भेजनी है उसको भेज दें, सूची के हिसाब से ही नाम बुलाया जायेगा, सूची के विपरीत किसी भी मा0 सदस्य का नाम नहीं बुलाया जायेगा। अगर किसी मा0 सदस्य को शिकायत है तो वह अपने मा0 मुख्य सचेतक एवं सचेतक से करेगा, पीठ के ऊपर आकर कोई भी मा0 सदस्य सवाल नहीं पूछेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों तरफ से मा0 सदस्यों की सूची आ जाए। मैं बुलाने का क्रम शुरू करता हूँ। अब मा0 सदस्य श्री मौहम्मद फहीम इरफान जी बोलेंगे।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर,

मुहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं,
मुखालिफ खुद हमारी गुफ्तगूं पर नाज करते हैं।
कहां से फितने उठते हैं कहां नफरत पनपती है,
समझ लेते हैं सब लेकिन नजर अन्दाज करते है।
किसी कमजर्फ की शोलाबयानी से नहीं डरना,
खाली होते जो बरतन बहुत आवाज करते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे राज्य सरकार के 2023-24 हेतु प्रस्तुत किए गए वार्षिक सामान्य बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया है सबसे पहले इसके लिए

---

† दिनांक 25 फरवरी, 2023 की कार्यवाही से।

आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद इस बजट पर नेता प्रतिपक्ष सहित समस्त विपक्षी मा0 सदस्यों द्वारा रखे जा रहे बयानों से स्वयं को संबद्ध करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का वर्तमान बजट जो अंको के हिसाब से 6.90 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन भाजपा सरकार के बड़े चुनावी वादों जिनके झांसे में फंसाकर उसने यह सरकार बनाई है उन वादों की जरूरत के सामने बहुत छोटा है। समय अभाव के कारण मैं यहां चंद अधूरे वादों का जिक्र करना चाहूँगा कि 25 हजार करोड़ की सरदार बल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की स्थापना इसमें नहीं है, 10 हजार करोड़ की लागत से शुरू होने वाली महर्षि सुश्रुत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना इसमें नहीं है, 5 हजार करोड़ की अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन योजना इसमें नहीं है। एक हजार करोड़ की नंद बाबा मिशन योजना इसमें नहीं है, पांच सौ करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम में चयनित महिला एथलीटों को पांच लाख की सहायता इसमें नहीं है, पांच सौ करोड़ की लागत से विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के तहत हर ब्लाक में एक आई0टी0आई0 की स्थापना इसमें नहीं है, एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एच0एस0जी0 क्रेडिट कार्ड के जरिए एक लाख तक का ऋण देने की योजना इसमें नहीं है, संकल्प-पत्र में अंकित पहला वादा अगले 5 साल किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाना इसमें नहीं है। समाज के महत्वपूर्ण आधे हिस्से महिलाओं के लिए उल्लेखनीय किसी नई योजना की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, उच्च शिक्षा हासिल करने वाली मेधावी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत दी जाने वाली मुफ्त स्कूटी इसमें नहीं है, बुजुर्ग महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा के लिए इंतजार करना पड़ रहा है अभी इसमें इंतजार बरकरार है। संकल्प-पत्र के कुछ वादे सांकेतिक रूप मैं पूरा करके उनका बड़े रूप में प्रचार करने की कोशिश की गयी है, संकल्प पत्र में आलू टमाटर प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक हजार करोड़ रुपए से भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने का वादा था, परन्तु बजट में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं है। ज्यादातर योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट योजनाओं के स्वरूप के सापेक्ष ऊंट के मुह में जीरे जैसा है। अगर मैं इस बजट में किसान हित की बात करूं तो 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, युवाओं को शिक्षा व रोजगार देने, बीमारों को बेहतर इलाज सुविधा और महंगाई की मार से राहत दिलाने पर खामोशी या सन्नाटा है। संकल्प-पत्र में 13 लाख नलकूप उपभोक्ता किसानों को मुफ्त बिजली का वादा था, लेकिन 50 फीसद छूट बरकरार रखने का इरादा है। गन्ना किसानों के पुराने बकाया और नवीन खरीद गन्ना मूल्य का भुगतान न होने और खरीद मूल्य न बढ़ाने का आंकड़ों के मकड़जाल में छुपाया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं की घोषणाओं से परहेज किया गया है, पुरानी योजनाओं पर भी काम चलाऊ फोकस किया गया है। न तो राज्य कर्मचारियों के रुके भत्तों, कैशलेस योजना सहित किसी कल्याण की योजना का जिक्र बजट में है न ही स्वीकृत पदों के सापेक्ष लगभग आधे खाली पदों

पर कोई स्पष्ट नजरिया है। कुल मिलाकर इस बजट में डबल इंजन सरकार होने की भी कोई निशानी मौजूद नहीं है, क्योंकि यह बजट आम आदमी के लिए किसी तौर से खास कल्याणकारी नहीं है।

(इस समय 12 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ओम प्रकाश पीठासीन हुए)

बजट में सरकारी विभागों और सरकार समर्थित बड़े ठेकेदारों के बीच बंटवारा या उनका वारा न्यारा है, लेकिन जनता जनार्दन बदस्तूर बेफायदा और बेसहारा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब ये बजट गरीबों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बजट में कटौती से भरा है तब कैसे कह दूं कि ये बजट हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा है। बजट में वर्ष दर वर्ष जो राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जा रहा जिसके परिणामस्वरूप सरकार पर इतना ऋण हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में करीब 30 हजार रुपये आयेगा उसे कम करने का कोई तरीका बजट में नहीं सुझाया गया है। मैंने जो कुछ बयान किया उसके मुताबिक पहली नजर में प्रदेश सरकार का ये बजट गैर यकीनी और घिसा पिटा है, क्योंकि सरकार के बेहतर राजस्व वसूली अनुमानों पर टिका है। इस बजट में न तो किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा गया है, न ही इसमें स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, पानी, सड़कों, बेरोजगारों, मदरसा शिक्षकों तथा हटाये गये शिक्षा अनुदेशकों व एम्बुलेंस ड्राइवरों आदि के पुराने बकायों के भुगतान का कोई प्लान किया गया है। मान्यवर, सरकार का ये बजट मेरी विधान सभा क्षेत्र 30, बिलारी में ग्राम न्यायालय के शुरुआत की बात मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जमाने में मेरा वालिद-ए-मोहतरम विधायक जी ने इस ग्राम न्यायालय की जमीन भी चिन्हित करा दी थी लेकिन अभी तक ग्राम न्यायालय की शुरूआत नहीं हो पायी। कोटा की तर्ज पर कोचिंग सेंटर की स्थापना बिलारी विधान सभा क्षेत्र के बच्चे-बच्चियों के लिए होनी चाहिए। हमारे यहां खेल प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे बैडमिंटन का खेल हो, चाहे खो-खो हो, कबड्डी हो, उसके लिए खेल स्टेडियम नहीं है, इसलिए एक मिनी खेल स्टेडियम की स्थापना का प्रावधान किया जाना चाहिए। हाईटेंशन लाइन और बंच केबल का इंतजाम, हमारे यहां 28 ग्राम पंचायतें सम्भल जिले में पड़ती हैं, उन 28 ग्राम पंचायतों में कई गांवों में बिजली का इंतजाम नहीं किया गया है, मैं चाहता हूं कि उनकी हाईटेंशन लाइनें चेंज की जाएं और वहां पर ट्रांसफार्मर का इन्तजाम किया जाए।

मंडी समिति की स्थापना, वर्ष 2012 से 2016 तक मेरे वालिद साहब जब विधायक रहे तो बजट भी जारी हो गया, मंडी समिति की जमीन भी चिन्हित हो गयी, चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से उनकी तवज्जो चाहूंगा कि मंडी समिति की सारी की सारी जमीन भी चिन्हित है और मंडी के नाम से वह जमीन चली भी गयी है, लेकिन अब तक मंडी समिति का निर्माण नहीं हो सका है। मंदिर पोडाखेड़ा, दादा कर्म अली शाह की दरगाह, बेरनी का शिव मंदिर, तिसावां की दरगाह को पर्यटक स्थल घोषित कराकर उसमें फंड जारी

करने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बिलारी के अन्दर एक बड़ा मुद्दा सूत डिपो का है, हमारे यहां सहारनपुर ,बिलारी, महमूदपुर माफी हो, बहुत-सा बुनकर समाज रहता है उनके लिए सूत डिपो की व्यवस्था हो जाएगी तो बुनकर समाज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे यहां राजकीय डिग्री कॉलेज की बहुत जरूरत है, उसका भी कोई नहीं प्रावधान किया गया। मेरे वालिद-ए-मोहतरम हाजी इरफान साहब ने लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए सीलिंग की जमीन देने की बात कही, बहुत जमीन हमारे यहां मौजूद है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बिलारी, कुंदरकी और बनियाखेड़ा ब्लाक के लगभग 206 गांव श्मशान विहीन हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करिए।

श्री मौ0 फहीम इरफान-

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम उन गांवों में तो अन्त्येष्टि स्थल बना दिये जाएं, जहां पर हिंदू आबादी रहती है और मुस्लिमों के लिए भी कब्रिस्तान बना दिये जाएं। बिलारी नगर पालिका में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना किया जाना बहुत जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारियों के रहने के लिए कोई व्यवस्था इस समय बिलारी में नहीं है। हमारे सी0ओ0 साहब हों, एस0डी0एम0 साहब हो, कोतवाल साहब हों, आदि के लिए आवास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हमारा थाना बहुत बुरे हालात में टूटा हुआ है, उसे ठीक कराना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता-

इरफान जी, अब समाप्त करिए।

श्री मौ0 फहीम इरफान-

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा। पावरलूम बुनकरों की सब्सिडी, बहुत गहरा मुद्दा है। पिछली सरकार में उनको सब्सिडी दी जाती थी, आज सहसपुर, बिलारी और महमदपुर माफी के बुनकर बहुत परेशान हैं, उनकी सब्सिडी बहाल जरूर कर दी जाये। वे बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, लाखों रुपये के उनके बिल हैं, उनकी सब्सिडी बहाल कर दी जाए। अटल आवासीय योजना के आस-पास के गांव खासेपुर, पालनपुर, अहमदाबाद कसौरा, बरौली रूस्तमपुर, धमावली, अर्जुनपुर झरियाई, सेफपुर जगना में सड़कों का जाल बन जाना चाहिए, जो हमारे वालिद साहब की महत्वकांक्षी योजनाओं में थी और माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री थे, हमने बहुत जमीनें मुहैया कराई, आज मैं खुशनसीब हूं कि मेरी विधान सभा में एक अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। 100 से अधिक गांवों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए, जो पी0डब्ल्यू0डी0 का काम रहा है। उसे कराया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

श्री इरफान साहब, ये बहुत गलत बात है, अब आप समाप्त करिए, अभी बहुत से मा0 सदस्यों को बोलना है। श्री फतेह बहादुर सिंह जी आप बोलिए।

श्री मौ0 फहीम इरफान-

मान्यवर, बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं,

जिंदगी दी है तो जीने का हुनर देना,
पांव बख्शे हैं तो तौफी के शफर भी देना।
मैं तो गूंगा था, तूने बख्शी है जबां
मेरे मौला मेरी बातों में असर भी देना।।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री फतेह बहादुर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट के पक्ष में मुझे चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान किया। महोदय, 'उत्तर प्रदेश की यह यशस्वी सरकार, जिसके लिए जनता का भरोसा न टूटे, उस आस पर होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास पर होनी चाहिए' मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश की लगभग 24 करोड़ की आबादी है और वर्तमान जो बजट है, वह 06 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का है, जो अब तक का उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बजट है, जिसे हमारे वित्त मंत्री जी ले करके आए हैं। महोदय, अभी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुआ था और उसमें जो एमओयू साइन हुए हैं, 2023 की इन्वेस्टर्स समिट में, लगभग 35 लाख 50 हजार करोड़ के निवेश की सम्भावनाएँ उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। हमारे गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गीडा, वीडा, सीडा, ये तीन एथॉरिटीज हैं, जिनमें उद्योग विभाग के माध्यम से उद्योगों की स्थापना की जाती है। आज गीडा की स्थिति यह है कि वहाँ पर जमीन की कमी के कारण उद्योग अभी नहीं लग पा रहे हैं। जो नया पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बन रहा है, उसके कॉरीडोर में जमीन अधिग्रहीत करके पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारे की स्थापना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा दावा है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 30 वर्षों के कार्यकाल में हमने देखा है, सर्वाधिक मकान ग्रामीण अंचल में और शहरी अंचलों में भारतीय जनता पार्टी की देन है और वह आवास बन करके तैयार हो गये है इसी प्रकार से नए नगर पंचायतों के निर्माण की व्यवस्था हमारी वर्तमान सरकार ने किया है। ये बड़े-बड़े कार्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो चीनी मिलें रूग्ण पड़ी थीं, जिन पर किसी ने विचार नहीं किया, लोगों ने उन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया। उन चीनी मिलों को उच्च स्तर पर उनकी

पेराई क्षमता को बढ़ा करके उन्हें किसानों को समर्पित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। महोदय, आज जब हम चर्चा करते हैं, नेता विपक्ष ने कुछ कहा, मैंने उन्हें बड़े ध्यान से सुना। वास्तव में व्यक्तिगत चर्चाएँ राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम सीमाएँ पार कर जाते हैं, सदन की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, वहाँ हमको भी विचार करना चाहिए। अभी पिछले वित्तीय वर्ष में नेता विपक्ष ने जो कहा, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े पैमाने पर ग्रामीण स्टेडियमों की स्थापना की गयी। मेरे विधान सभा में महन्त अवैद्यनाथ ग्रामीण स्टेडियम बना करके पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र स्टेडियम गोरखपुर में बन करके तैयार है। मान्यवर, गन्ना विभाग के माध्यम से गन्ना किसानों के लिए सहज तौल बिक्री केन्द्र की स्थापना की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तीन चिड़िया घर हैं, एक आपका गोरखपुर में है, एक लखनऊ में है और एक कानपुर में है। मान्यवर, जो गोरखपुर का चिड़ियाघर बना, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने 1986 में उस चिड़ियाघर के लिए जमीन अधिग्रहीत की थी और उनके मरणोपरान्त बहुत सी सरकारें आयीं और चली गयीं, लेकिन ध्यान देने का काम हम लोगों ने किया। मान्यवर, 2011 में 18 मई को मेरे द्वारा मंत्री रहते हुए उसका शिलान्यास किया, सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी से उसकी परमीशन 02 साल में मिलती है, सेन्ट्रल जू एथॉरिटी से परमीशन 01 साल में मिलती है, सरकार का 04 साल का कार्यकाल बीत जाता है, चौथे साल हमने बजट आवंटित करके उस चिड़ियाघर का शुभारम्भ करा करके गोरखपुर की जनता को समर्पित करने का काम प्रारम्भ किया।

महोदय, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि उस चिड़ियाघर को मात्र 6 करोड़ पूर्व की सरकारों ने दिया है, आप बजट आवंटित करके जो फारमैलिटीज हैं, उनको पूरा करा करके इसका उद्घाटन करने का काम करें और मुख्य मंत्री जी ने उस कार्य को करा करके आज गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर सौंपने का काम किया है।

मान्यवर, रामगढ़ताल परियोजना की चर्चा आती है तो नेता विपक्ष कहते हैं कि हमने शिलान्यास किया, लेकिन उद्घाटन किसने किया सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कार्य प्रारम्भ करना कोई बड़ी बात नहीं है, कार्य को पूर्ण करना आवश्यक है। हम दो-दो, तीन-तीन बार सरकारों में रहें और उसके बाद कह दें कि हमने शिलान्यास किया और उद्घाटन कोई और करे तो उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है। मान्यवर, बहुत से विषय हैं और मैंने बहुत से लोगों को सुना आज उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कम हो गए हैं मैं मानता हूं इस बात को कि पूर्वांचल के बंटवारे और उत्तराखण्ड के बंटवारे के बाद हमारा वन क्षेत्र कम हो गया है, जबकि वनावरण और वृक्षावरण को हमें बढ़ाना चाहिए। मैं वर्तमान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा ठीक है उत्तरांचल बट गया, लेकिन हवाएं नहीं रुकी है। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल लगा हुआ राज्य है कोई ऐसा नहीं है कि हमारा क्षेत्र चला गया और एक राज्य बन गया। निश्चित रूप से वृक्षावरण पर हमको ध्यान देना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति हमें सचेत कराना होगा। मैं वन मंत्री जी से कहना

चाहूंगा कि यू0पी0 बायोडायवर्सिटी बोर्ड का गठन मेरे द्वारा किया गया है। बायोडायवर्सिटी बोर्ड और बायोडायवर्सिटी एक्ट का मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हम लोगों ने इसका गठन किया था, लेकिन मैंने इस बजट में अभी देखा कि उस पर कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं है जिससे पूरे प्रदेश के जनपदों में इस एक्ट के इस बोर्ड के अनुपालन को कराने में कोई विशेष कार्य हो। मेरा सुझाव है कि जब अनुपूरक बजट कभी आएगा तो उसमें प्रस्तावित करा करके उसे भी आगे बढ़ाने का काम हमारे साथी करेंगे। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सरकार के कार्यकाल में लगभग 21 हजार 6 सौ 96 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है और वहीं चौड़ीकरण में लगभग 18 हजार 407 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है।

हमारी बेचारगी का हाल कुछ इस कदर है कि,
तंज कस रहे हैं वह जो खुद शहर में बदनाम हैं।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का शुभ अवसर दिया है मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। यह सत्य है और सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट मा0 योगी जी की सरकार ने यहां प्रस्तुत किया है और मैं जब बजट की ओर देखता हूं तो हमारे विपक्ष ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बजट को वर्टिकली देखा है इसको क्रॉस सेक्शन में जाकर नहीं देखा इसको हॉरीजेन्टली देखा है। वह बजट के आंकड़ों से ज्यादा उन्होंने उसके पीछे छिपे भाव को, उस बजट की आत्मा को और बजट के सार को नहीं देखा। मैंने कई बार इस बजट को पढ़ा है और जब भी मैंने इस बजट को पढ़ा है तो मुझे इसके पीछे भगवान श्रीकृष्ण का मनोविज्ञान, जैमिनी ऋषि का दर्शन शास्त्र, आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, बिहारी बाजपेयी जी की संवेदना और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी अन्त्योदय दृष्टिगत होता है और मुझे लगता है कि मा0 योगी जी के नेतृत्व में यह सिर्फ एक बजट नहीं है, बल्कि उनकी अर्थनीति का एक नियामक ग्रंथ है। ऐसा लगता है कि एक परिवार के मुखिया ने सम्पन्नता के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी सन्तुष्टि के लिए और उसके समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए पूरा बजट बहुत सूझ-बूझ और दूरदर्शिता के साथ बनाया है।

यह सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है, सारे वर्गों की चिन्ता इस बजट में की गई है। हमारे युवाओं के कन्धों से आज देश विकसित होगा, समृद्ध होगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम युवाओं को आगे ले जाएँ। आज के समय के हिसाब से ताल से ताल और कदम से कदम मिलाकर वे चलें, वे अपडेटेड हों, इसके लिए हम युवाओं के लिए तमाम योजनाएँ लेकर आए

हैं। इसलिए इसमें हमने 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है स्मार्ट फोन और टैबलेट देने का । मान्यवर, यह जरूरी नहीं है कि हर युवा सरकारी नौकरी पा सके, इसलिए हम युवाओं के रोजगार के लिए स्टाट-अप को बढ़ावा देने जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएँ मा0 मोदी जी की सरकार ने चलाई हैं, बहुत सारी योजनाएँ हमारी योगी जी की सरकार ने चलाई हैं। युवाओं को हम मौका दे रहे हैं, एपॉरचुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाकर अपना स्टार्ट अप शुरू करो। इस प्रकार से हम अपने युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। किस प्रकार से हम उनको रोजगार दें, कैसे उनको संस्कार दें, कैसी उनकी शिक्षा हो, इस बात का बजट में पूरा चिन्तन किया गया है। महिलाएँ हम सभी जानते हैं कि अगर वे आज सुरक्षित हैं तो मा0 योगी जी की सरकार में सुरक्षित हैं, महिलाएँ जो परेशान रहा करती थीं, शाम को छः बजे के बाद निकलती नहीं थीं, आज वे महिलाएँ कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमारी सरकार में सुरक्षित हैं। हमने महिलाओं का भी बहुत चिन्तन किया है। हम बहुत सारी योजनाएँ उनके लिए लेकर आए हैं। खासतौर से जो निर्धन परिवार हैं, जिनको अपनी बच्चियों की शादी करने में दिक्कतें आती हैं, उनके लिए हम अपने बजट में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना लेकर आए हैं। हम मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना लेकर आए हैं। हम अपनी निराश्रित बहनों की मदद करना चाहते हैं, उनको सहायता देना चाहते हैं। हमारा पूरा महिला समाज, जो हमारी माताएँ और बहनें हैं, वे कैसे सुरक्षित रहें, कैसे सुव्यवस्थित रहें, इसके लिए उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से भी हम उनको लाभान्वित कर रहे हैं, 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने इस बजट में उनके लिए भी रखा है। जो हमारा अन्न दाता है, जो किसान है, जो सूरज की पहली किरण उगने से भी पहले खेत में चला जाता है और पानी लगाता है। जो लू में, तपती दुपहरी के थपेड़ों में परिश्रम से काम करता है, चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, चाहे कड़ाके की ठण्ड हो, लेकिन वह पूरे परिश्रम से वहाँ काम करता है तो उसको भी हमने नमन किया है, हमने विनम्रता से नमन करते हुए उसके लिए भी प्रावधान किया है।

किसानों की सिंचाई के साधन कैसे अच्छे हों, जो किसानों के निजी नलकूप हैं, उनमें हम निःशुल्क बिजली और रियायती दरों पर उपलब्ध कराने जा रहे हैं। मान्यवर, इसके लिए 1950 करोड़ रुपये की हमने बजट व्यवस्था की है। गन्ना किसानों के सम्बन्ध में हम पहले भी कहते आए हैं कि अगर सबसे ज्यादा चिन्ता किसी ने की है तो मा0 योगी जी की सरकार ने की है। एक लाख छियानबे हजार करोड़ रुपया हम गन्ना किसानों को दे चुके हैं। कैसे चीनी उद्योग विकसित हो, कैसे हमारी खेती-किसानी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मा0 योगी जी की सरकार को कि हमारी सरकार की जो नीतियाँ हमारी कृषि के क्षेत्र में रही हैं, आज यही कारण है कि कई उत्पादों में पूरे देश में अगर कोई नम्बर एक आ रहा है तो वह उत्तर प्रदेश आ रहा है। हमने किसानों की भी चिन्ता की, हमने कृषि की भी चिन्ता की, हमने गोवंश की भी चिन्ता की, हमने इसमें पशु पालन के

लिए भी प्रावधान किया है और हम मत्स्य पालन के लिए भी 257 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान हमने इसमें किया है। हम सारे वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, आज हमने कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में सुधारी है। किस प्रकार निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से, ईमानदारी से यहाँ पुलिस भर्तियाँ हुई हैं तो आज उनके आवास की भी आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ेगा, अगर उनको आवास मिलेगा। इसके लिए हम 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान लेकर आ रहे हैं। जो हमारा महिला पुलिस बल है, उस महिला पुलिस बल को हम मुख्य धारा में लाने के लिए तीन महिला पी0ए0सी0 बटालियन गठित करने जा रहे हैं। फोरेंसिक लैब लेकर आ रहे हैं, साइबर क्राइम कैसे रुके उसको लेकर आ रहे हैं। एक तरीके से जो पूरी गुण्डागर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, जो माफिया तंत्र पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, जिस प्रकार से माफियाओं की पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, आज वे मिट्टी में मिल रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश इसको देख रहा है। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि गर्मियाँ आने वाली हैं तो-

आम के पेड़ पर आते हुए बौर का स्वागत करें
माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, ये दौर योगी का है,
इस दौर का स्वागत करें।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आपका बहुत धन्यवाद। देख लीजिए आप 06 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, हम ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं और ऊर्जा में जो हमने अद्वितीय कार्य किया है पूरे उत्तर प्रदेश में तो इस बार हम उसे सौर ऊर्जा से भी सप्लीमेण्ट करने जा रहे हैं। मैं विपक्षियों को सुन रहा था। मैं अपने फर्रुखाबाद के बारे में एक बात कह दूँ मान्यवर, हमारे फर्रुखाबाद में एक उत्तर प्रदेश की दूसरी या तीसरी बड़ी नगर पालिका है। शासन से सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको स्मार्ट नगर पालिका के रूप में घोषित कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद मेजर साहब, मा0 सदस्य विनोद सरोज जी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

दूसरा मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारा एक विद्युतीकरण, केबिलीकरण का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है, वह भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पार्कों का निर्माण हो जाए और एक राम नगरिया मेला लगता है उसके लिए व्यवस्था और स्थल निर्माण हो जाए तो अच्छा रहेगा। मा0 अधिष्ठाता जी,

'किसी तूफान के डर से सफर अपना नहीं रुकता।
इरादा कर लिया तो फिर इरादा नहीं रुकता',. ...

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य विनोद सरोज जी, पाँच मिनट का समय है आप बोलिए। मेजर साहब, प्लीज मेजर साहब आप तो मेजर हैं आपको भी समझाना पड़ रहा है। अब आप समाप्त करें।

श्री विनोद सरोज-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों, बेरोजगारों और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। हमारे प्रदेश में पढ़े-लिखे डिग्रीधारक युवा घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगार युवा माता-पिता के ऊपर आज तक निर्भर हैं उनके माता-पिता ने बड़ी उम्मीद एवं विश्वास के साथ अपने बच्चों को पढ़ाया उसके बाद भी नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं तथा नौकरी भी नहीं मिल रही है। निश्चित रूप से इस सरकार में बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिये जाने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं की गयी है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। इस समय आप देख रहे हैं कि बिजली के जो अलग से थाने गठित किये गये हैं उसके कर्मचारी, अधिकारी गाँव में जाते हैं और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन लिए हुए हैं उनको भी परेशान किया जाता है। वह लोग अपनी बात करते हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं होते हैं। हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं तो क्षेत्र के लोग जो बिजली के कनेक्शन धारक हैं उनकी यह समस्या होती है कि गाँव के अन्दर जो जर्जर तार टूटा होता है। कभी-कभी विद्युत पोल भी तोड़ दिये जाते हैं उनको बनाने की बात वे करते हैं और उनके स्थान पर नये पोल लगाने की बात करते हैं तो बिजली विभाग के अधिकारी मना कर देते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हम सरकार से चाहते हैं कि जो कनेक्शन धारक उपभोक्ता हैं उनके विद्युत पोल बदले जायें और जो जर्जर तार की समस्या है उसको बदलने का काम करें।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं के सम्बन्ध में सभी मा0 सदस्यों ने जो सब अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उन सब लोगों ने अपनी-अपनी बात रखी, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे किसान चाहे वह ठण्डी का महीना हो या गर्मी हो किसान दिन रात अपने खेतों की तकवाही करते हैं लेकिन तकवाही करने के बाद भी आवारा पशु उनके खेतों की फसलों को चरने का काम करते हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार उन किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दे और उस ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से किसान अपने खेतों की बैरिकेटिंग करा सके और उसके माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें, यह मैं सरकार से चाहता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र बाबागंज प्रतापगढ़ में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा बिहार का निर्माण सन् 2007-2008 में शुरू हुआ था जिसकी आधी-अधूरी बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद सन् 2007 से मैं लगातार इस विधान सभा में हूँ और लगातार हर सरकार में बात करता रहा और अपनी माँग करता रहा लेकिन इस बिल्डिंग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यही नहीं बाद में कागज में पूरा दिखा दिया गया और इस बिल्डिंग को अभी भी पूरा नहीं किया गया और वह आधी-अधूरी बिल्डिंग आज तक पड़ी है। अभी दो साल पहले हमने यहाँ सत्र में अपनी बात उठायी थी तो सरकार ने इस पर अपना बजट भी अलॉट किया था, उसका टेण्डर भी किया गया लेकिन आज तक न तो उस अधूरी बिल्डिंग को बनाया गया और न तो उस पर कोई काम शुरू हुआ है। ये ही नहीं इस आई0टी0आई0 कालेज में जो एडमिशन होता है, वह जिला मुख्यालय में किया जाता है और हमारा क्षेत्र जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। हमारे क्षेत्र के बच्चों को एडमिशन कराने के लिए प्रतापगढ़ जाना पड़ता है और वहीं उसकी पढ़ाई होती है। हम सरकार से चाहते हैं कि आई0टी0आई0 जो आधा-अधूरा बना हुआ है उसको पूरा कराया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे इस संस्थान में पढ़ सकें और टैक्निकल शिक्षा ग्रहण कर सकें।

मा0 अध्यक्ष जी, सड़कों की बात की जाए तो हमारे सभी मा0 सदस्य इस चीज से दु:खी हैं और सब परेशान हैं कि ग्रामीण सड़कें वास्तव में काफी खराब हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र में संगरासुन्दरपुर, बाबूगंज, डेरवा गलगली मार्ग, परिवायाँ-लवाना मार्ग, ताजपुर लरू केसरी का पुरवा विदासिन मार्ग ऐसी कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो कि काफी खराब पड़ी हैं, मैंने कई बार विभागीय अधिकारियों को सूचना दी। पत्र भी लिखा लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी से चाहता हूं कि वह इन सड़कों का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण करायें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके। इसके अलावा माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी विधान सभा में सिंचाई के लिए किसानों के 02 रजवाहा महत्वपूर्ण है। एक मानिकपुर रजवाहा और दूसरा हीरागंज रजवाहा, जो कि काफी लम्बा है और हमारे विधान सभा क्षेत्र के बीचों-बीच से होकर जाता है। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार एक परियोजना बनाकर इस नहर का चौड़ीकरण करे ताकि हमारे किसान समय से पर्याप्त पानी पा सकें और अपने खेतों को सींच सकें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाय क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी पेंशन पर आश्रित रहते हैं और उसी पेंशन से उनका पूरा परिवार चलता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है वैसे ही पुरानी पेंशन यहां भी बहाल की जाय। हमारी विधान सभा क्षेत्र में बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, मैं सरकार से चाहता हूं कि एक स्टेडियम बनाया जाय ताकि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वह स्टेडियम में खेल सके।

***श्री राम सिंह-**

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2023-24 के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इस बजट भाषण को पढ़ने के बाद ''हुकूमत मुझे अशरफ मालवी की दो लाइनों का जिक्र करना आवश्यक प्रतीत होता है। हुकूमत से एजाज़ अगर चाहते हो अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है।'' जो युवा सालों-साल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे रहते थे, वर्ष 2023-24 के पूरे बजट भाषण में किसी भी विभाग में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिये गये हैं। प्रदेश सरकार 14 करोड़ गरीबों को राशन देने की बात लगातार कहती जा रही है, यानि सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि प्रदेश में 14 करोड़ आबादी जो एक बड़ी संख्या होती है, वह आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। उनके जीवन स्तर को बढ़ाने पर सरकार ने विचार किया है ? पिछले 05 साल की सरकार ने और वर्तमान सरकार ने अभी तक उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया है इसका भी जिक्र पूरे बजट भाषण में कहीं नहीं है। विश्व स्तर पर इस पैमाने को अगर देखा जाय तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक का एक आंकड़ा जारी किया जाता है जिसमें हम 191 देशों की सूची में 132वें पायदान पर खड़े हैं। यह डबल इंजन सरकार का पूरी तरह से नाकामी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक में हम 107वें पायदान पर खड़े हैं लेकिन हमारे सत्ता पक्ष के साथी इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं जबकि यह सोचनीय विषय है कि इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी गरीबी स्तर से नीचे जीवन यापन कर रही है तो आखिर कैसे हम वन ट्रिलियन इकनॉमी की बड़ी-बड़ी बातें किए जा रहे हैं। रोजगार तथा नौकरी के नाम पर सरकार के प्रयासों के लिए भी मुझे 02 लाइनें कहकर ही अपनी बात आगे बढ़ानी पड़ेगी ''नामुमकिन है कि कोई नतीजा निकले, एहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है।'' सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। सरकार को इस सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहिए कि वह निवेश कहां-कहां हुआ है और किस निवेश के माध्यम से कितने युवाओं को अब तक रोजगार प्राप्त हो चुका है। अभी हाल ही में इंवेस्टर्स समिट लखनऊ में आयोजित हुई, जहां बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गयी कि 33,50,000 करोड़ के इस बार एम0ओ0यू0 साईन हुए हैं। जब कि वास्तविकता यह है कि जो पिछला इन्वेस्टर्स समिट, 2018 में हुआ था। उसके नतीजे आज तक हम लोगों के पास नहीं हैं कि उद्योग कहाँ लगा है और कहाँ नहीं लगा है और कितने युवाओं को रोजगार मिला है। तो इस तरह सरकार केवल युवाओं को हवाई सपने दिखा रही है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सब लोग ग्रामीण अंचलों से आते हैं और हम लोग जानते है कि ग्रामीण सड़कों की हालत क्या है ? हम लोग जहाँ भी जाते हैं, निश्चित तौर पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर गाँव में पब्लिक द्वारा सड़कों के निर्माण की बात हम लोगों से की जाती है और हम लोगों के द्वारा जो पत्राचार होते भी हैं, उनका न कभी समुचित उत्तर मिलता है और न ही उन पर ध्यान दिया जाता है। मैं इस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य एक हमारी मूलभूत आवश्यकता है और वास्तविकता यह है कि हमारे जितने सी0एच0सी0 और पी0एच0सी0 बने हैं, वह सारे केवल रेफरल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ पर गरीबों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। हमारे जिला अस्पतालों में जो मूलभूत आवश्यकतायें और सुविधायें होनी चाहिए, कहीं न कहीं उसका अभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इन चीजों पर आप जरूर ध्यान देंगे। इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र की कुछ माँगे हैं, जिन्हें मैं बहुत संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। मान्यवर, मेरे वहाँ कुछ जरूरी सड़कें हैं, जो ग्रामीण अंचलों की है। एक सड़क, खानपुर बॉर्डर से लाला का पूरा (ग्राम-पीथापुर) होते हुए कोटिया बार्डर तक, दूसरी, उपाध्यायपुर नहर की पटरी से सपहाछात जूनियर हाई स्कूल तक, तीसरी, देवसरा बाजार से बिझला नहर के पुल तक है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, श्री राम सिंह जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम सिंह-

मान्यवर, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मण्डी का निर्माण कार्य पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ था, आदरणीय अखिलेश जी ने उसकी बाउंड्रीवाल का पैसा भी दे दिया था। लेकिन यह बड़े दुःख का विषय है कि पिछले पाँच वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वहाँ केवल बाउंड्रीवाल ही खड़ी है और उस मण्डी का निर्माण कार्य अभी तक चालू नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उस मण्डी का निर्माण कार्य जल्दी कराया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद। अब डा0 अमित सिंह चौहान जी बोलें।

श्री अमित सिंह चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले युग पुरुष जो अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, आम जनमानस, गाँव, गरीब, किसान, मजदूर युवाओं के हित की बात करने वाले जो अपना सर्वस्व अनजाने-अनदेखे लोगों को देने को तैयार रहते हैं, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। इस बार का बजट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट

6 लाख 90 हजार 2 सौ करोड़ 43 लाख का है, जो पिछली बार से करीब 75 हजार करोड़ अधिक है। मैं धन्यवाद देता हूँ, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को जो कहते हैं, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती और पार्टी से बड़ा देश होता है, ऐसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में भारत को जी-20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। उनको धन्यवाद देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स महाकुम्भ का आयोजन हुआ, जिसमें देश-विदेश से करीब 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेन्ट उत्तर प्रदेश को मिला। जो लोग पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार कहाँ हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसके सापेक्ष में 93 लाख नये रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 24 करोड़ लोगों के लिए निरन्तर बिना रुके, बिना थके आदरणीय योगी जी कार्य कर रहे हैं। मैं अपने विपक्ष के साथियों से बताना चाहता हूँ कि 'जहाँ आँख में होंगे पानी, जहाँ जुल्म के मौसम होंगे, बारूद लिए सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे।' 'बाजू भी बहुत हैं, आदरणीय योगी जी के लिए, सर भी बहुत हैं, आदरणीय योगी जी के लिए, कटने से ये कहाँ कम होंगे, कटने से ये कहाँ कम होंगे।' आज पूरा उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के साथ खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की नगरी से आता हूँ। हमारे जनपद में भी करीब 49 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसके सापेक्ष में करीब 56 हजार नये रोजगार अयोध्या को भी मिलने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। चाहे केन्द्र में इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे डेयरी डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हाउसिंग डिपार्टमेण्ट की बात करें, हेल्थ की बात करें, मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हर फील्ड में इंवेस्टमेंट मिलने जा रहा है।

(इस समय 01 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं)

मान्यवर, आज अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होने जा रहा है। हमारी सरकार ने अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। अयोध्या में सभी मार्गों का चौड़ीकरण/उच्चीकरण हो रहा है। इसके साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अयोध्या के सभी मार्गों पर भव्य द्वार का भी निर्माण प्रस्तावित है। जल्द ही अयोध्या नगरी चाहे, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वाटर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो हर क्षेत्र में अयोध्या का विकास हो रहा है। इसके पूर्व के मुख्य मंत्री कभी अयोध्या नहीं आना चाहते थे लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे पूज्य मुख्य मंत्री अयोध्या करीब 40 बार का दौरा कर चुके होंगे। आज योगी जी के आने से अयोध्या अपने त्रेता युग को याद कर रही है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर निरन्तर पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्य मंत्री आवास योजना हो, चाहे विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे हर घर जल की बात हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की बात हो, चाहे सामूहिक विवाह की बात हो, चाहे आयुष्मान

भारत की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो ऐसी सैकड़ों लाभकारी योजनायें केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारी सरकार में जितनी भी योजनायें हैं वह बिना जाति, धर्म, सम्प्रदाय, मजहब के भी पात्र व्यक्तियों को मिल रही हैं। मुझे कहने में खुशी हो रही है कि यह हमारी सरकार है। जितना पैसा मुख्य मंत्री राहत कोष से हमारी सरकार में पिछले 6 वर्षों में निरन्तर मिल रहा है, शायद किसी भी सरकार में मिला हो। मैं एक डाक्टर हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी हेल्थ हमारे सी0एच0सी0 में उनको भी हमारी सरकार लेपटॉप देने का काम कर रही है। आज चाहे हमारे जनपद की सी0एच0सी0 हो, चाहे पी0एच0सी0 हो अपडेट हो रही है। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मैं स्व0 मुन्ना सिंह चौहान जी का पुत्र हूँ। मैं किसानों की बात जरूर करूंगा। आज चाहे आलू के किसान हों, चाहे धान के किसान हों, चाहे गन्ने का किसान हो सबके चेहरे पर खुशहाली है। वर्ष 2017 के पूर्व में गन्ने का भुगतान नहीं होता था। मैं दावे के साथ कहता हूं आज हमारी सरकार में गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द हो जाता है। चाहे गेहूँ के किसान की बात करें, चाहे धान के किसान की बात करें। वर्ष 2017 के पूर्व में धान और गेहूँ का पैसा साल-साल भर नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार में धान और गेहूँ का भुगतान जल्द हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक 5 मिनट में समाप्त करिये।

श्री अमित सिंह चौहान-

मान्यवर, 1 मिनट और लूंगा। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी विधान सभा क्षेत्र बीकापुर अन्तर्गत मसौदा सुजितागंज मार्ग तहसील सोहावल को जोड़ता है, इसको उच्चीकरण व चौड़ीकरण करने की जरूरत है। अन्त में मैं एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। कश्ती चलाने वालों ने, जब हार कर दी पतवार हमें, लहर-लहर तूफान मिलें और मौज-मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमनें और फिर यह दिखायेंगे सबको, इन हालतों में आता है करना दरिया पार हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

***डा0 विमलेश पासवान-**

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। उसके लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र की भाग्य विधाता जनता की तरफ से जिन्होंने इस सदन में मुझे दोबारा भेजने का आशीर्वाद दिया उनकी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देता हूँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट जो 6 लाख 90 हजार करोड़ का है वह सर्वसमावेशी, बहुआयामी है। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस परिकल्पना को भी पूर्ण करता है जिन्होंने अन्त्योदय से सर्वोदय का जो सपना देखा था। और इस बजट से पूरा हमें विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आयेगा। इस बजट में विशेष तौर पर जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने जो बजट निर्धारित किया है साढ़े 12 हजार करोड़ का, जिसमें 45 जिलों में पहले से ही, मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और 16 जनपदों में पी0पी0पी0 मॉडल पर जो सरकार ने कॉलेज बनाने का सोचा है, यह भी सारे लोगों को हेल्थ रिलेटेड सर्विस देने का कार्य करेगा और पी0पी0पी0 मॉडल पर कार्य करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने हमारे हेल्थ सेक्टर को चैलेंज दिया और जब चैलेंज दिया तो हम लोगों ने सारी चीजों पर कार्य करना शुरू किया। तथा वर्ष 2021-22 में जब कोरोना ने सारी चीजों को उजागर किया तो सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 पर भी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गयी। जिसमें सी0एस0आर0 फंड से बहुत से उद्योगपतियों ने सहयोग किया। तो सरकार के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी काम करते हैं, वह वाकई काबिले तारीफ के पात्र होते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदया, गोरखपुर में ग्रेटर ग्रीडा की स्थापना के लिए अच्छा खासा बजट प्रस्तावित है और इस बजट में हमारी बांसगांव विधान सभा क्षेत्र के कुछ आंशिक गांव भी आ रहे हैं और मेरी यह मांग है कि उन गांव के लोग जिनकी जमीन अधिग्रहीत होगी, वहां पर ऐसा नियम जरूर बने कि, वहां के लोगों को, वहां के श्रमिकों को उनकी स्किल्स के अनुरूप जॉब मिले और उनके लिए वहां पर रोजगार की एक व्यवस्था हो। क्योंकि रोजगार की व्यवस्था न होने के कारण उनको इधर उधर पलायन करना पड़ता है और जो सबसे प्रमुख चीज है इस बजट में कि इसमें इंडस्ट्रीज पर काफी ध्यान दिया गया है और हम बात करें वर्ष 2017 से लेकर अब तक प्रस्तुत किये गये सारे बजट पर तो सारे बजट बहुत ही प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ से बनाये गये हैं। वर्ष 2017-18 का बजट जो किसान, महिलाओं, और युवाओं पर आधारित था। वर्ष 2018-19 का बजट नए निवेश के लिए आधारित था तथा उसके बाद के सारे बजट जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर अयोध्या से लेकर काशी, काशी से लेकर प्रयागराज और उसके बाद चित्रकूट का, सारे जो हमारी आस्था के केन्द्र है, वह कैसे जीर्ण-शीर्ण हालत में पड़े थे कैसे उनका उत्थान करके हमारी सरकार ने उसको एक नया स्वरूप दिया है, भव्य रूप दिया है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपसे अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस क्षेत्र ने हमको चुना है बहुत ही आशा भरी निगाहों से हमें देखता है और हमारे क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत से काम किये हैं, शून्य से शिखर पर ले जाने का हमने अपने क्षेत्र में काम किया है और जो हमारा क्षेत्र गोरखपुर के दक्षिणांचल में बसता है, वह रोहन राप्ती के तट पर बसा हमारा दो तिहाई क्षेत्र है वह बन्धों के किनारे है, हमने बन्धों को तो बहुत अच्छा

किया लेकिन बन्धे अगर बाढ़ की सुरक्षा के साथ-साथ आवागमन का भी स्रोत बने तो अच्छा होगा। सारे बन्धों पर अगर पिचिंग हो जाए और बन्धों का सुदृढ़ीकरण करके 2 लेन बना दिया जाए तो एक अच्छा आगमन का स्रोत बनेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदया, क्योंकि मैं पेशे से डाक्टर हूं और मैने पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद 5 साल सरकारी मेडिकल कॉलेज बी0आर0डी0 में बतौर लेक्चरर काम किया है और मैंने देखा कि जो कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं उससे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस ड्राइव की बात करूंगा जिसमें 13 मार्च, 2018 को देश को ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था और वर्ष 2024 तक उसको पूरा करने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसी की तर्ज पर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर यह प्रमुख तीन कैंसर है, इन तीनों कैंसर के लिए एक प्रोग्राम बने जिसमे जागरूकता और प्रोग्राम के तहत् चूंकि इतने कम समय में हम जनपद को कैंसर फ्री नहीं कर पायेंगे, लेकिन हम एक प्रोग्राम बनायें जिसमें पी0एच0सी0 लेवल से लेकर सी0एच0सी0 लेवल तक एक जागरूकता प्रोग्राम बने और समय-समय पर हर महीने उसकी जनपद स्तर की स्वास्थ्य कमेटी से जांच हो, तो इसमें हमारे आने वाली जो पीढ़ी है जो कि कैंसर से ग्रसित हो रही है उनको इससे निजात दिलायी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे सुपर स्पेशलिटी सेंटर है कैंसर को ट्रीट करने के लिए मान्यवर, लखनऊ, वाराणसी एन0सी0आर0 रीजन में बहुत सारे हैं। हमारी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन स्क्रीनिंग-टेस्टिंग के बाद जब नम्बर इलाज का आता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, अपनी बात को समाप्त करें।

डा0 विमलेश पासवान-

मान्यवर, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूँ, हमें एक मिनट बोल लेने दीजिए। इसमें जो ग्रांट मिलती है, उसमें काफी समय लग जाता है। जैसे हमारे गोरखपुर में एक रेडिएशन सेंटर है, ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी लेवल पर एक-एक रेडिएशन सेंटर की स्थापना हो जाए, क्योंकि कैंसर की बीमारी काम्बीनेशन थेरेपी से ठीक होती है। अगर हम तीनों थेरेपी लेकर आ जाते हैं, तो भी रेडिएशन के लिए हमें बार-बार जाना पड़ता है और जाने के लिए हमें बहुत सारी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सारे कमिश्नरी पर एक रेडिएशन सेंटर खोला जाना चाहिए, जिससे हमारे कैंसर रोगियों को ट्रीटमेंट कराने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। पिछले बजट में मैने माँग किया था कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक जगह जानेपुर है। जानेपुर में हमारे तीन ब्लाकों के जो आंशिक गाँव आते हैं, वहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। हमारी बात का सरकार ने संज्ञान लिया था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आपको बोलते हुए सात मिनट हो गया। आप अपनी बात को समाप्त करिए।

डा0 विमलेश पासवान-

मान्यवर, ये लोग एक एलास्टेड एरिया में रहते हैं। मैं जानेपुर ब्लॉक की माँग अरसे से करता आ रहा हूँ। इस ब्लाक की माँग और पुरजोर करता हूँ। एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा कि इतने दिनों में बजट की चर्चा में कटाक्षों का माहौल देखा और यूं तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जो हमारी कार्यशैली है, जो हम लोगों ने काम किया है। हम लोग ने महिलाओं का दिल जीता है, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में करीबन 22 से 23 हजार महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सदन में भेजती है। हम लोगों ने महिलाओं को स्थान, सम्मान, पहचान दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरा भरोसा मा0 योगी आदित्यनाथ जी पर करती है और उनकी बात और कार्यशैली को देखते हुए दुष्यंत जी की मुझे वो दो लाइनें याद आती हैं कि 'कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों।, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक डा0 पल्लवी पटेल जी।

डा0 पल्लवी पटेल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का अवसर इस सदन में प्रदान किया, इस बावत मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। सरकार इतने गाजे-बाजे के साथ और बजट में की हुई तमाम घोषणाओं के साध आगे बढ़ रही है। आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सरकार यह जरूर सुनिश्चित कर ले कि पिछले कार्यकाल में आपने बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को आवंटित जो सरकारी पैसे में बंदरबांट किया है, वह न होने पाये और अगर हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह पहले सुनिश्चित कर लें ?

मान्यवर, कुम्भ के नाम पर लगातार पैसा सरकार दे रही है, लेकिन मेरी विडंबना यह है और मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि वहाँ पर कौन-सा ऐसा सन्यासी है, कौन-से ऐसे साधु-सन्त हैं, कौन से ऐसे अखाड़े के पाण्डाल है, जो वहाँ सरकारी पैसे पर रहते और खाते है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया मा0 योगी जी स्वयं नाथ सम्प्रदाय से आते है। मैं नेता सदन से पूछना चाहती हूँ कि यदि आपको ऐसे किसी सन्यासी, साधु-सन्त, अखाड़े का नाम अगर याद हो, जो सरकारी पैसे पर वहाँ रहते हैं, तो मुझे भी बताने का काम कर दें।

मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप स्वयं जानते हैं और आपसे भली-भांति कोई नहीं जानता कि आस्था दिव्यता का प्रतीक होता है और आप उस दिव्यता को भव्य बनाने के

नाम पर अरबों-खरबों रुपये देने का काम कर रहे है और खुश हो रहे हैं। चलिए, मान लेते हैं, आपने पैसे दे दिए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि आप जो अरबों-खरबों पैसा कुम्भ के नाम पर दे रहे हैं, हिन्दुओं की आस्था के नाम पर दे रहे हैं, इसका बंदरबांट न होने पाए, इसकी लूट न होने पाए, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे ?

आपकी सोच और आपके बजट में विकास सबसे ऊपर है, ये बात तो समझ में आ रही है और बजट को देखने में लगता भी है (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। मान्यवर, पूरा सुन लीजिए, तब मेजें थपथपा दीजिएगा, क्योंकि अब तालियां रिवाइन्ड नहीं होंगी। आपके बजट में विकास आपकी प्राथमिकता पर है, बहुत बढ़िया। इसलिए क्योंकि लगातार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए आप बजट पर बजट देते चले जा रहे है (समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाई और शेम-शेम बोले)। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आपके आस-पास ही बैठे होंगे, कोई अपने ही होंगे, जो पिछले कार्यकाल में अपने गाल बजाते हुए बोल रहे थे कि 100 दिन में गड्ढे भर देंगे और फिर आज पुनः उन्हीं गड्ढों में गड्ढे भरने का काम हो रहा है, तो मेरा प्रश्न नेता सदन से है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहूँगी कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें कि गड्ढों में गड्ढे कर कर के जो आप पैसा वहाँ ढाकने का काम कर रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब भी दे दीजिए ?

मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा, क्योंकि मेरे क्षेत्र सिराथू में एक शहजादपुर का पुल लगभग 300 करोड़ रुपये का बना है और उद्घाटन के तीन माह बाद उसकी सरिया उखड़-उखड़ कर सामने आने लगी (समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शेम-शेम बोला) और नाम दे दिया 'दुर्गा भाभी' सेतु। एक ऐसी महिला का नाम दिया, जिन्होंने अपने गौरवशाली योगदान की वजह से इतिहास में अपना नाम दर्ज किया और उनके नाम पर होने के बावजूद 300 करोड़ का पुल तीन माह भी नहीं चल पाया। अगर नाम देना था, तो मेहुल चौकसी का दे देते, नीरव मोदी का दे देते, गौतम अडानी का दे देते, 'दुर्गा भाभी' का क्यों दिया। अगर दुर्गा भाभी का दिया था, तो कम से कम उसकी क्वालिटी/गुणवत्ता तो इतनी मेनटेन कर लेते कि कम से कम उतने साल चल जाता, जितना पुराना इतिहास दुर्गा भाभी का है।

मान्यवर, आपकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हैं, तभी तो आपने उल्लिखित किया है कि 45 जनपद मेडिकल कॉलेजेज से आच्छादित हैं, 14 निर्माणाधीन है और 16 पी0पी0पी0 मॉडल पर बनाये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा आधी-अधूरी जानकारी ही क्यों देते हैं ? आप किसको धोखा दे रहे हैं, इस प्रदेश की जनता को। मान्यवर, ये पब्लिक है, सब जानती है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, आपका समय पूरा हो गया। आपको बोलते हुए 5 मिनट हो गया। बहुत सदस्य हैं, सभी का नाम आ जाए। अब आप बैठ जाएं।

डा0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, प्रदेश की जनता को सांस लेते, जीते-जागते काम करते अस्पताल चाहिए, मुर्दा, खोखले जर्जर भवन नहीं चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक गौरी शंकर वर्मा जी आप बोलें।

डा0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, आप एक अस्पताल बनाइए, उसकी गुणवत्ता ऐसी हो, जहाँ 5 से 10 हजार मरीजों की सेवा हो सके और उनको उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पिछले दिन सदन में तो मा0 नेता सदन बहुत उत्तेजित हो गए थे, रौद्र रूप दिखाने का उन्होंने काम किया, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपके रौद्र रूप की गरिमा और सम्मान और बढ़ गया होता, यदि आपने अपना ये रौद्र रूप और अपनी आँखें उन पर तरेरने का काम किया होता, जो आपके बगल में बैठ करके 100-100 मुकदमें झेल रहे हैं, हत्या के आरोपी हैं, जमीन की लूट-पाट में शामिल हैं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर आपके बगल में डिप्टी सी0 एम0 बनकर बैठे है। अगर आपने उनके ऊपर आँखें तरेर ली होतीं, तो आपका स्वार्थ सिद्ध हो गया होता। हम तो हैं ही, विपक्ष के।

मान्यवर, मानते हैं, आपसे कम संख्या में हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि उस पक्ष में आने में हमको वक्त नहीं लगेगा। आप सुरक्षा की बात करते हैं और सुरक्षा का मखौल उड़ाते हैं। आप देख लीजिए, आपका सदन, आपकी सरकार इन विधायकों की सुरक्षा के साथ क्या मजाक कर रही है ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 विधायक जी, मैंने मा0 सदस्य गौरी शंकर वर्मा जी का नाम पुकार दिया है, फिर भी आप लगातार बोल रही हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा रखे गये वर्ष 2023-24 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 खन्ना जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक बजट पहली बार सर्व-समाज के लिए बनाया गया है। निश्चित तौर से इससे हमारे प्रदेश का विकास होगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार गरीबों के कल्याण एवं सामूहिक विकास के लिए कृत संकल्प है। सुशासन, सुरक्षा, जन विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के साथ-साथ शक्ति एवं विकास का वातावरण

सुनिश्चित किया है। समाज के सभी वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ माँग के अनुरूप यह सुन्दर बजट रखने का कार्य मा0 योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सबसे वरिष्ठ मा0 सदस्य वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास के दर को उत्साहजनक बनाते हुए गाँव-गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन यह ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है।

मा0 अधिष्ठाता जी, यह उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। 2017 के पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। मैं बुन्देलखण्ड के उरई विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। बुन्देलखण्ड में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लूटने का काम किया और वहाँ पर अपराध बढ़ाने का काम किया। चाहे सड़क, पानी, चाहे बिजली हो उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड हमेशा प्यासा रहता था, हमेशा बेरोजगार बना रहता था। 2017 के बाद योगी जी ने हर घर को नल से जल देने का काम किया। आज बुन्देलखण्ड का कोई भी गाँव या मजरा शिक्षा, सड़क व बिजली से वंचित नहीं है, क्योंकि यह आदरणीय योगी जी की सरकार है। बुन्देलखण्ड को देख के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया है। 2017 के बाद मेरी विधान सभा में 4600 करोड़ के काम हुए। 371 करोड़ के अकेले सड़कों के कार्य हुए। मैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्या जी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी विधान सभा में 251 प्राइमरी पाठशालाओं व जूनियर स्कूलों की बाउण्ड्री बनाकर दिये हैं। हमारी विधान सभा में कायाकल्प के माध्यम से पूरी विधान सभा क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हो गया।

मैं अधिष्ठाता महोदया से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुछ काम अभी अधूरे हैं। सामने बैठने वाले लोगों ने कोई काम नहीं किया। आज हमारी विधान सभा क्षेत्र में रेनिया रेलवे फाटक से लेकर राजकीय मेडिकल चौराहे तक सड़क बनवाने का काम करे। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में रेनिया रेलवे फाटक है जहाँ घण्टों जाम लगा रहता है उस पर ओवर ब्रिज बनाने का काम करें। जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र में उरई नगर की आबादी लगभग 03 लाख से अधिक है। उरई नगर में शहर के बीचोबीच मलंगा नाला है, उस पर समाजवादी पार्टी के लोग कब्जा किये हुए हैं उस कब्जे को हटाकर मलंगा नाला को बनवाने की व्यवस्था की जाये। जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र में झाँसी को जाने वाले रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनवाया जाये। उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटरा गुरूसराय को जाने वाली सड़क के बीच में अजनारी रेलवे कासिंग पर अण्डरग्राउण्ड पास बनवाया जाये। मेरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल पुनर्गठन योजना हेतु दो ट्यूबवेल का निर्माण कराया जाये तथा एक ओवरहेड टैंक (70 हजार गैलन) का 13 कि0 मी0 पाइप लाइन का विस्तारीकरण कार्य, आवासीय कमरे का कार्य कराये जाने की कृपा करें। मेरी विधान सभा में कोटरा एवं विस्तारित क्षेत्र सहित आबादी क्षेत्र में वेतवा नदी से लिफ्ट कैनाल, फिल्टर प्लाण्ट सिस्टम से पेयजल

आपूर्ति का कार्य कराने की कृपा करें। मान्यवर, कोटरा नगर पंचायत में नदी क्षेत्र में कटाव की समस्या से निजात हेतु 04 रिटेनिगंवॉल का निर्माण कराने की कृपा करें। मान्यवर, 2017 से पहले हमारी वेतवा नदी से खनिज लेकर झाँसी, इटावा, मैनपुरी के लोगों ने बालू का खनन करके हमारी वेतवा नदी को बर्बाद किया है वहाँ पर कटाव रोकने के लिए रिटेनिंगवाल बनाने की कृपा करें। हमारी विधान सभा क्षेत्र नगर पंचायत कोटरा एवं विस्तारित क्षेत्र की जल निकासी हेतु 04 कि0 मी0 नालों का निर्माण कराने की कृपा करें। उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटरा नगर पंचायत बड़ी में माता मंदिर के पास महलो (कगारो) की जगह पर सनसेट पार्क निर्माण कराये जाने की कृपा करें। जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र में कोटरा नगर पंचायत में नदी वेतवा पुल से नक्कीबाबा मंदिर तक एप्रोच निर्माण कराये जाने की कृपा करें। जनपद जालौन के उरई विधान सभा में कोटरा नगर पंचायत में क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने की कृपा करें। उरई विधान सभा में कोटरा नगर पंचायत में प्राचीन माँ रक्तदंत के मंदिर तक कोटरा क्षेत्र बड़ी माता मंदिर तक नदी वेतवा के किनारे पाटन क्षेत्र तक विकास कार्य कराये जाने की कृपा करें। जनपद जालौन के उरई नगर में 04 नग रि-बोर नलकूप का निर्माण कराये जाने की कृपा करें। जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर के वार्ड नं0-15 में पेयजल पाइप लाइन का विस्तारीकरण कराये जाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, पाँच मिनट का समय हो गया है, अब कृपया समाप्त करिये।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र में प्राइमरी पाठशालायें कायाकल्प के माध्यम से बहुत सुन्दर हो गयी हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में अन्त्येष्ठि स्थल व बारात घर बनवाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अमित अग्रवाल जी, प्रारम्भ करें।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

मान्यवर, नगर पंचायत एट नई निर्माण हुई है वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने की कृपा करें। इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।

श्री अमित अग्रवाल-

मान्यवर, प्रदेश के ग्रोथ इंजन मा0 योगी जी की सरकार के 2023-24 के बजट पर बोलने के लिए आपने मुझको अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 'अमन्त्रम

अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधं अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः।' योजना से काम करने वाले दुर्लभ ही होते हैं और कोरोना काल की शमशान और कब्रिस्तान वाली शांति और आपदा की चुनौतियों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश को और विकास की राह दिखाने वाले मा0 योगी जी को और इनकी सरकार को मैं बधाई देता हूं और बेरोजगारी दर में कमी लाने पर भी बधाई देता हूं 14.4% से 4.2% लाने के लिए। इन्वेस्टर्स समिट के साढ़े तैंतीस लाख करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव के फलस्वरूप और पंचानबे लाख रोजगार बढ़ने से बेरोजगारी की दर और घटेगी। कारखानें उद्योग लगेंगे और विकास की बयार बहेगी, अनेकों योजनाओं में मा0 योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जहां पिछली सपा सरकार में आतंक, डकैती, महिला उत्पीड़न, गुंडा माफिया टैक्स वसूली में प्रदेश नम्बर 1 स्थान में था वहीं पर हमारे लिए आज हर्ष का विषय है कि आज मा0 योगी जी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण भारत सरकार ने 'इन्स्पाइरिंग लीडर' के रूप में उत्तर प्रदेश को चयनित किया है इसीलिए तो हम इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। अनेकों रोजगार सरकार द्वारा दिए गए हैं महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, अनेक योजनाएं दी गई हैं। पुलिस में लगभग डेढ़ लाख रोजगार, रोजगार मेलों के द्वारा 7.3 लाख रोजगार, खाद्यान्न योजनाओं में इक्यासी लाख मीट्रिक टन राशन का वितरण और महिलाओं के लिए दो गैस सिलेंडर निःशुल्क वितरण हेतु तीन हजार सैंतालिस करोड़ की व्यवस्था की गई है, इसीलिए तो कहते हैं 'मां, बहनों के नैन का तारा युवा किसान मजदूरों का सहारा, जन-जन का दुलारा, सबसे न्यारा बाबा योगी हमारा।' मैं आभारी हूं मेरठ को जो मा0 योगी जी ने प्रदान किया है। मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए छत्तीस सौ करोड़ की परियोजना, उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया की पहली रेपिड रेल मेरठ-दिल्ली के लिए तेरह सौ छह करोड़ रुपये दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए तीन सौ करोड़ रुपये दिया है, कृषि विश्वविद्यालय की अवस्थापना हेतु पैंतीस करोड़ रुपये का अंशदान दिया है, डेरी परियोजना में साठ करोड़ के अंश में मेरठ को अंशदान दिया है। मेरठ के न्यायालय परिसर में 20 व्यक्तियों हेतु लिफ्ट प्रदान की मल्टिलेबिल पार्किंग दी जाए ऐसा इस बजट में मैं अनुरोध करता हूं पांच नेशनल हाई-वे को जोड़ने व यातायात सुगमता हेतु बेगम ब्रिज जीरो माइल से सूरज कुंड तक ढाई किमी0 एलिवेटेड रोड, मेरठ को फोरेन्सिक लैब, रिजिनल कनैक्टिविटी हेतु हवाई जहाज, नई टाउनशिप शहीद स्मारक से बच्चा पार्क तक नौ सौ मीटर का एलिवेटेड रोड, एन0एच0 अट्ठावन दिल्ली-रूड़की रोड पर जटौली से गढ़ रोड तक आबुनाले प्रथम के किनारें की पटरियों पर तेरह किमी0 लंबे रिंग रोड का निर्माण, छावनी परिषदों को जी0एस0टी0 व अन्य करों के संग्रह के अनुपात में वित्तीय धनराशि का स्थानान्तरण, मेरठ कैंट विधान सभा क्षेत्र में सौ बेड वाला अस्पताल, मैं आशा करता हूं कि मा0 योगी जी की सरकार द्वारा यह हमको प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट मात्र खुश करने वाला नहीं, बल्कि जनता को पीढ़ियों तक आगे

खुश करने वाला बजट है हर हाथ को काम, हर खेत को पानी घर-घर खुशहाली मोदी-योगी की निशानी।

माफिया, गुण्डों पर होने वाली बुल्डोजर और कानूनी कार्यवाही से विपक्षी साथी परेशान है। रातों की नींद, दिन का चैन गायब हो गया।

लहू में अब हमारे एक नया उबाल आएगा।
सभी के दिल में अब अमिट यही सवाल आएगा।।
किया है जितना जुल्म गरीबों और कमजोरों पर तुमने।
एक-एक का हिसाब बाबा द्वारा चुकता किया जायेगा।।

जय हिन्द-जय भारत, जय श्रीराम।

(सदस्य का माइक बन्द होने पर)

***श्रीमती मीनाक्षी सिंह-**

मान्यवर, आज आपने मुझे इस सदन में बजट पर चर्चा करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रवासियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज मैं इस सदन में अपनी बात रख पा रही हूं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छह लाख नब्बे हजार दो सौ बयालिस करोड़ रुपये का बजट विधान सभा में कुछ दिन पूर्व ही प्रस्तुत किया है। यह बजट अत्यन्त लोक कल्याणकारी एवं सर्वसमावेशी बजट है।

इसके लिये मैं मा0 वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करती हूँ। यह बजट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के कल्याण के लिये और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा। मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट साबित होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, यह बजट न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि अमृतकाल का यह बजट अगले पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 01 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। आज उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों की उन्नति और प्रदेश के समग्र विकास के लिये निरन्तर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपना कर जिस प्रकार के कार्य किये हैं उससे प्रदेश में अपराधमुक्त और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भयमुक्त वातावरण स्थापित हुआ है। आज समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं, व्यापारियों और कमजोर वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुयी है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मा0 मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकास के नये-नये आयाम स्थापित कर रहा है। चाहे वह कानून का राज स्थापित करने की बात हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात हो, चाहे वह बड़े स्तर पर निवेश लाने की बात हो या नोयडा में फिल्म सिटी बनाने की बात हो, चाहे वह किसानों-मजदूरों के कल्याण की बात हो या महिलाओं-युवाओं के उत्थान की बात हो, आदरणीय योगी जी ने सभी क्षेत्रों में अपनी कार्यशैली से पिछले 06 वर्षों के अन्दर उत्तर प्रदेश को देश-विदेश में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है और हमारा प्रदेश सुशासन, सुरक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुये एक नयी गाथा लिख रहा है। इसके लिये मैं आदरणीय महराज जी का वन्दन करती हूँ, अभिनन्दन करती हूँ और उनके लिये दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि 'परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुये उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।' मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने के लिये हमारी सरकार जहाँ एक ओर नये-नये एक्सप्रेस-वे बना रही है वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कई नये नये एयरपोर्ट बना रही है और इस प्रकार के एक्सप्रेस-वे और अच्छी एयर कनेक्टिविटी के कारण उत्तर प्रदेश का तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश में जहाँ एक ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और औद्योगिक निवेश पर बल दिया गया है वहीं दूसरी ओर समाज के हर वर्ग जैसे गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और दुर्बल वर्ग के लोगों के सशक्तीकरण के लिये भी भरपूर प्रयास किया गया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, जब से केन्द्र में मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें आयी हैं तबसे महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तीकरण के लिये अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं। उत्तर प्रदेश में आज माताएं-बहनें अपने आपको काफी सुरक्षित महसूस करती हैं और यह केवल योगी जी की मजबूत कानून-व्यवस्था का ही परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं महिला सुरक्षा के कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं जैसे बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराना, अब तक 01 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरियाँ उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश में 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियनों का गठन करना इत्यादि, इसके लिये मैं देश और प्रदेश की सभी महिलाओं की तरफ से मा0 प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मैं दो पंक्तियाँ जो विपक्ष के मा0 सदस्यों के लिये कहना चाहूँगी कि 'जो हो गया उसे

सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है उन्हें ही सफलता, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।' मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगें रखना चाहती हूँ।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 विधायिका जी, पाँच मिनट हो गये हैं। अब आप समाप्त करें। मा0 विधायक जियाउर्रहमान जी।

(इस मध्य सदस्या श्रीमती मीनाक्षी सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर बोलती रहीं, लेकिन उनका माइक बंद था)

***श्री जियाउर्रहमान-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि सदन के अन्दर काफी शायरी चल रही है।

'हमारे मुँह से जो निकले वही सदाकत है
हमारे मुँह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है
मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं
लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है
जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे
किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है
सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में
किसी के बाप का हिन्दोस्तान थोड़ी है'

माननीय महोदया जी, 2022 में जो बजट आया था वह 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का था, लेकिन अफसोस की बात है कि आप वह बजट ही खर्च नहीं कर पाये हैं और आज आप 6 लाख 90 हजार करोड़ का बजट लाकर कहते हो कि हमने इतिहास रचा है। अगर आप उस बजट को सही तरह से खर्च कर पाते तब इस इतिहास को रचने की बात कर सकते थे। हेल्थ सेक्टर में जहां आप 44 हजार 387 करोड़ का बजट लाए हैं, अफसोस की बात है कि सिर्फ 21 हजार करोड़ ही खर्च कर पायें हैं। जहां हमारे गरीब परिवार के लोगों को दवाई नहीं मिल पाती है अगर यह बजट सही से खर्च होता तो उनके इलाज में सुविधा हो सकती थी। पी0डब्ल्यू0डी0 ऐसा विभाग है जहां पर 27 हजार 470 करोड़ का बजट आया था, लेकिन आपने सिर्फ 5 हजार 470 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं। मुझे अफसोस है कि आपने 2022 के चुनाव में वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, अरे रोजगार देने की तो दूर की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात है आप तो रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, जो परमानेंट नौकरियाँ हैं उनको संविदा पर रख रहे हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार चाहे वह प्रदेश की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो सबके सब निजीकरण करने पर तुले हुए हैं। पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो सबके अन्दर पद रिक्त हैं, लेकिन भर्तियाँ नहीं निकाली जा रही हैं। आज आपने वादा किया था कि हम 6 हजार डाक्टर और 10 हजार पैरामेडिकल स्टाफ रखेंगे, लेकिन चाहे मेरा कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्र हो, जिला मुरादाबाद हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर डाक्टर्स की कमी है। कहीं पर अल्ट्रासाउण्ड की मशीन नहीं है, तो कहीं पर सिटीस्कैन की मशीन नहीं है तो कहीं पर दवाओं की कमी है। मा0 अखिलेश यादव जी ने 102 एम्बुलेंस चलायी थी आपने सिर्फ उसका नाम बदलने का काम किया है। अगर आप उसको सही से चला लेते तो भी आप कुछ काम कर सकते थे। आपने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अन्दर 24 घण्टे बिजली देंगे, लेकिन आप सिर्फ कागजों में 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं। बिजली के तार इतने खराब हैं कि वह लोड झेल नहीं पा रहे हैं और जहां पर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि होनी चाहिए वहां पर यह कार्य भी नहीं हो रहा है। आपने कोई भी पॉवर प्लान्ट लगाकर बिजली बढ़ाने का काम नहीं किया है। रिवैम्पड योजना में आपने कहा था कि हम इसमें केन्द्र सरकार का पैसा लगायेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। बिजली के नाम पर जो शोषण होता है, जो भेद-भाव होता है, लोगों के साथ जो लूट-घसोट होती है, मैं चाहता हूँ कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया गया था अभी तक वह बिजली नहीं मिली है। किसान देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है उसका कर्जा माफ होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। किसानों का समय पर गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अन्दर आपने कहा था कि हम विद्यालयों के अन्दर एक क्लास एक टीचर की नीति अपनायेंगे, लेकिन 8 हजार ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक स्कूल और एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। किताबें और ड्रेस समय से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, मिड-डे-मील की गुणवत्ता इतनी खराब है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि शिक्षामित्रों को परमानेंट किया जाए।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने 2017 और 2022 में कहा था कि हम गड्ढामुक्त करेंगे लेकिन सड़कों में गड्ढे तो छोड़िए, गड्ढों में सड़कें बन चुकी हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से भी कह चुका हूँ, मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर से भी कह चुका हूँ कि मेरी कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कुन्दरकी से डींगरपुर मार्ग इतना खराब है, मेरा निवेदन है कि वह बनना चाहिए। मच्छरिया से रोंडा मार्ग, करनपुर से सींघनखेड़ा, गोविन्दपुर से हमीरपुर, चमरवा से दुलारी और मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि लाउड स्पीकर हमारे प्रदेश के अन्दर खासतौर से सम्भल और आस-पास के जिलों में हाई कोर्ट का यह कहना था कि उसकी आवाज कम कराई जाय, लेकिन मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटा दिए गये हैं आज रमजान शरीफ आने वाले हैं वहां पर जरूरत है। मैं आपसे मांग करता हूँ कि वहां पर स्पीकर दुबारा कम आवाज में चालू

कराने का काम करें। मदरसा के अन्दर सरकार ने बजट में कहा है कि विज्ञान के जो टीचर हैं उनको हम वेतन देंगे, लेकिन यह नहीं कहा कि कब देंगे और कितना देंगे। बेटियों के विवाह के लिए भी आप पार्शियल्टी कर रहे हैं। मेरे पास एक पत्र है जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार संविधान द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, आप बेटियों के विवाह में पक्षपात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई हो या फिर सरकार जाहिर करें कि वह सबका विकास चाहती है या सिर्फ कुछ लोगों का ही विकास चाहती है। मैं अपनी बात एक शायरी के साथ और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के साथ समाप्त करता हूँ।

'हम आतिशे सोजां में भी हक की बात कहेंगे,
कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे।।
तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में,
हम जिन्दा थे, हम जिन्दा हैं, और जिन्दा रहेंगे'

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपका समय हो गया है।

श्री जियाउर्रहमान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के ग्राम नियामतपुर इकरौतिया, वीरपुर थान, सिरस खेड़ा, मुंडिया मलूक, नान कार, ताहरपुर, रोडा, फतेहपुर खास, सिहोरा बाजे, नरखेड़ा में बिजली के तार जर्जर हैं, व ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि होना आवश्यक है।

(सदस्य श्री जियाउर्रहमान का माइक बंद कर दिया गया)

***श्री वाचस्पति-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमानों पर एवं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपना दल की अध्यक्षा श्रीमती अनुप्रिया पटेल का भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं तथा प्रयागराज के बारा की धरती को प्रणाम करता हूं। जिन्होंने मुझे तीसरी बार वहां से चुनाव जिताने का काम किया। मैं ऐसे बारा की धरती को बार-बार प्रणाम करता हूँ। वर्तमान सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है मैं अपने आपको एवं अपने दल को उसके साथ सम्बद्ध करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, आज बजट पर चर्चा हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा बारा जो 60 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। मात्र 40 प्रतिशत ही ऐसा है जिसमें खेती होती है। परन्तु नहरों का जाल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने के कारण मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था है इसलिए वहां धान की खेती सबसे अच्छी होती है, परन्तु सबसे अधिक पहाड़ व घने जंगल होने के कारण वहां खाली जमीन बहुत पड़ी है और खाली जमीन होने के कारण वहां पर 22-23 साल पहले एक रिफाइनरी कम्पनी को वह दे दिया गया था जिसका अधिग्रहण किसानों से कर लिया गया। किसानों को भुगतान भी कर दिया गया लेकिन 22-23 साल हो गया 962 हेक्टेयर लगभग 600 बीघा जमीन बिल्कुल समतल पड़ी हुई है। उसमें न तो रिफाइनरी का काम हुआ न शिलान्यास हुआ न ही होने की कोई सम्भावना है। अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अभी 21 तारीख को मिला था तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वह जमीन बंजर पड़ी हुई है और अगर उस पर कोई भी फैक्ट्री लगा देंगे तो निश्चित रूप से बारा की जनता को बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें हैं जो 26 किलोमीटर घूतपुर से पडुआ प्रतापपुर तक सड़क है, वह काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है। पी0डब्लू0डी0 की सड़क है। कई बार हमने अवगत कराया, लेकिन अभी तक वह सड़क ठीक नहीं हो पाई। मैं आपके माध्यम से सड़क ठीक करवाने का अनुरोध करता हूं। शंकरगढ़ में एक राजकीय महिला इण्टर कालेज है जो बहुत जर्जर स्थिति में है, उसे भी ठीक करायें। हमारे यहां आस्था का मसूरियन मां का मन्दिर है उसके सौन्दर्यीकरण के लिए मैंने अनुरोध किया है। पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। इस बार हम लोगों ने हैण्डपम्प देना बन्द कर दिया है। हर घर नल योजना की व्यवस्था की गयी है। यह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वर्तमान समय में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे टी0वी0 पर हम लोग देखते हैं। अगर गर्मी बहुत बढ़ जायेगी तो निश्चित रूप से पानी का बहुत संकट होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई न कोई व्यवस्था की जाये।

मान्यवर एक पीपा का पुल है और जैसे ही बरसात होती है तो उसे हटा दिया जाता है और 3-4 महीने आवागमन रुक जाता है वहां पर एक पक्के पुल की व्यवस्था हों क्योंकि हमारी विधान सभा चारों तरफ से घिरी हुई है और मध्य प्रदेश, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज से घिरा हुआ है यह पुल बन जायेगा तो हम 15 मिनट में कौशांबी और चित्रकूट पहुंच जायेंगे। आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूं और जसरा में बहुत भीड़ लगती है तो वहां भी पुल का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री रवि शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मैं बजट पर चर्चा करूं उस से पहले इस विधान सभा में हुए परिवर्तन पर बोल देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी ने इस विधान सभा का जैसे डिजिटलाइजेशन किया है और जिस तरीके से पीछे की लॉबी में परिवर्तन हुए हैं और जिस तरीके से इस विधान सभा के इतिहास को आम जन-मानस को दिखाने की व्यवस्था की गयी है और जिस तरीके से सत्ता

व विपक्ष के सदस्यों का सम्मान बढ़ाते हुए उनके प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा लेने की व्यवस्था की गयी है। जहां की नियमावली के साथ-साथ विधायकों के सम्मान और स्वाभिमान पर भी नई-नई व्यवस्था देने का काम किया है। सम्पूर्ण विधान सभा के सदन के माध्यम से अपने मा0 अध्यक्ष महोदय, को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं वर्ष 2012 में जीत कर आया था तो पीछे लॉबी में हाजिरी के लिए जाना पड़ता था और हाजिरी के लिए लाइन लग जाती थी, लेकिन आज हम हाजिरी का काम इसी टैबलेट के माध्यम से कर सकते हैं। उस समय से आज का परिवर्तित स्वरूप निश्चित रूप से इस विधान सभा में बैठकर इन विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए और आज प्रश्नकाल में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लेते हुए मा0 अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है कि हम उनका जबाव सरकार को बाध्य करके दिलवाएंगे, ये विपक्ष के सदस्यों के लिए भी सम्मान की बात है। इस शानदार व्यवस्था के लिए मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। हम सभी के घर में मांगलिक कार्यक्रम जब होते हैं तो मांगलिक उद्घोष होता है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, गऊ माता की जय हो, गंगा मां की जय हो, हम उन संस्कारों को लेकर इस विधान सभा में आने वाले लोग हैं आज जिस तरीके वर्ष 2012 से 2017 तक गऊ माता को अनाथ करने का काम पिछली सरकारों ने किया था। मैं आज इस सदन में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज पूरे प्रदेश में निराश्रित गऊ माता के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था सरकार ने देने का काम किया है। मैं उस बुंदलेखण्ड से आता हूं जिसने दस्यु होने के दंश को झेला है जिसे लगातार कई वर्षों तक वहां पर बैठे लोगों के द्वारा लूटा गया और वहां की खनिज सम्पदाओं का दोहन हुआ और तो और वहां पर जो खनिज मंत्री हुआ करते थे। उनकी अन्त में सी0बी0आई0 जांच हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। यह भ्रष्टाचार का उदाहरण ही तो है। सरकार के द्वारा प्रस्तुत यह बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को गति देने वाला बजट है।

इस बजट में वह सारी चिंता की गई है जो सरकार को अपनी 25 करोड़ की जनता के लिए करनी चाहिये। मैं इस सदन को स्मरण कराना चाहूँगा कि जब 2014 में माननीय मोदी जी ने बनारस से चुनाव लड़ने का संकल्प लिया था उस समय हमारे विपक्ष के लोग सत्ता में बैठे थे उनको मालूम नहीं था कि अब क्या होने वाला है। जब मोदी जी ने बनारस से चुनाव जीतकर दिल्ली की राजनीति को सम्भालने का काम किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश में जब पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी तब दिल्ली के नेतृत्व ने तय किया कि हम योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में भेजने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्य मंत्री बने तब इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बदलने का जो काम किया है वह निश्चित रूप से एक योगी के लिए ही सम्भव था। वह योगी जिन्होंने जीवन भर साधना की, जिनका परिवार न हो, जिनको व्यक्तिगत सुख-दुख की चिंता न हो, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों

के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अभी एक सदस्य सामने से बोल रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता नहीं की गई है और मैं उन सदस्य की चिंता का जवाब देते हुए कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियों में जाकर तो देखिये आज उन बस्तियों में विकास की बयार आई हुई है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने जालीदार टोपी लगाना बंद कर दिया है, आज मुस्लिम महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुत सारा परिवर्तन देखा है तभी तो उनका विश्वास योगी जी और मोदी जी पर जमा है। आज उनको मिलने वाली मूलभूत योजनाओं का वास्तव में उनको लाभ मिल पा रहा है। माननीया अधिष्ठाता महोदया, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरे क्षेत्र के विकास के जो कार्य हैं वह मैं लिखकर दे दूंगा और आप उसे मेरे भाषण में शामिल करवा देंगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप बैठिये। अब श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' बोलेंगे।

श्री महबूब अली-

माननीया अधिष्ठाता जी, माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि सत्ता पक्ष से दो सदस्य बोलेंगे फिर विपक्ष से एक सदस्य बोलेगा, लेकिन सत्तापक्ष की तरफ से माननीय सदस्य लगातार बोल रहे हैं। कृपया हम विपक्ष के सदस्यों को भी मौका दीजिये। यह उचित नहीं है।

श्री वीर विक्रम सिंह-

माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे वर्ष 2023-2024 की बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश को नये शिखरों पर स्थापित करने के लिए अपने भागीरथी प्रयासों से राष्ट्र स्तर ही नहीं, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाने वाले हमारे कर्मयोगी तेजस्वी एवं यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री परम् श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ को मैं उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं, किसानों, व्यापारियों, मातृ शक्ति एवं सभी बुजुर्गों की ओर से प्रणाम करता हूँ एवं करोड़ों देशवासियों की ओर से विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं अत्यन्त अनुभवी वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी तथा उनके वित्त मंत्रालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों, व्यापारियों आदि सभी वर्गों की आकांक्षाओं को समझा एवं हर वर्ग के विकास के लिए अत्यन्त परिश्रम से विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत किया। इस बजट को मैं आंकड़े की दृष्टि से नहीं, बल्कि असीम सम्भावनाओं की दृष्टि से देखता हूँ। आंकड़ों की दृष्टि से तो यह बजट सभी पूर्ववर्ती सरकारों की कल्पना से भी परे जा चुका है इसलिये मैं इस बजट को अपार सम्भावनाओं वाला बजट कहना चाहूँगा। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनामी का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग एक ट्रिलियन

डालर/इकोनामी बनाने के लिए तमाम योजनायें निकाली गई हैं। चाहे वह इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हो।

इन्वेस्टर्स समिट में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि से पूरे भारत और पूरे विश्व ने देखा। जहाँ पूववर्ती सरकारों में मात्र गुण्डई हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में आदमी आने से डरता था। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने गया तो जब मैंने उत्तर प्रदेश का नाम बताया तो लोग मुझसे भयभीत हो गये कि यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता था। जिसको बदलने का काम मा0 आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा क्षेत्र कटरा विधान सभा जो कटरी का क्षेत्र कहा जाता है, तीन-तीन नदियों के किनारे बसा हुआ यह क्षेत्र है। महोदय, पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे क्षेत्र में पकड़ का व्यापार चलता था, अपहरण का व्यापार चलता था। हमारे क्षेत्र में एक विजय गुप्ता जी थे जो नाव से अपने घर जा रहे थे उनको धमकाकर जबरदस्ती उनका अपहरण करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे क्षेत्र में हुआ था। अधिष्ठाता महोदय, यह सब चीजें खत्म करके मा0 योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व मैं बरेली के द्वारके चीनी मिल में गया तो वहाँ जी0एम0 के द्वारा मुझको बताया गया कि उन्होंने वहाँ पर ई प्रणाली सिस्टम बना रखा है जिसमें काश्तकारों को मालूम चल जाता है कि कितनी लढ़ियाँ वहाँ पर गन्ने की खड़ी हुयी है कितने ट्रैक्टर गन्ने के वहाँ पर खड़े हुये हैं। निश्चित रूप से ई प्रणाली सिस्टम हमारे सभी चीनी मिलों द्वारा अपनाया जायेगा और जो भी हमारा भुगतान है पूर्ववर्ती सरकारों से काफी अच्छा किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मण्डल में बरेली एयरपोर्ट बना जिसमें तमाम बड़े शहरों को जोड़ने का काम किया गया। मेरे क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेस निकला, दुगला करीमनगर से लेकर चमलपुर कला तक गंगा एक्सप्रेस-वे निकला। डी0बी0टी0 के माध्यम से सभी काश्तकारों को मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जनपद में कोई मेडिकल कालेज नहीं था। मा0 खन्ना जी द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में हमारे जनपद में मेडिकल कालेज दिया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि इस एम0ओ0यू0 में जो अभी समिट हुआ था हमारे विधान सभा क्षेत्र कटरा में बिरला सीमेंट ग्राइंडिंग फैक्ट्री का एम0ओ0यू0 साइन हुआ है जो लगभग 5000 करोड़ की लागत से हमारे क्षेत्र में बिरला सीमेंट ग्राइंडिंग फैक्ट्री स्थापित की जायेगी। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार में राजश्री कम्पनी वरेली द्वारा लगभग 100 करोड़ की लागत से हमारे क्षेत्र में एथेनाल प्लाण्ट लगा। आज वह एथेनाल प्लाण्ट बनकर तैयार हो गया और लोगों को रोजगार भी मिला है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से दो-चार बातें बताना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में रामगंगा के किनारे बसा खूबपुर दुगला करीमनगर।

श्री अधिष्ठाता-

इसको आप दे दीजिएगा, जुड़वा दिया जायेगा। मा0 विधायक श्री राम अचल राजभर।

श्री वीर विक्रम सिंह-

हमारे क्षेत्र में एक राजकीय इण्टर कालेज खंगेड़ी बना। उसको राजकीय डिग्री कालेज में तब्दील कर दिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा।

(इसके बाद सदस्य का माइक आफ हो गया जिसके कारण उनका भाषण नहीं सुना जा सका।)

श्री राम अचल राजभर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-24 पर चर्चा के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो बजट में व्यवस्था है वह बजट दिशाविहीन है और यह किसान, गरीब, नौजवान, महिला, छात्र विरोधी है। इस बजट में बड़ी चर्चा की गयी और यह हल्ला मचाया जा रहा है लेकिन आज विकास, शिक्षा, महंगाई, ऊर्जा, कानून-व्यवस्था देख लें तो आज पूरी तरह से चौपट हो गया है। मैं विकास की बात करता हूँ। आज बड़े-बड़े एन0एच0 सड़कें बन रही हैं। फ्लाई ओवर बन रहा है, तमाम ओवर ब्रिज बन रहे हैं लेकिन हमारे सभी सम्मानित विधायकों से जुड़ा मामला है जब हम गाँव में, अपनी विधान सभा क्षेत्र में घूमते हैं तो उसके अन्दर जो विकास होना चाहिए उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र में गाँवों में भी बजट देकर वह सड़कें, पुलिया बनवायी जायें और जिनके लिए हम लोग वादा करके आते हैं हम लोग तमाम याचिकायें लगाते हैं। नियम-51 और नियम-301 में जो स्वीकृत सड़कें हैं।

मान्यवर, जो स्वीकृत है उस पर भी काम नहीं होता है। हम लोगों ने 17वीं विधान सभा में तमाम याचिकाएं, नियम-301 एवं नियम-51 में सूचनाएं लगाई थीं लेकिन आज उन पर काम नहीं हुआ है। मैं लम्बी बात नहीं करूंगा लेकिन मैं विधान सभा के क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार से निवेदन करुंगा कि इस बजट में इन प्रोजेक्टों को भी जोड़ने का काम किया जाए। हमारी अकबरपुर विधान सभा क्षेत्रों में मुख्यालय से एक बाईपास लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। उसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है लेकिन किसानों को मुआवजा बहुत ही धीमी गति से दिया जा रहा है और मार्च आएगा तो पैसा वापस हो जायेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहां से निर्देश जाए कि जो बाईपास अकबरपुर मुख्यालय से बन रहा है उसका काम तेजी से किया जाए। वर्ष 2017 के पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो उस समय अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में एक बेवाना ब्लॉक प्रस्तावित था, वह स्वीकृत भी था और उसका शिलान्यास भी हुआ था लेकिन आज तक सरकार द्वारा बेवाना ब्लॉक बनाने के लिए पैसा नहीं दिया गया है। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस बजट में बेवाना ब्लॉक बनाने के लिए पैसे

का प्राविधान करके पैसा भेजने का काम किया जाए। इसी तरह हमारे यहां अकबरपुर में एक एकलव्य स्टेडियम बना हुआ है वह बहुत पुराना स्टेडियम है उसका ग्राउण्ड मानक के अनुसार निर्माण कराया जाए एवं पानी निकासी की व्यवस्था को सुचारु रूप से किया जाए। वहां पर एथलीट कोच की भी व्यवस्था नहीं है और पूरी बिल्डिंग एवं हॉस्टल में मरम्मत की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरफ भी ध्यान देकर उस एकलव्य स्टेडियम को बनवाने का काम किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चर्चा हुई है और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा लम्बा-चौड़ा बजट आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला अम्बेडकरनगर की अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड, अकबरपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तारा खुर्द की बाउण्ड्री वाल नहीं है। इसलिए मैं वहां पर बाउण्ड्री वाल के लिए बजट में मांग करता हूँ। इसी तरह अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवाना है जहां अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके लिए भी मैं सरकार से बजट की मांग करता हूँ कि वहां पर अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स-रे मशीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी तरह अकबरपुर विधान सभा में सैदापुर बाजार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराई जाए और इसी अकबरपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत सिबलीपुर हेड के आगे ग्राम दुधौरा के पास शारदा सहायक नहर पर बनाई गयी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है तो उसके लिए भी बजट देकर उसका भी निर्माण कराया जाना आवश्यक है। हमारी विधान सभा अकबरपुर में में टोन्स नदी पर स्थित ग्राम पलई कल्याणपुर, ग्राम अमौली के मध्य रपटा पुल और खानपुर शाह सुलेमपुर ग्राम कटुई के मध्य रपटा पुल, और ग्राम मीर मलूकपुर ग्राम लहंगी का पुरा के मध्य रपटा पुल की मांग करता हूँ। इसी तरह अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में मैं अकबरपुर ब्लॉक के अन्तर्गत बेवाना से कुढा मोहम्मदगढ़ बाजार तक सड़क उच्चीकृत एवं चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ। मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री रमेश जायसवाल-

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बजट पूरी तरह से प्रदेश के हित में है और यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवानों एवं महिलाओं के हित में है। बजट प्रस्तुत होने के बाद मैं रविवार को अपने क्षेत्र गया था और हम लोगों ने वहां की जनता से सीधे बात की, वहां के लोगों ने इस बजट को सराहा और कहा कि यह अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट था जो इस सत्र में पास हुआ है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 से 2017 तक के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसे भी पांच बार बजट पेश करने का अवसर मिला। उस पांच बार के बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं था और लोगों ने मनमाने-हरजाने तरीके से बंदरबांट करके उस बजट का व्यक्तिगत हितों में प्रयोग किया। इधर बैठी बहन पल्लवी पटेल कह रही थीं कि जो प्रयाग के अन्दर कुंभ का मेला लग रहा है उसमें पूरा का पूरा बजट बंदरबांट की भेंट चढ़ गया जबकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है कि जब सपा की सरकार हुआ करती थी तब भ्रष्टाचार के आतंक में ये लोग डूबे हुए थे, उसका परिणाम था कि इनके पूरे पांच साल के बजट को और इनको खुद प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आज छोटी सी जगह इनको सदन में प्राप्त है। अपने द्वारा पेश किये गये बजट और देश-प्रदेश के प्रति अपनी नियति का, अपनी अन्तरात्मा से परीक्षण करें कि वास्तव में हमने कौन सी गलती की थी, किस गलती का परिणाम हम भुगत रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, जो ईमानदारी की पराकाष्ठा पर जाकर देशहित एवं प्रदेश हित में लगातार काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस 2023-24 के बजट पर, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, लोक-कल्याण के हित में यह बजट है। जनता के हित में यह बजट है, पूरे प्रदेश की जनता इस बजट की प्रशंसा कर रही है। अनेकों मुद्दे हमारे साथियों ने बताये, आप उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं और न ही सक्षम हैं। लगातार बजट के बारे में खराब बोलना और दूसरी तरफ अपने क्षेत्र के विकास के बारे में अपेक्षा करना, यह दोहरी नीति, यह दोहरा प्रतिफल, आप जताना चाहते हो, जनमानस के लोग आपको अच्छी तरह जानते हैं। इस सदन के माध्यम से कुछ विषय रखना चाहता हूं क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं वह जायसवाल समाज है। अभी प्रयाग के अन्दर राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, और हम सब लोग पूरे देश के अन्दर अलग-अलग नामों से कहीं चौधरी, कहीं गुनहरे, कहीं शिवहरे, कलवार, कलाल,नाडर आदि बिरादरी के नाम से जायसवाल समाज के लोग रहते हैं और सभी लोग राष्ट्रवादी विचाराधारा के साथ जुड़े हुए हैं और हम सब लोगों के आराध्य राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज के हम सब लोग वंशज हैं। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की मूर्ति की स्थापना वाराणसी के अन्दर एक जगह आवंटित करके की जाए। साथ ही राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज के नाम से एक बोर्ड का भी गठन किया जाए जिससे समाज का उत्थान और समाज को सम्मान मिल सके। साथ ही साथ अन्ध्रापुण चौराहा जो हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ, तीस भाषाओं के जानकार, विधिवक्ता, हिंदी के प्रकाण्ड विद्वान डॉ0 काशी प्रसाद जायसवाल जी, जिनको हम सब अपना आराध्य मानते हैं उनके नाम से चौराहे का नाम डा0 के0पी0 जायसवाल चौराहा रखा जायें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां वाराणसी में साहू समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उन लोगों के मान-सम्मान की चिंता करते हुए सांस्कृतिक

राजधानी वाराणसी में तमाम पर्यटक आते हैं, कुछ स्थलों के नामों में परिवर्तन करना उस समाज के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है। जैसे वाराणसी में तेलिया नाला, तेलिया घाट और तेलिया बाग का नाम बदलकर तेलीबाग, तेली घाट और तेली नाला रखा जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं जहां पर पार्टी के विश्व हिंदू परिषद् के राष्ट्रीय संगठन मन्त्री ठाकुर गुरजन सिंह रहा करते थे, उनका गांव चंदौली विकास खण्ड के खुरजुहां में आता है। वे लाखों-लाखों नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। विश्व हिंदू परिषद् के राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी पहचान थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिप्टी सी0एम0 श्री केशव प्रसाद मौर्या जी वहां उनके गांव पर गये थे, उनकी प्रतिमा को लगने की बात कहे थे, मैं सदन के माध्यम से ठाकुर गुरजन सिंह जी की आदमकद प्रतिमा को बबुरी बाजार या नजौली चट्टी बाजार में लगने की मांग करता हूं। बाकी मांगों को जोड़ने हेतु अधिष्ठाता महोदय ने निर्देश दिया था, जिसकी मांग को भेज दिया था, जिसे जोड़ लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, आप पांच मिनट के अन्दर अपनी बात रखिए। बहुत लंबी लिस्ट है, मा0 विधायक श्री शशांक त्रिवेदी जी आप बोलिए।

(श्री रमेश जायसवाल जी लगातार बोलते रहे उनका माइक बंद कर दिया गया)

श्री शशांक त्रिवेदी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे एक सदस्य बोल रहे थे...

श्री अधिष्ठाता-

जायसवाल जी, आप कागज दे दीजिएगा, कार्यवाही में जोड़ दिया जाएगा।

***श्री शशांक त्रिवेदी-**

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी हमारे एक सदस्य बोल रहे थे, शायद समयाभाव के कारण उनका सेर अधूरा रह गया। उसको मैं पहले पूरा कर दूँ।

'बहुत लूटा फिरंगी ने कभी बाबर के पूतों ने,
यह मेरा घर है, मुफ्त की सरांय थोड़ी है ?
बिरले मिलते हैं सच्चे इंसान दुनिया में,
हर कोई अब्दुल हमीद और कलाम थोड़े है।'

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, इतना अच्छा बजट, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। यहाँ पर हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं आभारी हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए जो इतना बढ़िया बजट दिया है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, वह अतुलनीय है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में यह शेर आम प्रचलित था-'कातिल की यह दलील मुंसिफ ने मान ली, मकदूल खुद गिरा था खंजर की नोंक पर।' यह 2017 से पहले होता था। लेकिन हालात बदल गए, माफिया जमानत रद्द कराकर जेल जाने लगे। जिस तरीके से कानून-व्यवस्था में, बिजली व्यवस्था में पिछले 6 वर्ष में योगी जी के नेतृत्व में सुधार हुआ है, वह ऐतिहासिक है और क्षेत्र के लोग कहने लगे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कहने लगी है कि जिस तरीके से बिजली में सुधार हुआ है और कानून-व्यवस्था में, जब तक पूरे प्रदेश में हर चीज में सुधार नहीं होगा, तब तक इसी सरकार को, योगी जी की सरकार को बार-बार लाना है। मान्यवर, यहाँ सदन के एक बहुत बड़े नेता, विपक्ष के बड़े नेता, उन्होंने स्टार्टअप पर बहुत उपहास किया। युवा हैं, इंजीनियर हैं, वह आक्रोशित हो गए थे, किसी बात पर मुझे नहीं पता, वह उनको पता होगा। स्टार्टअप युवाओं के लिए बहुत बढ़िया योजना है, वरदान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा आत्मनिर्भर होना चाहता है और उत्तर प्रदेश का युवा तब आत्मनिर्भर होगा, जब वह अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। मैं इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई विदेश चला गया, वह फेसबुक में रहा और जब से यह स्टार्टअप योजना शुरू हुई, वह और उसके मित्र कैलीफोर्निया से वापस उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आने लगे हैं। मान्यवर, आप इंजीनियर थे, मैंने सुना है कि आप आस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए। आपको हम इंजीनियरों का उपहास तो नहीं उड़ाना चाहिए था। लेकिन दोष आपका नहीं है क्योंकि 'राजनीति को बिरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं, अहंकार में इतने चूर हैं कुछ लोग कि लोकशाही को अपनी रियासत समझ बैठे हैं।' स्टार्टअप योजना के तहत् जिस तरह से युवा जुड़ रहा है, वह अनुकरणीय है और मैं मोदी जी और योगी जी का जीवनभर आभारी रहूँगा। ऐसी योजनाएँ उत्तर प्रदेश और भारत वर्ष में लाने के लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अधिष्ठाता महोदया, पहले उत्तर प्रदेश घोटालों का प्रदेश था, घोटाले हो रहे थे। 2002 से लेकर 2027 तक अगर घोटाले गिनाने लगें तो अटल जी का लिखा शेर याद आता है-'बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं', लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, पहले खाद्यान्न घोटाला होता था और अब अन्न महोत्सव होता है। यह है क्रेडिबिलिटी और हुजूर, कम से कम आप लोग क्रेडिबिलिटी की बात तो मत करो। भूल गए प्रदेश के वह दिन जब दंगे, दिन-दहाड़े बिटिया का घर से उठ जाना, आपके क्षेत्र में सी0ओ0 की हत्या, यह केडिबिलिटी थी ? क्रेडिबिलिटी आज है और विपक्ष को सहयोग देने वाले जो लोग सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ, महाभारत की

कुछ पंक्तियाँ हैं-'मूक बनकर अधर्म को जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म, द्रोण या कर्ण हों, सबके सब युद्ध में मारे जाते हैं।'

श्री अधिष्ठाता-

माननीय विधायक जी, 05 मिनट हो गए हैं। अब माननीय विधायक लक्ष्मी राज सिंह

श्री शशांक त्रिवेदी-

महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूँ। जिस तरीके से चिकित्सा सुविधा में सुधार हुआ है।

(माइक बन्द कर दिए जाने के कारण सदस्य श्री शशांक त्रिवेदी का भाषण आगे सुनायी नहीं दिया)

(इस मध्य सदस्य श्री शशांक त्रिवेदी अपने स्थान से लगातार बोलते रहे, लेकिन उनका माईक बंद था।)

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में अपनी बात को रखने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए हृदय स्थल से आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ अपने जिले व विधान सभा क्षेत्र की जनता का अभिनंदन और वंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्येक जन की पार्टी, हरजन की पार्टी जिन्होंने मुझे मौका दिया एक सामान्य परिवार के बेटे को मौका दिया मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि सत्ता कोई जमीन या भूमि का टुकड़ा नहीं जो पिता के बाद खतौनी में पुत्र के नाम आती है। सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्ता के लिए जनता की सेवा करनी पड़ती है। सत्ता विरासत में एक बार तो मिल सकती है, लेकिन बार-बार सत्ता विरासत से नहीं मिल सकती इसके लिए मा0 योगी जी, मा0 मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है कि राजनीति में व्यक्ति पैसे या परिवार से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि जनता के हित के लिए किये कार्यों से बड़ा होता है उसके द्वारा की गई योजनाओं से बड़ा होता है। आज पूरी दुनिया भारत देश की ओर देखती है और पूरा देश, उत्तर प्रदेश की ओर देखता है, लेकिन मेरे विपक्ष के साथी अभी अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे थे कि हमें यह नहीं मिल रहा, लेकिन यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। यहां पात्रता देखकर योजनाएं मिलती हैं नाकि तिलक व टोपी देखकर और यह सिद्ध कर दिया है आदरणीय योगी जी ने गुड गवर्नेस के माध्यम से आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को देख रही है, आज पूरी दुनिया के 40 देशों के अधिक के लोग यहां अपना व्यापार करना चाहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और इस उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि यहां लोग व्यापार करना चाहते हैं नहीं तो दिन दहाड़े यहां कत्लेआम होता था और हमारे यहां की बेटियां सुरक्षित नहीं थीं अभी हमारे विधायक बोल रहे थे कि कितना नंगा नाच हुआ करता था सपा की सरकारों में और अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की आज कानून ठीक प्रकार से काम

कर रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि कोई माफिया हो या कोई भी हो उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया जाएगा, उन्होंने इस बात को सदन में कहा। मैं कहना चाहता हूं कि आज राजतंत्र नहीं जहां राजा का बेटा राजा बनता था वह चाहे योग्य हो या अयोग्य हो। मैं धन्यवाद देता हूं संविधान के निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी को जिन्होंने यह व्यवस्था दी आज यह लोकतंत्र है जहां जनता के द्वारा सांसद, विधायक, जिला पंचायत प्रधान आदि चुने जाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आज ऐसी जातियों को मौका दिया और सपा के कार्यकाल में केवल एक ही जाति ध्यान में रहती थी और एक धर्म याद रहता था, उसके अलावा उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म के लोगों का सम्मान किया जा रहा है यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे विपक्ष के साथियों की यह कार्यरूपी विश्वसनीयता (क्रेडिबिल्टी) की बात हैं। आज पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं और किसी भी प्रदेश में चले जाएं आज उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात होती है जिस प्रकार कानून व्यवस्था चल रही है आज पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होती है और इसी के साथ मैं दो लाइनों में अपनी बात कहता हूं मैं 'इतना सुन्दर बजट मत पूछो कि बजट कैसा आया है, बजट देखकर आज लगता है जन-गण-मन-तन हर्षाया आया है।' यह बजट प्रत्येक व्यक्ति का बजट है और इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मा0 वित्त मंत्री जी का जिन्होंने 6 लाख 90 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की आशाओं और अकांक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश एवं अन्त्योदय के सपने को साकार करने वाला है। यह लोक कल्याणकारी बजट है इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, शोषित, वंचित, युवा, बुजुर्ग आदि वर्गों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें स्थान दिया गया है मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और मा0 वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ बजट वर्ष 2023-24 में पर्यटन विभाग के द्वारा हमारी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद का भी ध्यान दिया गया है।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक स्टेडियम का निर्माण हो क्योंकि बहुमुखी खेल प्रतिभाओं के साथ-साथ, सैन्य भर्ती की दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत अग्रणी है। इस क्षेत्र के नवयुवक बड़ी संख्या में भारतीय सेना और खेलकूद में जाते हैं। अभी हाल में ही हमारे क्षेत्र की बेटी पार्श्व चोपड़ा ने वर्ल्ड कप में 11 विकेट लेकर मेरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऐसे ही बहुत सारे नवयुवक और युवतियाँ हैं चाहे अनुष्का पंडित हों, चाहे स्वाति यादव हों, चाहे अतुल यादव हों, चाहे विवेक कुमार हों, चाहे निधि नागर हों, चाहे गरिमा नागर हों, चाहे सलमान गाजी हों, चाहे आदित्य सैनी हों, चाहे सचिन यादव हों, चाहे नरेश कुमार हों, चाहे दीपक चौधरी हों, चाहे अखिलेश सोलंकी हों, इन सबने खेलकूद में हमारे क्षेत्र का नाम

रोशन किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके अलावा मेरी कुछ मांगें हैं, मैं उन मांगों को आपके द्वारा लिखकर देना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने उधर से तीन लोगों को बुलवा दिया दो-दो बार और इधर से एक। आपसे आग्रह है कि अब इधर से लगातार तीन लोगों को बुलवा दीजिए। फिर उधर से बोलवा दीजिएगा।

***श्री अखिलेश-**

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं अपनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इस सदन में नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव जी का भी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि जिनके सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद के बल पर मुझे यहाँ तक आने का अवसर मिला है। साथ ही मैं मुबारकपुर की सम्मानित जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसके सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है। अधिष्ठाता महोदया, हमारे विपक्षी दल के और हमारे दल के कई साथियों ने बजट पर चर्चा करते हुए बजट में रखे गए फर्जी दावों और झूठ की बुनियाद पर तैयारी की गई इस बजट पुस्तिका को और फर्जी अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए इस बजट पर अपनी असहमति जाहिर किया है। मैं अपने साथियों से अपने आपको जोड़ते हुए अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूँगा। इसलिए कि मेरे क्षेत्र की जनता की जरूरतों के समाधान के लिए मैं बजट में इन्हें भी जोड़वाना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो हमारे यहाँ चार सौ करोड़ रुपये का बजट दे करके चीनी मिल स्थापित करने का काम किया गया था। अधिष्ठाता महोदया, रिकॉर्ड समय में वह चीनी मिल बनकर तैयार हुई लेकिन आज की तारीख में जब आप रिकॉर्ड पेमेण्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड खरीदारी भी कर रहे हैं तो सठियाँव चीनी मिल में कल की तारीख में 80 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया है लेकिन अभी तक मात्र 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। हम उसकी समस्या के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। उस चीनी मिल में गन्ना ढुलाई के दो ही रास्ते हैं।

सठियाँव चीनी मिल के दोनों तरफ रेलवे गेट है, एक रेलवे गेट रेलवे वालों ने बन्द कर दिया है, सिर्फ दूसरा ही खुला रहता है। वह जनता के आवागमन का भी रास्ता है और साथ ही चीनी मिल में गन्ना ले जाने वालों का, ट्रक-ट्रैक्टर ट्रॉली का भी रास्ता है। हम चाहते हैं कि आप सठियाँव की रेलवे कॉसिंग पर एक आर0ओ0बी0 पुल बनाएँ, उपरिगामी सेतु का निर्माण कराएँ ताकि वहाँ दुर्घटनाओं से बचा जा सके, वहाँ की भीड़-भाड़ को कम किया जा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके। सठियाँव में उस रेलवे गेट से होकर उस रेलवे ट्रैक पर दिन-रात दर्जनों ट्रेनें चला करती हैं तथा हमेशा दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। महोदया, हमारा मुबारकपुर कस्बा बुनकर बाहुल्य कस्बा है। वहाँ की बहुत बड़ी आबादी है, एक लाख से भी ज्यादा की आबादी है। जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मा0 नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए मुबारकपुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई थी। लेकिन महोदय आज की तारीख में वह नाकाफी साबित हो रहा है और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अक्टूबर-नवम्बर के महीने में डेंगू की बीमारी से और जुलाई-अगस्त के महीने में वहाँ पर हैजा की बीमारी से सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और हजारों परिवार पीड़ित होते हैं। हम चाहते हैं कि मुबारकपुर में एक सौ शैय्या का संयुक्त हॉस्पिटल बना करके मुबारकपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हम यह भी कहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी ने भी अपने सम्बोधन में, अपनी चर्चा में उसको शामिल कराया था। हमारे क्षेत्र में दाउदपुर से लेकर कोल घाट का एक रास्ता है, जिसके बीच में तमसा नदी बहती है। उस पर एक पुल की आवश्यकता है, हम वित्त मंत्री महोदय से चाहते हैं कि उस पर बजट दे करके पुल का निर्माण कराने का कष्ट करें। हमारे यहाँ एक बड़हलगंज बाजार है जहाँ से सदर हॉस्पिटल की दूरी, मण्डलीय हॉस्पिटल की दूरी 35 किलो मीटर है। हम चाहते हैं कि उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तबदील करके उस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।

अधिष्ठाता महोदय, हमारा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर एक नगर पालिका, एक टाउन एरिया और दो ब्लॉकों का एरिया है और हम चाहते हैं वित्त मंत्री महोदय से कि एक तहसील केन्द्र मुबारकपुर के अन्तर्गत खोला जाए ताकि प्रशासनिक कार्यों में हमारे क्षेत्र की जनता को सुविधा मिल सके। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, हमने चर्चा में बहुत बातें सुनी हैं हमारे उधर के साथी तो बता रहे हैं कि उनके क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, विकास की बारिश हो रही है और सूखा इधर ही पड़ा है। हम कहना चाहेंगे वित्त मंत्री महोदय से कि कुछ दिन हमारे उधर के भाइयों के विकास कार्यों को नजरअन्दाज करके हम लोगों को भी इस विकास की कड़ी में शामिल करिए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अजय सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपने उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के बजट पर जिसको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री हैं उनके नेतृत्व में हमारे आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है उस बजट के समर्थन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर,

'मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है।
पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।'

अभी हाल ही में 10, 11 और 12 फरवरी को यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पूरे देश और विदेश के निवेशक आये और उत्तर प्रदेश में 33 लाख 52 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ है उसके लिए मैं अपनी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, बस्ती की जनता और हरैया की जनता की तरफ से मा0 मुख्य मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, आप जानते हैं कि पहले देश और प्रदेश का निवेश पश्चिम में हुआ करता था किन्तु 10, 11 और 12 फरवरी को जो समिट आयोजित हुआ है उसमें कैसे समावेशी और पूरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया है देख लें, पश्चिमांचल में 45 प्रतिशत, पूर्वांचल में 29 प्रतिशत, मध्यांचल में 13 प्रतिशत और बुन्देलखण्ड में 13 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आये हैं। मान्यवर, आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में और बाहर एक विशेष दल द्वारा जातियों पर चर्चा हो रही है। यह चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश को विकास मार्ग से भटका कर पीछे ढकेलने का षडयंत्र हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे उपयुक्त निवेश गन्तव्य बन गया है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसका जीता जागता उदाहरण है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि चाहे प्रभु राम का त्रेता युग रहा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग रहा हो यह सभी युगों में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है। मान्यवर, श्रीमद् भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि-

'चतुवर्ण मयाश्रृष्टिं। गुण कर्म विभागशः।।
तस्य कर्ताभपि मां। विद्यय कर्तारभव्यम्।।'

अर्थात्, मेरी सृष्टि में में चार वर्ण हैं, जिसका निर्धारण कर्म के आधार पर किया गया है। ये चार वर्ण/जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमिक हैं और आज हम देख रहे हैं कि हर वर्ग में प्रत्येक कार्य करने की आजादी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप समाप्त करें, मा0 सदस्या केतकी सिंह।

श्री अजय सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, कृपया समय दिया जाए।

(सदस्य का माइक बंद हो जाने के कारण व्यवधान)

हमारे वेदों और पुराणों में सबको सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गयी है। समाज को सुचारु रूप से और समरसता के साथ चल सके इसके लिए व्यवस्था दी गयी है जैसे चार

आश्रम की व्यवस्था है 1- ब्रह्मचर्य आश्रम 2- गृहस्थ आश्रम 3- सन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, चार पुरुषार्थो की व्यवस्था-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद और इसी तरह से चार दिशाएँ-पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हैं तथा इसी तरह से चार वर्णों की व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रमिक और इसी तरह से 4 युगों की चर्चा है, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग और सतयुग।

(इस समय 02 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

और इतना ही नहीं देश और प्रदेश के बारे में जब चर्चा होती है तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तर और दक्षिण की चर्चा होती है लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई देश, कोई समाज धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है तो मैं अवतार लेता हूं। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि-

''यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युथानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।''

मान्यवर, मुझे गर्व है कि मैं बस्ती की उस पूज्य भूमि से विधायक हूं जहां पर भगवान श्री राम के पुत्र की यज्ञ स्थली है, चौरासी कोसी का प्रारम्भ स्थल है, चौरासी कोसी के 03 स्थल हमारे यहां पर हैं, हमें गर्व है कि बस्ती का एक भाग जो गौतमबुद्ध नगर है, बस्ती का एक भाग जो सिद्धार्थ नगर है, कपिलवस्तु है और उसी बस्ती से जुड़ा हुआ सन्तकबीरनगर है, जो सन्त कबीर की तीर्थ स्थली है। मेरा अपनी सरकार से अन्त में अनुरोध है कि कृपया अयोध्या से मथ्थौड़ा धाम के लिए एक कोरीडोर बनाया जाय, अयोध्या से सिद्धार्थनगर के लिए एक कोरीडोर बनाया जाय, अयोध्या से सन्तकबीरनगर के लिए एक कोरीडोर बनाया जाय और अयोध्या से हम लोगों के महान गोरक्षपीठाधीश्वर, गोरक्षपीठ तक कोरीडोर बनाया जाय, इससे पर्यटन का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर पा रहा हूं। अध्यक्ष जी, यह लिखकर मैं आपको दे दूंगा। आपने सदन में मुझे बोलने का मौका दिया, बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय श्रीराम।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश के बजट को ले करके जो सामान्य चर्चा इस सदन में हुई है, उस पर आपने मुझे यहां पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया है। मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का, दलीय नेताओं का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग ले करके न केवल बजट के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है बल्कि 25 करोड़ जनमानस की भावनाओं को उनकी आशा और आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का

कार्य किया है कुल 134 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में अब तक भाग लिया है। इसमें सत्ता पक्ष के 83 माननीय सदस्यों ने और प्रतिपक्ष के दलीय नेताओं समेत 51 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं इन सबका हृदय से अभिनन्दन करता हूं। महोदय, जब हम लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो वास्तव में हमें पिछले 06 वर्षों की इस यात्रा को जरूर देखना होगा। आज से लगभग 06 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आवाह्न पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के अन्दर सत्ता परिवर्तन करने का कार्य किया था।

सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप 2017 से ले करके 2022 तक, इन 5 वर्षों में सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अन्दर कार्य किया और जनार्दन का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सरकार ने फिर से पूर्ण जनादेश प्राप्त करके अपना यहाँ पर बजट प्रस्तुत भी किया। मैं अपने सहयोगी वित्त मंत्री, श्री सुरेश खन्ना जी को धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके अपना बजट प्रस्तुत किया और प्रदेश के अन्दर एक सर्वसमावेशी, समग्र विकास की अवधारणा को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला, हर एक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की भावी तस्वीर क्या होनी चाहिए, इसके लिए भी अपना बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अन्दर बजट का जो आकार है, यह दुगने से अधिक बढ़ा है। 2016-17 के अन्दर इस प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, वह 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का बजट था और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री, श्री सुरेश खन्ना जी ने इस सदन में अपना 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया तो इस बजट का आकार इस समय दुगने से अधिक, 06 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश की जी0डी0पी0 में हुई लगभग दुगनी प्रगति को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है, वह जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है। जहाँ पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है, कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, हर एक तबका अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है।

सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए। समस्याओं से मुँह मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत् कार्य भी कर सके और मुझे यह बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले

6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने पूरा किया है। मैं कल यहाँ पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वह अपनी बात को कह रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वह कह रहे थे तो उन्हें इस बात की प्रसन्नता हो रही थी, उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर ढकेलने पर मान्यवर, उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था। वर्ष 2017 के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था। हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है हर समस्या के दो समाधान होते हैं। हर समस्या के दो समाधान भाग लो या भाग दो या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुये उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसे समाधान के स्तर पर पहुंचाओ। जैसे कि 6 वर्ष के अन्दर किया गया है। दूसरा है जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। यह केवल यहीं पर नहीं हुआ है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, भागे नहीं हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपका भी बहुत सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी सम्मान करते हैं। उनको वहाँ सम्मान मिले या न मिले हम तो उनका सम्मान करते हैं। इसलिए आखिर प्रदेश के प्रति हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है। यह 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सब इस सदन में बैठे हैं और यह जिम्मेदारी भी सामूहिक है लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही का परिचय दिया। कल नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, अगर आप दावोस गये होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया है कि प्रस्ताव आ रहे हैं लेकिन यह जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आये हैं। यह भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। यह उसी का प्रतीक है क्यों नहीं आता था वर्ष 2017 के पहले। वर्ष 2013 के उस वाक्या को दुनिया थोड़ी भूली होगी। जब कुंभ के बारे में प्रेजेंटेशन करने के लिए हावर्ड विश्वविद्यालय गये थे और चच्चा जान को तलाशी से गुजरना पड़ा था उसके बाद वह लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाये। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी। हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था। किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया होता लेकिन इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वायदे किये थे उन सबको भी उसमें समाहित किया है। वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव के पहले लोकल्याण संकल्प-पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किये थे कुल 130 संकल्प थे अब आप लोग भी वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा-पत्र घोषित करते थे। घोषणायें बड़ी-बड़ी होती थी लेकिन वह कभी पूरी नहीं होती थी। एक घोषणा आप लोगों ने की थी। मान्यवर, अगस्त 2016 में रेयोडिजेनेरियों, ब्राजील

में आयोजित ओलम्पिक गेम्स देश के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए घोषणा हुई थी कि उन्हें हम एक-एक करोड़ रुपया देंगे। अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी लगभग छः माह गुजर गए, खैर मार्च में जनता ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि कुछ कर सकें। बैडमिंडन में सुश्री पी0वी0 सिंधू, कुश्ती में सुश्री साक्षी मलिक, जिमनास्टिक में सुश्री दीपा करमाकर। इन तीनों खिलाड़ियों के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन उनको राशि नहीं मिल पाई। जब हमें इसकी जानकारी मिली कि घोषणा राज्य शासन की है, तो 26 जनवरी, 2018 को इन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने वह राशि उपलब्ध करायी। आप लोग घोषणा के अलावा करते क्या थे ?

हम लोग संकल्प करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर ही हम लोगों ने कार्य प्रारम्भ किया है। गत् वर्ष और इस वर्ष में सरकार गठित होने के बाद से ले करके 130 में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई)। इसके लिए 64 हजार 7 सौ करोड़ रुपये की धनराशि बजट में की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के अन्दर उन सभी योजनाओं को, जो प्रदेश के अन्दर गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए और उनके हितों के लिए लोक कल्याण पत्र, इस संकल्प-पत्र की भावनाओं के अनुरूप होगा। उसके लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था भी इस संकल्प-पत्र में की गयी है।

मान्यवर, हमारे संकल्प-पत्र को जो कल यहाँ मा0 नेता विरोधी दल प्रस्तुत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में भी उचित होगा कि हम आपको बता दें और याद कर सकेंगे, तो अच्छा होगा। याद होना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। महोदय, वित्तीय प्रबन्धन कैसे होना चाहिए और किस रूप में पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी, उसमें कैसे हर तबके के लोग लिप्त थे ? कैसे प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने आपको मिलेंगे ? कई एक के रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जाँचे चल रही हैं, उसमें भी मिलेंगे। मेरे पास एक है नोएडा का, यमुना एक्सप्रेस-वे एथारिटी। हाऊ येडा वेन्ट फ्राम सिक्स फोरटी टू करोड़ लॉस इन 2016 टू रिकार्ड प्राफिट इन जस्ट सिक्स इयर्स। यानी, 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपये के लॉस तक गया और पिछले छः वर्ष के अन्दर कैसे वह रिकार्ड प्राफिट की तरफ गया है, यह आपके सामने उदाहरण है ? ये लोग क्या बात करते थे कहते थे कि नोएडा अगर कोई मुख्य मंत्री जायेगा, तो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता है ? जब मैं नोएडा गया था, तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे कि अब तो पक्का मान लिया कि दोबारा सत्ता में ये नहीं आएंगे। मैंने कहा कि डंके की चोट पर दोबारा सत्ता में आऊंगा (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)। अगर ये थोड़ा देखे होते, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है और आप कैसे कर रहे थे ? वर्ष 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वह कुल 86 हजार करोड़ रुपया था और इस बार

का जो वित्तीय वर्ष अभी 2022-23 चल रहा है, 31 मार्च तक। 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं वह 2 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। कहां 86 करोड़ और कहां 2 लाख 20 हजार करोड़ और आप दोगुने की बात कर रहें हैं, यह दोगुने से भी ज्यादा है। सेल टेक्स में जो आज जी0एस0टी0 के रूप में रेवेन्यू आया है, आपके समय वर्ष 2016-17 में यह केवल 49 हजार करोड़ से लेकर 51 हजार करोड़ रुपया आ पाता था और आज वर्ष 2022-23 में इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक को पार करने जा रहा है। एक्साइज में जगह-जगह हर जनपद में इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को वर्ष 2016-17 में कुल 12 हजार करोड़ रुपया मिला था और इस बार वर्ष 2022-23 में 45 हजार करोड़ रुपये मिलने जा रहा है। यह पैसा किसके पास जाता था, ऐसे ही थोड़े कोई इंग्लैंड में होटल खरीद रहा है और ऑस्ट्रेलिया में टापू, यह सब प्रदेश को लूटकर खरीदा गया है। महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सर प्लस स्टेट है, हमारे पास आज जो बढ़ा हुआ राजस्व है, यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है, गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, माता और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए यह इन सबके कल्याण का भी आधार बन रहा है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी यह आधार बन रहा है। रेवेन्यू सर प्लस यू0पी0 जैसे स्टेट में जिसको आपने बीमारू बना दिया था, आज वह बीमारू से उभर चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है और मैं कह सकता हूं अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए, उत्तर प्रदेश नम्बर 2 की अर्थव्यवस्था होगी और अगले 5 वर्ष के बाद देखना, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। महोदय, यह तब हुआ है जब हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में कोई अतिरिक्त टैक्स प्रदेश की जनता जनार्दन पर नहीं लगाया है। पेट्रोल और डीजल के दाम अगल बगल के स्टेट में जाकर देखिये, यू0पी0 में दाम सबसे कम है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब, हर उपभोक्ता वस्तु का दाम बढ़ जाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज जी0एस0टी0 देने के लिए, हमारा व्यापारी बन्धु उतावला है, व्यापारी कहता है कि साहब हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 26 लाख से अधिक व्यापारियों ने वर्तमान में जी0एस0टी0 में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और यही नहीं वह रजिस्ट्रेशन लगातार कर रहा है तथा सरकार ने भी हर एक व्यापारी को 10 लाख रुपये की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया है। महोदय, यह तब है जब हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी और उसमें इस महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अन्दर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन तथा सभी चीजें उपलब्ध करायी गयीं। गरीबों को, कमजोर तबके के लोगों को, स्ट्रीट वेंडर को भरण पोषण भत्ता, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को स्किल मैपिंग के साथ-साथ उन्हें समायोजन करने की व्यवस्था, इन सबको करने के बावजूद भी आज प्रदेश एक अच्छी दिशा में

आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बैंकों से लोन ले लेंगे। वित्तीय संस्थाओं के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। एफ0 आर0 बी0 एम0 एक्ट की जो लिमिट है उसके अन्दर ही उत्तर प्रदेश की वर्तमान की व्यवस्था है और राजकोषीय घाटे को हमने उसके दायरे में सीमित रखा, यह प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन का एक नमूना भी है। इतनी बड़ी आबादी को कोविड-19 जैसी महामारी का सामना करते हुए, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए, यह वित्तीय प्रबन्धन का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है। जिसके लिए विपक्ष को सरकार की सराहना करनी चाहिए थी।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

आखिर जो टेस्ट हुए वह किसी की जाति देखकर हुये थे क्या ? क्या वैक्सीन किसी की जाति देखकर लगाये गये थे ? राशन किसी की जाति देखकर वितरित की गयी थी क्या ? नहीं, यह तो सबके लिए था। सबका साथ, सबका विकास यही तो है। यह वही मूर्त रूप है योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, सब तक लाभ पहुँचाने का काम किया गया है और उस सीमा तक हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। कल मैं नेता विरोधी दल के भाषण को सुन रहा था, कैसी बात कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर खन्ना जी के बजट भाषण में शेरो-शायरी पर भी काफी टिप्पणी की। राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता को वो भले ही पढ़ नहीं पाये हों, लेकिन खन्ना जी की शेरो-शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे, टिप्पणी करने से उन्हें बचना चाहिए था। जाति की बात कर रहे थे-

जाति, हाय री, जाति, कर्ण का, हृदय क्षोभ से डोला।
कुपित सूर्य की ओर देख, वह वीर क्रोध से बोला।।
जाति-जाति रटते, जिनकी पूँजी केवल पाखण्ड।
मैं क्या जानूँ जाति ? जाति हैं, ये मेरे भुजदण्ड।।

(मेजों की थपथपाहट)

महोदय, कल मैं देख रहा था, प्रयागराज की घटना को ले करके पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे। पूरी घटना का जो साजिशकर्ता है उसकी फोटो कल वायरल हो रही थी और कोई उससे भाग भी नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी किया जा सकता है। अरे! हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिम्बल लगा हुआ है तब भी आप उससे मुँह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। (शेम, शेम) जो उमेश पाल मारा गया था क्या उसकी कोई जाति नहीं थी, सन्दीप निषाद जो हमारा कांस्टेबिल मारा गया क्या उसकी कोई जाति नहीं थी ? यानि आप जाति का ठेका ले चुके हैं लेकिन किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी अति पिछड़े को ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर मरवायेंगे। (शेम, शेम) यह क्या तमाशा है ? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जांय, यह बड़ी अजीब सी बात है। राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या ? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और

माफिया के संरक्षणदाता कौन थे ? माननीय अध्यक्ष जी, राजू पाल का यही था ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति-जाति की बात करते हैं मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था कि जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेकर आते हैं। हम गरीब कल्याण की बात को करते है तो आप जाति के मुद्दे को लेकर आते हैं। हम प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते है तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं हँसते है अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा। अरे यू0पी0 आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। हम लोग इस बात को मानते है कि 'है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।' यह होगा 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। जरूर बनेगी इसमें किसी को भी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए है। लेकिन मुद्दे को भटकाने का प्रयास कैसे होता है एक और नमूना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे थे न 2012 से 2017 के बीच में क्या हुआ था यह तो हर व्यक्ति जान ही रहा है। लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे उस समय इक्कीस लाख इक्कीस हजार छह सौ उन्तीस छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी और जब हमारी सरकार आई मार्च, 2017 में तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया था। उन बच्चों की क्या गलती थी। इसमें तो पूरा पैसा भारत सरकार देती है लेकिन बहुत सारी जैसी योजनाओं में अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा। यही लोग जो गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, कमजोरों का, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे वही जब कुछ नहीं चलता है तो फिर जाति जाति जाति यह सब चलाने लगते हैं। यह बड़ी विचित्र सी स्थिति है कोई मुद्दा न मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का काम होता है और यही तो हो रहा है यही करने का प्रयास हुआ है। प्रदेश के अन्दर वित्तीय प्रबन्धन का और नमूना मैं देता हूं 2016-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें राज्य के जो अपने रेवेन्यू थे कुल सोर्स थे उसमें से केवल तैंतीस फीसदी का ही उपयोग हो पाया है यानी तैंतीस फीसदी ही उसमें योगदान कर रहा था और आज जब श्री सुरेश कुमार खन्ना जी वर्ष 2023-24 के बजट को प्रस्तुत करते हैं इसका कंट्रीब्यूशन 44 परसेंट है, चौवालीस फीसदी है। वर्ष 2016-17 में ऋणों से बजट का जो वित्त पोषण होता था वह 20 फीसदी था और वर्ष 2023-24 में यह घटकर के आज मात्र 16 फीसदी रह गया है यानी यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुये कदम हैं। पहले पूर्व के बजट की 08 प्रतिशत राशि तो ऋणों के ब्याज में ही चुकता हो जाती थी, आज वह घटकर लगभग साढ़े छः फीसदी पर आया है। वर्ष 2022-23 में यह साढ़े छः फीसदी पर आ गया है, इसको और

कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बजट का दायरा बढ़ा है और हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, प्रदेश के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा रोजगार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, अगर हम वर्ष 2016-17 की तुलना में देखें तो यह दोगुने से अधिक बढ़ा है। प्रदेश के अन्दर आज 01 लाख 47 हजार करोड़ रुपये की राशि केवल कैपिटल एक्सपैन्डिचर पर ही खर्च होगी। यह एक बड़ी राशि है। पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक राशि है। नेता विरोधी दल कल ओ0डी0ओ0पी0 की बात कह रहे थे। यह 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' है जिसने यहाँ के परम्परागत उत्पाद को, एम0एस0एम0ई0 को एक नया जीवन दिया है और एम0एस0एम0ई0 को नया जीवन देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश वर्ष 2016-17 की तुलना में दोगुने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा 01 लाख 56 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का एक्सपोर्ट केवल वर्ष 2021-22 में ही पहुँच चुका है। यह सच है कि आप ओ0डी0ओ0पी0 तो नहीं दे पाये, लेकिन 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' आपने जरूर दे दिया था। (सत्ता पक्ष द्वारा सदन में हँसी) कौन सा जिला ऐसा था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ हो। कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे और आम उत्तर प्रदेश वासी इस बात को जानता है, आम उत्तर प्रदेश वासी इस बात को कहता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारी इस सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' की जो अभिनव योजना प्रदेश की एम0एस0एम0ई0 को देश और दुनिया के अन्दर एक नयी पहचान दिलाने के लिये प्रस्तुत की थी आज वह दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना से जुड़ी हुयी कोई एक प्रतिकृति उपलब्ध करवाते हैं तो वह कलाकार, वह हस्तशिल्पी, वह कारीगर भी गौरवान्वित होता है। उसका बिजनेस वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। जियो टैग मिल रहे हैं। मार्केट में ओ0डी0ओ0पी0 छा रहा है। यह यूनियन बजट का पार्ट बनता है। इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय हम इसकी तौहीन करें, यह तो हम अपने हस्तशिल्पियों का, अपने कारीगरों का अपमान कर रहे हैं, हम लोग उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। हमें तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिये, वह हमारी उपलब्धि है, हमारी विरासत का हिस्सा है। आपके लिये वह जाति का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे लिये यह एक हस्तशिल्पी, एक कारीगर की कला का, उसके हुनर का सम्मान है और उसको सम्मान देने के लिये हम लोगों ''वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'' सहित अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की हैं। इसकी हम चर्चा भी करेंगे।

महोदय, इस बजट में जो व्यवस्था की गयी है, अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग कार्य किए गये हैं, और इसमें खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 2012 से 2017 के बीच में जो बैंकिंग व्यवसाय था वह कुल 12 लाख

79 हजार 995 करोड़ रुपये का हुआ था, और 2017 से 2022 के बीच में यह बढ़कर 22 लाख 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हुआ है। बैकिंग व्यवसाय में बैंकों की जो पूँजी जमा हुई है उसमें से कितना पैसा यहां के यूथ को, यहां के उद्यमियों को लोन के रूप में मिला है जो पहले 2017 में मात्र 46 फीसदी था आज यह बढ़कर लगभग 55 फीसदी अधिक हो रहा है। 2017 से 2022 के बीच में 9 लाख 52 हजार से अधिक का ऋण भी वितरित हुआ है। यानी एक वह तस्वीर सबके सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की उन नौजवानों के आकांक्षाओं को पूर्ति करने का माध्यम कैसे बैंक वित्तीय संस्थाएँ बन रही है उसकी एक झलक यह प्रस्तुत करता है, यह रोजगार का सृजन करता है यूथ के मन में एक विश्वास भरता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करता है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, राज्य के श्रम शक्ति का सम्मान करता है और अर्थव्यवस्था में भी सन्तुलन लाने का कार्य करता है। भविष्य में और अधिक उत्पादन करने की क्षमता को भी आपके प्रोटेन्शियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज यह प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसी के लिए आज हम लोगों ने जब यहां पर चर्चा हुई, चर्चा होने लग गयी कि आखिर कैसे इस वन ट्रिलियन की बात कर रहे थे। 1946 की घटना है जब भारत के संविधान निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। पहली बैठक थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अपना भाषण दिया था वह बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। उन्होंने उस समय कुछ बात कही थीं, उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि 'इति' को लेकर नहीं 'अति' को लेकर चिन्ता होनी चाहिए। अर्थात् लक्ष्य साफ है प्रश्न है उसे पाने के लिए शुरूआत कैसे करें ? 'इति' को नहीं बल्कि 'अति' को लेकर चिन्ता होनी चाहिए। यानी शुरूआत कैसे होनी है ? शुरूआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा आएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हर भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। अपार श्रद्धा का भाव रखता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बात उस समय कही थी उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अन्दर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में, क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर प्रदेश कैसे इस भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

5 ट्रिलियन की इकॉनमी अगर भारत को बनना है तो क्या उत्तर प्रदेश को अपनी आबादी के हिसाब से कन्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए ? आज हमारा योगदान क्या है ? हर सोलहवां सत्रहवां व्यक्ति देश का उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है लेकिन क्या हमारा कान्ट्रीब्यूशन उतना है। भारत की जी0डी0पी0 में उत्तर प्रदेश का योगदान अभी तक मात्र 8 फीसदी है। इसको बढ़ाकर 16 से 20 फीसदी तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चला है, यह अवश्य होगा। यू0पी0 के अन्दर सम्भावना है। उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारम्भ किया। नेता विरोधी दल तो कल इसी पर प्रश्न लगा रहे थे। प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहे थे। क्या यह सम्भव हो पायेगा ? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसी बात

कर रहे है ? क्यों नहीं हो सकता है ? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है ? देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। देश का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। अगर दुनिया के अन्दर सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे अच्छा यूथ भारत के पास है तो भारत में वह क्षमता यू0पी0 के पास है। यू0पी0 सबसे अच्छा यूथ भी रखता है। सबसे बड़ा श्रम बाजार भी है और युवा शक्ति को भी रखता है। 96 लाख एम0एस0एम0ई यूनिट यू0पी0 के पास है। यू0पी0 की कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर वेज हर प्रकार की कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश के पास है। कल मैं सोच रहा था कि नेता विरोधी दल यह न बोल दें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर हम बना रहें हैं या हमने शुरू कर दी थी। खैर हो सकता है, भूल गये हों अगले भाषण में फिर बोल देंगे। सोलह हजार किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क यू0पी0 के पास है और फेट कॉरीडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। इनलाइन वॉटर वे वाराणसी से हलदिया के बीच अभी 13 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लम्बे रिवर्ज ब्रिज का शुभारम्भ किया। उत्तर प्रदेश के अन्दर एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। व्यापक सम्भावनायें है और इसलिए हम इस बात को मान सकते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 टी का मन्त्र दिया। टैलेन्ट, ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म, टैक्नालॉजी। इसको प्रदेश के अन्दर विस्तार दिया जा रहा है। हर फील्ड में देख रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश के अन्दर एक्सप्रेस हाई-वे ही नहीं आई वे भी है। ब्रॉड बैंड आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर भी फोकस किया जा रहा है। सभी 58 हजार ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण करके सभी स्कूल कालेज को भी इन सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्यवाही की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। इसमें तो हर एक को खुश होना चाहिए। हमारे पास स्केल भी है और स्किल भी है। 6 वर्ष में स्पीड भी बढ़ी है। यह भी उत्तर प्रदेश के पास है।

मान्यवर, प्रदेश के इस सम्भावना का लाभ अब उत्तर प्रदेश को कैसे प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के माध्यम से देश को कैसे प्राप्त हो इन सभी पर ध्यान देने के लिए ही हमने कार्य प्रारम्भ किया है और मैं बार-बार कहता हूं देश की कृषि योग्य भूमि 11 से 12 फीसदी हमारे पास है लेकिन खाद्यान्न उत्पादन 19 से 20 फीसदी उत्तर प्रदेश करता है और मेरा मानना है अभी इसमें 3 गुना अधिक क्षमता है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल गाजीपुर, राजघाट, रामनगर, प्रयागराज में भी टर्मिनल बनाने की कार्रवाई प्रारम्भ हुई है और पोर्टिंग टर्मिनल बनाने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है जिससे यहां के उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में व्यवस्था दे सके। दादरी में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और बोड़ाकी में भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किया जा रहा है। वाराणसी में सौ एकड़ भूमि में फ्रेट विलेज विकसित किया जा रहा है और प्रदेश के अन्दर इन बाउंड और आउट बाउंड लोगों के लिए ट्रांन्शिपमेंट हब के रूप में यह कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश की सभी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने 1 ट्रिलियन डालर की इकोनामी की दिशा में कार्यक्रम को आगे

बढ़ाया है। उसमें हम लोगों ने दस सेक्टर चिन्हित किये हैं जिस पर लगातार कार्य चल रहा है। मैं तो चाहता था कि इस सदन में 1 ट्रिलियन डालर की इकोनामी पर चर्चा हो और होनी भी चाहिए लेकिन हमारे सहयोगी दलों के लोग तो आयेंगे लेकिन सस्टेनेबुल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा हुई थी तब समाजवादी पार्टी सदन से वॉक आउट करके भाग गयी थी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गरीबी उन्मूलन और सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, अन्नदाता किसानों का हो उत्थान, मातृ शक्ति को मिले सुरक्षा की गारंटी, फाईनेंस इनक्लूजन इन सभी मुद्दों को लेकर के दिया और 36 घण्टे तक इस सदन में चर्चा हुई लेकिन शिवपाल जी को छोड़कर बाकी सपा गायब थी और उनकी कभी-कभी रुचि डेवलपमेंट पर है लेकिन बाकी सपा गायब थी और इसलिए चुनाव में जनता ने भी इनका सफाया कर दिया। यह 10 सेक्टर जो हमने चिन्हित किये हैं उत्तर प्रदेश के इसी पोटेंशल को ध्यान में रखकर किये हैं। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश उसे अचीव करेगा और जो टारगेट तय किये गये हैं वह अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि कोविड़ कालखंड ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और हमारी स्पीड को भी प्रभावित किया है लेकिन बिना रुके बिना डिगे फिर भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। जिसमें पहला सेक्टर है कृषि का कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, रेशम विकास, लघु सिंचाई, भू-गर्भ सिंचाई, सिंचाई और जल संसाधन, सहकारिता यह सभी सेक्टरों को एक साथ जोड़ा गया है।

दूसरा सेक्टर है अवस्थापना और औद्योगिक विकास का विकास के साथ-साथ एम0एस0एम0ई0, हथकरघा और वस्त्र उद्योग, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स नागरिक उड्डयन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, चाहे वह लोक निर्माण विभाग के हों, या एक्सप्रेस हाई-वे के हों, खादी ग्रामोद्योग, एन0आर0आई0 और संस्थागत वित्त इस सेक्टर में रखे गये हैं। सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण से जुड़े हुये महिला कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण सशक्तीकरण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, श्रम एवं सेवायोजन, खाद्य एवं रसद यह सभी इस सेक्टर में रखे गये हैं जिस पर कार्य चल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेक्टर में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, बाल विकास एवं पुष्टाहार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन यह सभी इस सेक्टर के अन्दर कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य विकास सेक्टर में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे एवं जलापूर्ति, राजस्व और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा यह सभी इस सेक्टर के अन्दर कार्य कर रहे हैं। नगरीय विकास सेक्टर में आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण तथा वन, वन्य जीव यह सभी इस सेक्टर के अन्दर कार्य कर रहे हैं। पयर्टन और संस्कृति सेक्टर में संस्कृति, पयर्टन, धमार्थ कार्य, भाषा आदि इस सेक्टर में हैं। शिक्षा के सेक्टर में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी और युवा कल्याण से जुड़े हुये सेक्टर हैं। राजस्व संग्रह में जिसमें जी0एस0टी0 है, कर एवं निबन्धन है, आबकारी है,

परिवहन, भू-तत्व एवं खनिकर्म है, विविध सेक्टर में गृह, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक विभाग और होमगार्ड इत्यादि हैं। प्रत्येक सेक्टर की बहुत क्लोज मानीटरिंग हो रही है। उसके टारगेट फिक्स किये गये हैं और उस पर लोग निरन्तर कार्य कर रहे हैं। मैं सेक्टरवाइज चर्चा करूँगा क्योंकि कुछ सेक्टर पर इसके बाद चर्चा भी होने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में फैमिली आई कार्ड की घोषणा हुई है। हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने के एक महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम प्रत्येक परिवार की मैपिंग कर रहे हैं और इस दिशा में हमारा कार्य लगातार जारी है और बहुत शीघ्र ना केवल रोजगार अथवा स्वरोजगार अपितु शासन की उन योजनाओं से जोड़ने जैसे राशन कार्ड किसके पास है, आवास की सुविधा की क्या स्थिति है, शौचालय की स्थिति क्या है, विद्युत कनेक्शन की क्या स्थिति है, उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है, पेंशन की क्या स्थिति है, किन-किन योजनाओं से परिवार आच्छादित है और उनकी क्या आवश्यकतायें हैं। बिना किसी भेदभाव के कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, बल्कि हर प्रदेशवासी के लिए फैमिली आई कार्ड की घोषणा इस बजट में की गई है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की स्पीड को देखना है तो नीति आयोग ने देश में 112 आंकाक्षात्मक जनपद चिन्हित किए थे। यह वह जनपद थे जो विकास की दौड़ में पिछड़ गये थे उनमें से 08 यूपी के भी थे। चार जनपद नेपाल सीमा से जुड़े हुये थे जिनमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच और शेष चार जनपद थे चन्दौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर। इन 08 जनपदों में 75 इण्डिकेटर्स के साथ कुछ पैरामीटर तय किए गए थे जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, स्किल डेवलपमेण्ट, रोजगार, वित्तीय समावेशन था जिन पैरामीटर्स पर कार्य होना था। उस पर कार्य करते समय 2017 के पहले की तस्वीर और 2017 के बाद की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। मुझे पूरे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नीति आयोग के द्वारा जो पैरामीटर तय किये गये थे देश के अन्दर 112 जनपदों में जिन 10 जनपदों ने विकास की रफ्तार को सामान्य जनपदों की तर्ज पर आगे बढ़ाया है उन 10 जनपदों में 10 में से 5 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और टाप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी आठ के आठ जनपद हैं और उसी फार्मूले को अपनाते हुये हम लोगों ने आज विकास खण्डों की तरफ भी इस यात्रा को प्रारम्भ कर दिया है। खण्डित विकास खण्ड को एस्प्रेशनल विकास खण्ड की उन्हीं पैरामीटर उन्हीं इंडीकेटर्स के आधार पर चिन्हित करते हुये उनको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की व्यवस्था है। बजट में 100 नगर निकायों की भी घोषणा हुयी है। हम सब जानते हैं कि पिछले पांच-छह वर्ष के अन्दर नगर निकायों की संख्या बढ़ी है। आज 762 नगर निकाय हैं। इन 762 नगर निकायों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अभी-अभी नये नगर निकाय बने हैं। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि नगरीय सुविधा का लाभ हमें भी मिले और मिलना भी चाहिए। यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह वहाँ की जनता को उनका हक दे उनका अधिकार दे उनकी भावनाओं के अनुरूप वहाँ पर

उनके विकास की बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य करे और पहली बार 100 नगर निकाय को चिन्हित करने के लिए भी बजट की व्यवस्था की गयी है। जिसमें हम उनको चिन्हित करेंगे। स्मार्ट सिटी से अलग है, अमृत योजना का अलग है, पं0 दीनदयाल उपाध्याय की नगरीय विकास योजना का अलग है और 100 नगर निकाय जो अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर आये हैं लेकिन उनके मन में चाहत है कि मैं भी विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ सकूं। उन पर भी पैरामीटर तैयार करते हुये हम आगे कार्य करने जा रहे हैं। बजट का प्राविधान इसके लिये भी किया गया है।

महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर हर जनपद की भी अपनी जी0डी0पी0 होगी। प्रदेश की जी0डी0पी0 तो है। मैं पूरे सदन का अभिनन्दन करूंगा कि उसकी शुरूआत आप लोगों ने कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के हर जनपद में आयोजन करके शुरूआत कर दी है कि विकास की चाहत हर जनपद की है और विकास हर जनपद का होना चाहिए। यह पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के अन्दर निवेश के प्रस्ताव आये हैं। एस्प्रेशनल विकास खण्डों का अगर हम डाटा देखेंगे तो जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का शुभचिन्तक होगा उसका हृदय प्रफुल्लित होगा। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर, सोनभद्र, चन्दौली इन जनपदों में भी नये निवेश के प्रस्ताव आये हैं। यह निवेश विकास और रोजगार का भी सृजन करता है और यह जी0डी0पी0 के निर्माण की कार्रवाई है। सेक्टोरियल और प्रोसेक्टोरियल बेस्ट प्रेक्टिसेस को भी एकत्रित किया जा रहा है। इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके माध्यम से प्रदेश की इकानॉमी को बूस्टअप करने की दिशा में एक नया प्रयास है। महोदय इसमें जो सबसे बड़ी बात है। जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुये 33-35 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुये हैं। यह केवल एक क्षेत्र विशेष में नहीं हैं। मैं कह सकता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही 10 लाख करोड़ के प्रस्ताव आये हैं। बुन्देलखण्ड में भी 4 लाख 29 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और सभी 75 जनपदों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन को भी दूर करने में मदद करेगा। ईज आफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धि है वह हर व्यक्ति जानता है कि 14 से नम्बर दो पर आना देश के अन्दर इस स्पीड को और तेजी के साथ हर सेक्टर को रिफार्म करते हुये आज जिस दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है वह एक अच्छा प्रस्ताव है और मैं इसलिए आज के इस अवसर पर जो हमने सेक्टर चिन्हित किये हैं।

मान्यवर, आज के अवसर पर हमने जो सेक्टर चिन्हित किए हैं, मेरा मानना है कि जो 06 लाख 90 हजार करोड़ रुपए का बजट है, यह उत्तर प्रदेश की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप एक सर्व-समावेशी समग्र विकास की आधारशिला के साथ ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के आधार को रख रहा है, उत्तर प्रदेश को एक स्पष्ट दृष्टि दे रहा है और उसका पूरा प्राविधान इस बजट में किया गया है। मैं इसके लिए मा0 वित्त मंत्री जी एवं उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो अलग-अलग सेक्टर चिन्हित है, वन ट्रिलियन डॉलर के लिए और उसका

किस रूप में यहां पर किया गया है। आप देखेंगे कि वर्ष 2017 के पहले क्या था। चीनी मिलें औने-पौने दाम पर बिक रही थीं या फिर बन्द हो रही थीं। किसान की आय बढ़ने का कोई भी प्रयास नहीं, किसान आत्महत्या करने को विवश थे, फसल खरीदने में दलालों का हस्तक्षेप था। कृषकों हेतु दोषी मण्डी में उत्पाद विक्रय के प्राविधान नहीं थे। मण्डी परिसर के बाहर विक्रय पर प्रतिबन्ध था, मण्डी यार्ड के बाहर किसी उत्पाद के विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबन्ध था और मण्डी शुल्क की दर एक-दो प्रतिशत थी और हर व्यक्ति परेशान था। वर्ष 2017 के बाद अगर आपको देखना है तो अन्नदाता किसान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है, सरकार का पहला बजट ही अन्नदाता किसान को समर्पित था, हमने पहले ही कैबिनेट की बैठक में किसानों के 36 हजार करोड़ रुपए के कर्जमाफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और 86 लाख किसानों को इसका लाभ दिया गया था। प्रदेश की जी0डी0पी0 में आज भी एग्रीकल्चर का 26 फीसदी योगदान है। यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में फोकस करना ही था और राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कृषि विकास की दर अगर हम स्थिर मूल्य के आधार पर देखेंगे तो वह लगभग तीन गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसम्बर, 2018 से प्रारम्भ हुई थी, इसमें 51,639.68 करोड़ रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे-सीधे पहुंचा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज की आवश्यकता क्या है, विष मुक्त खेती, कैंसर, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर के जो मामले आ रहे हैं और असमय हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं। यह क्षमता से अधिक केमिकल, फर्टीलाइजर एवं पेस्टिसाइड का उपयोग करने का दुष्परिणाम है। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज कृषि विभाग ने इस पर कार्य प्रारम्भ किया है। अभी हमारे कृषि मंत्री इस पर विस्तार से बतायेंगे कि जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती क्या है, उन्होंने कितनी कार्यशालाएं की हैं, कैसे इसका विस्तार दिया है, हम हर कमिश्नरी हेड क्वार्टर पर लैब की स्थापना कर रहे हैं, कैसे अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाने और विष मुक्त खेती से हम एक किसान की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त्र कर सकते हैं, इस पर कार्य प्रारम्भ हुआ है। वर्ष 2017 के पहले सिंचाई की स्थिति क्या थी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना वर्ष 1972-73 में इस परियोजना के बारे में योजना आयोग ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया था और यह वर्ष 2017-18 तक भी नहीं बन पाई थी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने 105 किलोमीटर तक बनवा दी थी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए मुझे तो अच्छा लगा कि मा0 शिवपाल जी आपको याद है। आपकी इस सद्भावना के लिए और ईश्वर करे आपकी याद्दाश्त बनी रहे। मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। लेकिन बाणसागर...

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बाणसागर की भी मैंने बनवायी थी। (हंसी)

श्री योगी आदित्यनाथ-

बाणसागर आपसे पहले प्रारम्भ हो गयी थी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

और बताइए, मैं और बता देता हूं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आ रहा हूं। (हंसी) बाणसागर में, अर्जुन सहायक में...

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अर्जुन सहायक में हमने करीब-करीब 50 प्रतिशत काम करा दिया था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप करीब-करीब ही कर पाये थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि आप पूरा करा ही नहीं पाएंगे, इसलिए जनता ने हमें चुन लिया था।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अगर 6 महीने पहले यह विभाग नहीं हटता तो सब हम ही करा दिय होते। (हंसी)

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपके साथ अन्याय तो जरूर होता है, सचमुच। (हंसी) व्यवहारिक चीज यह है कि आप जमीन पर संघर्षों से बढ़े हैं इसलिए आपको संघर्ष की कीमत भी मालूम है और सचमुच अगर यहां पर होते (नेता प्रतिपक्ष की सीट की तरफ इशारा करके) तो तस्वीर कुछ और होती,

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जब जागो तभी सवेरा। (हंसी) हम आपके सम्पर्क में भी बहुत रहे, तीन साल सम्पर्क में रहा हूं। (हंसी) अभी भी हमारा सम्पर्क है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आपको तो सब पता है। (हंसी)

श्री योगी आदित्यनाथ-

इन लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। (हंसी) देखिए, हम लोग संघर्ष को हमेशा सम्मान देते हैं और संघर्ष व्यक्ति को करना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन वर्ष 2017 से लेकर 2022 के बीच में सिंचाई की 20 से

अधिक परियोजनाएं हम लोगों ने पूरी कीं और जिनसे अन्नदाता किसानों को जल उनके खेत के लिए मिलना प्रारम्भ हुआ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, 11 डैम मैंने बुंदेलखण्ड में और बना दिये थे और 100 तालाब खुदवा दिये थे, ये भी तो बताइए। (हंसी)

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप करना चाहते थे, आपको करने नहीं दिया गया। जितना पैसा हम दे रहे हैं उतना पैसा आपको दिया गया होता तो आप कर सकते थे।

श्री इकबाल महमूद-

आपकी तो डबल इंजन की सरकार है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

डबल इंजन की सरकार तो सबके लिए है। महोदय, इससे लगभग 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर जमीन को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा, अगर मैं अन्नदाता किसानों की तरफ बढ़ूं, वर्ष 2012 से 2017 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है, शिवपाल जी अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, देख लेना कि डबलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। वर्ष 2012 से 2017 के बीच 94 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीद, 12 हजार 800 करोड़ रुपये का भुगतान, मीडिएटर के माध्यम से ही हुआ है, एजेंट के माध्यम से हुआ है, लेकिन हुआ है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच में 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और 40 हजार 159 करोड़ रुपये का सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भुगतान हुआ है। अब यह 12 हजार 800 सौ करोड़ और 40 हजार 159 करोड़ रुपये में तो तिगुने से अधिक पैसा है यानी अन्नदाता किसान को तीन गुना अधिक दाम मिला है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, लागत भी बता दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

देखिए, एम0एस0पी0 की घोषणा सन् 1967 में हुई थी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मार्केट में ज्यादा दाम था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हां, वह तो हर व्यक्ति जान रहा है। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने एम0एस0पी0 का नया प्रारूप घोषित किया तो उसमें लागत का डेढ़ गुना सीधे-सीधे किसान को मिल रहा है,

एम0एस0पी0 की घोषणा उसी आधार पर हुई है। यह पहली बार मिलना प्रारम्भ हुआ है और यह मोदी सरकार ने दिया है, डबल इंजन की सरकार ने दिया है।

अन्नदाता किसानों को इससे पहले कोई नहीं दे पाया है। 2012 से 2017 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ, 17, 190 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, वह भी एजेण्ट के माध्यम से। 2017 से 2022 में 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ और 50,420 करोड़ रुपये धान के मूल्य का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हुआ है और इस वर्ष भी अब तक 64 लाख 64 हजार मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ है और 13, 192 करोड़ रुपये का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में हुआ है। अगर आप जोड़ेंगे तो यह लगभग तीन गुना से ज्यादा है। देखिए ये अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाने के तरीके हैं और हमारे राष्ट्रीय लोक दल के माननीय सदस्य होंगे और जानना चाह रहे होंगे गन्ना किसानों के बारे में। चौधरी साहब की कर्मभूमि रमाला की चीनी मिल इसी सरकार में बन पायी है। पिछली सरकार को फुर्सत ही नहीं थी। चौधरी साहब के नाम पर वोट लेने के लिए, जैसे डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर वोट लिया जाता है, लेकिन उनके किसी आदर्श को फॉलो नहीं किया जाता। ऐसे ही चौधरी साहब के साथ भी होता था। रमाला चीनी मिल, बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल, गोरखपुर की पिपराइच सब डबल इंजन सरकार के द्वारा ही लगायी गयी हैं। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) और अब तक 01 लाख 98 हजार 434.98 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है और कुल 5800 से लेकर 6000 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का गन्ना मूल्य का बकाया है। 119 चीनी मिलें चलीं, 119 चीनी मिलों में से 100 से ज्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। महोदय, हमारा बुन्देलखण्ड पानी के लिए तरसता था। यह विभाग तो आपके पास नहीं रहा होगा, क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मैंने पारीक्षा में एक डैम बनाया था, बुन्देलखण्ड में पानी पीने के लिए, लेकिन पूरा नहीं किए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, और उस समय 2015-16 में भारत सरकार ने पानी टैंकर भी भेजे थे, लेकिन आप लोगों ने लेने से इन्कार कर दिया था, फिर बाद में वे वापस हुए थे। इस समय बुन्देलखण्ड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही हो रही है। 'हर घर नल योजना' आज साकार रूप ले रही है। शिवपाल जी, आपको थोड़ा वहाँ भ्रमण करना चाहिए, जाकर देखना चाहिए, जरूर जाइये और मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप वहाँ जायेंगे तो अब तक लगभग 82 लाख से अधिक घरों को कनेक्शन दिया जा चुका है और हमारा प्रयास है कि 2024 तक हम लोग प्रदेश के अन्दर 2 करोड़ 26 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं, जिन तक

अब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन परिवारों को हम 'हर घर नल योजना' के माध्यम से शुद्ध और क्वालिटी वाटर की सप्लाई कर सकेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह योजना टंकियों के माध्यम से है, गर्मी के दिन हैं, जो आपकी टंकियाँ बन रही हैं, 10 साल में पानी गाँव में पहुँच पायेगा। बड़े-बड़े मजरे और गाँव सभाएँ हैं, 15-15, 20-20 पुरवे हैं, वहाँ पर टंकियों से पानी नहीं पहुँच पायेगा। हमारा निवेदन है कि वहाँ हैण्डपम्प लगाने की भी व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए। कोई एक-आध विषय हो तो पूछा जा सकता है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

महोदय, हम लोग प्रदेश के अन्दर हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, डबल इंजन सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे परियोजना में कानपुर तो सबके सामने उदाहरण है। कानपुर में सीसामऊ से 14 करोड़ लीटर अपशिष्ट गंगा जी में गिरता था। टेनरीज का अपशिष्ट भी जाजमऊ के पास गिरता था और उसके बाद नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल प्वाइंट था कानपुर। आज सीसामऊ में एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता। एस0टी0पी0 परियोजनाएं स्वीकृत हैं 28 पूर्ण हो चुकी हैं और 17 पर कार्य चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। 7 अन्य परियोजनाओं पर कार्य बहुत शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है। हम लोगों ने वर्ष 2019 में प्रयागराज कुंभ भी किया था, प्रयागराज कुंभ अपनी स्वच्छता, अपनी सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए विख्यात है, प्रयागराज में दुनिया उमड़ पड़ी थी। हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प-पत्र में वर्ष 2023-24 में कृषि के निजी नलकूप में उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में 50 फीसदी की छूट दी और इस बजट में फेजवाइज बढ़ाने के लिए 15 सौ करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि हम उसको 100 परसेण्ट तक पहुंचा सकें वहां तक कार्यवाही हो रही है। पी0एम0 कुसुम योजना 30 हजार सोलर पम्पों की स्थापना की कार्यवाही और सिंचाई की जो परियोजनाएं लम्बित हैं जिन्हें हम लेने जा रहे हैं सहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, कचनौधा बांध, लखेरी बांध इन सब पर हमारा वर्तमान में कार्य चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और इनको भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नीति के लिए भी धनराशि की भी व्यवस्था की गई है और अपने अन्नदाता किसानों को दलहन, तिलहन की मिनी किट उपलब्ध कराने के लिए भी बीज आदि की मिनी किट उपलब्ध कराने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अन्नदाता किसान अत्याधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें। मुझे याद है कि वर्ष 2015-16 में भारत सरकार ने 20 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को कहा, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं लिया। वर्ष

2017 में आने के बाद हमारे कृषि मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव भेजा और हमें मिला। आज प्रदेश के अन्दर हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विद्यालय आपस में एक बेहतर कोलैबरेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों की ट्रेनिंग उनके लिए डिमांस्ट्रेशन अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए भी एक मंच पर सब केंद्र बन रहे हैं और महात्मा बुद्ध के नाम पर कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी सरकार देने जा रही है और इसी बजट में प्राविधान भी किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रोटेक स्टार्टअप और इंक्यूवेशन सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का प्रस्ताव किया गया है कृषि शिक्षा के लिए भी और उसके उन्नयन के लिए भी टिशू कल्चर प्रयोगशाला के लिए सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। गो-आश्रय स्थल के लिए भी मैंने पिछली बार विस्तार से इसके बारे में बताया है। दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति वर्ष 2022 के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन नीति की व्यवस्था की गई है। मुख्य मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना निषादराज बोर्ड सब्सिडी योजना इन सबके लिए भी व्यवस्था की गई है और जल जीवन मिशन, हर घर नल के लिए भी वर्ष 2022-23 के बजट में 19 हजार 5 सौ करोड़ और 2023-24 के बजट में 21 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को हम आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय बाढ़ नियंत्रण के लिए हमारे मा0 सदस्य इस बात को जानते हैं कि वर्ष 2017 के पहले बाढ़ की स्थिति प्रदेश के अन्दर क्या थी।

तब 34 से लेकर 38 जनपद ऐसे थे जो संवेदनशील और अति संवेदनशील थे। आज हमने इसके दायरे को कम किया है। नदियों की ड्रेजिंग के काम को आगे बढ़ाया है, नदियों को चैनलाइज किया है और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अब लगभग 23 लाख हेक्टयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में 277 परियोजनाओं को भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अन्दर सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वे बड़ी परियोजनाएँ हैं, मध्यम सिंचाई की परियोजनाएँ हैं, लघु सिंचाई की परियोजनाएँ हैं, उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अन्य नदी कटान से अन्नदाता किसानों की उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा सेक्टर में भी इस सरकार का पूरा फोकस है। सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी सभी शिक्षा पर फोकस करते हुए कुछ न कुछ अच्छा किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इसको देखेंगे कि पहले प्रदेश में क्या होता था, हम प्रदेश को लेकर कहाँ चले गए थे ? महोदय, अगर मैं प्रदेश की एक छोटी सी झलक इसके बारे में बताऊँ कि यह हाल प्रदेश के अन्दर वर्ष 2015 का है। विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यू0पी0, वर्ष 2013-14 में राज्य की जी0डी0पी0 5.8 फीसदी से गिरकर 5 पर आ गई, कृषि के साथ मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की भी सुस्त रफ्तार, यह तस्वीर वर्ष 2015 की है, नेशनल सैम्पल सर्वे-2015 शर्मनाक! लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार, 05 मार्च, 2015

बी0आर0जी0एफ0 घोटाला, लुटता रहा सरकारी पैसा किसी ने देखा नहीं, हर जिले में उड़ी नियमों की धज्जियाँ निगरानी तंत्र रहा महज कागजी, उस समय ये सुर्खियाँ होती थीं। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो यह भी सुर्खी रही कि सूबे में 5वीं के 56 फीसदी बच्चे हिन्दी तक नहीं पढ़ पाते, यह वर्ष 2015 का है। 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, यह सुर्खी उत्तर प्रदेश की है 20 अगस्त, 2015 की। तीसरी कक्षा के 91.2 फीसदी बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं, 5वीं कक्षा के 75 फीसदी बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते, 69 फीसदी 5वीं कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते, 67 फीसदी चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिन्दी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। यह वर्ष 2015 की स्थिति थी और ये इन बच्चों पर ध्यान देने की बजाय कुछ और ही करते रहे। अगर वहाँ नेता और अफसर के बच्चे भी पढ़ते तो क्या तब भी ये स्कूल ऐसे ही बदहाल होते, ये भी एक टिप्पणी थी उस समय की और यू0पी0पी0एस0सी0 की हर परीक्षा पर सवाल, के लिए दो-दो साल इंतजार करते हैं अभ्यर्थी, इण्टरव्यू में नियमों की अनदेखी।

'स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल' यानि यह प्रदेश की स्थिति थी। खुदकुशी पर सियासत, 'किसान सदमे में आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति' यह 6 अप्रैल, 2015 का है।' 'आत्म हत्या या हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा मौतें' यह राज्य की स्थिति थी। 'वर्ष 2014 में सूखा, रु0 490 करोड़ मिले पर बँटे नहीं' यह भी 17 मई, 2015 का है। मान्यवर, यह प्रदेश में होता था, पूरा सूबा तो छोड़िए। महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुँच सकी मद्द और वर्ष 2015 की एक और सुर्खी है कि 'सी0ए0 ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाये' यह है मजबूरी । (विपक्ष द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर) सवाल यह है कि आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसा उसका जवाब दिया जाएगा। उस समय की क्या सुर्खियाँ थीं, जो मैं बोल रहा हूँ, उन मुद्दों को उस समय आपने भी उठाया होगा। (श्री लालजी वर्मा जी के बीच में टोकने पर) आप काहे परेशान हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए उस समय हम उठाते थे और आज सरकार ने उसको अपने एजेण्डे का हिस्सा बनाया है, उसको हटाने के लिए उससे मुक्ति के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) जब आप वर्ष 2012-2017 की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपकी स्थिति वही हो जाती है कि 'बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना' (मेजों की थपथपाहट) कम से कम आपको तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप भी उसका हिस्सा रहे हैं, उस समय बोलते रहे हैं और इसीलिए मैंने याद दिलाया है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव, विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति थी। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी, नियुक्तियों में लेट लतीफी, कौशल विकास पर सरकार का कोई फोकस नहीं, भविष्य के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम को लेकर कोई रोडमैप नहीं और मिड-डे मील में भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। महोदय, 2017 के बाद आपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे 91 फिसदी से अधिक स्कूल अब तक सेचुरेट हो चुके हैं। वर्ष 2016-17 में जो मात्र 01कोरड़ 34 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में पढ़ते

थे। आज वह संख्या 1 करोड़ 91 लाख हो चुकी है। प्रदेश के अन्दर ड्रॉप आउट रेट लगातार घटा है और प्रदेश में शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी भी की गई है। 1 लाख 64 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। डिजिटले लर्निंग में गुणवत्ता शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लॉस की स्थापना और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। निःशुल्क यूनीफार्म जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि के लिए अभिभावकों के खाते में गत वर्ष से हमने डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि देनी प्रारम्भ की है, 1200 रुपये प्रति छात्र धनराशि दी जा रही है। प्रदेश के अन्दर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। उन वंचित क्षेत्रों में जहाँ पर कभी स्कूल नहीं बन पाये थे, वनटांगिया गाँव हैं, छोटे-छोटे समूह हैं, उन सभी तक पहुँचने की कार्यवाही के लिए भी हमने बजट में व्यवस्था की है। शिक्षा माफिया पर नकेल कसी गई है। नकल विहीन, शुचितापूर्ण परीक्षा व्यवस्था आज प्रदेश की पहचान बन रही है। असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थापना हो रही है। स्मार्ट क्लास, रेयर टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट टेकिंग सिस्टम और डाटा प्रबन्धन ये सभी इसमें आज बन रही हैं।

महोदय इन सबके साथ-साथ माध्यमिक में गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। यानि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए गवर्नमेन्ट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगी जिससे जर्जर बिल्डिंग के नीचे बच्चों को पढ़ना न पढ़े, उनको वहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, इसके लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है। संस्कृत विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालय जर्जर थे, संस्कृत भारतीय संस्कृति की आधार है, उन विद्यालयों के उन्नयन के लिए भी 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है और संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था बजट में की गयी है। उच्च शिक्षा में प्रदेश के अन्दर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं। पहली बार 11 विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सहभागिता की है। 4 विश्वविद्यालय, विश्वस्तरीय रैकिंग के लिए उस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं और प्रदेश के अन्दर असेवित जो हमारी कमिश्नरी थी उनमें देवीपाटन मण्डल, मिर्जापुर मण्डल और मुरादाबाद मण्डल में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पैसों की व्यवस्था भी बजट में की गयी है। इसके साथ ही यूथ के लिए एक सी0एम0 इंटर्नशिप की स्कीम भी लागू की गयी है। बी0ए0, बी0एस0सी0 बी0काम0 पढ़ने वाले छात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स के लिए हमने पहले से ही इसको घोषित किया है, लेकिन इन छात्रों को भी हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ेंगे जिससे उन्हें अनुभव भी हो सके और वे अपनी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए भी आधा मानदेय इंस्टीट्यूशन देगा और आधा शासन देगा। इस व्यवस्था के साथ इंटर्नशिप स्कीम भी हम लोगों ने लागू की है। उत्तर प्रदेश के युवा, कोरोना काल खण्ड में

हमने देखा था हमारे लगभग 14 से 15 हजार छात्र ऐसे थे जो राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे।

अचानक लॉक डाउन होने और उन छात्रों को वापस घर लाने की जब समस्या आयी तो उस समय हमने यहां से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को वहां पर भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम किया और उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी कि अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था प्रारम्भ करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी बाहर जाने की नौबत न आने पाये, उनके जनपद में, उनकी कमिश्नरी में उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो सके। सभी 18 कमिश्नरी में पहले से ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है। 75 जनपदों में इसे ले जाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उन छात्रों को अलग-अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन में 43 छात्र वे आये हैं जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग ली थी, वे छात्र भी उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अन्दर न्यू एज कोर्सेज को ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आफ थिंक्स, साइबर सिक्योरटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक कोर्सेज को भी आज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में बाजार की जरूरत के अनुरूप हम स्किल युवाओं को तैयार करने पर जोर दे रहे हैं और उसके लिए इन कोर्सेज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अन्दर खेल सुविधाओं के विकास के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन की राशि को बढ़ाने की कार्यवाही हुई, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ाया गया। प्रदेश की शासकीय सेवाओं में उन्हें स्थान मिले, इसके लिए हम लोगों ने जहाँ भी संशोधन करने थे, एक्ट में संशोधन करके उस प्रकार की व्यवस्था की और कुछ यूथ को भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा चुका है, कुछ प्रचलित है, बहुत शीघ्र लगभग 600 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी अपना योगदान दे पायेंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हो रहा है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी चिन्हित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि वहाँ के उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार का पूरा सपोर्ट उनके साथ में है, वह लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक और अपने तकनीकी संस्थानों को हम ओ0डी0ओ0पी0, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं से युवानुकूल बनाने की कार्यवाही के साथ भी जोड़ रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन का टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ 505 हजार करोड़ रुपये की लागत से डेढ़ सौ आई0टी0आई0 के तकनीकी उन्नयन के लिए एक एम0ओ0यू0 पर हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें 12 फीसदी शेयर स्टेट गवर्नमेण्ट का होगा, 88 फीसदी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगायेगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को टाटा की कम्पनियाँ न केवल प्रशिक्षण देंगी बल्कि उनके समायोजन के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवायेंगी। हर वर्ष 35 हजार यूथ इससे जुड़ेगा और 10 वर्ष का यह एम0ओ0यू0

अगले 9 महीनों के अन्दर प्रारम्भ होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने की कार्यवाही होने के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक अवसर है, इसके साथ इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान के साथ ही प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। महोदय, सामाजिक सुरक्षा में भी प्रदेश के अन्दर जो कार्य हुए हैं, वह बहुत अच्छी दिशा में कार्य हुए हैं।

एक अच्छा प्रयास प्रारम्भ किया है। निराश्रित महिला पेंशन-2012 से 2017 के बीच में 17 लाख महिलाओं को यह सुविधा मिलती थी और 5 सौ रुपये की पेंशन मिलती थी। आज हम 31 लाख महिलाओं को 12 हजार रुपये सालाना यह सुविधा दे रहे है, यानी 01 हजार रुपये महीने यह सुविधा दे रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन-37 लाख लाभार्थी 2012 से 2017 के बीच में थे और उन्हें 5 सौ रुपये की राशि उपलब्ध होती थी। आज 37 लाख से बढ़ करके 56 लाख यह लाभार्थी हैं और इन्हें भी हम 12 हजार रुपये सालाना सुविधा देते हैं। 2012 से 2017 के बीच में इसके लिए बजट का प्रावधान मात्र 1550 करोड़ था। आज इसके लिए बजट का प्रावधान 7948 करोड़ है। दिव्यांगजन पेंशन-8 लाख लाभार्थी थे और 3 सौ रुपये पेंशन मिलती थी। राजभर जी ने 5 सौ रुपये करवाया था और आज 11 लाख लाभार्थी हैं और प्रत्येक लाभार्थी को 01 हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। आपके 2012 से 2017 के बीच में कोई बजट का प्रावधान नहीं था। 2023-24 में 1552 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था इसके लिए की गई है और इसी प्रकार से कुष्ठावस्था पेंशन के लिए भी 11430 लाभार्थियों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 42 करोड़ रुपये की राशि उन लाभार्थियों के लिए इसमें उपलब्ध करवाई गई है।

मान्यवर, अलग-अलग सेक्टर में अगर हम देखेंगे निराश्रित महिला पेंशन के साथ ही प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक बेटियाँ इससे लाभान्वित हो रही हैं, इससे 14 लाख 72 हजार बेटियों को इससे सीधे-सीधे जोड़ा जा रहा है और उन्हें एक पैकेज के रूप में 15 हजार रुपये पूरे काल खण्ड के दौरान उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना लगभग 2 लाख बेटियों की शादी इसके माध्यम से अब तक सम्पन्न हो चुकी है। 31 हजार से 51 हजार उस राशि को किया गया है और जब यह योजना लागू हुई थी उस समय समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। यह दो लाख बेटियाँ थीं जिनका विवाह इसके माध्यम से हुआ है और अभी तो उज्ज्वला योजना के लिए 1 करोड़ 74 लाख जो लाभार्थी हैं उनको हम लोग साल में दो सिलेन्डर फ्री देने जा रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। यह सरकार की योजनायें हैं जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित है और जिनको हम लोग आज भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ रहे हैं।

चिकित्सा सेक्टर में आज हम देख सकते है कोविड न्यूनतम स्तर पर हैं, एकदम समाप्त है। प्रबन्धन कोऑर्डिनेशन इसका परिणाम है। लगभग 40 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई है। इसमें किसी की जाति, किसी का मजहब नहीं देखा गया। पिछले तीन वर्ष से हर गरीब को 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे भुखमरी की स्थिति न आने पाये। अब तक लगभग 13 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं और क्या स्थिति थी इससे पहले। आप लोगों का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का बजट ही 12 हजार करोड़ रुपये से कम का था। आज यह बजट 30 हजार 870 करोड़ रुपये का वर्ष 2023-24 में होने जा रहा है। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ए0एल0एस0 यू0पी0 में वर्ष 2017 के पहले नहीं थी। भारत सरकार एम्बुलेंस देना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार लेना नहीं चाहती थी। जब उस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भारत सरकार फ्री में दे रही है तो हमने कहा तत्काल ले लो और आज 500 ए0एल0एस0 प्रदेश के अन्दर हर जनपद में प्रदेश की जनता को सेवा दे रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार 453 परिवार हैं। लाभार्थी इसका 5 गुना है, लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े हुये हैं और इसमें अब तक 1448 करोड़ रुपये जिन लोगों ने लाभ लिया है उन परिवारों की ओर से भुगतान किया गया है जो बीमा कवर मिला है यह भुगतान भी हो चुका है। डायलिसिस यह की सुविधा आज हर जनपद में बढ़ रही है। यह दुर्भाग्य है कि किडनी फेल्योर के मामले आ रहे हैं। नये-नये यंग नौजवानों के ऊपर यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है लेकिन सिस्टम बैठा नहीं है डबल इंजन सरकार भी सुविधा उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम किसी के लिए मना नहीं करते।

मान्यवर, लखनऊ की ओ0पी0डी0 की बात हो रही है। राज्य के लोग तो आते ही हैं, अगल-बगल के राज्यों के लोग भी आते हैं, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, झाँसी, आगरा, नोएडा में आते हैं। यह मानवता की सेवा है, हम इसमें भेद नहीं कर सकते। कोई भी आयेगा, हम उसको सेवा देंगे, भरपूर सहयोग करेंगे और उसके तहत ये कार्यक्रम कराये जा रहे हैं।

महोदय, 'मुख्य मंत्री आरोग्य मेला' से अब तक 11 करोड़ 72 लाख 29 हजार से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। 2 लाख 670 गम्भीर रोगियों को हायर सेंटर में रेफर किया गया है और 11 लाख 80 हजार से अधिक गोल्डन कार्ड जारी हुए हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए कैसलेस उपचार का बजट में प्रस्ताव किया गया है। महोदय, वर्ष 2017 के पहले हम लोगों को तस्वीर देखने को तब मिली थी, जब कोविड आ गया। यानी ज्यादातर जनपद ऐसे थे, जिन पर कोई वेंटीलेटर ही नहीं था। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों के पास अपने वेंटीलेटर हैं, आई0सी0यू0 की सुविधा है और टेलीकंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन की सुविधा की कार्यवाही भी युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश के अन्दर संचारी रोग नियंत्रण का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें स्वास्थ्य विभाग को अनेक पुरस्कार मिले, कोविड प्रबन्धन तो है ही,

लेकिन मलेरिया उन्मूलन के लिए, डेंगू के लिए, कालाजार, चिकनगुनिया और इंसेफेलाइटिस। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, तराई क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वे सरकारें कितनी संवेदनहीन थीं, जब बच्चे तड़प-तड़प कर मरते थे, ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों कर रहे है ? मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार ने 96 फीसदी इंसेफ्लाइटिस को रोक दिया है अब बच्चों की मौत नहीं होती है और संचारी रोग नियंत्रण के लिए साल में तीन से चार बार विशेष संचारी रोग नियंत्रण के अभियान भी चलते हैं।

मान्यवर, वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, तेजी के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। एम0बी0बी0एस0 और पी0जी0 की सीटें भी बढ़ी हैं।। प्रदेश के अन्दर अन्य तमाम योजनाओं के लिए बेड्स की संख्या आज प्रदेश के अन्दर काफी बढ़ायी गई हैं। एक पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 होता है, वर्ष 2016-17 में इनकी संख्या केवल 150 थी, लेकिन आज बढ़कर 6 हजार 7 सौ से अधिक हो गयी है। 300 संस्थाओं में नर्सिंग और पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 33 वर्षों से बंद पड़े 35 ए0एन0एम0 सेंटर में प्रशिक्षण फिर से प्रारम्भ हो गया है। अब सोचिए कि वहाँ जिन बेटियों को एडमिशन मिला होगा, उनको रोजगार की गारंटी होगी, लेकिन इसके लिए संवेदना चाहिए। पोषाहार में महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा आज रेसेपी आधारित टेक होम राशन के आधार पर वितरण की व्यवस्था की गयी है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को एक लाख 77 हजार से अधिक स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं। सारे डाटा अपलोड हो रहे हैं। अगर प्रदेश के अन्दर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिर्पोट को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अन्दर बेहतर काम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, रिजल्ट अच्छे आये हैं। उसमें नेशनल एवरेज और कुछ में नेशनल एवरेज से आगे बढ़कर आज उत्तर प्रदेश काम कर रहा है।

यह हेल्थ सेक्टर की स्थिति है और प्रदेश के अन्दर अभी हम लोगों ने अलग-अलग क्षेत्र में भी कार्य प्रारम्भ किया है, एण्टी नारकोटिक्स का गठन भी प्रदेश के अन्दर किया गया है। प्रदेश के अन्दर अन्य कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा जिस प्रतिबद्धता की आवश्यकता होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। महोदय, ऐसे ही अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए भी, इस सेक्टर में भी अच्छा प्रयास हुआ है। हमारी जो एम0एस0एम0ई0 दम तोड़ रही थी, आपके जनपद फिरोजाबाद में भी ग्लास का अच्छा काम होता है, पता नहीं आपने निवेश क्यों नहीं किया, आपको निवेश करना चाहिए था, इसमें अगर निवेश करते तो अच्छा होता, लोग देखते कम से कम आप अपने उत्पाद को दुनियां के मंच पर पहुंचाते, आज भी हमारे जो फिरोजाबाद का कारीगर है बहुत अच्छा काम करता है। उनके सामने परेशानी थी, उस परेशानी से मुक्त करने के लिए तमाम कार्य किये गये। लोगों ने एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से 1 हजार दिवस तक किसी भी विभाग में निरीक्षण से छूट का प्रावधान भी उनको उपलब्ध करवाया। आज परिणाम है कि सरकार के द्वारा जो उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है, वह परिणाम हमारे लिए रोजगार के माध्यम का भी सर्जन बना है और औद्योगिक

निवेश का आधार स्थापित करने का भी एक आधार बना है। इस दिशा में इसने हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है, आज 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपये का निर्यात उत्तर प्रदेश इस दिशा में कर रहा है।

महोदय, ऐसे अलग-अलग फील्ड में हथकरघा में प्रदेश के अन्दर अलग-अलग प्रदेश ने हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया किया है। प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने विद्युत वितरण की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया है, आपके समय में विद्युत वितरण में भी भेदभाव होता था, अब भेद-भाव नहीं होता है अब तो सभी 75 जनपदों को समान रूप से बिजली प्राप्त होती है। 1 लाख 21 हजार से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का काम सम्पन्न किया गया है। कुल विद्युत का उत्पादन वर्ष 2012 से 2017 के बीच में 18631 मेगावाट थी, वर्ष 2017 से आज की स्थिति क्या है ? 30 हजार मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता हमारे पास है। प्रदेश के अन्दर इस दिशा में हमने सोलर पॉवर के लिए भी एक अच्छा प्रयास प्रारम्भ किया है, हमारा मानना है कि प्रदेश को आने वाले समय में जीरो नैट की तरफ जाना ही होगा और इस दिशा में जो प्रयास प्रारम्भ हुए हैं, उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है और हम लोग चाहेंगे कि जो सरकार की बायोफ्यूल की पॉलिसी रिन्यूवल एनर्जी की और फ्यूचर में हाइड्रोजन के फील्ड में जो कार्य होने जा रहा है, यह अनेक सम्भावनाओं को आगे विकसित करने जा रहा है। इसकी क्षमता को 16348 मेगावाट से बढ़ाकरके इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 28 हजार मेगावाट और वर्ष 2025 तक 32 हजार मेगावाट से अधिक करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है और यह सरकार की योजना का हिस्सा है। महोदय, प्रदेश के अन्दर इंफ्रास्ट्रेक्चर के लिए इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी, शिवपाल जी पता नहीं आपके पास पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्रालय था कि नहीं था, आपके पास से छीन लिया होगा। नहीं तो गड्ढे नहीं होते सड़कों पर। इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी उसको बेहतर किया गया है, 4 लेन के साथ जोड़ा गया है और ऐसे 54 मार्ग है जो इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी में आते हैं। नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सबसे जुड़े हुए है।

अगर आप लोग शिवपाल सिंह जी को रखे होते तो सम्भवतः जनता यह नहीं बोलती कि जहाँ सड़क पर गड्ढे दिखायी दें तो समझ लो कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आ गया।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मेरे समय में गड्ढे नहीं थे।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपके समय गड्ढ़े नहीं थे, इसीलिए आपको हटा दिया। लेकिन 2017 के बाद आज गड्ढ़ामुक्ति अभियान, इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस हाई-वेज बने। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि भारत सरकार ने क्या किया ? थोड़ा दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाई-वे पर नेता विरोधी दल चल लेते तो उनको पता लगता कि क्या किया है ? 12 लेन का वर्ल्ड क्लास इन्फास्ट्रक्चर के

साथ यह हाई-वे बना है। पहले 3 से 4 घण्टे लगते थे, आज मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। लखनऊ से कानपुर के बीच में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाई-वे का निर्माण हो रहा है। अभी परसों ही पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे का बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास माननीय सड़क परिवहन मंत्री, भारत सरकार ने किया है। (मेजें थपथपायी गयीं।) दिल्ली से सहारनपुर को जोड़ने के लिए जो कार्य हुए हैं तथा अन्य तमाम उस पर कार्य चल रहे हैं, यह सब बताते हैं कि कार्य हुआ है। पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश अपने सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यही लोगों के विश्वास का प्रतीक बना है, इसी से आम-जनमानस का विश्वास बढ़ा है। मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में काफी प्रगति की है और इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।

महोदय, प्रदेश के अन्दर ग्राम्य विकास एवं नगरीय क्षेत्र में भी एक नया प्रस्ताव दिया गया है 'मातृ भूमि योजना'। उत्तर प्रदेश का कोई प्रवासी जो उत्तर प्रदेश के बाहर रहता है, वह प्रदेश के अन्दर किसी एक फील्ड में निवेश करना चाहता है अर्थात् अपने गाँव में, अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई कन्वेंशन सेण्टर, कोई सामुदायिक भवन या कोई भी ऐसा सेण्टर बनाना चाहता है तो राज्य सरकार ने उसके लिए 'मातृ भूमि योजना' प्रारम्भ की है। 'मातृ भूमि योजना' जिसके माध्यम से उसे भरपूर सपोर्ट कर रही है। 60 प्रतिशत पैसा वह देगा और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। बड़े पैमाने पर लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं।

ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर जो झाँसी के अन्दर काम कर रहा है, बहुत अभिनंदनीय कार्य इस प्रोड्यूसर ने किया है। लगभग 150 करोड़ रुपये का इनका वार्षिक टर्नओवर है और 13-14 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट है। केवल महिलाओं का समूह है, यह महिलाओं के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। बैंकिंग करेस्पांडेंट सखी उत्तर प्रदेश के अन्दर लगभग हर ग्राम पंचायत के पास है। बैंकिंग लेन-देन का काम सभी बहिनें कर रही हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। गाँव-गाँव में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अन्दर अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ग्रामीण सेक्टर में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया गया है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जायेंगे तो एलईडी स्ट्रीट लाइट से आपको वहाँ की सड़कें जगमगाती हुई दिखायी दे रहीं होंगी। स्वामित्व योजना में 50 लाख से अधिक परिवारों को जहाँ पर उसका घर है, वहाँ का मालिकाना अधिकार 'घरौनी' उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है। यह प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर पहली बार हुआ है। हम मा0 प्रधानमंत्री जी के इसके लिए आभारी हैं कि उनकी प्रेरणा से आज यह कार्यक्रम प्रदेश के अन्दर और इसका लाभ प्रदेश के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। अन्य तमाम सेक्टर्स में कार्य प्रारम्भ हुए हैं...

माननीय अध्यक्ष जी, मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश के अन्दर लखनऊ में एक नाइट सफारी की घोषणा हो रही है बजट का प्राविधान किया गया है यह कार्यक्रम कुकरैल में होने जा रहा है और कार्यक्रम को तेजी से साथ इकोटूरिज्म के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अन्दर वृक्षारोपण वनाच्छादन की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे वह मुझे लगता है कि आप सबने इस कार्य को यहां पर देखा होगा। प्रदेश के अन्दर पिछले पांच वर्ष के दौरान एक सौ पैंतीस करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और इस बार फिर पैंतीस करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के पर्यावरण और वन विभाग कार्य कर रहा है जिसमें इससे सम्बन्धित तमाम स्वयंसेवी समूहों को भी इसके साथ जोड़ने की कार्यवाही हो रही है, महोदय, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अन्दर उससे पहले क्या थी, 2017 के पहले की क्या स्थिति थी यू0पी0 में बेबस मुख्य मंत्री। भर्ती और प्रशिक्षण पिछले पांच वर्ष के अन्दर हम लोगों ने जो कार्य किया, भर्ती की प्रकिया को पूरी पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया। पुलिस बल के आधुनिकीकरण का कार्य हुआ है, अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि की गई है और बेहतर कोऑरडीनेशन के माध्यम से हर एक कार्य को रिजल्ट ओरिएन्टेड किया गया। मिशन शक्ति का कार्यक्रम आज वह एक मॉडल बन रहा है। सेफ सिटी 17 नगर निगम के साथ-साथ गौतमबुद्धनगर जनपद को सेफ सिटी के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है और एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट भी इस बात को बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अन्दर नम्बर एक पर है। उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया है। 2016 की तुलना में डकैती में 80.31 प्रतिशत, लूट में 61.51 में प्रतिशत, हत्या में32.45 प्रतिशत बलवा में 51.65 प्रतिशत, फिरौती में 43.18 प्रतिशत, दुष्कर्म में 21.75 प्रतिशत की कमी आई है। यह प्रदेश के अन्दर लगातार कार्य हो रहा है और प्रदेश के अन्दर हर ग्राम सचिवालय में मिशन शक्ति रूम की गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो हर माता को हर बेटी को सुरक्षा की पूरी गारण्टी देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। तीन महिला बटालियन का गठन पी0ए0सी0 की 54 बटालियन जो समाप्त कर दी गई थी उन कम्पनियों को फिर से बहाली करने की कार्रवाई हुई। यू0पी0एस0एस0एफ0 स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया। एस0डी0आर0एफ0 का गठन भी किया गया। प्रदेश के अन्दर एक दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की कार्रवाई जो हुई आज उसके परिणाम हैं, निवेश उसका परिणाम हैं, पुलिस रिफॉर्म सात पुलिस कमिश्नरेट भी घोषित किए गए और एक लाख चौंसठ हजार पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी प्रदेश के अन्दर पूरे पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुई है साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए साइबर थाने की व्यवस्था, एफ0एस0एल0 लैब्स की स्थापना, लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन्सिक साइन्सेज की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है इसी सत्र में हम लोग वहां पर अपने कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में प्रारम्भ करने जा रहे है और ई-प्रॉसीक्यूशन में देश के अन्दर उत्तर

प्रदेश नम्बर 1 पर है। नवीन संशोधित जेल मेनुअल यह प्रदेश ने घोषित किया है और मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की कार्यवाही भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अन्दर वह कार्यक्रम है जिन्हें अलग-अलग सेक्टर के माध्यम से 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और इन्हीं सब मुद्दों को ले करके मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, आपने देखा होगा कि बजट में हर एक सेक्टर के लिये पैसा है, हर एक योजना के लिये पैसा है, हर एक तबके के लिये पैसा है। आज कोई तबका अपने आपको उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता है और फिजूलखर्ची भी नहीं है। एक रिपोर्ट जो मुझे बताती है कि प्रदेश में वर्ष 2012 से 2017 के बीच में अकेले सैफई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपये खर्च हुये थे और हम लोगों ने 17 से 22 के बीच में जो इन्वेस्टर्स समिट की है उसमें मात्र 21 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गन्तव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। शिवपाल जी, इसी लिये मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि 'वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हों। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों।' (सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) जो शूल आप लोगों ने बोए थे उन्हीं शूल को ठीक करते हुये, दुरुस्त करते हुये रोलर और बुल्डोजर चला-चला करके प्रदेशवासियों के लिये फूल उगाने का कार्य हो रहा है। वही हो रहा है। यह देश रामराज्य से ही चलेगा। यह बजट रामराज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है। इस वर्ष भगवान राम के भव्य मन्दिर का निर्माण होने जा रहा है। (सत्ता पक्ष द्वारा सदन में 'जय श्री राम, जय श्री राम' का उद्घोष) मा0 अध्यक्ष जी, समाजवाद दुनिया के अन्दर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कम से कम आप लोग शिवपाल जी के सानिध्य में रहकर उनसे कुछ तो ज्ञानार्जन किया करें। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी और इसीलिये मैं बार-बार कहता हूँ कि यह एक बहुरुपिया ब्राण्ड है, इसके अलग-अलग रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहाँ गयी, उसके बारे में आप थोड़ा बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। क्या यह प्रदेश का कल्याण कर पायेंगे और इसीलिये इसके बारे में बार-बार कहा जाता है कि यह एक मृगतृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है। केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखण्ड है समाजवाद। महोदय, मैं फिर कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश रामराज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश रामराज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सम्पन्नता, विकासोन्मुख समाज तथा राजनीतिक अखण्डता का निर्माण, यही

चीजें प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हम अपनी विरासत को पहचानें कि हमारी विरासत क्या है। हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी में है। गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुम्भ, जिस पर 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्राविधान किया है। वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परम्परा को भूमि वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया है यही नैमिषारण्य है जोकि हमारे बगल में है। शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विन्ध्यवासिनी धाम जाइये, माँ पाटेश्वरी के धाम में जाइये, माँ शाकुम्बरी के धाम में जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

गोरखपुर धाम के बारे में भी बता दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हां गोरखपुर में भी विकास हो रहा है। अरे, आप गोरखपुर जाकर तो देखिए। गोरखपुर धाम का भी विकास हो रहा है। वह पहले से विकसित है उसको और विकास की आवश्यकता नहीं है। देखिए, गोरक्षपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं न, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुँह तोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेन्टर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाको चने चबवाया है और फिर उठ खड़ा होकर मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और आदर्शों से समझौता नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। लेकिन रामराज्य यही है जो राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी ही होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें लेकिन हम तो सम्मान करेंगे ही और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डा0 राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही इन लोगों को करा देते जो आज भगवान राम पर, सन्त तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते कि क्या कहा था डाक्टर लोहिया ने, आप तो डा0 लोहिया पर लिखते हैं। आप ही उनको समझा दिए होते।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आप पाँच साल में नहीं समझा पाये।

(सदन में हंसी)

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप सच बोल देते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी-कभी कर लेते हैं और इसी लिए हम आपको पसन्द भी करते हैं।

(विपक्ष की एक सदस्या के द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास किया गया)

अरे आप महिला है, आप स्पीकर साहब से परमीशन ले लेंगी तो हम आपके लिए बैठ जायेंगे। आपका हम सम्मान करते हैं सभी बहनों का सम्मान करते हैं, यह जो काम हो रहे हैं यह सब आप ही लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में रामराज्य है। रामचरित मानस में कहा गया है।

'दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।

सब नर करहिं परस्पर प्रीति। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।।'

आप मुझे एक बात बताइये कि इसमें क्या बुरा है ? एक दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के जो तुक है एक शारीरिक है, एक मानसिक है यानी आध्यात्मिक बोल सकते हैं, एक दैविक प्रकोप है आपदा है, एक भौतिक ताप है माफिया और आतंकियों का है, यह भौतिक ताप है। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक में आते हैं और दैविक आपदा, किसी प्रकार की आपदा, इन तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के तुक को रोकने का सामर्थ्य किसी में है तो उसके लिए सद्भावना चाहिए सत्संकल्प चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। गरीबों को जो मकान मिल रहे हैं तो क्या किसी की जाति पूछी गयी है।

किसी का मत और मजहब पूछा गया। शौचालय दिये गये, किसी को पूछा गया, सबको दिये गये। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है। उसको समझने का अगर आपने प्रयास किया होता तो इस मृग तृष्णा में नहीं फंसे होते। इसके बारे में आचार्य रजनीश ने ऐसे ही नहीं कहा था। कुछ इस प्रकार की चीजें थीं। जो व्यवहारिक नहीं थीं। जो व्यवहारिक नहीं होगा वह कभी सच नहीं होगा। जो सत्य होगा हर देश, हर काल हर परिस्थिति में वह सत्य होगा और शाश्वत भी होगा। हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि विरासत को न कोसें। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आपने यह कह दिया। अगर आप आक्षेप करेंगे तो उसका जवाब आक्षेप के रूप में ही होगा। प्रश्न टेढ़ा होगा तो उत्तर भी तो टेढ़ा ही होगा। वह सीधा थोड़ी हो सकता है। सदन की मर्यादा तो हमें स्वयं ही देखना चाहिए। हम सबको संकल्प लेना है और प्रदेश वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बने यह सबका संकल्प होना चाहिए। पूरे सदन का संकल्प होना चाहिए। बजट उस मंशा को पूरा करने के लिए आप सबका आवाहन कर रहा है। हर एक सेक्टर को प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। मैंने प्रयास किया और अभी कुछ सेक्टर पर यहां सदन में चर्चा होगी। मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को पास करने में सभी लोग सहयोग करें। उत्तर प्रदेश और देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें। 25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर कार्य करेंगे तो सचमुच उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इन्जन बनेगा। उत्तर प्रदेश

को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस जिम्मेदारी के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था।

जी-20 के समिट हुए थे। हमारा काम है सौन्दर्यीकरण करना। हमने किया। अतिथि आये हमने सौन्दर्यीकरण किया, हमने खूब सजाया था और आगे भी खूब सजायेंगे। जिसका काम चोरी करना होगा वह चोरी तो करेगा। क्या करेंगे आप ? हमारा काम है अच्छा करना। हमारा काम है हर गरीब के जीवन में खुशहाली लाना, उनके लिए फूल बिछा देना। स्वागत के लिए उनका खूब आवभगत करना लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही शूल पैदा करने की होगी उससे फूल की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं विनम्रता से कहूंगा कि राम-राज्य की अवधारणा समाजवाद से नहीं सत् संकल्प से होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़कर होगी। एक ऐसी अवधारणा जिसमें किसी के साथ भेद-भाव न हो। न जाति, न मत, न मजहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यह राम-राज्य का मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं वित्त मंत्री को, उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं और पूरे सदन से अपील करूंगा कि इस बजट को पास करके उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी एक समग्र विकास की आधारशिला रखने वाले आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस बुनियाद को और मजबूत करने में अपना योगदान दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्टीकरण चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, किस बात का स्पष्टीकरण। चर्चा पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होता।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 करोड़ विधायक निधि की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष-

यह बात तो कई बार हो चुकी है। आप वहीं पर अटके हुए हैं। हम इसके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय वित्त मंत्री जी इसके बारे में बता चुके हैं।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, विधायक निधि का प्राविजन इसमें कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें विधायक निधि का प्राविजन कर दिया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से सभी विषयों के ऊपर अपनी बात कह दी और हम केवल एक बात कहकर इसको कन्क्लूड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से जितनी बातें सदन में उठाई थीं हमारे सभी विपक्षी साथियों ने उन सभी का जबाव तो आ गया अब केवल एक ही बात कहेंगे कि विपक्षी लोगों ने एक बात बार-बार कही कि बजट दिशाहीन बजट है।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

मान्यवर, हमने नहीं कहा था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने इनके बारे में नहीं कहा यह तो हमारे मित्र हैं। यह ऐसा क्यों कहेंगे हमने तो विपक्षी लोगों के लिए कहा है यह तो हमारे साथी हैं। अध्यक्ष जी हमारी पार्टी और योगी सरकार के इस बजट की दिशा एक ही है जो यह कहा गया था कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का होगा और यह बजट पूरी तरह से इस बात को साबित करता है कि हमने गरीब को केंद्र मैं लेकर यह बजट बनाया है और यह दिशाहीन बजट नहीं है। हम आपसे केवल एक ही बात पूछना चाहते हैं कि जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना आयी थी जिसके बाद पौने दो साल तक आपकी सरकार रही और एक भी मकान और 11486 लोगों का रजिस्ट्रेशन तो किया गया, लेकिन एक भी मकान नहीं दिया गया। योगी जी ने आने के बाद लाखों मकान शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दिये और आज भी बजट में 9 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आज भी की गयी है और जो आपने विकास दर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया तो हम दावे के साथ कह सकते है कि जो भी बजट में हमने अनुमान दिया है कि हम 19 प्रतिशत की विकास दर देंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं उसमें और जो हमारी एफ0आर0वी0एम0 की लिमिट के अन्तर्गत हम रहेंगे। मान्यवर 135 लोगों ने इस बजट पर बोला और मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक विषय का जबाव भी दिया है और मैं समझता हूं।

मान्यवर, एक सवाल का उत्तर अभी नहीं आया है। यह लोग कह रहे थे कि बजट दिशाविहीन है, लेकिन बजट में सब कुछ है हम लोग कुछ कह नहीं रहे हैं हम तो यह कह रहे है कि जो पांच करोड़ आप लोग दिये हैं बजट से तो उसमें से जी0एस0टी0 हटवा दीजिए और कुछ मत करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो पक्ष और विपक्ष के लोगों ने चर्चा में भाग लिया और विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से प्रत्येक विषय का जबाव दिया। हम विकास की सोच लिए हर कदम बढ़ाते जाते हैं, नई फिजायें निर्मित कर हर कोने शमां जलाते हैं। फिर से मान्यवर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस बजट पर सामान्य चर्चा पर उदारतापूर्वक दिन और रात में 12 बजे तक सदन चलाया और सभी लोगों को इसमें बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन में कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

सदन को सूचना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 01 मार्च, 2023 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 02 मार्च, 2023 को अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) एवं अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान करा लिया जाये।

2-दिनांक 03 मार्च, 2023 को अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास), अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) की अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान करा लिया जाये।

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मद संख्या-11, इसमें कुछ नहीं है, मद संख्या-12 व 13 स्थगित है, अब मद संख्या-14।

औद्योगिक विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु समय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान होना है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि पहले औद्योगिक विकास कार्य मंत्री अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करके अपना वक्तव्य दे दें फिर उसके बाद नगर विकास विभाग मंत्री अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करके अपना वक्तव्य दे दें। दोनों विभागों के बजट पर साथ-साथ कटौती रख दी जाये इसके बाद जो माननीय सदस्य जिस विभाग पर जितना चाहें बोल ले।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक विकास विभाग और नगर विकास विभाग का बजट अलग-अलग प्रस्तुत कराकर अलग-अलग चर्चा कराई जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दोनों विभागों का बजट साथ में प्रस्तुत करना उचित होगा।

श्री अध्यक्ष-

इस समय 5.30 बज रहे हैं और हम 8.30 बजे तक चलाना चाहते हैं। दोनों विभागों का बजट आ जाये और एक साथ चर्चा हो जाये। इसमें क्या नुकसान है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप इसे अलग-अलग रखवाईये। समय भले ही कम कर दीजिये। एक माननीय सदस्य को दोनों विभाग पर एक साथ बोलने में कठिनाई होगी।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर एक विभाग को डेढ़ घण्टे और दूसरे विभाग डेढ़ घण्टे का समय दे देते हैं। माननीय मंत्री जी आधे घण्टे में बजट रख दें, उस पर पन्द्रह मिनट में कटौती रख दी जाये और बाकी समय में माननीय सदस्य बोल लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

श्री अध्यक्ष-

माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी, कृपया बजट रखिये।

औद्योगिक विकास निर्यात मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20586,54,10,000 रुपये (बीस हजार पाँच सौ छियासी करोड़ चौवन लाख दस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे औद्योगिक विकास विभाग के बजट पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली, उन्नति और भविष्य का बजट प्रस्तुत करने के लिए नये भारत और नये उत्तर प्रदेश के शिल्पकार माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ।

मा0 अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2014 में उत्तर प्रदेश के जनमानस ने जाति धर्म मजहब के बन्धनों को तोड़कर प्रचण्ड बहुमत के साथ 90 प्रतिशत से ज्यादा सीट देकर 80 में से 73 सीट जिताकर देश की बागडोर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथ में सौंपने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2017 में फिर एक बार उत्तर प्रदेश के जनमानस ने 325 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी और एक कर्मयोगी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंपी। मा0 मुख्य मंत्री जी 2017 से बिना थके, बिना रुके प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रहे हैं यही कारण है कि 2019 में सपा, बसपा का तथाकथित गठबन्धन होने के बावजूद 50 प्रतिशत से अधिक वोट देकर 2014 से भी अधिक 353 सीट देकर एक बार फिर से 56 इंच के सीने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में इस देश की बागडोर सौंपी। मान्यवर, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार सपा एक बार बसपा एक बार बसपा एक बार सपा यही पैटर्न बन गया था लेकिन 2022 में मा0 मुख्य मंत्री जी के सेवा सुशासन के मंत्र ने इस मिथक को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक बूथ जीतकर मान्यवर, 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में सबसे अधिक बूथ जीतकर प्रचण्ड बहुमत के साथ आदरणीय मुख्य मंत्री आदित्यनाथ जी के हाथों में फिर से इस प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम किया है। बार-बार हर बार और अधिक मजबूती के साथ हम पर भरोसा और विश्वास जताने के लिए प्रदेश की

जनता के प्रति चार पंक्तियों के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूँ-मिला सहयोग सभी का घड़ी यह आयी, सभी मतदाताओं को विजय श्री की बधायी विजय यह नहीं हमारी जीत है आप सबकी सरकार बनी हमारी प्रीत है। आप सबकी, हमारी जो सरकार बनी, आप मतदाताओं ने जिताकर दोबारा हम पर भरोसा जताया। 2014, 2017, 2019, 2022 में भी लगातार जो आपने जीत दी है यह जीत आपकी जीत है हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार का साथ अगर यूं ही रहा तो काम अच्छा करेंगे आपके लिए जियेंगे आपके लिये मरेंगे। मान्यवर, मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एवं मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान और ख्याति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश खुशहाली, समृद्धि, विकास के रास्ते पर डबल स्पीड के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, उ0प्र0 का इतिहास, उ0प्र0 का भूगोल, उ0प्र0 की विरासत बेहद विशिष्ट है। स्वर्णिम है। 25 करोड़ प्रदेशवासी अपनी संस्कृति और सामर्थ्य पर गौरव की अनुभूति करते हैं। प्रत्येक देशवासी उत्तर प्रदेश को चमकते दमकते मुकुट की तरह भारत माँ के मस्तक की शोभा बढ़ाते देखना चाहता है। हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर विश्व के करोड़ों सनातनियों के सपनों को साकार कर रहा है। बाबा विश्वनाथ का भव्य कारीडोर पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वालों को हर हर महादेव के जयघोष के साथ, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा नये कलेवर के साथ सज रही है। आज प्रत्येक भारतवासी के मन में एक ही भाव है कि रघुकुल रीति जहाँ की है राम रमैया, जिस धरती पर जन्मे कृष्ण कन्हैया। देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है। मान्यवर, लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का शासन रहा है और प्रदेश की तरक्की को जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण ने दीमक की तरह जकड़ रखा था। इन विकास विरोधी स्वार्थी ताकतों ने प्रदेश को भीतर से खोखला करने का काम किया।

मान्यवर, आज विपक्ष की कुर्सी पर बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कैसी दुर्गति थी यह जनता अभी तक भूली नहीं है। वर्ष 2012 का वह दृश्य आज भी याद है 2012 में सरकार बनी भी नहीं थी सिर्फ टेलीविजन पर रुझान आ रहे थे तभी पूरी की पूरी दलित बस्ती में आग लगा दी गयी थी, उसको प्रदेश अभी तक भूला नहीं है। जिन्होंने इस प्रदेश के संसाधनों को लूट का अपना कारोबार बना लिया था, जिन्होंने सत्ता को अपनी जागीर समझ लिया था, जब जनता जनार्दन ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया तो इनका तिलमिलाना स्वाभाविक है और तिलमिलाहट हमें सदन में बार-बार देखने को मिल रही है। मा0 नेता विरोधी दल एक तरफ तो अक्सर लैपटॉप एवं टेक्नालॉजी की बात करते हैं, आधुनिकता के बड़े-बड़े दावे करते हैं, खुद को इंजीनियर कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ मुख्य मंत्री रहते हुए कुर्सी जाने के डर से कभी नोएडा नहीं गये। इस प्रकार की दकियानूसी सोच देखकर उनके इंजीनियर होने की योग्यता पर भी सन्देह पैदा होता है। वह अक्सर अपने

बयानों में विदेश का उदाहरण देते हैं लेकिन बड़े दुःख की बात है कि उन्हें प्रदेश की जनता की हकीकत का जरा भी अन्दाजा नहीं है। मा0 नेता विरोधी दल ने इस सदन में बार-बार सांड़ की चर्चा करके अपमानजनक बातें कही हैं। यह कार्यवाही में भी है आप चाहें तो कार्यवाही निकलवाकर देख सकते हैं। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि जब हमारे यहां गांवों में बछड़ा पैदा होता है तो मिठाई बांटी जाती है, अगर कोई त्यौहार खण्डित होता है तो उसी दिन पैदा होने से पुनः वह त्यौहार मनाया जाने लगता है। इस तरह की बातें कहकर वह बार-बार हमारी परम्पराओं और गौ-पालकों को अपमानित करने का काम करते हैं। मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व है कि प्रदेश में टेक्नालॉजी और आधुनिकता का सर्वोत्तम उपयोग अगर किसी ने किया है तो वह हमारे नेता आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।

मा0 मुख्य मंत्री जी टैब पर काम करते हैं उन्होंने ई-फाइल प्रणाली को लागू किया है, प्रदेश में पेपर लेस बजट का आरम्भ किया है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा को देश की पहली ई-विधान सभा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मा0 अध्यक्ष जी आपने भी नये-नये प्रयोग के माध्यम से एक स्वस्थ परम्परा की शुरूआत की है और वह दिन दूर नहीं कि जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा देश में नम्बर 1 होगी। मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के दो करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट एवं स्मार्टफोन प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तक लगभग 20 लाख से ज्यादा टैबलेट एवं स्मार्टफोन की आपूर्ति हो चुकी है। इस बार वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने न केवल नोएडा जाने के मिथक को तोड़कर दोबारा प्रचण्ड बहुमत से इस प्रदेश की बागडोर सम्भाली है बल्कि अपने विजन से नोएडा को दुनिया के चुनिंदा शहरों में शुमार किया है। सपा की सरकार में एक चाचा नोएडा और दूसरे चाचा ग्रेटर देखते थे और भतीजे यमुना देखते थे। आज वही नोएडा और ग्रेटर नोएडा मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में समृद्धि का प्रवेश द्वार बनकर रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था, सत्ता के संरक्षण में कारोबारियों और व्यापारियों से वसूली का खेल चल रहा था। गुण्डे, माफिया एवं अपराधी सपा सरकार की आंखों के तारे बने हुए थे और यह अपराधी एवं माफिया थानेदार को निर्देशित करने का काम करते थे, कप्तान को निर्देशित करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेशकों का आना मुश्किल था, उत्तर प्रदेश में कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहता था, निवेशकों के बीच सरकार की क्रेडिबिलटी शून्य थी। जो अपने पिता एवं चाचा के नहीं हुए उनके मुंह से क्रेडिबिलटी की बात करना शोभा नहीं देती है। आज उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था एक मिसाल बनी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी अपने विभाग के बजट के बारे में तो बतायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य पहले माहौल बनेगा तभी तो इंडस्ट्री आयेंगी, आप उनको माहौल ही नहीं बनाने दे रहे है, लॉ एण्ड आर्डर वगैरह ठीक होगा तभी इंडस्ट्री आयेंगी।

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को नये भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में एक नयी पहचान मिली है। औद्योगिक विकास और निवेश को एक नयी रफ्तार मिली है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को दशकों तक बीमारू राज्य बनाये रखा उनको यह तरक्की बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है।

यही कारण है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश की तरक्की, प्रगति और नये सूर्योदय का बजट प्रस्तुत किया जाना था उस दिन माननीय नेता विरोधी दल ने अपने सदस्यों के लिए काले रंग का ड्रेस कोड लागू किया था, गर्मी के कारण पसीने छूट रहे थे लेकिन फिर भी काली शेरवानी पहनकर आये थे, जो समाजवादी पार्टी के काले कुशासन, बदहाली और अंधेरे को याद दिला रहा था। मान्यवर, एक बेहद महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब जी0आई0एस0 2023 में दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर मंत्री समूह द्वारा विभिन्न देशों में रोड शो आयोजित हो रहे थे, जब विश्व स्तर पर ब्राण्ड यूपी की चर्चा हो रही थी, जब उत्तर प्रदेश के बदले हुए परिवेश की चारों ओर सराहना हो रही थी, ऐसे समय में भी माननीय नेता विरोधी दल ने उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन अनर्गल, औचित्यहीन बयानबाजी, छोटे बच्चों की तरह वीडियो गेम जैसे, ट्विटर-ट्विटर खेलकर प्रदेशवासियों को अपमानित करने एवं प्रदेश को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुःखद एवं निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने संघर्ष से तो कुछ भी अर्जित नहीं किया है, उनकी बचकानी हरकतें सदैव प्रमाणित करती हैं कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। मान्यवर, सदन को मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि तमाम दुष्प्रचार के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा इंवेस्टर समिट सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, यू0के0, आस्ट्रेलिया, जापान, इटली, यूएई, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, साउथ कोरिया, मॉरीशस, सिंगापुर जैसे 10 महत्वपूर्ण देशों ने पार्टनर कन्ट्री के रूप में सहभागिता की। हमारी सरकार ने निवेश का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी0आई0एस0 2023 के लिए दुनिया के 16 देशों के 21 शहरों में इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किये गये। साथ ही भारत के 10 महानगरों और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इन्वेस्टर समिट आयोजित की गयी। यही कारण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33 लाख 52 हजार 553 करोड़ रुपये का रिकार्ड निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की रैपिड ग्रोथ, गुड गवर्ननेंस का स्पष्ट प्रमाण है। माननीय मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शी सोच और चौमुखी विकास के संकल्प को जी0आई0एस0 2023 ने एक नयी मजबूती प्रदान की है। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर हम 6 महीने के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने की दिशा में ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ रहे है। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने पिछली बार बताया था कि एक बार वे एक स्कूल में गये, एक बच्चे को बुलाकर पूछे कि मुझे पहचानते हो ? तो बच्चे ने लपककर कहा हां, पहचानते हैं तो उन्होंने

पूछा, मैं कौन हूं ? तो बच्चे ने कहा, आप राहुल गांधी हैं। (हंसी) माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी छवि को ऐसा बना लिया है कि आज जनता की नजरों में नेता विरोधी दल और राहुल गांधी दोनों एक सिक्के के दो पहलू बन गये हैं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, जो एक प्रदेश के मुखिया रह चुके हों, उनके लिए कहना चाहता हूं कि बड़े मुंह से छोटी बात अच्छी नहीं लगती, मेरी उनको सलाह है कि बार-बार बचकानी हरकतों से बाज आएं और अपनी जग हंसाई न कराएं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कल ही नेता विरोधी दल कह रहे थे कि एम0ओ0यू0 हवा हवा में है, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार केवल एम0ओ0यू0 साइन करने को उपलब्धि नहीं मानती बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने में विश्वास करती है। दिनांक 31-10-2022 को ग्रेटर नोएडा में माननीय मुख्य मंत्री जी के कर-कमलों से उत्तर भारत के सबसे बड़े मेगा डेटा सेण्टर का लोकार्पण हुआ है।

मान्यवर, उस डेटा सेण्टर के निर्माण में एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि इसकी जमीन को हीरा नन्दानी ग्रुप ने कोविडकाल के दौरान ड्रोन से देखा और देखने के बाद इसपर सहमति हुई, एम0ओ0यू0 हुए और हमारी सरकार में कोविड की चुनौतियों के बावजूद तय समय में बनकर तैयार हो गया। लखनऊ के गोल्फ सिटी स्थित द सेन्ट्रम होटल, जिसमें नेता विरोधी दल और हमारे तमाम साथी उसमें जरूर गए होंगे। उसका एम0ओ0यू0 हमारी सरकार में 2018 में हुआ था और वह बन करके तैयार है और जी-20 की मेजबानी किया है। मान्यवर, सूची लम्बी है, इसलिए मैं नेता विरोधी दल से यही कहना चाहता हूँ कि पहले खुद हवा से जमीन पर आ जायें, तब उन्हें जमीन की चीजें दिखायी पड़ेंगी। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए मोस्ट फेवरेट डिस्टीनेशन बनकर उभरा है। वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्री फ्रेन्डली इको सिस्टम, बेस्ट इन्डस्ट्रियल पॉलिसी ने प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक तरक्की को बुलेट रफ्तार दी है। निवेश मित्र, निवेश सारथी पोर्टल ने सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से सभी आवश्यक एनओसी समयबद्ध ऑनलाइन दी जा रही हैं। उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ निवेश मित्र देश का सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टल बन गया अग्रणी राज्य है। पी0एम0 गति शक्ति नेशनल प्लान लागू करने में उत्तर प्रदेश आज प्रदेश में ट्रान्सपोर्टेशन, लॉजिस्टिक सुविधाओं में 2017 से पहले की तुलना में जमीन और आसमान का अन्तर है। सपा, बसपा की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने कभी यह नहीं सोचा कि अच्छी सड़कें हों, कभी नहीं सोचा अच्छे हास्पिटल हों, कभी नहीं सोचा कि एयर कनेक्टीविटी हो, कभी नहीं सोचा कि रेल कनेक्टीविटी हो, अपना घर कैसे भरे, अपनी तिजोरी कैसे भरे, केवल और केवल इसी में लगे रहे। मान्यवर, यह बात करते हैं कि सब कुछ हवा में है। इनको बताना चाहता हूँ कि आजादी के बाद सपा और बसपा और लम्बे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन इतने सालों में उत्तर प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट संचालित थे। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 09 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं, 12 एयरपोर्ट पर

काम हो रहा है, बहुत जल्दी 21 एयरपोर्ट के साथ 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के सिग्नेचर बनकर के उभरे हैं। आज पूरे देश के कुल एक्सप्रेस-वेज का 37.7 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। 07 नए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर काम चल रहा है, उनका निर्माण पूरा होने पर देश के एक्सप्रेस-वे का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में हो जायेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के कर कमलों से बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण इन क्षेत्रों के सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी औद्योगिक विकास की रोशनी पहुंच रही है। यह प्रदेश के चहुमुखी विकास के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी की कमिटमेंट को दर्शाता है। डाटा सेण्टर, डिफेन्स कॉरीडोर, मेडिकल डिवाइस पार्क आदि उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था और औद्योगिक विकास को नयी ऊंचाई दे रहे हैं। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक बार फिर से जनकल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से चार पंक्तियाँ कह कर अपनी वाणी को विराम दूँगा-

''जाति-पाँत के भेद मिटाकर, जिसने सबको एक किया,
है विकास के पथ पर चलना, जिसने यह संकल्प लिया,
रिश्वतखोरी, गुण्डागर्दी को है जिसने खत्म किया,
भ्रष्टाचार की कमर है तोड़ी, अपराधों का नाश किया।''

ऐसे कर्मयोगी माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फिर से प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

अब माननीय नगर विकास मंत्री जी।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 25 हजार 3 सौ 47 करोड़ 10 लाख 57 हजार से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह अपने में एक विलक्षण बजट है और उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था में उसका एक प्रमुख अंग बनाने की दिशा में लिया गया एक कदम है। यह बजट मा0 प्रधानमंत्री जी के सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वपोषक, सर्वतोषक समाज की जो उनकी विचारधारा है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है मा0 मुख्य मंत्री जी का जो जनकल्याणकारी अभिप्राय है, अभिगम है, उसका पोषण करने वाला यह बजट है। मैं अपने दोनों नेताओं के लिए मा0 नंदी जी ने थोड़ा ज्यादा विस्तार से कहा, लेकिन मैं मा0 वर्मा जी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए नगर विकास पर ही केंद्रित करूंगा। फिर भी अपने दोनों शीर्ष नेताओं के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी के लिए और मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो विकास निर्माण की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और मा0 प्रधानमंत्री जी जो देश को विश्व का एक सिरमौर देश बनाने में लगे हुए हैं उन दोनों लोगों के लिए एक छोटी-सी बात करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा।

जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा,
किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता।

यह हमारे दोनों नेता ऐसे ही है। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि देश के ऐसे विलक्षण नेताओं के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। सौभाग्य से ईश्वर की कृपा से बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से हमें यह अवसर मिला है। मा0 अध्यक्ष जी अब मैं पूरी बात नगर विकास की करने वाला हूं आप सबको मालूम है कि मानव सभ्यता गांव से शुरू हुई जंगलों से शुरू हुई, लेकिन मानव सभ्यता की जो पहचान है चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो उसकी खुदाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे समाज की सभ्यता के जो शहरीकरण और नगरीकरण के जो चिन्ह है वह हम देखना चाहते हैं और यही हमारी पहचान रही है। हमारे नगर हमारे किसी भी देश की किसी भी प्रदेश की पहचान रहे हैं। हमारे नगर उस प्रदेश की उस देश का आइना माने जाते हैं। अगर आप किसी देश में गए और उस शहर की उसके दस शहरों में से किसी एक शहर में गए और शहर अगर अच्छा दिखा, नगर अगर अच्छा दिखा तो आपका इंप्रेशन बढ़ता है कि वाह क्या बात है कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए। हम सभी कहीं न कहीं गांव से सम्बद्ध हैं और गांव से आते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी नगरों में अब रहने लगी है। भारत की लगभग एक तृतीय आबादी 1/3 पापुलेशन नगरों में रहने लगी है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इसका अनुपात कम है, लेकिन हम यह कई बार भूल जाते हैं कि हमारे बाबा गोरखनाथ में नेपाल के लोग भी आते हैं। हमारे शाकुंभरी देवी में उत्तराखण्ड के लोग भी आते हैं। हमारे विंध्याचल में मा0 मुख्य मंत्री जी चर्चा कर रहे थे हमारे विंध्यवासिनी देवी के धाम पर बिहार के लोग भी आते हैं, हमारे यहां कुंभ नहाने, माघ मेला नहाने करोड़ों लोग हमारे प्रदेश के बाहर से भी आते है। अगर दो

तिहाई जनता हमारी होती चाहे है तो एक तिहाई जनता बाहर की होती है तो इस प्रकार चाहे मथुरा वृंदावन हो, अयोध्या हो इस प्रकार जो हमारे कृष्ण की जो जन्मस्थली, लीलास्थली जो मथुरा वृंदावन है वहां पूरी दुनिया के लोग आते है देश की बात तो छोड़िए। ऐसे ही भगवान राम का अयोध्या धाम है, भगवान शिव की अविनाशी काशी है वहां पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोग आते हैं इसी प्रकार हम प्रयाग की अपनी तीन प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तीर्थराज प्रयाग की बात करें, या हमारा जो आदि ऋषियों का जो संगम रहा है नैमिषारण्य उसकी बात करें यहां जो भी आते हैं ज्यादातर उसमें से बहुत सारे लोग बाहर के आते हैं।

अगर हम इस फुट फॉल की बात करें, लोगों के आवागमन की दृष्टि से बात करें और एक बात और है कि ये सारी चीजें जिनसे भारत की पहचान होती है, उनमें से ज्यादातर चीजें चाहे भगवान राम की परम्परा हो, चाहे भगवान कृष्ण की परम्परा हो, चाहे भगवान शिव की परम्परा हो, महाभारत की बात हो, गंगा-यमुना की बात हो, इनसे सम्बन्धित ज्यादातर चीजें अपने उत्तर प्रदेश में हैं और इन सबका केन्द्र हमारे नगर हैं। इन सारी एक्टिविटीज के केन्द्र हमारे नगर हैं। इसलिए हमें अपने नगरों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इतना ही नहीं हमारे नगर अर्थ व्यवस्था के ग्रोथ सेण्टर माने जाते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश की जो नगरीय अर्थ व्यवस्था है, उसका हमारे प्रदेश की कुल जी0डी0पी0 में लगभग 65 प्रतिशत योगदान है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई भी देना चाहता हूँ। मैं इस बात का साक्षी रहा हूँ। वर्ष 2014 में जब मा0 मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री बने, बनारस के सांसद के रूप में तो उन्होंने मुझे थोड़ा बनारस पर ध्यान देने का संकेत किया, आदेश दिया। मैं बनारस आने-जाने लगा, देखने-सुनने लगा। लेकिन उन दिनों में इतना हैरान रहता था कि पूरी भारत सरकार लालायित है बनारस की मदद करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर उनके आग्रह पर पूरी भारत सरकार के चाहे सी0एस0आर0 का फण्ड हो, चाहे पी0एस0यू0 का फण्ड हो, चाहे सरकारी फण्ड हो, सबके सब लोग हमारी एक हिण्ट पर, हमारे एक निर्देश पर बनारस आकर दो-दो दिन, तीन-तीन दिन रुक करके काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ की सरकार सोई पड़ी थी, यहाँ की सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं थी, बनारस के विकास का तो मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद पूरा का पूरा फोकस होने के बावजूद राज्य सरकार में कोई इच्छा नहीं थी कि बनारस का हम कोई विकास करें, भगवान महादेव के इतने बड़े धाम को, अविनाशी काशी को हम भव्य और दिव्य बनाएँ। जो काम बाद में मा0 योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद वह काम शुरू हुआ। मुझे यह भी याद है कि मैं निराश होकर बनारस से जाता था और मा0 प्रधानमंत्री जी से कहता था कि सर कुछ हो नहीं रहा है, बनारस में कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं यह वर्ष 2014 से 2017 के बीच की बात कर रहा हूँ तो वे कहते थे कि इसका इलाज क्या है तो मैंने उनको एक इलाज सुझाया था। हमारी उस समय की मानसिकता और बुद्धि चूँकि मैं अधिकारी था तो मैने

अधिकारी वाला ही इलाज बताया। हमने कहा कि साहब ऐसा करिए, कम से कम कुछ नहीं तो एक सीनियर अधिकारी को वहाँ ई0ओ0 के रूप में या सी0ओ0 के रूप में या एम0डी0 के रूप में लगाइए। आप ई0ओ0 उसे जो भी कहिए, एक मुख्य अधिकारी को वहाँ लगाइए, उसे एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। तब जाकर मा0 प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान भी लिया, किसी की नियुक्ति भी हुई थी। लेकिन जो वास्तविक नगर विकास होता है, जो वास्तविक नगर प्रशासन होता है, उसकी शुरूआत वर्ष 2017 में जब मा0 योगी जी की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनी है, तब जाकर के चाहे मथुरा-वृन्दावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, सब जगह अब विकास रफ्तार पकड़ने लगा है, इसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूँ, मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा है। मा0 अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं हम कई बार हम सब अपने धामों पर आते-जाते रहते हैं। एक बार हम मथुरा-वृन्दावन गए, हम तो गए थे भगवान के दर्शन करने, पहली बार मौका था, पाँच-छः साल हुआ होगा, दिल्ली से गए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने हमें पहचान लिया और कहा कि साहब आप प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं तो हमने कहा, हाँ साहब हम वहीं से आए हैं, भगवान के दर्शन करने। यह वर्ष 2015 के आस-पास की बात है। वह आदमी हमारे सामने इतनी जिद करने लगा कि साहब यहाँ की सरकार कर क्या रही है, आपका मथुरा-वृन्दावन ऐसी जगह है कि जहाँ कृष्णा कॉन्सेसनेस के चलते, सम्भवतः वे इस्कॉन टेम्पल के मानने वाले रहे होंगे। इस्कॉन के ही चलते लेकिन उनकी बात सच भी तो थी। इस्कॉन से हम लोगों ने जो भगवान कृष्ण की कॉन्सेसनेस है, जो भगवान कृष्ण की बात है उसको हम लोगों ने पूरी दुनिया में फैलाया है लेकिन जब हमारी बात सुन करके कोई टूरिस्ट मथुरा-वृन्दावन आता है, तब उसको इतनी निराशा होती है कि कुछ पूछिए मत और हमारी तो बड़ी बेइज्जती होती है। उसने हमसे यह बात मा0 प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए कही। हमारे यहाँ मथुरा-वृन्दावन जैसा धाम, काशी जैसा धाम, माँ विन्ध्यवासिनी जैसा धाम, अयोध्या जैसा धाम है। आपने यहाँ पर 25-30 साल शासन किया है लेकिन इन जगहों पर आपने एक ईंट तक नहीं रखी। ये सारी की सारी जगहें केवल हमारी आस्था का ही केन्द्र नहीं हैं, बल्कि ये जगहें हमारे लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के केन्द्र भी हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से सजाएँ, इनमें अच्छे से काम करें तो यहाँ से हमारे लाखों-हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिल सकता है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेण्ट में उनकी रोजी-रोटी का इंतजाम भी हो सकता है। इतने महत्वपूर्ण है हमारे ये सारे सेण्टर्स।

माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में जैसा मैंने कहा पिछले 6 साल में जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम हुआ है, वह पहले इस राज्य में कभी नहीं हुआ और उसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को फिर से बधाई देता हूँ। मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी के निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में इस बार भी जो नगर विकास विभाग का बजट हमको दिया गया है हम उससे बहुत ही खुश हैं और बहुत ही सन्तुष्ट हैं। मैं इस सदन से गुजारिश भी करूँगा कि हमारा 37 नम्बर का जो बजट का प्रॉविजन है उसका समर्थन भी करें। विशेष रूप से मैं कुछ

बातों का उल्लेख करना चाहूँगा जो मा0 वित्त मंत्री जी ने हमें बजट में व्यवस्था करके दी है, उसके सम्बन्ध में महाकुंभ के लिए जहाँ चार गुना राशि बढ़ायी गई है। आने वाले वर्ष 2025 में जैसा मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक ऐतिहासिक कुंभ, एक भव्य और दिव्य कुंभ जिसमें पिछले बार आने वाले 22-23 करोड़ के सापेक्ष, लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की सम्भावना बताई जा रही है, उस हिसाब से हमें इंतजाम करना है उसके लिए धनराशि देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर विकास विभाग को अपनी सड़कों की मरम्मत करने के लिए अपना खुद का बजट दिया गया है। इस हेतु हम सब नगरवासियों की ओर से मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि 500 करोड़ रुपये की बड़ी रकम हम लोगों के हवाले रखी गयी है जिससे हम अपनी सड़कों की मरम्मत करा सकें। अमृत योजना, पेयजल और इससे सम्बन्धित जो योजनाएँ होती हैं उसका भी बजट बढ़ाकर ढाई गुना के आस-पास किया गया है। उसका बजट 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5616 करोड़ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसी प्रकार से बजट डबल कर दिया गया है तथा 1353 करोड़ की जगह 2707 करोड़ कर दिया गया है। हमारी कान्हा गौशाला, हमारी गायों की और हमारे पशुधन की यहाँ पर बहुत बातें हुयीं। आप सबको मालूम है कि नगर विकास विभाग भी गौशाला बनाता है, चलाता है और उनको निभाता है और मैं फिर से मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा 100 करोड़ रुपये का जो प्रावधान हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 170 करोड़ रुपया कर दिया है। मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना, पिछली बार आप सबने देखा कि राज्य में 653 नगर निकाय हुआ करते थे। पिछले कुछ महीने में हमने बहुत सारे नये नगर निकायों की रचना की है और उनकी संख्या बढ़ी है और यदि वर्ष 2017 से बात करें तो 241 नगर निकायों का या तो नव रचना हुई है या तो उनका विस्तार हुआ है। जैसाकि यहाँ बातें भी हो रही थीं कि कई ऐसे जो विस्तारित, नव विस्तारित या नव रचित हमारे नगर निकाय हैं, उनमें बहुत सी सुविधाओं का अभाव है। मा0 मुख्य मंत्री जी भी बात कर रहे थे कि गाँव से ही वह नगर में शामिल हुये हैं इसलिए उनमें सुविधाओं का अभाव स्वाभाविक है। उनकी व्यवस्था के लिए पिछली बार 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जो कि पहली बार व्यवस्था की गई थी, अब उससे भी बढ़ाकर इस बार 607 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके हमको दी गई है जिससे कि उन बाहरी इलाके में आने वाले उन क्षेत्रों का भी हम ध्यान रख सकें। यह जो मैं धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि मेरा खुद का अनुभव है कि आपने खुद एक ईंट वहाँ नहीं रखी थी और हमारी सरकार द्वारा जैसा कि काशी के पूरे कॉरीडोर में काम हुआ, वह भव्य और दिव्य बना दिया गया है, मथुरा, वृन्दावन में काम हो रहा है, विन्ध्यवासिनी देवी के धाम पर काम हो रहा है। ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं, अनेक हमारे तीर्थ स्थलों पर, इसके साथ ही हमारे विभाग को इस बार डेडीकेटेड 50 करोड़ रुपये का बजट, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर निकायों में, हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनकी बेइतरी के लिए,

उनकी देख-रेख के लिए, उनके ऊपर खर्च करने के लिए हमारे हस्तगत यह राशि रखी गयी है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक जो मा0 मुख्य मंत्री जी, अभी बात कर रहे थे आकांक्षी नगर योजना, जो हमारे नगर निकाय पीछे रह गये हैं, पिछड़ेपन का शिकार हैं और इसमें हम जिलों की तर्ज पर ब्लॉक की तर्ज पर, जो उनको आकांक्षी मानते हुए उनका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए विकास करने के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन सारे प्रावधानों और ऐसे अनेक जन-उपयोगी प्रावधान जो किये गये हैं उन सबके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में नगरीय प्रशासन या नगरीय व्यवस्थापन अगर शुरू हुई है तो योगी जी के आने के बाद शुरू हुई है। इसलिए मैं बार-बार उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 साल बाद एक ऐतिहासिक जनादेश देते हुए माननीय योगी जी को फिर से मुख्य मंत्री बनाया है। माननीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो हमारे कार्यकाल की शुरुआत मार्च, अप्रैल में हुई, उसके बाद अनेक ऐसे प्रयास किये गए, अगर सब कुछ हम जुड़ाने जायेंगे तो बहुत लम्बा हो जायेगा, लेकिन सबसे पहला काम जो हमने किया वह था हमारे खुद के मंत्री के रूप में मेरे साइन से जो पहला निर्णय हुआ था वह राज्य के सफाई कर्मचारियों की पगार बढ़ाने का निर्णय था। मात्र पगार बढ़ाने का निर्णय नहीं किया गया उसके साथ हमने यह भी निर्णय लिया कि अब जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे-जैसे श्रम विभाग, माननीय राजभर जी का विभाग अपनी दरें सुधारेगा, न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ायेगा वैसे-वैसे स्वतः और स्वाभाविक वह सफाई कर्मचारियों पर लागू हो जायेगी, अब मंत्री के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार के विश्वास के साथ हमने शुरुआत की। दूसरा हमने जो निर्णय लिया था वह 31 मार्च का निर्णय था उसके बाद असंख्य ऐसे निर्णय हुए हैं जिसमें हमने कहा कि जो हमारा सफाई कर्मचारी मेनहोल में उतरता है उसके पास सेफ्टी किट होनी चाहिए, उसकी जान-माल की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यह सब हमने सफाई कर्मियों के खुद के वेल्फेयर हेतु शुरू किया। एक हफ्ते बाद फिर उनके संगठनों को हमने बुलाया और कहा कि भाई देखिये आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन नगर की सफाई का ध्यान रखना ये आपका भी कर्तव्य है, आपका भी धर्म है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में शायद कभी नहीं हुआ था कि उनकी स्वेच्छा से हमने सुबह 05 बजे से ले करके 08 बजे के बीच आग्रह किया कि हमारे नगरों की सफाई शुरू करके खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में ट्रैफिक हो जाता है, चिल्ल-पों होने लगती है, धूल उड़ने लगती है, लोगों का आवागमन उससे बाधित होता है, अगर हम उसी में झाड़ू लगाने लगें तो दिक्कत होगी। हमारी सफाई कर्मी महिलाओं ने भी हमारे इस आफर को, हमारी इस भावना को समझते हुए बहुत अच्छे से उसका सत्कार किया। हम राजनैतिक जो भी बातें करें लेकिन हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि आजकल इस ठण्डी में सुबह 05-06 बजे से मोहल्ले, गलियों और रास्तों में सफाई शुरू हो जाती है। मैंने कहा कि

खाली मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि करोड़ों-करोड़ रुपये की मशीनें आ करके हमारे नगर निगमों में, नगर निकायों में पड़ी थीं। उनका उपयोग कम हो रहा था, नहीं हो रहा था और डीजल इधर-का-उधर और उधर-का-इधर जाता था। लेकिन उनका उपयोग करते हुए मानव शक्ति में हम कैसे इजाफा करें, कैसे हम उसको कई गुना बनावें इस तकनीक के इस तरकीब के तहत हमने कहा कि मशीनों का भी उपयोग होना चाहिए ! इस प्रकार मनुष्य के पुरुषार्थ से और मशीन की कुशलता से हमने एक व्यापक सफाई अभियान शुरू किया है और मुझे यह कहना पड़ेगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों ने इसमें हमारा बहुत सहयोग किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह भी मालूम था कि सिर्फ कहने से, उपदेश दे देने से या आदेश दे देने से सफाई नहीं हो पायेगी। इसलिए हमने उसकी मानीटरिंग के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से नयी व्यवस्थाएं खड़ी कीं। अगर फील्ड पर सुबह 5 बजे से हमारा सफाई मित्र झाड़ू लगाता है तो हमारे डायरेक्टर लोकल बॉडीज के आफिस में डी0सी0सी0सी0 नाम की हमने एक व्यवस्था शुरू की। डेडिकेटेड कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर इस व्यवस्था के तहत अधिकारी सुबह 05 बजे आकर बैठ जाते हैं और वीडियो पर सबकी लोकेशन लेते हैं, जी0पी0आर0एस0 पर उनको ट्रैक करते हैं कि कहां सफाई हो रही है, सफाई कर रहे हो तो दिखाओ, सफाई करके अगर आगे बढ़ गये हों तो उसकी फोटो भेजो इस तरह से पूरा एक अभियान 11 महीने से लगातार चल रहा है और जिसके अच्छे परिणाम भी आते हुए दिख रहे हैं।

मान्यवर, साथ ही हमने कुछ विशेष तिथियों को चिन्हित करते हुए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितम्बर को जन्मदिन है, उससे ले करके परम् पूज्य गाँधी जी के जन्मदिन तक विशेष अभियान चलाने की शुरुआत किया और उसके बाद अभियानों का यह सिलसिला रुका ही नहीं और यह सिलसिला हमने कभी रोका ही नहीं, हर 15 दिन, हर 20 दिन पर एक नये कलेवर के साथ चलाया, क्योंकि अगर वही बात हम करेंगे तो हमारे कर्मचारियों का इंटरेस्ट खत्म हो जायेगा। इसलिए कुछ न कुछ उनको नया स्लोगन दे करके, कुछ न कुछ उनको नई तरकीब बता करके हमने गलियों और कूचों की सफाई, चौराहों का सुन्दरीकरण, पार्कों का सुन्दरीकरण कराया, हमारे अमृत तालाबों का, हमारे जो वॉटर बॉडीज सूख जा रही थीं, जिसमें गन्दगी, मलवा जा करके पट रहा था, जहाँ जानवर जैसे गाय, भैंस और सुअर जाती थीं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी वह हानिकारक होता था तो हजारों-हजार ऐसी जगहों की सफाई करायी है। अमृत तालाब, अमृत सरोवर, पार्क जो एन्क्रोचमेंट से बर्बाद हो गये थे, उनको भी हमने खाली करा करके ठीक किया। एक अभियान जिसका मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा, वह हमने 75 जिलों में 75 घण्टे का चलाया था। जिसको हमने वलनरेबल गारबेज प्वाइंट्स कहा था। कुछ ऐसे गारबेज प्वाइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कूड़े-कचरे के ढेर होते हैं कि हम बचपन से युवा हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन वह कूड़े का ढेर वैसे का वैसे रहता है, कभी उन्नीस हो जाता है, कभी बीस हो जाता है। वहाँ जानवर घूमते रहते

हैं, वहाँ सुअर और कुत्ते घूमते रहते हैं। वह कूड़े का ढेर उस मोहल्ले का एक परमानेंट नागरिक बन जाता है।

हमारे विभाग की भाषा में इनको वलनरेबल गारबेज प्वाइंट्स कहते हैं। ऐसे 4 हजार से ज्यादा जगहों को हमने उन 75 घण्टों में ठीक किया, साफ किया और इतना ही नहीं हमने यह भी कहा था कि देखिये आज तो आप साफ कर देंगे, कल फिर से वहाँ कूड़ा पड़ना शुरू हो जायेगा, वहाँ फिर से गन्दगी होना शुरू हो जायेगी तो क्या करेंगे ? इसलिए हमने यह कहा कि इन जगहों को अपने कंट्रोल में लेते हुए और उसमें से ज्यादातर जगहें खुद की नगर निकाय की ही थीं, खुद के अपने ओपन प्लॉट थे और गंदगी के केन्द्र बनते थे। हमने कहा कि उनको बाग-बगीचा बनाओ, पार्क बनाओ, सेल्फी प्वाइंट बनाओ और मुझे बताते हुए आनन्द हो रहा है कि ऐसे हजारों जो गारबेज प्वाइंट्स थे, कूड़े-कचरे के ढेर की जगह थी, उनमें से ऐसी हजारों जगहों पर सुशोभन का कार्य हो चुका है। ऐसी कई जगहें हैं। एक व्यक्ति ने उन्हीं दिनों ट्वीट किया था और मीडिया में मैंने उसका निवेदन देखा था, उसने कहा कि साहब ये हमारे घर के सामने जो कूड़े का ढेर था, उसे मैं जब से पैदा हुआ, तबसे देख रहा था और वह एक प्रकार से हमारे घर का पता हो गया था, एड्रेस बन गया था। लोग कहते थे कि इस चौराहे से दायें चले जाना, उस चौराहे से बायें चले जाना और उसके बाद जो कूड़े का ढेर मिलेगा, वही, उसका घर है। उसने कहा कि नगर निगम के लोगों ने हमारे घर का पता बदल दिया है। इस अभियान के चलते हमारे घर का एड्रेस बदल गया है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे हजारों स्कूल थे, हालाँकि स्कूल तो ठीक-ठाक थे, लेकिन चूँकि गन्दी जगह पर थे, इसलिए लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। कई ऐसे फ्लैट थे, कई ऐसी सोसाइटियाँ थीं, जहाँ फ्लैट खाली पड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ गन्दगी का ढेर था। ऐसी तमाम बातें हमारे अनुभव में आई हैं जिनका बहुत अच्छा परिणाम, बहुत सुखद परिणाम हमारे नगरीय जीवन पर पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के सक्रिय प्रशासन के चलते जो हमारे प्रदेश में, हमारी भूमि पर जी-20 की मीटिंग्स का आयोजन किया गया। वह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे नगर विकास विभाग ने , हमारे विकास प्राधिकरण ने, हमारी पूरी टीम ने, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत परिश्रम किया। माननीय अध्यक्ष जी इन सबने मिलकर जो काम किया है, यह भगीरथ काम उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। आगरा में इतनी प्रशंसा हुई, पूरी दुनिया के जो लोग आये थे, वह प्रशंसा करके गये। भारत सरकार के सचिव, जो उन मीटिंग्स के एक कोआर्डिनेटर थे, मुख्य संयोजक थे, उन लोगों ने हम लोगों को लिखित और मौखिक इतने अच्छे सन्देश भेजे, यहाँ तक कहा है, मैं आनन्द, खुशी और गौरव के साथ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, उन्होंने इतना बढ़िया कहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ के चलते हमारे देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है।

मान्यवर, हमारे देश को ले करके जो भ्रांतियां थीं, हमारे देश को ले करके जो लोगों के मन में कमी होने का एहसास था कि भारत में ऐसा ही होगा। वह एकदम से बदल गया है, यह हमारे आगरा और लखनऊ ने करके दिखाया है। उसी कड़ी में हमने अपने नगरीय निकायों को यह भी कहा था कि यह सिर्फ आगरा और लखनऊ में ही नहीं है, सिर्फ वाराणसी, नोएडा में ही नहीं, जहाँ जी-20 की मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जो व्यक्ति लखनऊ आयेगा हो सकता है वह नैमिषारण्य घूमने जाये, हो सकता है अयोध्या घूमने चला जाये। जो आगरा जायेगा, वाराणसी जायेगा अगल-बगल के टाउन में चला जाये, हमारे अलीगढ़ चला जाये, मुरादाबाद चला जाये तो क्या करेंगे क्या हम वहाँ गंदा छोड़ेंगे ? तो हमने यह कहा हमारे सभी नगरों में एक स्टैण्डर्ड सफाई होनी चाहिए और उसके लिए हमने ग्लोबल सिटी नाम का एक वैश्विक नगर बनाने के लिए अभियान छेड़ा जो जनवरी से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। यह अभियान 100 दिन का था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा और महामहिम राज्यपाल जी को जिन्होंने अपने अभिभाषण में भी उस वैश्विक नगर अभियान का उल्लेख किया है। इसके तहत् हमारा ऐम है कि हम अपने नगरों को स्वच्छ, सुन्दर, सुशोभित बनाते हुये वहाँ आजीविका के अच्छे अवसर पैदा करते हुये, वहाँ अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हुये। हम अपने नगरों को विश्व कच्छा के नगर, वैश्विक स्टैण्डर्ड के नगर, वैश्विक मापदंड के नगर हम कैसे बनायें इस बात के लिए काम कर रहे हैं । आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही हमारे पूरे नगरीय परिवेश में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी उसमें एक और आयाम जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। मैंने पहले यह भी कहा कि हम अपने नगरों को गुड टू ग्रेट बनाने की कोशिश में लगे हुये हैं। उसी दिशा में पहले हमने कहा था कि जैसे कई जगह शाम को युवा बच्चे म्यूजिक ले करके बैठ जाते हैं अपने नगरों में। अब जहाँ खुली जगह हैं वहाँ बैठें और म्यूजिक बजावें आनन्द करें। उसी कड़ी में हमने आयुष विभाग के साथ एक समझौता किया हैं, हमारे दोनों विभागों ने कि उनके पास योगा के प्रशिक्षक हैं हमारे पास पार्क खाली पड़े हुये हैं। उन पार्कों में कोई जाता नहीं है लोग जा करके अपना लारी गल्ला रखते हैं, इन्कोचमेंट करते हैं। अगर हम योगा अभ्यास शाम, सुबह करें तो उन पार्को की सफाई होगी। दूसरे उसके अगल-बगल के लोगों का वहाँ आनां-जाना होगा। लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, लोगों को योग की शिक्षा मिलेगी। इस प्रकार का माननीय आयुष मंत्री जी के साथ एक समझौता किया है, उनको धन्यवाद देते हैं। हम नगरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सुधारें इस दिशा में हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत् हैं, पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमने बुजुर्गों के लिए केयर सेन्टर बनाने का भी निर्णय लिया है। वायु प्रूदूषण में कुछ ही महीनों पहले लखनऊ को नम्बर वन का दर्जा मिला है पूरे देश में। सबसे स्वच्छ वायु के सर्वेक्षण में। बनारस हो या लखनऊ हो हमारे यह नगर बहुत ही ऊपर आये हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को हम लोग चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बाते एकतरफा नहीं जानी चाहिए नागरिकों का क्या फीड बैक है न कहीं नाली गंदी रहेगी, न कहीं

सड़क गंदी रहेगी। उसकी शिकायत करने की भी व्यवस्था, जन शिकायतें सुनने की व्यवस्था, अच्छी की हुई हैं। पहली बार नगर विकास विभाग में 1533 नम्बर का फोर डिजिट टोल फ्री नम्बर हम लोगों ने इस्टेबलिश्ड किया है। चार डिजिट अब नहीं मिलता है, खत्म हो गई सीरीज लेकिन भारत सरकार से किसी तरह से ले करके उसको हमने कार्यान्वित किया है। यह जून, 2022 से कार्यरत है। इसके बाद नगरीय लोगों की बेहतर सेवा हो सके उनकी शिकायतों का बेहतर संज्ञान लिया जा सके, उनको निस्तारित किया जा सके इस दृष्टि से मैंने अपने स्तर पर सम्भव नाम का एक पोर्टल शुरू किया है। जिसमें पहली हमारी सूचना है कि हर नगर निकाय का अधिशाषी अधिकारी हर सोमवार को 10 बजे जन-सुनवाई के लिए बैठेगा और लोग आ करके उसको अपनी शिकायत देंगे।

मान्यवर, उसी के साथ नगर निगमों में हर मंगलवार को हमारा नगर आयुक्त 10 बजे जन-शिकायतें सुनेगा। इसके बाद भी अगर जन-शिकायतें रह जाती हैं, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था किया है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के पोर्टल पर जो आई0जी0आर0एस0 पर शिकायतें आती हैं, प्रधानमंत्री के पोर्टल पर आती हैं, हमारे पोर्टल पर आती हैं, सोशल मीडिया/अखबारों के जरिये मिलती हैं, हम लोगों को लोग प्रत्यक्ष देकर जाते है। उन सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए हमने एक टीम बनायी हुई है कि आपका यही एक काम होगा कि पूरे महीने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या शिकायतें आ रही हैं, क्या-क्या निस्तारण होना बाकी है, उनको लेकर महीने के एक बुधवार को उसी सम्भव पोर्टल के तहत मैं स्वयं बैठता हूँ। उसमें एक तरफ सचिव स्तर के हमारे निकायों के अधिकारी होते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो शिकायतकर्ता हैं वे होते हैं। आज कल जूम मीट से किसी को भी जोड़ना बड़ा आसान हो गया है, उनको भी हम रखते हैं। उनकी जो प्रत्यक्ष शिकायतें निस्तारित नहीं हो पाती हैं, उन शिकायतों के निस्तारण की हम व्यवस्था करते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि एक ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन जायेगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आया ? मा0 मुख्य मंत्री जी ने काफी कुछ आपको समझाया है, मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी बात और ऐड करूँगा। अभी जो 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' हुई, उसमें 2 लाख 8 हजार करोड़ रुपये का निवेश हमारे नगरीय क्षेत्रों में कोई सफाई के काम में, कोई प्लास्टिक के काम में, कोई रि-साइकिलिंग के काम के लिए आए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार एक ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनती है। उसमें हमारा नगरीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करता है। आप पूरी दुनिया के किसी भी निवेशक से पूछिए, आप उसको सारी सब्सिडी दे दीजिए, सारी राहत दे दीजिए, सारी सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन अगर उसके परिवार को रहने के लिए हमारे शहरों/नगरों की क्वालिटी आफ लाइफ ठीक नहीं है, तो कोई अपने यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। अगर हम अपने नगरों को ठीक कर लें, हमारी नगरीय सुविधाएं/सेवाएं ठीक हो जाती हैं, तो कोई भी निवेशक कहीं भी निवेश करने में परहेज नहीं

करेगा। हमारा छोटा सा विभाग कितना बड़ा योगदान एक ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम कर रहा है, उसका एक उदाहरण है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ये हमारे जो ग्रोथ सेंटर हैं, इसमें बच्चे अपने सपने लेकर आते हैं, अपना टैलेन्ट लेकर आते हैं। हमारे गाँवों से नौजवान उनको जब काम करने का वातावरण मिलेगा, उनको काम करने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी, वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा, तो स्वाभाविक बात है कि उनका आउटपुट एक से डेढ़ गुणा होगा। इसलिए हमारे नगरीय क्षेत्र कैसे एक ट्रिलियन डालर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसका मैंने एक उदाहरण दिया।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। उसका उत्तर अपने भाषण में दे दीजिएगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, दो बातें कहकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा। मैं यह नहीं मानता कि यहाँ बैठे हुए अपने में से कोई ऐसा करता होगा, लेकिन आपके यहाँ आने-जाने वाले लोग अगर गलियों में थूकते हों, पब्लिक प्लेसेज पर थूकते हों, ऑफिस में, कचहरी में, अस्पताल में थूकते हैं, तो हमने मा0 योगी जी से बिना पूछे दण्ड का प्रावधान कर दिया है, क्योंकि ये चलेगा नहीं। मा0 योगी जी छः साल से तपस्या कर रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर एक साल से सफाई करने का जो तपस्या कर रहे हैं, मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदन, ये काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इसमें थोड़ी सी कड़ाई नहीं करेंगे।

गीला सूखा कूड़ा मेहरबानी करके अलग कर दीजिए, थोड़ा सा समय से दे दीजिए, जैसे ही सफाई कर्मचारी सफाई करके आगे बढ़ता है वैसे ही लोग आकर कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं। इतनी जिम्मेदारी से मैं 1 वर्ष से स्वयं लोगों को सिखाने में लगा हुआ था और मा0 मुख्य मंत्री जी यह काम कई साल से कर रहे हैं, लेकिन अब हमने वहां भी दंड का प्रावधान करने की सूचना दी है। मा0 सदन हमें सहयोग दे हमें आशीर्वाद दें, हम अपने नगरों को स्वच्छ बनायेंगे और हम नगरों में बेहतर सुविधाएं, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को आने वाली पीढ़ियों में मिलें। उस दिशा में और काम होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी 6:30 बजे हैं और जो कटौती का प्रस्ताव मा0 सदस्य रखेंगे उनको 15 से 20 मिनट का समय दिया जाएगा और फिर इधर से एक सदस्य और उधर से एक सदस्य बोलेंगे, वह मैं निर्धारित कर दूंगा। मा0 वित्त मंत्री जी, आज यहां पर दो महत्वपूर्ण विषय उद्योग विकास विभाग व नगर विकास विभाग से सम्बन्धित हैं, जरा इस बात की जानकारी कर लेंगे कि दोनों विभागों से सम्बन्धित अधिकारी आज बजट के समय में उपस्थित रहें तो उचित होगा। अगर उपस्थित नहीं है तो उनको जानकारी दे देंगे। क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दोनों विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर आये हुए हैं तो अच्छी बात है। वर्मा जी आप हर समय ऐसे ही बीच में खड़े हो जाते हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि कल चिकित्सा शिक्षा का बजट है उसकी कार्यपूर्ति का निर्देश क्या है, वह तो समय से मिलना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है आप से एक काम करवा दीजिए, इनकी सीट दिखवा लें कि कहीं ऑलपिन तो नहीं लगी वर्मा जी की सीट में। क्योंकि यह बार-बार खड़े हो जाते हैं। विषय होगा तब भी और विषय नहीं होगा तब भी यह खड़े हो जाते हैं। आप इनकी ऑलपिन मार्शल को भेजकर हटवा दीजिए।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपये कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी हम सब लोगों ने सदन में माननीय औद्योगिक विकास मंत्री के बजट भाषण में चर्चा को सुना 20 हजार 586 करोड़ 54 लाख 10 हजार रुपये का यह बजट जो वित्तीय प्रबन्धन का भाव दर्शाता है। जो बजट मा0 मंत्री जी पेश किया है, यह प्रदेश को खुशहाली के पथ पर ले जाने के बजाय रोजगार और उन्नति का विरोधी यह बजट है। मान्यवर, मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जिन भी चीजों की चर्चा करी है मैंने बजट पुस्तिका जो 4 बजे हमें मिली है। उसे पढ़ा शायद इसलिए मा0 मंत्री जी ने अपने बजट पर चर्चा न करके पूरा बजट भाषण विषयान्तर किया, मैंने बजट पुस्तिका के पेज नम्बर 1 से ले करके पेज नम्बर 127 तक पढ़ा है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी के बजट भाषण की पूरी मिनट्स देख लें तो लगेगा पेज नम्बर 1 से पेज नम्बर 127 तक का एक भी विषय, एक भी कार्य योजना, एक भी परियोजना उन नीतियों पर चर्चा करने का कार्य नहीं किया बल्कि मा0 मंत्री जी का पूरा का पूरा ध्यान नेता विरोधी दल के कपड़ों पर और सांड़ों पर है। जो सांड़ आज प्रदेश के किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं, मा0 मंत्री जी का पूरा ध्यान उन किसानों के बजाय सांड़ों पर रहा है। माननीय मंत्री जी ने औद्योगिक विकास विभाग के बजट पर चर्चा करने के बजाय उन

गौ-माताओं की चर्चा की, जिन गौ-माताओं को चारे के अभाव में, पानी के अभाव में आपने तिल-तिल करके मार डाला, (शेम, शेम की आवाजें आयीं।) उन गौ-माताओं की चर्चा करने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का पूरा का पूरा बजट भाषण इस बात पर केन्द्रित रहा है कि किस तरीके से बूथ जिता करके सरकार बनायी जाती है, उसका पूरा का पूरा महिमामंडन औद्योगिक विकास के बजट भाषण में रहा है। इससे समझा जा सकता है कि अगर बजट भाषण के दौरान विभागीय नीति की चर्चा न होगी या विभाग की कार्य-योजनाओं की चर्चा नहीं होगी तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश आयेगा, कैसे उद्योगों की स्थापना होगी और उद्योगपतियों में कैसे विश्वास जग सकेगा ? मान्यवर, औद्योगिक विकास विभाग के बजट भाषण पर मंदिर की चर्चा होना, कपड़ों की चर्चा होना और किसी का ट्विटर देख करके उसके ट्विटर की चर्चा करना, इससे लगता है कि माननीय मंत्री जी का मन अपने विभाग की योजनाओं, अपने विभाग में न लग करके केवल दूसरों को निहारने में लगता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बीस हजार पाँच सौ छियासी करोड़ चौवन लाख दस हजार रुपये का जो बजट है, यह बजट प्रदेश की खुशहाली का बाधक बजट है। चूँकि बजट में बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रबन्धन का अभाव दिख रहा है।

मान्यवर, हम सब लोग जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का आईना देखते हैं तो हमको मिलता है कि हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मानव सम्पदा, कृषि सम्पदा और खनिज सम्पदा पूरी दुनिया में अद्वितीय है। अगर इन सम्पदाओं का समुचित उपयोग करके औद्योगिक विकास को धरातल पर लाया जाता तो शायद हम सब लोगों ने कोविड-19 के वक्त 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो जो आईना उत्तर प्रदेश ने देखा, हम सब लोग शर्मसार हुए कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के अभाव में, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए कोई दिल्ली में जाकर, कोई मुम्बई में जाकर टैक्सी चलाने का काम करता था, कोई सूरत की साड़ी की फैक्ट्रियों में जाकर वहाँ पर काम करता था और कोई पंजाब में भट्ठों पर कारीगर का काम करता था। बड़े पैमाने पर ऐसे लोग रोजगार के अभाव में हमारे प्रदेश से पलायन कर जाते हैं। मान्यवर, इस मानव सम्पदा का उपयोग प्रदेश की खुशहाली के लिए हो सकता है। लेकिन हम सब लोगों ने हमेशा जो भी बजट है, हमने पूरा 01 से लेकर 127 पेज तक महज एक घण्टे में पढ़ा और जो निष्कर्ष निकलता है वह यही निकलता है कि यहाँ पर जो भी योजनायें बतायी गयीं, वो योजनायें केवल लकीर की फकीर साबित हो रही हैं। जिसका परिणाम है कि जो भी इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आये उन्होंने कोई ऐसा उद्योग नहीं लगाया जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी रोजगार मिलता और उत्तर प्रदेश को समृद्धि भी मिलती। बल्कि इस तरीके से लोगों ने अपने उद्योग लगाये कि केवल उनका व्यापार हुआ, उनकी तरक्की, समृद्धि तो हुई, लेकिन प्रदेश की समृद्धि नहीं हुई। प्रदेश के नौजवानों के हाथों में कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर देख लें कि जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उनकी योजनाओं को, उनके द्वारा किये गये कार्य योजनाओं को देख लें तो

उसमें मिलता है कि बड़े पैमाने पर जो उद्योगपति आये और इण्डस्ट्रियल हब का सपना दिखा करके आये थे, जो आपकी यू0पी0 इन्वेस्टिंग योजनाओं का लाभ उठा करके यहाँ के संसाधनों का उपयोग किया। जो कम पैसे में सरकारी जमीन को हासिल किया और इसके साथ-साथ ऊर्जा और न जाने कितने तरीकों के वाणिज्य टैक्सों आदि का फायदा उठाने का कार्य किया, लेकिन उन लोगों ने कोई ऐसा उद्योग नहीं लगाया जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इण्डस्ट्रियल हब डेवलप हुआ है, बल्कि यह कह सकते हैं कि उन लोगों ने उद्योग लगाने के नाम पर केवल और केवल रेजीडेंसियल-हब बना करके उसमें अपना व्यापार करने का काम किया, अपनी समृद्धि करने का कार्य किया। मान्यवर, मैंने बजट को पढ़ा और अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2018 को ले करके बड़ा महिमामंडन हुआ, मंत्री जी ने चर्चा की और...

मान्यवर, इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को भी ले करके चर्चा करने का काम किया। जो 2018 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी चार लाख अट्ठाइस हजार करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 साइन किए गए थे जिसमें लगभग एक हजार चौरासी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए थे चार लाख अट्ठाइस हजार करोड़ रुपये के लेकिन अगर उसमें का कोई भी पैसा इस्तेमाल हुआ होता तो जो भी उद्योगपति आए थे जिन्होंने एम0ओ0यू0 साइन किया था अगर उत्तर प्रदेश के किसी कोने में उद्योग लगाया होता तो 2020 के वक्त जब लॉक डाउन लगा था। तो आइना दिखा दिया कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी रोजी-रोटी के लिए अपने बच्चों का पेट भरने के लिए प्रदेश नहीं छोड़ना पड़ता इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पूरे बजट को पढ़ा इन्होंने जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की जो अभी दस से बारह फरवरी तक उत्तर प्रदेश में हुआ है इसमें 16 देशों के लोग आए थे और जो सरकार ने बताया जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि तैंतीस लाख बावन हजार करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 साइन किए गए और उन्नीस हजार दो सौ बानबे एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि दुनिया के कोन-कोने से उद्योगपति तो आए, लेकिन जो सरकार के सबसे भरोसे के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की राह मैं देखता रहा वह उत्तर प्रदेश नहीं आए शायद उनको पता था कि यह इन्वेस्टर्स समिट किसलिए हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप उसकी राह क्यों देख रहे थे।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं इन्वेस्टमेंट के लिए देश के सबसे बड़े उद्योगपति का उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं रहा दुनिया के कोने-कोने से आपका पूरा का पूरा मंत्री परिषद् गया और उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से उनका स्वागत-सत्कार तो

हुआ, लेकिन जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं जो आपके भरोसे वाले सबसे बड़े उद्योगपति हैं वह कहीं नजर नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि यह महाछलावा है इसलिए उन्होंने आपकी सरकार पर विश्वास नहीं किया और उत्तर प्रदेश की आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उन्होंने शिरकत करने का काम नहीं किया। मैंने जो बजट को पढ़ा यू0पी0 जो पहले उद्योग बन्धु के नाम से जाना जाता था अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं विभाग की तो उद्योग बन्धु के कार्यालय में जाकर के देख लें वहां पर बड़े पैमाने पर हमारी जो नीतियां है जो सरकार की नीतियां होती हैं क्योंकि उनको प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी आधार भूत सुविधाओं के लिए चाहे भूमि की जरूरत हो, या विद्युत की जरूरत हो, वित्त की जरूरत हो, वाणिज्य कर आदि की सुविधाओं का मुहैया कराना और इनका प्रचार प्रसार करना उसकी जिम्मेदारी होती है वो खुद भी बेकार पड़े हुए हैं अगर आप उन कार्यालयों में जाकर के देखेगे तो वहां पर अधिकारी, कर्मचारी या तो पान खाते नजर आएंगे या तो चाय पीते नजर आएंगे इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं बचा है। यूपीडा द्वारा जितनी भी क्रियान्वित परियोजनायें हैं मैं क्योंकि बजट पर चर्चा करूंगा मा0 मंत्री जी अपने बजट पर जो बजट पुस्तिका है जो बजट की कार्य योजनाएं है उस पर एक भी बिन्दु पर चर्चा करने का काम नहीं किया है मैं उनके बजट पर चर्चा करना चाहूंगा कि यूपीडा द्वारा जो भी क्रियान्वित परियोजनायें हैं चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना हो, चाहे पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना हो, चाहे बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हो, और चाहे डिफेन्स कॉरीडोर की परियोजना हो, समय समय पर हमेशा आप लोगों को बीच में खबरें आती रहती हैं पूरे प्रदेश के बीच में आती रहती हैं, निराशाजनक नकारात्मक भ्रष्टाचार की खबरें विभिन्न संचार माध्यमों के रूप में हमारे आपके बीच में परोसी जाती हैं। इसलिए उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है हर कोई यह जानता है कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देखें या ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देखें या यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देखे या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को देख लें जिसको हम लोग यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के रूप में जानते हैं। चाहे गोरखपुर औद्योगिक निगम विकास प्राधिकरण को देख लें, या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लि0 को देख लें या सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देख लें या उ0प्र0 राज्य वित्त निगम लि0 को देख लें या उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0 को देख लें या उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0 को देख लें या पिकप को देख लें या उ0प्र0 वित्तीय निगम को देख लें यह सारे के सारे निगम और प्राधिकरण की रुचि केवल और केवल अपना डेवेलपमेंट करना है औद्योगिक विकास के बजाय औद्योगिक हब विकसित करने के बजाय केवल और केवल रेजीडेंसियल हब विकसित करके अपने लोगों का व्यापार करना रह गया है।

मान्यवर, इनके प्राधिकरणों के सारे ब्यौरे को देख लें। आप प्राप्तियों के रूप में देखें तो चाहे वह पूँजीगत प्राप्तियाँ हों, राजस्व की प्राप्तियाँ हो, औद्योगिक योजनाओं से प्राप्तियाँ हों,

आवासीय भूखण्डों से प्राप्तियाँ हों, आवासीय भवन से प्राप्तियाँ हों, वाणिज्यिक योजनाओं से प्राप्तियाँ हों, संस्थागत योजनाओं से प्राप्तियाँ हों अथवा ग्रुप हाउसिंग योजनाओं से प्राप्तियाँ हों, सभी प्राप्तियों को आप देखें और उसके सापेक्ष जब आप भुगतान पर नजर डालते हैं चाहे वह पूँजीगत भुगतान हो या राजस्व भुगतान हो, सभी मदों को आप देख लें, इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यह केवल और केवल लकीर का फकीर है। इसके अलावा कोई भी नयी चीज इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। मान्यवर, जिन उद्योगों ने उत्तर प्रदेश को अपनी एक अलग पहचान दिलाने का काम किया, प्रदेश के कोने-कोने में हमारी अपनी एक गुणवत्ता है, प्रदेश के हर एक जनपद की अपनी कुछ न कुछ गुणवत्ता होती है, वहाँ की अपनी कुछ सम्पदा होती है, वहाँ का अपना एक स्किल्ड मैनपॉवर होता है, लेकिन औद्योगिक विकास में उसका इस्तेमाल करने का काम नहीं किया गया। इसीलिये मैंने कहा कि इसमें घोर वित्तीय प्रबन्धन का अभाव है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपने बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बात तो की होगी, लेकिन जो यहाँ की पहचान रहे हैं चाहे कानपुर के साबुन उद्योग तथा चमड़ा उद्योग को विकसित करने की बात हो, क्रतिम अंग बनाने के उद्योग हों उस पर मा0 मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। चाहे अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, उस पर मा0 मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। चाहे जनपद प्रतापगढ़ का ऑवला उद्योग हो, उस पर मा0 मंत्री जी का ध्यान नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, अब आप समाप्त कीजिये।

डा0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, चाहे सहजनवा का जूट उद्योग हो, मथुरा का पेन्टिंग उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग, बरेली का दियासलाई उद्योग, मिर्जापुर का बीड़ी उद्योग, फर्रुखाबाद का तम्बाकू उद्योग, मुजफ्फरनगर का कागज उद्योग, वाराणसी का आभूषण और साड़ी उद्योग, गाजियाबाद का इस्पात उद्योग, सहारनपुर का सिगरेट उद्योग, खुर्जा का चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग, गौतमबुद्धनगर का ऑटोमोबाइल का उद्योग, फिरोजाबाद का काँच की चूड़ियों का उद्योग, कन्नौज का इत्र का उद्योग, प्रयागराज की कताई मिल तथा महोबा के उद्योगों पर मा0 मंत्री जी की नजर नहीं गयी। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी ने यहाँ पर औद्योगिक विकास विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से प्रदेश की उससे जो अपेक्षा थी वह अपेक्षा पूरी नहीं हुयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस विभाग के माध्यम से मैंने जो चर्चा करी कि हर क्षेत्र की अपनी एक गुणवत्ता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जनपद प्रतापगढ़ में एक ए0टी0एल0 फैक्ट्री लगी थी। वहाँ की अपनी एक पहचान ऑवला है, वहाँ की अपनी सम्पदा आँवला का किसान है, वहाँ की अपनी पहचान आम है और अगर वहाँ पर ट्रैक्टर फैक्ट्री लगने के बजाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का काम किया गया होता तो वहाँ के किसानों का फायदा होकर हुनरमंद नौजवानों

का भी फायदा होता। उद्योग हमेशा ऐसे लगने चाहियें जिसमें बड़े उद्योग और बड़े कारखाने से लेकर के उसके रॉ मैटीरियल तथा उसके मैनपॉवर तक जब तक उसका लाभ नहीं पहुँचेगा, जब तक उसकी चेन नहीं बनेगी कि उसका रॉ मैटीरियल भी वहीं पर हो, उसका स्किल्ड मैनपॉवर भी वहीं पर हो, उसकी सम्पदा भी वहीं पर हो।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही।

डा0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की अपनी जो पहचान है। हमारे प्रदेश में खनिज बड़े पैमाने पर है। हमने सोनभद्र की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा और सुना है कि वहाँ पर सोना बड़े पैमाने पर है। मैं तो कहना चाहूँगा कि गुजरात के डायमण्ड के जो बड़े व्यापारी हैं वह आकर के उत्तर प्रदेश में सोने की खदानों पर भी काम करके देख लें जिससे प्रदेश खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ सके।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, धन्यवाद। श्री भूपेश चौबे जी।

डा0 आर0के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूँगा। मान्यवर, प्राधिकरण की जो समस्याएं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, वह आप लिखकर दे दें। मैं दो-तीन मिनट से आपको बोल रहा हूँ। मा0 वर्मा जी का माइक बंद कर दिया जाये तथा मा0 भूपेश चौबे जी का माइक ऑन दिया जाये। मा0 भूपेश जी, आप बोलिये।

श्री भूपेश चौबे-

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद। औद्योगिक विकास विभाग के मा0 मंत्री नन्दगोपाल गुप्ता 'नन्दी' जी द्वारा जो विभागवार बजट प्रस्तुत किया गया, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। मैं अपना समर्थन इस बात से प्रारम्भ करता हूँ कि अभी कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुये सोनभद्र की पहाड़ियों की चर्चा की गयी और यह संयोग देखिये कि सचेतक महोदय ने मुझे ही औद्योगिक विकास के बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा किया, क्योंकि मैं भी सोनभद्र से आता हूँ। उत्तर प्रदेश का यह संयोग है कि जिस बुलडोजर ने अपराध को नियंत्रित किया, नेस्तानाबूत किया, उसी बुलडोजर ने उद्योग बनाने के लिये धरातल बनाया। यह बुलडोजर का कमाल है।

मैं मा0 नंदी जी के द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव के आधार पर यह कहना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो बजट है वह केवल गाजियाबाद तक ही नहीं गोरखपुर तक जाता है, यह बजट केवल नोएडा से ही प्रारम्भ नहीं होता है यह नैनी तक जाता है, यह बजट बलिया और बरेली को भी संस्तृप्त करता है, तो सहारनपुर से सोनभद्र को भी सन्तृप्त करता है। उद्योग के क्षेत्र में जब हम उद्योग लगायेंगे तो हमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहां पर आवागमन बढ़ेगा तो वहां पर नगरीय क्षेत्र का विकास होगा, वहां पर पठन-पाठन का माहौल होगा। जहां हम उद्योग लगाते हैं वहां के आसपास का सर्वांगीण विकास होता है। अभी बात इन्वेस्टरर्स समिट की हो रही थी कि कहां हुआ कैसे हुआ उसका माहौल उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है, अब दिखने लगेगा। जिस पलायन की बात कर रहे थे वह पलायन के लिए दोषी कौन है ? वह पलायन उत्तर प्रदेश से जो हुआ हमने कोरोना काल देखा कि हमारे प्रदेश के तमाम लोग दूसरी जगहों पर फंसे हुए थे, लेकिन उसके लिए दोषी कौन था ? किसने उनको पलायन के लिए मजबूर किया ? किनकी अब तक सत्ता चलती रही ? या तो कांग्रेस की सर्वाधिक सत्ता रही या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मिला। लोग पलायन के लिए मजबूर हुए और यहां के प्रतिभाशाली लोग आज रोजगार भी करना चाहते हैं और अपनी प्रतिभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश का विकास भी चाहते हैं। यदि यहां की प्रतिभा दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां का भी विकास करे, दूसरे देशों में जाकर वहां भी इन्वेस्ट करे तो यह उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात होगी, इस पर हमको गर्व करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की प्रतिभा इतनी है कि तमाम राज्यों को और तमाम देशों को चलाने में सक्षम है। जो बजट उ0प्र0 के विकास हेतु बना है, मैं इसके लिए उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों और मा0 मंत्री जी को जहां धन्यवाद देना चाहता हूँ वहीं वित्त मंत्री जी ने उदार भाव से उद्योग विभाग को जो बजट दिया है इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं विशेष धन्यवाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी कर्मठता और अपनी कार्यशैली के बदौलत पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाये जाने के माहौल को बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को कि इन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाया पूरे देश में और दुनिया को सन्देश दिया कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है वहां आप जाकर इन्वेस्ट करो, वहां का माहौल अच्छा बना हुआ है। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जिस जिले से मैं आता हूँ वह सोनभद्र है और यह जिला खनिज सम्पदाओं से परिपूर्ण है। यह जनादेश के अन्य चार राज्यों से जुड़ा हुआ है वहां पर नदियाँ हैं, जलों का संचय है, वहां पर पहले से बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। चाहे वह कोयले का उद्योग हो, चाहे एल्युमीनियम की सबसे बड़ी फैक्टरी हो, चाहे सीमेन्ट का कारखाना हो, इस प्रकार खनन के मामले में सोनभद्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी डा0 आर0 के0 वर्मा जी कह रहे थे कि सोना भी वहां पाया गया है। सच में वहां की पहाड़ियों में, वहां की धरती में कई तरह के ऐसे खनिज हैं, वहां पर सोन, रेणु, बिजुल, कनहर, बेलन,

पाण्डू आदि नदियाँ हैं। इस नाते वहां पर उद्योग लगाये जाने के लिए अच्छा अवसर है। पहले से भी वहां पर उद्योग लगे हुए हैं इसके लिए मैं अपने औद्योगिक मंत्री और मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जहां उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ वहीं सोनभद्र में जो जिले का इन्वेस्टरर्स समिट था वहां पर भी 1 लाख 11 हजार करोड़ का एम0ओ0यू0 साईन हुआ है। इस प्रकार से हर जिले में जो जिले का इन्वेस्टर समिट हुआ है वह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक कारगर साबित हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सोनभद्र का अच्छा माहौल है और वहां पर जो पहाड़ियाँ हैं वह जिसे हम पहाड़ी चक्की कहते हैं, के माध्यम से बिजली पैदा करने का एक बड़ा अवसर है। वहां पर फिल्म सिटी के लिए भी एक अच्छा वातावरण है अगर सोनभद्र को भी चुना जाए तो अच्छा है। मिनी गोवा के नाम से अवाड़ी (कोरा) पयर्टन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसका विकास किया जाना चाहिए। एक ऐतिहासिक फॉसिल्स इस सोनभद्र में है जिसकी चर्चा अभी पर्यटन मंत्रीजी ने की है इसको भी एक टूरिज्म में अध्यात्म जोड़ा गया है। औद्योगिक मंत्रालय का बजट इस सबको जोड़ते हुए सोनभद्र से सहारनपुर को एक करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनेगा। उद्योग में जो इन्वेस्ट हो रहा है यदि उद्योग और आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन हर दृष्टि से मजबूत होगा। इसी निवेदन के साथ उद्योग विभाग द्वारा जो बजट रखा गया है यह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सार्थक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं पहली बार बजट कटौती के प्रस्ताव पर बोल रही हूं इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरी बात पूरी होने तक का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात 7 मिनट में पूरी करिये।

डा0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज औद्योगिक विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर श्री आर0के0वर्मा जी के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष जी, आज मैंने पहली बार इस तरीके की चर्चा को सुना और माननीय मंत्री जी की जो बातें मैं सुन रही थी। उनसे बहुत सारी उम्मीदें थीं और ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से 2023 का इन्वेस्टर्स समिट मीट का जिस तरीके से सौन्दर्यीकरण किया गया और लोगों को दिखाया गया। इतना बड़ा बजट सबके सामने आया तो मंत्री जी अवश्य ही उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बतायेंगे। लेकिन बहुत ही निराशा हुई क्योंकि पूरी स्पीच में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विभाग को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष जी की तारीफों में ही बिता दिया। कई सारी महत्वपूर्ण बातें थीं जो उन्हें करनी चाहिए थीं लेकिन उसे छोड़कर सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में बातें कीं।

अध्यक्ष जी, इस बार 2023 का इन्वेस्टर्स समिट मीट है उसमें कम से कम 33 से 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट की बात की गयी है। जब इस तरीके की बाते करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद बेसिक ढ़ाचे को या धरातल को हम कई बार भूल जाते हैं। अध्यक्ष जी भारत में जो टॉप 10 इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं अगर उनके नेट वर्थ की बात करें कि उनके पास कितना नेट वर्थ है तो मुकेश अम्बानी के पास 7.2 लाख करोड़ है, गौतम अडानी के पास 7.2 लाख करोड़ है, शिव नादर के पास 2.2 लाख करोड़ है, साइरस पूनावाला के पास 1.8 लाख करोड़ है, राधा किशन दमानी के पास 1.6 लाख करोड़ है, लक्ष्मी मित्तल के पास 1.4 लाख करोड़ है, कुमार बिरला के पास 3.5 लाख करोड़ है, दिलीप शांघवी के पास 1.2 लाख करोड़ है, पलौनी मिस्त्री के पास 1.2 लाख करोड़ है, उदय कोटक के पास 1.1 लाख करोड़ है। भारत के अगर टॉप-10 इण्डस्ट्रियलिस्ट को भी जोड़ ले तो उनकी पूरी की पूरी नेट वर्थ सिर्फ और सिर्फ 28 से 30 लाख करोड़ में सीमित हो जाती है। आपने अपने इन्वेस्टर्स समिट मीट में यह बताया कि हमारे पास 35 लाख करोड़ या पता नहीं इससे भी ज्यादा का निवेश आया है। अगर पूरे के पूरे टॉप-10 इण्डस्ट्रियलिस्ट अपना सब कुछ निछावर कर दें तब भी यह निवेश पासिबिल नहीं है। क्या यह निवेश सिर्फ उत्तर प्रदेश में आया है ? कोई और प्रदेश भारत में नहीं है जहां पर निवेश हुआ है ? अध्यक्ष जी, यह तो एक तरीके का बहुत बड़ा मजाक है जो हो रहा है। साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि मंत्री जी ने 2018 में भी साढ़े चार लाख करोड़ का जो निवेश आया था। उसकी भी बहुत सारी चीजें थी। हम लोग बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे कि शायद उसका भी कुछ विवरण हमें मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसका विवरण मंत्री जी के पास भी नहीं है क्योंकि धरातल पर तो कुछ है ही नहीं। आज सरकार ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की बात करती है। 2018 में साढ़े चार लाख करोड़ का जो निवेश हुआ। अगर पांच वर्षों में देखा जाये तो सरकार उसके 50 प्रतिशत का भी ब्योरा हमें नहीं दिखा सकी कि उन्होंने पांच सालों में उससे क्या चीजें की ? हम ईज ऑफ डूईंग बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। पहले तो हम नोएडा में और उसके आस-पास में जो भी बिजनेस मैन, जो भी इण्डस्ट्रियलिस्ट अपनी इण्डस्ट्रीज को डालने आते हैं उनको कहते हैं कि हम आपको 15000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पर जमीन देंगे। उसके बाद वह व्यक्ति वहां पर आता है। धीरे-धीरे आप क्या करते हैं, उस जमीन को बिडिंग पर लगा देते हैं। उसकी बिडिंग का दाम बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंच जाता है कि 60 हजार रुपये प्रति स्क्वायर फिट की जमीन हो जाती है और इण्डस्ट्रियलिस्ट बेचारा अपने रास्ते अपने घर भाग जाता है। इस तरीके से क्या कोई ईज ऑफ डूईंग बिजनेस होता है ? कैसी सहूलियत आप दे रहे हं ? 2018 में जो इन्वेस्टर्स समिट मीट हुआ उसमें आपने जनता को बड़े सुनहरे सपने दिखाए और आपने बताया कि जितने भी एक्सप्रेस-वेज हैं उन सब एक्सप्रेस-वेज के पास हम जमीन का आवंटन करेंगे और वहां कहीं न कहीं हम कोई न कोई इण्डस्ट्री लगायेंगे।

मान्यवर, आज किसी भी एक्सप्रेस-वे के पास एक इंडस्ट्रीज खड़ी हुई तो प्लीज उसका विवरण आज आप जरूर यहां सदन में दें और बात हुई भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस कारिडोर की बात की उन्होंने कहा कि हम डिफेंस में जो बाहर के देशों से खरीदते हैं उस पैसे को हम बचाकर अपने ही देश में हम उस चीज को बनायेंगे जैसे कि लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट होते हुए डिफेंस कारिडोर शुरू होगा लेकिन आज हम देखते हैं कि वह डिफेंस कॉरिडोर है कहां, मैं इस साइड को छोड़कर सामने से भी पूछती हूं कि क्या आपको कही पर दिखाई दिया अगर दिखाई दिया हो तो प्लीज मुझे भी बताइयें। जो हमार इन्वेस्टर्स आते हैं तो उन्हें बोलते है कि हम आपको कम दाम पर बिजली देंगे लेकिन जब वह काम शुरू करते हैं तो आपकी बिजलियों के दाम तो दूसरे प्रदेशों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं क्या इसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। आप लोग बात करते इतने बड़े निवेशों की तो मैं बोलना चाहूंगी कि समाजवादी सरकार थी और उसने जो काम किया वह कम से कम धरातल पर तो दिख रहा है। हमने दिया इकाना स्टेडियम, पलासियो, पुलिस मुख्यालय और मेट्रो, हमने दिया। जनेश्वर मिश्र पार्क हमने दिया गोरखपुर में एम्स हमने दिया और मेदांता अस्पताल दिया और आपसे अनुरोध है कि मैं एक डाक्टर हूं और आपका अगर इतना बड़ा निवेश आया है तो लखनऊ में सिर्फ एक प्राइवेट हास्टिपल है मेदांता कृपया करके कम से कम दो हास्पिटल और बनवायें यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद।

***डॉ0 राघवेन्द्र शर्मा-**

अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे औद्योगिक विकास पर बोलने का मौका दिया और मा0 नन्दी जी ने जो बजट पेश किया है उस पर बोलने का मुझे मौका मिला है। उत्तर प्रदेश 8 प्रतिशत जी0डी0पी0 बनाता है पूरे देश का वर्ष 2017 में जो बेरोजगारी दर थी वह करीब 14.8 प्रतिशत थी आप ही बताइये कि अगर विकास नहीं हुआ है तो यह दर 4 प्रतिशत कैसे हो गयी है। मैं अभी सुन रहा था व्यक्तिगत आदमी की इनकम नहीं होती है जो इनवेस्ट करता है तो वह उनकी कम्पनी की इनकम होती है और प्रोजेक्टेड रिपोर्ट होती है तो उससे 33.5 लाख हजार करोड़ का जो हमारे यहां इनवेस्टमेंट आया है तो वह कंपनीज के माध्यम से आया है अलग-अलग कम्पनीज में अलग-अलग अपनी व्यवस्थाएं की है उस तरीके से ही आया है। जो ओ0डी0ओ0पी0 में हमारे यहां यूनिटी मॉल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट की बात हुई है और जहां तक अस्पताल की बात हुई है तो हम लोगों ने खुद वहां इन्वेस्ट किया है करीब 100 करोड़ रुपये का हमने मेदांता अस्पताल बनाया है। अभी मैडम कह रही थीं कि अस्पताल नहीं आ रहे हैं मैं बरेली शहर की बात करता हूं तो वहां बड़ा हब हैं अस्पतालों का और तीन-तीन मेडिकल कॉलेज है और दो मेड़िकल कॉलेज अभी ही बने है जो कि हमारी सरकार के समय में बने है। हमारे सारथी मा0 मोदी जी व मा0 योगी जी हैं, के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ लोगों की नियत बदलती है कि कौन राजा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम देखे कि अमेरिका में कौन राज कर रहा है उसी के एकदम आगे मैक्सिको देश है और दोनों का लेवल अलग है यह बात जरूरी है कि आपका राजा कौन है और आपकी सोच कैसी है। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कस्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दिशा को बदलो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। सोच को बदलना पड़ेगा यदि सोच नहीं बदलेगी तब तक विकास नहीं आयेगा और इन सभी चीजों के लिए सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा कहां से आयेगी लेकिन आज के समय में योगी जी के समय में आप खुद समझ सकते हैं कि पुलिस की क्या बात है। गुंडों की तरह जो टैक्स वसूला जाता था और औद्योगिक लोग विकास करना चाहते थे वह टैक्स वसूली अब बंद हो गयी है। हमारे आंवला क्षेत्र में एक बड़ी गन्ना की मिल लगने जा रही है और जो इंगलैड का रिवाल्वर था अब वह भारत में मिलता है यदि मैडम खरीदना चाहें तो वह मिल सकता है। भारत में लोगों ने इन्वेस्ट किया है और विदेशी कंपनियां अपने प्रोडेक्टस यहां बना रही है।

यदि हम एम0एस0एम0ई0 की बात करते हैं तो हमारा जबर्दस्त इन्वेस्टमेण्ट हुआ है और उसी की वजह से हमारा 15 परसेण्ट ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। हमारी जो रीति और नीति है यह उसका फल है। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वह केवल जात-पात की बात करते रहते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप जातिगत जनगणना चाहते हैं तो यह नीतिगत फैसला है जो भी लिया जायेगा, लेकिन जो पाल्युशन होता है और व्यवस्थायें बिगड़ती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं पापुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। पापुलेशन पर भी कण्ट्रोल करने की बात होनी चाहिये और पापुलेशन की गणना होनी चाहिये। जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, वह बच्चे पाल पायेंगे या नहीं पाल पायेंगे। कई बार एक व्यक्ति पांच-पांच, छह-छह बच्चे पैदा करता है वह किसी भी धर्म और जाति का हो सकता है, लेकिन वह सरकार के ऊपर बोझ होता है क्योंकि सरकार को उनको पढ़ाना पड़ता है, उनके लिए सड़कें देनी पड़ती हैं और उनके लिए तमाम विकास कार्य करने पड़ते हैं। भारत और उत्तर प्रदेश में जो अनियंत्रित स्थिति है उसके लिए पापुलेशन जिम्मेदार है। मानव हमारी सम्पदा जरूर है और हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं। जहां तक बाहर काम करने की बात होती है। आप गुजरात को देख लीजिये वह एक डेवलप स्टेट है लेकिन वहां से भी लोग बाहर जाकर व्यापार करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह अमेरिका क्यों जाते हैं। यह हमारी स्किल्ड है। हमारे यहां मेडिकल कालेज बन रहे हैं। अब जब हर शहर में मेडिकल कालेज बनेगा, तो वहां से डाक्टर्स निकलेंगे, जब योग्य डाक्टर होंगे तो वह सब जगह जायेंगे और स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। यह केवल एक सपना नहीं है। यदि इतना इन्वेस्टमेण्ट होगा तो करीब-करीब एक करोड़ लोगों को हमारे यहां जाब मिलने वाला है। आप मानकर चलिये कि ऐसा होने वाला है। हमारे योगी जी राम चरित मानस को फालो करने वाले हैं और 'प्राण जाये पर वचन ना जाये' को निभाने वाले हैं। उन्होंने अगर कह दिया

है कि यह इन्वेस्टमेण्ट हो रहा है तो आप देखियेगा यह विकास और सुरक्षा जो आपको दिखाई दे रही है उसी तरीके से आपको दिखाई देगी। यहां का जो वातावरण है वह बिल्कुल बदल चुका है। अगर हम मत्स्य विभाग की बात करें तो उसमें भी भगवान राम के परम मित्र निषादराज गुह के नाम से योजना बनाई है जिससे गरीब लोग भी मत्स्य का ठीक से उत्पादन करके व्यापार कर पायेंगे। जब उनका व्यापार बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। रामचरित मानस में जिस तरीके से भगवान राम के समय में होता था कि 'मणि माणिक मँहगी किये, सहजे तृण जल नाद, तुलसी सोइ जानिये, राम गरीब नवाज।' यह हमारे आज का बजट है जो हमारी 20 करोड़ जनता को फ्री का अनाज देने का काम करता है। यह वह लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं या ऐसे टैक्स देते हैं जो उनको पता भी नहीं चलते हैं। एग्रीकल्चरल स्टार्ट अप के लिए काम हो रहा है। जो नेचुरल खेती कर रहे हैं और आर्गेनिक फार्मिग की जा रही है। गाय और सांड़ की समस्या का यह लोग उल्लेख करते हैं इसका मूल कारण है आपके लोगों और पूर्ववर्ती सरकारों ने गोचर भूमि को लोगों में बांट दिया और उसे खत्म कर दिया। जब गोचर भूमि रहेगी तो निश्चित रूप से गाय की समस्या कभी नहीं आयेगी। हमको गोचर भूमि की व्यवस्था करनी होगी। पांच-पांच एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं और एयरपोर्ट बन रहे हैं जो बताता है कि हमारा यू0पी0 किस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारे क्षेत्र में एक महिला कालेज की आवश्यकता है जिसे बनवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

डॉक्टर साहब, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्रीमती रेखा वर्मा जी बोलेंगी।

श्रीमती रेखा वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उस दिन उतनी बजट की चर्चा नहीं थी जितनी हमारे नेता के लिवास और शेरवानी की चर्चा थी। हर किसी को चिंता थी कि हमारे नेता जी ने शेरवानी क्यों पहन रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत मेरा महान है और बुलडोजर तंत्र ने देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचलकर रखा है। हो रही बेगुनाहों की हत्यायें, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं। लोगों को भिखारी नहीं, बल्कि कुछ काम करने के काबिल बनाओ,

(इस समय 07 बजकर 04 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मन्जू शिवाच पीठासीन हुईं।)

खाने के नहीं शिक्षा के भण्डारे लगवाओ। सचमुच इन दिनों मेरा भारत महान है। चाय से शुरू हुयी थी सरकार गाय सांड़ पर आकर अटक गयी। विकास की मम्मी रास्ते में भटक गयी। पुलिस रिश्वत खा रही है किसान जहर खा रहे हैं। जवान गोली खा रहा है। कौन कहता है कि भारत भूखा मर रहा है। झाडू वाला मुख्य मंत्री है और चाय वाला प्रधानमंत्री है। बारहवीं पास देश की शिक्षामंत्री हैं अंगूठा टेक सरपंच है। ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले फेसबुक पर

ग्रुप-ग्रुप खेल रहे हैं। बुद्धि का उपयोग करने वाले जापान में 603 किमी0 प्रति घण्टा की रफ्तार के बाद सातवीं ट्रेसिंग शुरू कर रहे हैं। इंण्डिया वाले पढ़े-लिखे लोग वाट्सएप पर ओम नमो शिवाय भेजकर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। पेट खाली है योग करवाया जा रहा है जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है। रहने को घर नहीं शौचालय बनवाया जा रहा है। गाँव में बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बन रहा है। कम्पनियाँ सारी विदेशी हैं और मेक इन इण्डिया कहा जा रहा है। जाति की गंदगी दिमाग में है और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। आटा इन दिनों महंगा है डाटा सस्ता हो रहा है। सचमुच भारत मेरा महान है। ऐ आदमी लोन चुका दे वर्ना तेरा घर बिक जायेगा। ऐ अमीर आदमी लोन चुका दे वर्ना मेरा बैंक बिक जायेगा। घर-घर नाली घर-घर गैस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय। स्कूल कालेज भाड़ में जाये। आम आदमी से मन की बात उद्योगपतियों से धन की बात। घर-घर अनाज बाटा जाये भर पेट कोई न खाये। खुद का वेतन खूब बढ़ायें कर्मचारी मांगे तो आँख दिखायें। जारी रहेगी अपनी पेंशन हम मांगे तो होगी टेंशन। वाह रे शासन तेरा खेल हम न्याय भी मांगें तो मिलती जेल। भारत मेरा महान है भारत मेरा महान है। धन्यवाद।

***श्री शशांक वर्मा-**

बहुत-बहुत धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, यह बजट जो यहाँ प्रस्तुत हुआ है युवाओं का, किसानों का और उद्योगों को बढ़ाने वाला अमृतकाल का बजट है। मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 वित्त मंत्री जी और मा0 मंत्री जी के प्रयासों से प्रदेश की 24 करोड़ जनता को लाभकारी योजनायें पहुंच सकें यह बजट उस दिशा में काम कर रहा है।अमृत काल वर्ष में लैण्डमार्क बजट के रूप में यह बजट एक उदाहरण की तरह पेश हुआ है उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य रूप से आयोजन किया जिसमें मा0 मंत्री, विधायकगण, प्रतिनिधि मण्डल नें 16 देशों में 21 शहरों में जाकर उत्तर प्रदेश की छवि को बढ़ाने का कार्य किया है। इस इन्वेस्टर्स समिट में 2022-23 में 25 हजार से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। मुझे यह बताने में अपार हर्ष हो रहा है कि लगभग 33 लाख करोड़ के 19 हजार से अधिक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये। जो इन्वेस्टमेंट हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री के रूप में आने वाला है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह सरकार युवाओं लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति के माध्यम से 50 इन्क्यूवेटर तथा 7200 स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है तथा साथ में कृषि जो हमारा बेस है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कृषि स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ के एग्रीकल्चर फण्ड की व्यवस्था की गयी है। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र 138 निघासन के उद्योग से सम्बन्धित जो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र इंडो-नेपाल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार्डर से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क का क्षेत्र भी आता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार जिस तरह से इंडस्ट्रियल कारीडोर बना रही है। वहाँ पर भी इको ट्यूरिज्म कारीडोर बनाने की बड़ी सम्भावना है। जिस कारीडोर के अन्तर्गत पलिया एयर स्ट्रिप है जिसको एयरपोर्ट की तरह संचालित करने की आवश्यकता है। इस कार्य को मेरे पूज्य पिताजी श्री रामकुमार वर्मा जी ने बनवाने का काम किया था।

मान्यवर, यही दुधवा नेशनल पार्क ऐतिहासिक तिकुनिया गुरुद्वारा भी इसी ईको कॉरीडोर के अन्दर आता है। इस धार्मिक टूरिज्म को देखते हुए इसका भी विकास कराये जाने की आवश्यकता है। ईको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिसमें किसानों की मुख्य उपज गन्ना है। इनके विकास के प्रति हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरजू सहकारी चीनी मिल बिलरायां है, जो सहकारी चीनी मिल के रूप में चल रही है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से हमारे औद्योगीकरण को बढ़ाने की तरफ सरकार प्रयास कर रही है जो हमारे सामने बजट प्रस्तुत हुआ है उसी बजट का भाग हमारे यहां चीनी मिल का उच्चीकरण एवं पिराई क्षमता को दुगनी करने में लगाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी निवेदन है कि इस चीनी मिल में डिसलरी प्लान्ट/एथेनॉल प्लान्ट लगाये जाने की आवश्यकता है, जिस कारण हम एथेनॉल की नॉन कन्वेन्शनल एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं और पल्यूशन को कम करने का काम करने के लिए एथेनॉल डेवलपमेण्ट का काम हमारे क्षेत्र की चीनी मिल में हो सके। मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र में आता है। वर्तमान में हमारी सरकार जिले स्तर पर 24 घण्टे तहसील स्तर पर 22 घण्टे और ग्राम स्तर पर 18 घण्टे बिजली पहुंचाने का काम कर रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सिंचाई के लिए नलकूल की किसानों के लिए पिछले बजट में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी थी हमारी सरकार इस बजट में उसको बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने जा रही है। हमारे युवाओं के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से टेबलेट/स्मार्ट फोन का वितरण आने वाले पांच सालों में सरकार करने जा रही है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में युवाओं की खेल कूद के प्रति विशेष रुचि है जिसमें अगर वह लोग आगे बढ़े तो उनके स्किल डेवलपमेण्ट एवं यूथ डेवलपमेण्ट के लिए एक स्टेडियम बनाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। मेरे जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गयी है, इसी क्रम में निवेदन करता हूं कि इसी बजट के माध्यम से वहां पर एक नर्सिंग कालेज की स्थापना की जाए और तिकुनिया पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 में कन्वर्ट कराया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेण्ट व स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित करने का कार्य सरकार कर रही है। मुझे गर्व होता है कि मेरे निघासन ब्लॉक में जहां सारे स्कूलों को स्मार्ट क्लास करने का काम आदरणीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से किया गया है। मैं आपको

यह बताना चाहता हूँ कि स्किल डेवलेपमेंट की तरफ जिससे हमारे लोग एवं हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें, उद्योगों में हमारे बच्चों को नौकरी मिल सके, उसके लिए न्यू ऐज कोर्स ट्रेनिंग के लिए छात्र/छात्राओं की ट्रेनिंग के लिए 21 राजकीय पॉलीटेक्निकों का निर्माण सरकार कर रही है। इसमें मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बजट में 50 करोड़ रुपए की सुविधा की गयी है। मुझे गर्व है कि जिस तरह से बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट हमारे समिट में आए वैसे ही टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहभागिता से पूरे प्रदेश में इण्डस्ट्री ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के माध्यम से माडर्न वर्कशॉप व माडर्न क्लास रूम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए हमारे बजट में पांच सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। जिसमें 88 प्रतिशत टाटा टेक्नोलॉजी एवं 12 प्रतिशत राज्य सरकार देने का काम करने जा रही है। हम लोग जिस प्रकार से इण्डस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं उसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमारी सरकार पूरे प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने का काम कर रही है और पांच इण्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर कुल 21 एयरपोर्ट आने वाले समय में हमारे यहां पर क्रियाशील होने जा रहे हैं। किस प्रकार से हमारा देश एक्सप्रेस-वे के नाम से जाना जा रहा है। पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, गोरखपुर, गंगा, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के माध्यम से पूरी तरफ डिफेन्स कॉरीडोर बनाने का काम उसके अगल-बगल डिफेन्स कॉरीडोर और विभिन्न इण्डस्टियल कॉरीडोर बनाने का काम सरकार करने जा रही है। जिस प्रकार से हमारे उद्योगों को बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी एवं आदरणीय योगी जी की सरकार ने पिछले पांच-छः सालों में किया है उसको यह बजट आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं इस सदन के सभी मा0 सदस्यों को धन्यवाद दूंगा और पीठ को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे औद्योगिक विकास के बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। जिन उद्योगों की बात की गयी है उन उद्योगों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी है, जिसमें पांच लाख रोजगार सृजित करने की बात कही गयी है। मैं सिर्फ आलोचना के लिए नहीं बल्कि उसके साथ सुझाव के लिए भी मैं खड़ा हुआ हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं, मऊ जिले में दो स्पिनिंग मिलें हैं, एक केंद्र सरकार की है और एक स्टेट गवर्नमेंट की है। दोनों बंद पड़ीं है, दोनों मिलों को अगर सरकार चालू करा दे तो काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाएगा और वहां के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा, इसलिए मेरी इस कटौती के माध्यम से सरकार से मांग है कि इस काम को पूरा करने में ध्यान दें। अगर वह वास्तव में नौजवानों के प्रति संवेदनशील हैं, मजदूरों के प्रति संवेदनशील, दस्तकारों और बुनकरों के प्रति संवेदनशील हैं तो मेरी सरकार से यह मांग है कि बंद पड़ी मिलों, जिसमें बिल्डिंग खड़ी है, बाउण्ड्री लगी है, आवास बने हुए हैं, मशीनें लगी हैं, कुछ करना नहीं है, बस संचालित करने की जरूरत है।

मेरा निवेदन है कि उन दोनों स्पिनिंग मिलों को चालू करा दिया जाए ताकि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सके। हमारा जिला बुनकर बाहुल्य जिला है, 20 प्रतिशत बुनकर वहां पर पावरलूम के काम में लगे हैं। लेकिन पावरलूम के बुनकरों को जो बजट की व्यवस्था दी गयी है, जिसमें कहा गया है कि पावरलूम के बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है, इसे 350 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। 350 करोड़ रुपये में उत्तर प्रदेश के बुनकरों का कितना हित होगा ? जिसमें बड़ी तादाद में गरीब वर्ग के लोग हैं। महोदया, इतने गरीब लोग हैं कि बड़ी तादाद में पति-पत्नी पूरा परिवार लगता है तब दो वक्त की रोटी मिल पाती है और उससे अपना गुजारा करते हैं। उनके पास खेती नाम की कोई चीज नहीं है। उनका एकमात्र सहारा पावरलूम है और बहुत से उसमें सक्षम लोग भी है, जो 10-20 की संख्या में पावरलूम लगाकर दूसरों को रोजगार भी देने का काम करते हैं।

हमारी मांग है कि वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उनको जिस तरह से पूर्व की माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम किया गया था, सौभाग्य से बिजली मंत्री जी भी हमारे मऊ जिले के हैं, सौभाग्य से हम दोनों एक ही विधान सभा क्षेत्र के भी हैं, हम निवेदन करते हैं कि यदि उन गरीबों का उत्थान सरकार चाहती है जिसमें मुस्लिम वर्ग के अलावा अन्य गरीब लोग भी पावरलूम लगाकर अपनी रोजी-रोटी चलाने का काम करते हैं, उनको फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम सरकार सुनिश्चित करे ताकि पावरलूम को बढ़ावा मिले और वस्त्र उद्योग आगे बढ़े। हमारी सरकार से मांग है कि खादी वस्त्र उद्योग की बात कही गयी है, खादी वस्त्र उद्योग को आज देख रहे हैं वह धीरे-धीरे बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सरकार वास्तव में उसे बढ़ाना चाहती है तो इसके बजट को बढ़ाकर बड़े पैमाने पर इसके लिए प्रोत्साहन राशि सुनिश्चित करे ताकि गांव-गांव में इसका विस्तार हो और लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि जो तमाम लंबी-चौड़ी बातें सरकार ने नौजवानों के लिए कहीं, बेरोजगारों, किसानों के लिए कहीं, निःशुल्क बिजली देने की बात कही, वास्तव में सरकार किसानों की उन्नति चाहती है, मैं बिजली मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि अपनी बात पर खड़े रहेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे, उनको निःशुल्क बिजली देंगे, तो इस दिशा में सतत् प्रयास करना चाहिए। उसी तरह से देश के बड़े पैमाने पर लोगों को तन ढकने के लिए वस्त्र उद्योग में लगे बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली सुनिश्चित कराने हेतु पुनः मांग करेंगे। उनकी धनराशि बढ़ाई जाए और विशेषकर ऊर्जा मंत्री एवं अपना क्षेत्र होने के नाते, अधिष्ठाता महोदया मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात को कहना चाहता हूं कि 19 अक्टूबर 2022 को जब यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा था। भारी बारिश होने के नाते टौंस नदी में भारी बाढ़ आ गयी। नाव से 16 बच्चे नदी पार कर रहे थे। बन्दी घाट जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, नाव नदी में पलट गयी, बच्चे डूबने लगे। वहाँ के मल्लाह, नाविक 15 बच्चों को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक बच्चा डूब करके मर गया। मैं बार-बार नियम-51 में भी लगाता हूँ, क्वेश्चन में भी लगाता हूँ, पता नहीं क्यों

नही आ पाता ? आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर पुल बनवाया जाय ताकि वहाँ पर भी लघु उद्योग का विकास हो सके।

मा0 अधिष्ठाता-

यह चीज आप लिखकर दे दीजिएगा। अब श्री धीरेन्द्र सिंह जी।

श्री राजेन्द्र कुमार-

धन्यवाद।

श्री धीरेन्द्र सिंह-

मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अधिष्ठाता महोदया और सदन के सभी सदस्यों का यथायोग्य अभिवादन के साथ । हमारे औद्योगिक विकास मंत्री ने औद्योगिक विकास की जो तस्वीर प्रस्तुत की है। मेरे साथियों ने उसके बारे में बताया, इमारतों के बारे में बताया, लेकिन यह भूल गए कि हम लोगों ने 2017 से पहले का ग्रेटर नोयडा और नोयडा प्राधिकरण का सीएजी आडिट कराया था। जिसमें ग्रेटर नोयडा में तकरीबन 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला निकला, पूर्ववर्ती सरकारों का और नोयडा प्राधिकरण में 50 हजार करोड़ रुपये का घोटाला निकला। ये लोग औद्योगिक विकास पर चर्चा करते हैं। इनके समय में जो उद्योग धन्धे थे, वह एनसीआर से पलायन करने लगे थे। आज मेरे जेवर क्षेत्र में, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 01 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आता है तो इन्हें यह चीज पच नहीं रही है। इनके समय में पूर्ववर्ती सरकारों के समय में भोले-भाले किसान जब अपना हक माँगते थे तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती थीं। इसका सीधा-साधा उदाहरण हमारे क्षेत्र के आस-पास भट्ठा परसौल, जिकरपुर और घोड़ी बछेड़ा है और आज देखिए कि क्या परिदृश्य बदला है। आज प्रदेश के मुखिया किसानों को अपने आवास पर बुलाकर उनकी सहमति के आधार पर इस प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसा उदाहरण नजर नहीं आता, जब औद्योगिक विकास में सहभागिता के लिए किसानों की मुआवजा वृद्धि की गयी और वह भी एक साथ 800 रुपया मीटर। तो मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि इन्हें कटौती से कोई लेना-देना नहीं है, इन्हें तो सिर्फ यह है कि इनकी दुकानें आज गौतमबुद्धनगर में नहीं चल रही हैं, बन्द हो गयी हैं। इन लोगों ने भोले-भाले किसानों के नाम पर वहाँ जमीनों का जो अधिग्रहण किया। इन्होंने ग्रेटर नोयडा वेस्ट में रात-रात में भू-उपयोग चेंज कर औद्योगिक विकास के लिए ली गयी जमीन को अपने साथ के बिल्डरों में बाँट दिया। आज भी वहाँ के बायर्स, उन बिल्डर्स के लिए खून के आँसू रो रहे हैं, उनके खून-पसीने की कमाई को वह बिल्डर्स हड़प कर गये, वह इन्हीं के साथी लोग थे। आज हमारे प्रदेश में वह स्वर्णिम युग है, जब मैं पढ़ता था, कभी सुनता था कि हिन्दुस्तान का कौन सा काल स्वर्णकाल कहा जाता है। वह काल सुनने में आता है, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जी का जिनके समय में आर्थिक विकास के साथ-साथ, कानून-व्यवस्था की

स्थापना हुई थी। यह वही काल है मैं बता दूँ, 2017 से पहले मेरे जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे पर 35 ऐसी घटनाएँ लूट की सड़क पर हुई थीं, जहाँ बहन-बेटियों की इज्जत को तार-तार किया गया था, हत्याएँ की गयी थीं। इनके समय में अपराध के अभियोग पंजीकृत नहीं होते थे, लेकिन 2017 के बाद वहाँ कानून का राज है, निवेश आ रहा है, जो उद्योगपति वहाँ छोड़कर चले गए थे, वह उद्योगपति दोबारा वापस आने लगे हैं। इनका जो कटौती का प्रस्ताव लाने का मकसद है, वह इस प्रदेश के हक में नहीं है, चूँकि अब इनके वह मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं, जब वहाँ जमीनों पर नाजायज कब्जे किए जाते थे।

इन्हें यह सी0ए0जी0 का ऑडिट नहीं पच रहा, क्योंकि यह तो सिर्फ 10 साल का कराया है अगर हम और पीछे चले जाएंगे तो इन्होंने जो अकूत सम्पत्तियां गौतमबुद्धनगर को माध्यम बनाकर बनाई हैं। वहां भोले-भाले किसानों के नाम पर अपनी तिजोरियां भरी हैं यह किस मुंह से कटौती का प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग के लिए रखना चाहते हैं यह मेरी समझ से बाहर है। मैं मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के जो लम्बित प्रकरण हैं मेरे जनपद में उनका निराकरण किया जाए, क्योंकि वह सभी इन्हीं महानुभावों की देन हैं। खेतिहर मजदूर जमीन लेने के बाद जो बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि किसान को हम मुआवजा देते थे, लेकिन खेतिहर मजदूरों के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हों, क्योंकि वहां प्राइवेट अस्पतालों का जो जाल है उसमें और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अस्पतालों पर सरकार का थोड़ा अंकुश हो जिससे आम आदमी को भी यहां पर इलाज की सुविधा दे सकें, ऐसी व्यवस्था मेरी सरकार करे। अन्त में किसानों के बच्चे जिनकी जमीनों पर शिक्षण संस्थाएं बनी हुई हैं और जिनकी जमीनों पर उद्योग धंधे लगे हुए हैं उन बच्चों को सौ फीसदी उसका फायदा दिया जाए और उन शिक्षण संस्थानों में एडमिशन मिलें और औद्योगिक कंपनियों में उन्हें नौकरियां मिलें। अन्त में मैं समापन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं अपने प्रदेश के उन किसानों का जिन्होंने आगे आकर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बनाए जाने के लिए अपनी जमीनों को अपनी सहमति से दिया है और इस प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया उस जेवर विधान सभा क्षेत्र से घूमेगा और जेवर विधान सभा इस प्रदेश की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन तक ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक

रुपए कर दी जाए, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मैं मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा और मंत्री जी का ध्यान इधर चाहूंगा नंदी जी ध्यान दें मैं, क्योंकि मुरादाबाद जिले से आता हूं। मुरादाबाद जिले में एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत चरम सीमा पर है और एक्सपोर्ट भी इतना है कि हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है जहां डॉलर और यू0एस0ए0, गल्फ कंट्री, दुबई, बड़ा कारोबार हमारे यहां होता है। एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बड़ा उद्योग है पूरे उत्तर प्रदेश को इससे फायदा मिलता है। इसमें एक्सपोर्टर के लिए कोई भी ध्यान पूरी तरीके से इस सरकार ने बजट में नहीं दे पाए हैं। एल्यूमिनियम कास्टिंग जो होती है वह हाथों से कराई जाती है और एल्यूमिनियम कास्टिंग की वजह से जो हमारे मजदूर हैं उनको बीमारी का खतरा हो जाता है कोई टी0बी0 से पीड़ित हो जाता है, कोई हेपेटाइटिस सी से तो उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें अगर ऑटोमैटिक प्लाण्ट लग जाए तो एक बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी और जो ज्यादा देर से काम होता है वह जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से वायर बाइंडिंग का काम है वायर बाइंडिंग के काम में जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज मुकाबला चीन से है और चाइना एक्सपोर्ट करता है और बड़ा एक्सपोर्ट करता है और हम लोगों को चौलेंज अगर कोई करता है तो चाइना ही करता है, हमारे एक्सपोर्ट को अगर कोई प्रभावी करता है तो वह चाइना करता है। उनके पास मशीन भी हैं उनके पास काम करने का तरीका हमसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वह मशीन से ज्यादा काम कराते हैं। उसी क्रम में मुरादाबाद के अन्दर लोहे की और लोहे से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें जो टोकरी है क्रिसमस के सामान है और हम लोगों के जितना भी धार्मिक सामान हों उसके जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं वह तार से बनते हैं और खासतौर पर उस तार को और उस लोहे को खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है या पास के बराबर के सूबों में जाना पड़ता है जिससे देर तो होती ही है और आसानी से हम लोग उनको लोहा मुहैया नहीं करा सकते जिससे एक्सपोर्टर को भारी नुकसान होता है। मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि लकड़ी का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मुरादाबाद से होता है लकड़ी के एक्सपोर्ट में जो लकड़ी को छीजन करने का काम होता है उसमें हमारे मुरादाबाद में तीन या चार ही प्लाण्ट हैं। इसमें खासतौर पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि अगर यहां ऑटोमैटिक प्लाण्ट की मशीनें लग जाएंगी एक्सपोर्ट के लिए तो लकड़ी के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, चूँकि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, एक्सपोर्टर्स के लिए हमारे मरहूम विधायक, हमारे वालिद हाजी इरफान साहब ने भी पिछली बार क्योंकि हमारे वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, हमारे वालिद साहब ने मा0 अखिलेश यादव साहब जब मुख्य मंत्री थे तो यह प्रस्ताव दिया था कि वहाँ पर एयरपोर्ट चालू हो जाए जो अभी तक चालू

नहीं हो पाया है। उससे भी हमारे उद्योग में जो हमारे बायर आते हैं, जो हमारे इण्डिया के बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों को दिल्ली में उतरना पड़ता है, उन लोगों को आसानी से मुरादाबाद आने में काफी वक्त लग जाता है जिससे बायर को काफी अन्कम्फर्टेबिल फील होता है और बायर के साथ अगर एक्सपोर्टर की लाइजेनिंग अच्छी होती है, बायर को सुविधाएँ मिल जाती हैं तो बायर एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मुरादाबाद को देता है। एक्सपोर्टर चूँकि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं तो एक्सपोर्टर को मजबूत करने के लिए मंत्री जी मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक्सपोर्ट का काम जो हमारे मुरादाबाद के लोग करते हैं तो मशीन के अभाव में, मशीन न होने के कारण हम लोगों का जो काम एक-डेढ़ महीने में होता है, वही काम चाइना 15 दिन में कर देता है। इस प्रकार हम लोगों का एक्सपोर्ट लेट हो जाता है। हमारी जो कन्साइनमेण्ट, हमारा जो ऑर्डर दो से ढाई महीने में पहुँच पाता है और वही ऑर्डर चाइना वाले 15 से 20 दिन में पहुँचा देते हैं। इससे हमारे एक्सपोर्टर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैं मा0 मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पर खासतौर से तवज्जो दी जाए। हमारा यही काम मुरादाबाद, सम्भल में भी होता है। इसी तरीके से हमारा पूरा मुरादाबाद इसका हब माना जाता है। इसलिए पीतल नगरी को बचाने की जिम्मेदारी मा0 मंत्री जी और सरकार की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि अगर इस पर एक्सपोर्टर के साथ एक मीटिंग कर ली जाए। मा0 मंत्री जी की एक्सपोर्टर के साथ एक मीटिंग हो जाए, अगर मा0 मंत्री जी बैठकर एक्सपोर्टर के साथ एक मीटिंग कर लें तो उनके दर्द को भी अगर आप जान लें, तो यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और बढ़े हुए एक्सपोर्ट से जो हमारी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, हमारे प्रदेश में जो डॉलर आने वाले हैं, जो बाहर का हजारों करोड़ रुपया आने वाला है तो एक्सपोर्ट से हमारे यहाँ बाहर का बहुत सारा रुपया आता है। इसी क्रम में मैं अपने बिलारी विधान सभा क्षेत्र की एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि हमारी बिलारी विधान सभा क्षेत्र के सहसपुर में आपने इण्डस्ट्री के लिए एक छोटी सी जगह एलॉट की है। वहाँ पर कई लोगों की इण्डस्ट्रीज हैं, वहाँ पर इण्डस्ट्री तो लग गई है लेकिन उनको वहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई है। जैसे पहले वहाँ पर लाइट 08 से 10 घण्टे आती थी, लेकिन अब वहाँ केवल मात्र 04 घण्टे लाइट आती है तो सहसपुर के इर्द-गिर्द जितनी भी छोटी-छोटी इण्डस्ट्री लगी हुई है, उन इण्डस्ट्रियों में बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार का कोई ध्यान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। उद्योगपति पूरी तरह से परेशान हैं, अगर उद्योग मजबूत नहीं होगा तो कैसे उत्तर प्रदेश मजबूत होगा ? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब मुख्य मंत्री थे, तो हर उद्योग, हर चीज को बढ़ावा देने के लिए हर बार मीटिंग हुआ करती थी। विधायक बैठकर अपने उद्योगपतियों के साथ मीटिंग किया करते थे। हमारे मंत्री जी भी उद्योगपतियों और एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग करते थे। आखिर में बस

मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं दावत दूँगा मा0 मंत्री जी को कि वे एक्सपोर्टर्स के साथ और उद्योगपतियों के साथ बैठक करें, उनका समाधान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी)-

अधिष्ठाता महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस अमृत काल के ऐतिहासिक बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं समर्थन करता हूँ हमारे मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2023-24 के इस बजट का। अभी जैसे हमारे औद्योगिक विकास मंत्री आदरणीय नन्द गोपाल नन्दी जी ने उद्योग से जुड़े बजट को पेश किया। मैं उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की तरफ से और खासतौर से नौजवानों की तरफ से इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं इस बजट के विषय में इस बजट की खासियत अपनी इन चार लाइनों से इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी ये चारों लाइनें मा0 मुख्य मंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, हमारे औद्योगिक विकास मंत्री आदरणीय नन्द गोपाल नन्दी जी, हमारे तमाम मंत्रि-मण्डल की तरफ से हमारी जनता को समर्पित है। नये बजट ने दर्शाया है आने वाला काल

योगी जी के दौर में होगा हर व्यक्ति खुशहाल
प्रदेश में विकास का कुछ ऐसा बिछ रहा जाल
शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हो और कृषि हो मालामाल
याद रखेगी दुनिया अपना आजादी का अमृत काल, आजादी का अमृत काल।

अधिष्ठाता महोदया, आज जिस तरीके से हम तमाम हिन्दुस्तानियों ने पूरे गर्व के साथ अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का काम किया और इस आजादी के अमृत महोत्सव में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने एक ऐतिहासिक बजट पेश करके उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी लिखी है।

मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे प्रदेश के जन-जन को उन्होंने हमें वर्ष 2022 में फिर से चुनकर इस आजादी के अमृत महोत्सव में, इस ऐतिहासिक बजट को पेश करने का अवसर दिया। महोदया, मैं युवा हूँ तो सबसे पहले युवाओं की बात इस सदन के सामने रखना चाहूँगा और जिस तरीके से इस बजट में और खास तौर से इस उद्योग से जुड़े बजट में हम युवाओं को आगे प्रोत्साहित करने के लिए वह तमाम योजनाएँ हैं, वह तमाम प्रावधान हैं कि हम युवाओं ने अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए जो सपना देखा था, निश्चित तौर पर हम नौजवानों के सपनों को पूरा करने का काम यह बजट करेगा, ऐसा हमें पूरा यकीन है। (मेजों की थपथपाहट) तमाम ऐसी योजनायें हैं और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे शहर हो या चाहे गाँव हो, हर जगह विकास पहुँचाना चाहिए और इस सोच को सुनिश्चित करती हुई हमारे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरे दिन और रात मेहनत करके अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की की एक नई कहानी लिखने का काम

किया है। इस तरीके से इस बजट में गाँव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से गाँव-गाँव तक रोजगार पहुँचाने का काम हो। चाहे 'ओ0डी0ओ0पी0' (वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट) जहाँ कल तक उत्तर प्रदेश में सीमित संसाधन हुआ करते थे और सीमित उद्योग हुआ करते थे आज हमारे मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके विजन में उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में हमने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' लाकर और प्रदेश के हर जिले को विकास से जोड़ने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो वह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। यह हमारी सरकार की देन थी। जहाँ कल तक, जब विरोधी दलों की उत्तर प्रदेश में सत्ता हुआ करती थी तो उत्तर प्रदेश के जिलों में माफियाओं और गुण्डों का राज हुआ करता था और उद्योगपति यहाँ से पलायन करते थे। 2017 के बाद से जबसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आयी तो हमने सुनिश्चित किया कि जीरो टॉलरेन्स, जीरो अपराध और 100 प्रतिशत उद्योग को बढ़ावा देने का काम यह हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया और जिस तरीके से हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना लाये हैं। इसमें हमारे जो नौजवान हैं, इनको आज मा0 योगी जी के राज्य में अच्छी सरकारी और प्राइवेट नौकरी तो मिल ही रही है। हमारे नौजवानों के हाथों को और मजबूत करने का काम हमने मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किया। कौशल विकास के तहत गाँव-गाँव में हमारे नौजवानों के स्किल को बढ़ाने का काम हमारी योगी सरकार ने किया और पिछले 6 साल में साढ़े बारह लाख नौजवानों को कौशल से विकसित करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम यह हमारी उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति हो, चाहे हमको हमारे काम हमारी योगी सरकार ने किया और पिछले को कौशल से विकसित करके उनको रोजगार से की योगी सरकार ने किया। इसी तरीके से चाहे नौजवानों को डिजिटली पॉवरफुल करना हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स को बढ़ावा देना हो, चाहे ग्रामीण युवाओं को एग्रीकल्चर स्टार्ट अप से जोड़कर उनको विकास की तरफ आगे बढ़ाना हो, हर कसौटी पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारी से खरी उतरी है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था। उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर देश में ही नहीं पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया है। इन चंद लाइनों से यह सभी हमारे सदन में बैठे हुए सम्मानित सदस्य जान सकते हैं कि-

''है कायल आज दुनिया के सितारे साथ चलने को,
कशिश यू0पी0 के नक्शे में बाबा ने वह रचाई है,
इरादा है, नजरिया है और बेहतर रहनुमाई है,
यही वह खास बातें हैं कि पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश चलकर आई है।''

(मेजों की थपथपाहट)

चूँकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते, उद्योग से जुड़ी जो अल्पसंख्यकों के लिए सरकार की नीतियाँ हैं, जिस तरीके से हमारे अल्पसंख्यक समाज को आज आगे बढ़ाने का काम

पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम अल्पसंख्यक समाज की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस सदन में (मेजों की थपथपाहट) और मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से (विपक्ष के सदस्यों के बीच में टोका टाकी करने पर) जब अल्पसंख्यक की बात है तो विपक्षी लोग परेशान हैं कि कौन-सा अल्पसंख्यक आगे बढ़ रहा है यह तो हमेशा चाहते थे कि यह अल्पसंख्यक समाज विकास से पीछे रहे।

लेकिन ये योगी सरकार है जिसने डंके की चोट पर कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जन को विकास की तरफ आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक समाज का हाथ पकड़ के तरक्की की तरफ अगर आगे किसी ने बढ़ाया तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बढ़ाया है। चाहे अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर कसौटी पर अल्पसंख्यक समाज की तरक्की को सुनिश्चित करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। हमारे एजुकेशन के लिए इम्पलायमेंट के लिए, इंपावरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, हर तरीके से अल्पसंख्यक समाज को देश की मुख्य धारा में अगर जोड़ा है तो हमारे डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा है। एक आम मुस्लिम परिवार का बच्चा मदरसों में पढ़ने जाता है। मैं भी एक गांव में पला-बढ़ा हूं, मैंने देखा है कि पिछली सरकारों में मदरसों की कितनी बुरी स्थिति थी, लेकिन वर्ष 2017 के बाद से मदरसों को आधुनिक बनाने का काम किया गया और मदरसों में अब हमारे बच्चे, दीनी इस्लाम भी पढ़ रहे हैं, उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ रहे हैं और मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं। ये काम शुरू किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। मुस्लिम कैसे अंग्रेजी पढ़ रहा है यह बात विपक्षियों को हजम नहीं होगी, यह बात बुरी लगती है लेकिन आज हमारे मदरसे में पढ़ा बच्चा कुर्ता, पैजामा पहन के, अच्छी उर्दू भी बोलता है और फरार्टेदार इंग्लिश भी बोलने का काम करता है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लिए पिछले 02 महीनों से एक विशेष अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले लगाकर हमारे अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को सीधे रोजगार देने का काम कर रही है, जिसकी शुरुआत पिछले महीने लखनऊ में हुई। अभी 15-20 दिन पहले आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में हमने विशेष रोजगार मेले लगाये जहां पर प्लेसमेंट कम्पनियों ने आकर सीधे अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को हजारों नौकरियां दी और उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया। आज हमारे नौजवानों को दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, कम्पनियां उनके दरवाजे पर आकर उनको नौकरी देने का काम करती हैं। ये काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। चंद लाइनों की एक कविता के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा।

''दुनिया भर में आज हो रहा यूपी का गुणगान,
किसी पे कोई जुल्म-जबर न किसी का कुछ नुकसान,
बेखौफ है जी रहा आज यहाँ हर तबके का इंसान,
भुखमरी की फिकर से फारिंग ऐसा हुआ किसान,

सावन में तर हो जैसे सब फसल खेत खलिहान,
मुजरिम सारे भाग रहे ऐसे बचा के जान,
जैसे उनको पता चल गया अब क्या है उनका अंजाम,
तो भैया, उत्तर प्रदेश को योगी जी ने ऐसा दिया निज़ाम,
दुनिया भर में आज हो रहा यूपी का गुणगान।''

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद। अब माननीय मो0 जाहीद जी बोलें।

श्री जाहीद-

मान्यवर, मैं जाहीद बेग हूँ। मैं माननीय वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज सरकार कितनी असंवेदनशील है, इस बात से पता चलता है कि इनके जो मंत्री हैं, उनको बोलना किस बात पर है और बोलते किस बात पर हैं।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

अधिष्ठाता महोदया, आपने किसको बुलाया है ?

श्री अधिष्ठाता-

मनोज जी ने लिस्ट दी थी, अब मो0 जाहीद जी को बोलना है। मैं नई हूँ इसलिए अभी सभी के चेहरे नहीं पहचानती हूँ। मो0 जाहीद जी बोलें। माननीय सदस्य, बस 4-5 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री जाहीद-

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए क्योंकि साथियों, गला भी खराब है, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। औद्योगिक विकास प्राधिकरण का बजट आपने रखा है। आप हमारे बगल के हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इसका जिक्र अपने भाषण में किया है कि भदोही से 5 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उद्योग मंत्री बैठे हैं कि 2015 में जो एक्सपोर्ट 11,299 करोड़ का था, 2016 में 11,895 करोड़ का एक्सपोर्ट था, लेकिन 2019 में यह घटकर 11,799 करोड़ रह गया। यह आँकड़ा हमारा नहीं है, आपके अधिकारी बैठे होंगे। यह आँकड़ा भारत सरकार के कॉमर्स मंत्री का है। आज वह 2023 में कुछ बढ़ा है। लेकिन उस वक्त 2015 में डॉलर का रेट 64 रुपया था, आज डॉलर का रेट 82 रुपया हो गया है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि यह रुपया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में कम होता जा रहा है। डॉलर बढ़ता जा रहा, यह आपको आइना है। बड़ी-बड़ी बातों के कहने से काम चलने वाला नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पहली बार हरियाणा से कालीन एक्सपोर्ट में पीछे हो गया है। मंत्री जी के मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, लगभग 16 हजार करोड़ का पूरे देश में कारपेट का एक्सपोर्ट

होता है। भदोही, मिर्जापुर और बनारस मिलाकर यह लगभग 6 हजार करोड़ होता है। पहली बार गलीचा एक्सपोर्ट में प्रदेश हरियाणा से पीछे चला गया। यह आपकी उद्योग नीति का नतीजा है। बड़े-बड़े एक्सपोर्टरों को, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को फॉरेन से बुला करके लखनऊ की सड़कों पर घुमा देंगे, लेकिन आपका आँकड़ा सही नहीं होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आपके विभाग का औद्योगिक विकास का प्राधिकरण है, जिसका काम क्या होना चाहिए ? उसे बने लगभग 40 साल हो गये हैं। संविधान के अनुच्छेद-4 (क्यू) के अन्तर्गत जिस पर राज्यपाल का साइन होता है, आज तक वह साइन नहीं हुआ है। आज भी भदोही विकास प्राधिकरण द्वारा धारा-176 के 8 एवं 9 के अन्तर्गत वहाँ के व्यापारियों को नोटिस दिया जा रहा है, जबकि बिना अनुच्छेद-243 (क्यू) की अधिसूचना के उनको यह अधिकार नहीं है। औद्योगिक विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने भाषण में बताइयेगा कि अगर यह पास हुआ है तो कब पास हुआ है ? उस पर राज्यपाल ने कब साइन किया है ? यह सदन जानना चाहता है। बगैर कानून पास कराये, बगैर राज्यपाल के परमीशन के आपका विभाग, भदोही विकास प्राधिकरण नक्शा के नाम पर वहाँ के उद्योगों को लूटने का काम कर रहा है। आप अपना ध्यान बड़े नेताओं के कमेंट पर न लगायें कि कौन बड़ा नेता क्या बोल रहा है ? भाषण हम भी जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, साढ़े चार मिनट हो गये हैं, आप आधे मिनट में समराइज कर लीजिए।

श्री जाहीद-

मान्यवर, आप अपना ध्यान अपने उद्योग पर लगाये होते तो आज शायद यह स्थिति न होती। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भदोही में औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से जो अवैध वसूली हो रही है और उद्यमियों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उसको खत्म किया जाये और सही आँकड़ा रखा जाये। माननीय अखिलेश जी ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भदोही में कॉरपेट का अभी माननीय मुख्य मंत्री जी वहाँ दो बार जा चुके हैं, जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बुलाने का काम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया जल्दी खत्म करें।

श्री जहीद-

मान्यवर, लेकिन भदोही में कारपेट के कार्य अधूरे पड़े हैं जो हमारी सरकार ने बनवाया था शिलान्यास और लोकार्पण भी हम लोगों ने किया था। यह पहली बार है एक मुख्य मंत्री अगर काम करता है तो दूसरा मुख्य मंत्री उसको जा करके रोकता है। यह आप पे आइना

है, यह आपका चरित्र है। हमारे बनाये काम को आप लोग पत्थर लगा सकते हैं लेकिन उसका स्वरूप है जिसने काम किया भदोही की जनता जानती है। इस बात से अपनी बात को समाप्त करते हुये मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उद्योग विभाग पर ध्यान दें और अनावश्यक टिप्पणी बन्द करें। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

नगर विकास विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए माननीय सदस्य अतुल प्रधान जी।

***श्री अतुल प्रधान-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय धन्यवाद। आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपये कर दी जाये। कमी कराने का उद्देश्य विभाग की आलोचना अथवा सुझाव देना है।

हमने मंत्री जी को सुना अगर और भी समय मंत्री जी को देते तो बहुत सुलझे हुये मंत्री जी हैं। काफी लम्बे समय तक नगर विकास के बारे में बता सकते थे लेकिन फिर भी उनके भाषण उनकी तकरीर कई बार आती है तो कई बार सदन में लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ। यह आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पर इसके गहरा निशान है। अभी मुझे नगर विकास के लिए कटौती पर बोलने के लिए कहा गया है। चूंकि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम सब लोग जानते हैं कि तेजी से पलायन ग्रामीण अंचल से शहरों की तरफ हो रहा है। चाहे वह नगर पंचायत हो, चाहे वह नगर पालिका हो और चाहे नगर निगम हो। बहुत तेजी से लोग शहरों की तरफ और कस्बों की तरफ जा रहे हैं, संसाधन ढूंढने के लिए कि संसाधन बेहतर मिल जायेंगे। अभी कुछ देर पहले माननीय नेता सदन बोल कर गये, उससे पहले भी कई लोगों ने बोला है। मंत्रियों का समूह अभी विदेश के दौरे पर गया था और एम0ओ0यू0 साइन करके लाया लेकिन उन्होंने वहाँ जा करके चाहे वह डेनमार्क गये हों, चाहे वह अमेरिका गये हों, चाहे वह फ्रांस गये हों, चाहे वह जर्मनी गये हों वहाँ के शहर जरूर देखे होंगे और जब वहाँ के शहर देखे होंगे जब वहाँ से वापस हिन्दुस्तान एयरपोर्ट पर उतर कर अपने उत्तर प्रदेश के शहरों में पहुंचे होंगे तो आपको अन्तर जरूर नजर आया होगा। पुरानी सरकार के लिए कहा जा सकता है लेकिन सरकारें कुछ-न-कुछ काम करती हैं। मैं इस पर कोई कटाक्ष या आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का जितना महत्व है, उतना ही महत्व विपक्ष का है। आपकी आलोचना करना, आपकी कमियाँ गिनाना, आपके वायदों को आपको याद दिलाना, आपकी उन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चाओं को जो आप भाषणों में जनता के बीच में दिया करते थे। उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना यह हमारे विपक्ष का काम है इस काम को अगर हम नहीं करेंगे तो हम विपक्ष के रूप में स्थापित नहीं हो पायेंगे। इसलिए नगर विकास में कटौती करने के लिए जो कुछ सुझाव है जो आप इस बजट में नहीं ला पाये मैं उसके बारे में एक दो चीज आपसे कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने यह तो बताया कि अब वाला बजट कितना है 25 हजार 347 करोड़, 10 लाख 57 हजार का बजट और यह भी कहा क्योंकि माननीय नेता सदन उस समय सदन में थे और सदन में रहते हुये माननीय मंत्री जी को कुछ ऐसी बातें जरूर बोलनीं थी जिससे कि नेता सदन खुश हो जायें। इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बजट मुझे मिला। मान्यवर, हम भी खुश हैं कि बजट बहुत मिला, लेकिन इससे पहले के बजट के बारे में आपने नहीं बताया। इससे पहले जो बजट था, उस बजट के बारे में अगर सदन को और देश की जनता को बता दिए होते, तो बहुत बेहतर रहता। वह बजट कितना था और उस बजट में से आप कुल 39 प्रतिशत खर्च कर पाए और आने वाले समय पर हमें आस नहीं है कि आपको इतना बजट मिलेगा। हम और आप सही रहें, तो मान्यवर, अगले बजट में इसकी जानकारी जरूर देंगे।

मान्यवर, मैं सबसे पहले जिनके लिए इस कटौती बजट पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना काल का समय हमने, आपने, सबने देखा है। वह कोरोना का समय, जिसमें सड़कें बंद थी, सन्नाटा था, यातायात बंद था, बसें नहीं चल रही थीं, जहाज बंद थे, दुकाने बंद थी, पूरा देश थम सा गया था। उस समय कोरोना वारियर्स की संज्ञा अगर किसी को दी गयी, तो हमारे डाक्टर्स को दी गयी, कर्मचारियों को दी गयी और खास तौर से हमारे उन साथियों को, जो उस कोरोना के समय पर पूरे नगरों में नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में घूम-घूम कर हमारा कूड़ा साफ कर रहे थे। वे ऐसे सफाई कर्मचारी भाई, जिनको कोरोना वारियर्स बोला गया, लेकिन उस कोरोना वारियर्स को बोलने के नाम पर जो तीन कैटेगिरी आती हैं, मैं उन सफाई कर्मचारियों के लिए सबसे पहले इस बजट में पूछना और कहना चाहता हूँ और आपको सुझाव देना चाहता हूँ। आपने भी अपने भाषण में सफाई कर्मचारियों की तारीफ की, उनके बारे में जानकारी रखी और आपने कहा कि उनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों का एक वर्ग नियमित है, जिनको परमानेंट कहते हैं, दूसरा वर्ग संविदा वाला है और तीसरा वर्ग आपका आउटसोर्सिंग वाला है। आउटसोर्सिंग पर वे लोग हैं, जो किसी ठेकेदार के अन्दर होते हैं और ठेकेदार ठेके के पैसे काटकर आउटसोर्सिंग कर्मचारी को देता है।

मान्यवर, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया इलाहाबाद/प्रयागराज के 'कुम्भ' का। वह दृश्य अभी तक हम सब लोगों के जेहन में होगा। वह ऐसा दृश्य था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों को बुलाए थे और उनके चरण स्पर्श किए, तीन तरफ कैमरे लगे हुए थे, वे ऐसे कैमरे थे, जो लाइव प्रसारण लोगों तक पहुँचा रहे थे। जैसे ही

सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, तो पैर धोकर वे सीधे उसी जगह पहुँच गये। मा0 मंत्री जी, आपकी डबल इंजन की सरकार थी। पैरे धोते-धोते प्रधानमंत्री जी आदेश करते कि जितने भी संविदा सफाई कर्मचारी हैं, मैं उन सबको नियमित/परमानेंट करता हूँ, जिससे उन सफाई कर्मचारियों को कोई फायदा होता। अगर उतना भी नहीं करना था, तो कम से कम बैकलॉग की भर्तियाँ निकालकर उनको भरने का काम कर देते। अगर ये भी काम आप नहीं कर सकते थे, तो कम से कम इतना कर दिया होता कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, उनके खाते में सीधा पैसा भेजने का काम कर देते। इस महंगाई के दौर में, मान लिया रु0 2000, 3000 उस गरीब व्यक्ति को, जो दिन-रात काम करता है, जिसको हमने और आपने कोरोना वारियर्स की संज्ञा दी। मा0 मंत्री जी, उनके खाते में कुछ ज्यादा पैसे पहुँच जाते और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ भी न करते, तो कम से कम इतना कर जाते कि रु0 500/-उनकी सैलरी बढ़ा जाते, लेकिन नहीं कर पाए। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से सुझाव है, आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सफाई कर्मचारी, जो बड़े-बड़े शहर हैं, आपने इलाहाबाद/प्रयागराज, वाराणसी, वृंदावन मथुरा और गोरखपुर का जिक्र कर दिया, लेकिन शहर यहाँ पर आकर नहीं रुकते। 17 नगर निगम हैं। सहारनपुर से शुरुआत करिए, आपने लखनऊ की स्वच्छ हवा की बात की, लेकिन मान्यवर, मेरठ की स्वच्छ हवा की आपने बात नहीं की। क्योंकि अगर बात करते, तो वह झूठ कहलाता, क्योंकि वहाँ वातावरण प्रदूषित है।

मान्यवर, मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जब भी बजट लायेगी, चाहे अनुपूरक बजट लाए, तो सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था जरूर करेगी। मान्यवर, इसके साथ-साथ अभी एक बात बहुत अच्छी कही गई 'कान्हा गऊशाला' की। हम सब जानते हैं कि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम और मैने विदेश घूमने की बात इसीलिए की। आप किसी शहर चले जाइए। अगर और ज्यादा दर्शन करने हैं। और जिस मेरठ की जिस क्रांति के साये से मैं आता हूं वहां पर आकर देखिये, सड़कों पर कितने आवारा छुट्टे जानवर घूमते रहते हैं। आपने अभी कान्हा गऊशाला की बात कही, लगभग 17 नगर निगम जिनका इस समय आकार बढ़ गया है, ग्रामीण अंचल को आपने उसमें समायोजित कर लिया है, उसका आकार बढ़ गया है। ऐसे में जो आपका बजट 170 करोड़ रुपये का कान्हा गौशाला के लिए है, यह बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, पहले इन्होंने 30 रुपये और 30 रुपये में कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन वह 30 रुपये भी अभी तक किसी भी गौशाला में नहीं पहुंचे हैं। मैं अपने यहां सरधना की बात करता हूं, दौराला की बात करता हूं, लावल की बात करता हूं और मेरठ शहर इस समय 25 से 30 लाख की आबादी का शहर है, आप पता कर लीजिए कि पुराना पैसा भी अभी तक नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं कि कटौती के प्रस्ताव में कान्हा गौशालाओं में आप आने वाले समय में आप जरूर व्यवस्था करेंगे। एक बात और कहूंगा सरकारी जमीन के रखरखाव के बारे में, यह सरकार हमेशा बुल्डोजर की बात करती है, हमेशा तोड़ने-फोड़ने की बात करती है। अब यह नहीं पता कौन किसको ठोक दे, या तो इधर वाला पक्ष ठोक दे या उधर वाला पक्ष

ठोक दे। यह हम रोजाना देखते हैं और मैं पूछना चाहता हूं अभी तक कितनी जमीनें चिन्हित की हैं आपने ? कितनी नगर निगम की, कितनी नगर पालिकाओं की, कितनी नगर पंचायतों की, जिन सरकारी जगहों पर अवैध कब्जे हैं, मा0 मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जांच करवा लीजिए, आपको पता लग जायेगा कितने अरबों खरबों की जमीने भू-माफिया दबाये बैठें हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। सड़कों के निर्माण की बात हुई, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 500 करोड़ रुपये हमें पहली बार मिले हैं। किसी भी शहर में घूम लीजिए आपके पास पता नहीं कितने पत्र आते हैं कि हमारी मलिन बस्ती में सड़क ठीक नहीं है। सड़क में गड्ढे नहीं हैं गड्ढों में सड़क है। इसमें अभी आपको और बजट की जरूरत पड़ेगी।

मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा और मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा, मैंने भ्रष्टाचार की बात की थी, अभी आप पता कर लीजिए मेरठ में भ्रष्टाचार के नाम पर मेरठ में क्या खेल चल रहा है। एक नगर निगम का ठेकादार जिसका सालों से पैसा नहीं मिला था कमीशन न देने की वजह से उस ठेकेदार ने कल 28 फरवरी 2023 को फांसी लगा ली और मौत के आगोश में चला गया। वहां ई0ओ0 हों या किसी नगर पंचायत के ई0ओ0 हों चाहे आप किसी शहर के नगर आयुक्त हों, आप पता कर लीजिए, वहां पर किस तरह की वसूली चल रहीं है कार्यों के नाम पर, जब आपको पैसा देने की बात आती है तो 40 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जाता है। जितने विधायक बैठे हैं सबकी नगर पंचायतें हैं, सब लोग नगर निगम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बात की आप जांच करवा लीजिए और जांच से आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आयेगा और इतना उत्पीड़न हैं हमारे मेरठ नगर में दो लोगों ने फांसी लगाई हैं, उनका परिवार बिलख रहा है वह परेशानी में हैं, वह दिक्कत में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को जरूर दिखवां लें। इसके अलावा नगर निगम में जो कर्मचारी है, ड्राफ्ट मैन हैं, कनिष्ट लिपिक हैं, और चपरासी हैं, अमीन हैं, इंजीनियर हैं, जेई हैं सारे जितने पद हैं, जब आप बात करते हैं नौकरी देने की, रोजगार देने की तो मैं चाहता हूं विपक्ष होने के नाते आपने बजट में एक बार भी उसका जिक नहीं किया। अगर जिक्र किया होता कि जितनी हमारी बैकलॉग की भर्तियाँ हैं, जितने हमारे रिक्त पद हैं, उन सारी की सारी रिक्तियों पर पुनः निकालकर सारी नगर निगमों को, सारी पंचायतों को फुल कर देंगे। मैं अकेले मेरठ का जिक करूं तो 25 से 30 लाख की आबादी का शहर है और 2200 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। इस समय पर लगभग 7 हजार लोगों की मेरठ में जरूरत है और इसी तरह कानपुर में चले जाएं तो वह बड़ा शहर है, आगरा में चले जाएं तो वह भी बड़ा शहर है, आप लखनऊ आ जाइये बड़ा शहर है। आप बनारस चले जाइये क्योंकि फैलाव बढ़ रहा है वह भी बड़ा शहर है और हमे उम्मीद है कि आप उसमे जरूर आने वाले हाउस में इस चीज को जरूर रखेंगे। टैक्स के नाम पर वॉटर टैक्स लेकिन पानी आता नहीं, किसी के नाम पर कितना हाउस टैक्स लगा

दिया। किसी के नाम पर कितना हाउस टैक्स लगा दिया ? इसमें तमाम भ्रष्टाचार है। हमें उम्मीद है कि जब इतने बड़े डिपार्टमेंट को माननीय मंत्री जी देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में जरूर संज्ञान लेंगे कि इस पर किस तरह की चीजें चल रही हैं। अभी पर्यावरण संरक्षण की बात की। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने लखनऊ की हवा की बात की और कहा कि यू0पी0 में नहीं देश में फर्स्ट नम्बर की है। क्या आपने किसी एक लैब के लिए पैसा दिया है कि इस लैब में जाँच-पड़ताल कराकर हम इस चीज को सुधारने का काम करेंगे जिससे हवा ठीक हो जायेगी। माननीय मंत्री जी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शहर बढ़ते जा रहे हैं। आप छोटे-छोटे मोहल्ला क्लीनिक बनवा दीजिए क्योंकि अस्पताल वहीं के वहीं है और गरीब लोगों को वहाँ पर सुविधा नहीं मिलती है। अगर माननीय मंत्री जी ऐसा हो जाये तो प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में जरूर सोचेंगे।

अभी आपने नगरीय परिवहन की बात की। आप लो-फ्लोर सी0एन0जी0 की कुछ बसें दे रहे हैं। आज जो पुरानी बसें चल रही हैं, उनकी हालत देखिये। आपने जो बसें दी हैं वह बहुत कम हैं, उन बसों की हालत देखेंगे कि कितनी खराब स्थिति में हैं। आप स्मार्ट सिटी की बात करते थे। आपने 35 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन करने की बात की है, अगर एक एम0ओ0यू0 ऐसा भी साइन हो जाता जिसमें लो-फ्लोर बसों की संख्या बढ़ जाती तो काफी अच्छा होता। अभी पार्कों का जिक्र किया, मान्यवर, पार्कों का जिक्र जब चल रहा था, जो प्राधिकरण से कालोनियाँ नगर निगमों को हस्तांतरित होती हैं, प्राधिकरण के पार्क की हालत देखिये और उसके बाद नगर निगम के जो पार्क हैं वहाँ पर गन्दगी का आलम देखिये कि कितनी गंदगी और कितनी अव्यवस्था है ? मान्यवर, आपने कहा कि हमने लगातार 75 दिन या 75 घण्टे तक सफाई अभियान चलाया। यह एक सतत् प्रक्रिया है। क्योंकि लोग कूड़ा सड़क पर डालते हैं लेकिन इस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते कि वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। फिर आइये मलिन बस्तियों पर आपने सारी चीजें पढ़ीं लेकिन किसी नगर निगम में जाकर देखिये भारी भरकम बजट आता है, जैसे किसी बड़े नगर निगम में बजट आता है तो अखबारों में सुर्खियाँ बनती हैं कि 600, 800 करोड़ का बजट और कहते हैं कि प्रत्येक पार्षद को बराबर हिस्से में बाँट दिया जाये। मैं इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूँ कि जो मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ लोग दिक्कत में रह रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बजट की व्यवस्था की जाये जिससे उन मलिन बस्तियों के गरीबों, शोषितों, वंचितों व कमजोर लोगों को बेहतर सुविधायें मिल सकें। जब बात आती है सबका साथ, सबका विकास व सबके विश्वास की, तब हम मान्यवर, आपसे अपेक्षा करेंगे कि ऐसी मलिन बस्तियों का संज्ञान ले करके आप सोचिये और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समय में जरूर इन मलिन बस्तियों के बारे में सोचा जायेगा।

मा0 अधिष्ठाता-

संक्षेप करिये, 15 मिनट का समय हो चुका है।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने 20 मिनट के लिए कहा था। मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूँ। दो-तीन मिनट और दे दीजिए। अभी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक की बात हो रही थी, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक में जब माननीय मंत्री जी छापा डाला जाता है तो गरीब के घर पर छापा डाला जाता है और पन्नियाँ छीन करके ले लायी जाती हैं लेकिन जहाँ पर इनका निर्माण हो रहा है, जब भट्ठियाँ लगाकर सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को निकाल रहे हैं। जब कूड़ा वेस्टेज में ये प्लास्टिक इकट्ठा हो जाती हैं तो वो गलती नहीं है। उसके लिए आपने कोई योजना इसमें नहीं बनायी है। हमारा मेरठ शहर है, जिसके आस-पास चाहे काली नदी हो, चाहे हिंडन नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, नमामि गंगे इतनी बड़ी योजना हैं, आप नदी को साफ नहीं कर सकते जब तक उसमें डलने वाले वाले गंदे पानी को साफ नहीं करेंगे। एस0टी0पी0 प्लाण्ट के नाम पर फैक्ट्रियाँ क्या कर रही हैं ? मेरे अकेले मेरठ शहर से अप्पू नाला प्रथम, अप्पू नाला द्वितीय व दिल्ली रोड का नाला जाकर काली नदी में गिरता है। एस0टी0पी0 प्लाण्ट की बात पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं लेकिन एस0 टी0 पी0 प्लाण्ट नहीं लग पाया। मुझे उम्मीद है कि एस0टी0पी0 प्लाण्टों का संचालन सुचारु रूप से करेंगे जिससे जो भूगर्भ दूषित हो गया है, जल प्रदूषित हो गया जिससे कैंसर, चर्म रोग, काला पीलिया होता है और हमारे बच्चों की स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद कि उसका संज्ञान ले करके जो गंदा पानी निकलता है वह सिर्फ भूगर्भ को ही दूषित नहीं करता, एअर पोल्यूशन भी फैलाता है जिससे तमाम वायु जनित रोग निकलते हैं।

मान्यवर, अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि एक अध्यादेश आया था 1992 में 74वाँ संविधान संशोधन यह ऐसा संशोधन था जो नगर निगमों को ताकत देता था लेकिन इसको किसी ने नहीं मानी हम उम्मीद करते हैं कि डबल इंजन की सरकार इस संशोधन को मानेगी अगर हम संशोधन को मान लेंगे तो निश्चित रूप से नगर निगमों को ताकत मिल जाएगी। वह ऐसी ताकत होगी जिससे आम लोगों को फायदा होगा। आमजनों को फायदा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जब मा0 मंत्री जी अभी पढ़ेंगे तो इस बारे में जरूर बोलेंगे कि इसके बारे में अपनी बात रखें और जरूर बताएं। एक डूडा और सूडा विभाग है वह डूडा और सूडा ऐसा है कि जितने भी मा0 विधायकगण यहां पर मौजूद होंगे एक-एक डूडा और सूडा विभाग के बारे में जरूर जानता होगा। इतना भ्रष्टाचार अगर ठीक ढंग से जांच हो जाए तो अधिकतर अधिकारी उसके जेल के सलाखों के पीछे होंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों की जांच कराके मा0 मंत्री जी उनको जेल की सलाखों के पीछे तो भेजेंगे बुल्डोजर का इस्तेमाल भी उनके लिए आप जरूर करेंगे। मैं लास्ट बात करता हूं कि मा0 मंत्री जी ने थूकने की बात की थी मैं जानता हूं कि थूकना गलत है, यह गलत चीज है।

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपके 20 मिनट हो चुकें है।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं थूकने की बात कर रहा था मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने जो थूकने की बात की, लेकिन इसके साथ-साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुटका राजस्व देता है, खैनी राजस्व देती है, हम तो मांग करेंगे कि गुटका, खैनी, सुरती पर सरकार प्रतिबन्ध लगाए जिससे थूकने की नौबत ही नहीं आए। अभी एक शेर सुना कर अपनी बात को खत्म करूंगा और मा0 मंत्री जी से उम्मीद है कि मेरी बातों को अन्यथा न लेकर उसको एक सुझाव के रूप में मा0 मंत्री जी लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपकी कोशिश को हम लोग देख रहे है और मुझे उम्मीद हैं कि आप इन पर जरूर ध्यान देंगे। 'हमें तो आखिर यह देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक हमें तो यह देखना है तुम्हारे लफ्जों के कैंचियों से परिन्दे होंगे शिकार कब तक यह वक्त दुनिया में जिन्दगी भर किसी का होकर नहीं रहता है यह जो समय है आपका, आपका भी नहीं रहेगा, हमारा भी नहीं रहेगा, यह वक्त दुनिया में जिन्दगी भर किसी का होकर नहीं रहता, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक बनोगे तुम होशियार तब तक' मैं मा0 मंत्री जी और मान्यवर आपका धन्यवाद करता हूं कि इस प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करते हुए मा0 मंत्री जी को यह सुझाव मेरी तरफ से आप जरूर मानेगे बहुत बहुत शुक्रिया जय भीम, जय भगत सिंह।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री असीम अरूण)-

मान्यवर, जो नगर विकास का बजट प्रस्तुत किया गया है जैसी हम लोगों को अपेक्षा थी कि यह बजट अमृतकाल को निर्धारित करने वाला बजट है। पिछले पांच वर्ष में मा0 योगी जी के सरकार में या आप छह वर्ष मान लें और उसके अलावा मा0 मोदी जी के नेतृत्व में जो परियोजना के जरिये, अवस्थापना को मजबूत करने के जरिये, उसके परिणाम हम लोगों को अच्छे मिले हैं और अब उसको और उंचाइयों पर ले जाना है। जो मूल विषय मैं रखना चाहता हूं अवस्थापना के दृष्टिकोण से जल, सीवर, सड़क आदि यह सभी व्यवस्थाओं को नगरों में मजबूत करने के लिए व्यवस्थाएं इस बजट में की गई हैं जो अत्यंत स्वागत योग्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आगे बढ़ाएगा। जल मिशन नगर में भी चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है नगर क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति है जितना छूटा वह और अब पूरा होने वाला है। साथ ही साथ पानी की गुणवत्ता अच्छी हो, सेहत के लिए पानी अच्छा हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो नगर निकाय देते हैं और जल संवर्धन करते हैं, परीक्षित करते हैं, उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था दी गई है। लगातार हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि जो जन-सेवाएं हैं वो आसानी से सुलभ हों नागरिकों के लिए और उसके लिए ई-गवर्नेन्स एक और महत्वपूर्ण स्तम्भ है जो नगर निकाय के सभी कार्यों के नगर विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है और उसमें इस प्रकार स्मार्ट सिटी के जरिए और सभी नगर पालिकाओं में हेल्पलाइन नम्बर बनाए गये हैं, ऐप बनाई गई है, जिस पर लोग शिकायत कर रहे है और उनकी समस्याएं बहुत तेजी से हल भी हो रही हैं।

इसी से जुड़ा हुआ जैसे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' है उसी प्रकार से 'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' है, उसमें उत्तर प्रदेश के नगर बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। मा0 सदस्य श्री अतुल प्रधान जी द्वारा अभी महत्वपूर्ण विषय रखे गये। उनके कुछ सुझाव अच्छे थे जिन पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। मा0 अधिष्ठाता जी, किसी भी नगर में हम लोग जब नगर को अच्छा करते हैं तो पहले तो अपने लिये अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर हमारा नगर अच्छा होता है तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से अगर कोई कम्पनी अथवा बैंक आदि अपना कार्यालय खोलना चाहता है तो वह ऐसे नगर को चुनते हैं जहाँ पर 'ईज ऑफ लिविंग' हो और उनके कर्मचारियों को रहने में आसानी हो और अच्छा लगे। हमारे नगर इस चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, वह सुन्दर हो रहे हैं, 'ईज ऑफ लिविंग' अच्छी हो रही है। इसीलिये अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें लोग यहाँ पर आये और आकरके हमारे समस्त जनपदों को देखा और इस बात से प्रसन्न हुये और उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का संकल्प लिया। जो मूल 06 स्तम्भ हैं उसमें अन्तिम स्तम्भ परिवहन का है। ट्रांसपोर्ट के लिये सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपके क्षेत्र का भी उदाहरण है जहाँ पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे बनाया गया, जिससे अब केवल 45 मिनट की दूरी रह गयी है। जल्दी ही रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम 'आर0आर0टी0एस0' का भी उद्घाटन होगा, वह उस दूरी को और भी कम कर देगा और वाहनों की आवश्यकता को भी समाप्त कर देगा। इसलिये मा0 सदस्य की प्रदूषण को लेकर जो चिन्ताएं थीं वह वाजिब हैं, लेकिन यह उनका दीर्घकालिक हल है और वह इस प्रकार के बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही सम्भव होगा। यद्यपि हम नगर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिये भी प्रबन्ध किया गया है। इसको पॉपुलराईज किया जा रहा है, लोकप्रिय बनाया कम किया गया है और इस पर टैक्स कम किया गया है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, इसके साथ-साथ स्वच्छता अभियान जिस पर मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, उसके अन्तर्गत हम लोग हर घर, हर गली में काम कर रहे हैं। इसको और आगे बढ़ाया जायेगा और आप सभी लोगों को जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2022 में स्वच्छता से सम्बन्धित जो अवॉर्ड्स थे, इनाम थे, उत्तर प्रदेश को 13 अवॉर्ड मिले जो हम सबके लिये बड़े गौरव की बात है। जहाँ डबल इंजन की सरकार ऐसे काम कर रही है जिससे अवॉर्ड मिल रहे हैं वहीं पर डबल इंजन की सरकार में यह देखने के लिये एक गार्ड का डिब्बा भी है कि कोई पीछे न छूट जाये। नगर विकास में जो हमारे भाई प्रायः युवा यह काम कर रहे थे जिसको अंग्रेजी में मैनुअल स्क्वेन्जिंग कहा जाता है या हिन्दी में गटर में उतर करके सफाई कर रहे थे, आज के समाज में यह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, इसको हल करने के लिये 'सफाई सुरक्षा मित्र' नाम से एक योजना लाये हैं, जिसमें दो काम किये जा रहे हैं। जो हमारे श्रमिक साथी हैं उनको उद्यमी बनने का अवसर दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत उनकी छोटी-छोटी कम्पनियाँ बना रहे हैं। अब मशीनों से सफाई होगी।

उनको ऋण दिया जा रहा है, उनको सब्सिडी दी जा रही है जिससे कि पूर्व में जिस काम को हाथ से किया जाता था वह उसको मशीन से करें, अपनी सुरक्षा के साथ करें और इस प्रकार से काम हो जिससे उनकी सेहत भी न खराब हो और उनके जीवन को खतरा भी न हो।

इसी के साथ-साथ जो शहरी गरीब हैं उनकी मदद करने के लिये पी0एम0 आवास योजना (शहरी) में कुल 16.8 लाख आवास स्वीकृत हुये हैं जिसमें से 12 लाख आवास निर्मित हो चुके हैं तथा शेष लगभग 04 लाख आवास वर्तमान में निर्मित हो रहे हैं और आगे इसमें और योगदान रहेगा। इसी प्रकार 'पी0एम0 स्वनिधि' योजना है जिसमें 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार तक के ऋण दिये जा रहे हैं, बहुत अच्छे और अट्रैक्टिव लोन है, यह इसीलिये हैं कि शहर में जो ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले बहन-भाई हैं, छोटी दुकान करने वाले बहन-भाई हैं वह आगे बढ़ पायें और तेजी से उनका विकास हो। अभी तक जो अमृत योजना चल रही थी उसको हम लोग और आगे बढ़ायेंगे। इसमें 60 नगरों में नल, सीवर आदि की व्यवस्था हो चुकी है। यह 08 हजार 300 करोड़ रुपये की योजना है। इसके साथ-साथ हमको सौन्दर्यीकरण की ओर भी बढ़ना है। मा0 प्रधानमंत्री जी ने 'अमृत सरोवर' की एक बहुत अच्छी योजना हम लोगों को दी है। यह योजना ग्रामीण में भी है, लेकिन अभी हम नगर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 194 अमृत सरोवर बना रहे हैं, जिससे सुन्दरता भी बढ़ेगी और साथ-साथ जो नगरवासी हैं उनको शाम को घूमने-फिरने तथा मौज-मस्ती के लिये एक स्थान भी मिलेगा। एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर सुबह योग का प्रबन्ध भी किया गया है तथा शाम को बच्चों के खेलकूद का भी प्रबन्ध किया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, प्रबन्ध की बात आयी थी तो प्रबन्ध के बारे में मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि 10 स्मार्ट सिटी केन्द्र द्वारा पोषित हैं और 07 नगर ऐसे हैं जो कि राज्य द्वारा पोषित हैं तो कुल 17 स्मार्ट सिटी इस तरीके से हैं जिनके लिए हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि कुम्भ मेले के लिए अभी से 300 करोड़ की व्यवस्था की गयी है, आगे और व्यवस्था की जायेगी। इसलिए कि जब तक कुम्भ आए तब तक हमारी सभी तैयारियाँ मजबूती से पूरी हो चुकी हों और जैसा पिछला कुम्भ रहा, हम सबने देखा कि पूरे विश्व से लोग आए और हर आने वाला व्यक्ति एक हफ्ते बाद उसने पाँच और मित्रों को भेजा, क्योंकि व्यवस्थायें इतनी अच्छी थीं। कुल मिलाकर योजना बनाकर काम करने का प्रस्ताव रखा गया है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बजट को सभी अंश में बांटा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला एक वर्ष इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, हमारे नगर और अच्छे होंगे। इन्वेस्टर्स समिट में 35 लाख करोड़ का एक बड़े निवेश का संकल्प हम लोगों ने लिया है उसमें नगरों का अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण अंश है। उस इन्वेस्टमेंट के जरिए तो अच्छा होगा ही लेकिन उससे पहले हमको अपने नगरों को अच्छा करना है। मैं बधाई देना चाहूँगा मा0 मंत्री शर्मा जी को कि उन्होंने जिस प्रकार इन्वेस्टर्स समिट के लिए लखनऊ को सजाया और वह सजावट अभी तक बरकरार है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह सजावट बरकरार रहेगी,

जारी रहेगी हम अपने नगरों को सुन्दर करते हैं अतिथियों के लिए भी, लेकिन उससे पहले अपने लिए सुन्दर करते हैं और जब कोई अतिथि आता है तो उसको और अच्छा कर लेते हैं। आदरणीय मंत्री जी आपकी पूरी टीम का आभार, मा0 मुख्य मंत्री जी के जैसे निर्देश हैं हम सब मिलकर उसमें अपना-अपना योगदान कर रहे हैं, बहुत-बहुत आभार।

***श्री पंकज कुमार मलिक-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, धन्यवाद आपने मुझे अतुल प्रधान जी के द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ और दो पंक्ति पहले कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज गांव का आदमी अच्छे जीवन को पाने के लिए शहर की तरफ रुख कर रहा है। मान्यवर, जब वह शहर में आता है तो सोचता है कि मुझे अच्छी सुविधायें मिलेंगी, साफ कालोनियाँ मिलेंगी, अच्छी हवा मिलेगी, लेकिन शहर आकर वह यह महसूस करता है कि 'शहर की यही जिन्दगी है अब तो हवाओं में भी गन्दगी है' मा0 मंत्री जी ने जितनी पॉजिटिव बात कही है वह बहुत अच्छी बात है और हम लोग उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। अगर इन सारी बातों को अमली-जामा पहना दिया जाय और जितनी योजनायें आपने बतायी हैं बहुत अच्छी बात है तारीफ के काबिल बात है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग होना भी जरूरी हैं अगर हम विपक्ष के लोग कोई बात आपके सामने रख रहे हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ आलोचना नहीं है। हम लोग जो देखते हैं वही यहां आकर बताते हैं। वह कहते हैं चूँकि हम हों या आप हों नागरिकों के अपने क्षेत्र के वोटरों की चिन्ता यहां पर बैठ कर करते हैं। नगर विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। नगरों में सड़क, जल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट आदि मूलभूत सुविधाओं को देने का काम करता है। अभी मैं पुस्तिका पढ़ रहा था इसमें मैंने देखा है, नगर जिनमें सीवर की व्यवस्था नहीं है नगर निगम, नगर पालिका परिषद् 194 में 148 हैं, नगर पंचायत 520 तो कहीं न कहीं अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि इन सब चीजों पर जल्द से जल्द काम किया जाय। नगर निकाय के अधिकारों को भी मजबूत करने की बात है। कई बार जो जनपद में बैठे अधिकारी होते हैं, कमिश्नरी में बैठे अधिकारी होते हैं वह जनता को अन्धेरे में रखते हैं जिससे जनता अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर की बात करता हूँ मुजफ्फरनगर की मेरी विधान सभा क्षेत्र में चरथावल नगर पंचायत है, जो नगर विकास से बहुत दूर है। वहां पर विकास की बहुत आवश्यकता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा एक जनपद आप मुझे बता दें जहां पर जरा सी बारिश हो जाए और पानी न भरता हो। चाहे मेरठ के मुख्य बाजार हों, सहारनपुर के मुख्य बाजार हों, बिजनौर के बाजार हों, मुजफ्फरनगर शामली के बाजार हों, मुजफ्फरनगर और शामली में एक जगह है शिन्चौक दोनों जगह, एक जगह है थालापार आपका बारिश में निकलना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुश्किल हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि लखनऊ में ही अगर तेज बारिश हो जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। चूँकि सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सड़कें वहां पर हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो नई बस्तियाँ वहां पर बनी हैं।

नई बस्तियों में काम नहीं होता। अभी अतुल भाई मलिन बस्तियों की बात कर रहे थे। मैं विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 6 साल से आपकी सरकार है। आपने कहा था कि एक-एक गरीब को सम्मान देने का काम करेंगे। विकास करेंगे। विकास को एक-एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 6 साल से मलिन बस्तियां मलिन क्यों हैं ? केन्द्र में आपकी सरकार है, यू0पी0 में आपकी सरकार है और काम करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां छोटी-छोटी गलियां हैं, छोटे-छोटे मोहल्ले हैं वहां कूड़े की बहुत समस्या है। बड़ी दिक्कत है। ऐसा कोई वाहन जो अन्दर तक जा सके, एक क्वीन्ट वहां बना दिया जाये। स्वच्छता अभियान की आप बात कर रहे थे। इस पर काम करने की जरूरत है और यह जेन्यून बात है। मैं आपके सामने बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूं। बहुत आवश्यकता है इन सब चीजों की। आपने मुझे मौका दिया आपका लम्बा समय न लेते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल-

अधिष्ठाता महोदय, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का यह बजट है। नगर विकास के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का विकास क्यों हो रहा है एक लाइन में हम समझ लें। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो नीचे तक मात्र 15 पैसे पहुंचते और अपने आपको स्वयंभू, कट्टर ईमानदार कहने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार होती, बसपा की सरकार होती तो इस बजट का भगवान ही मालिक होता। अभी जी-20 के बारे में ये कह रहे थे कि इन्वेस्टर्स समिट में हमारे माननीय मंत्रीगण विदेश गये थे जब लौटकर आये तो कैसा शहर लग रहा होगा हिन्दुस्तान का इस बारे में उन्होंने कहा। मैं इनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप आगरा में देखकर आइये। हमारे नगर विकास मंत्री माननीय शर्मा जी, योगी जी स्वयं आगरा गये थे और आगरा को कितना खूबसूरत बनाया है। आप आइये आगर मैं दिखाता हूं। जी-20 के मेहमान तो चले गये अब मैं आपको मेहमान के तौर पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप देखकर आईये कि आगरा कितना खूबसूरत बन चुका है ? केवल इसलिए क्योंकि एक-एक रुपया हमारे नगर विकास मंत्री जी एवं माननीय योगी जी के नेतृत्व में कायदे से खर्च हुआ है। जहां तक डूडा का सवाल है तो उसके बारे में बता दूं कि डूडा का आपके जमाने में हाल क्या आया ? आपके जमाने में जब आपकी सरकार 2002 में थी तो डूडा के द्वारा वाटर लाइन डाल दी गयी, लेकिन पानी आज तक नहीं गया। 'सीवर लाइन डाल

दी गयी पर चालू नहीं हुई।' जब लाइन खाली रहेगी तो डैमेज होगी। जब अधिकारियों को ढूढने के लिए निकले तो पता लगा कि अगर अधिकारियों को दण्डित करवाना है तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। इतने पुराने हैं। आज हमसे बात करते हैं कि डूडा में क्या किया ? आज हमने नियंत्रण किया है। अगर 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये ही खर्च होते हैं। आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के विकास की बात करनी है तो टी0वी0 चैनल खोलिए और पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है कि हमको मोदी चाहिए। हिन्दुस्तान की धज्जियां उड़ाने का कोई काम कर रहा है तो यह सपा के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हमसे सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जब आपके जमाने में राशन बंटता था तो राशन का दुकानदार घटतौली भी करता था, लोगों को राशन नहीं देता था। आज हम चैलेन्ज के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार के समय में पूरा राशन मिल रहा है, आप बताइये मिल रहा है कि नहीं ? हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई हो तो बताइये कहां पर राशन नहीं मिल रहा है ? हिन्दुस्तान में चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो अपने ही देश धज्जियां उधेड़ने में लगे हुए है। अब तो पाकिस्तान भी कह रहा है। आपके नेता जी कहते थे कि पाकिस्तान से दोस्ती करो। हम तो दोस्ती करना चाहते हैं। अब तो पाकिस्तान की आवाम भी चिल्ला रही है। जरा अब तो आप लोग शर्म कर लो।

अधिष्ठाता महोदय, क्षमा करना मैं संसदीय शब्द का प्रयोग करूंगा। पूछ को कितना भी गाढ लो निकलेगी टेढ़ी ही सीधी नहीं हो सकती है। यह भाजपा की सरकार है योगी जी व मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है और अब भारत माता को डॉट-डॉट कहने वाले लोग बिलों में घुसे रहेंगे निकल कर नहीं आ सकते हैं। क्या कोई माई का लाल है कि अब भारत माता को 'डॉट-डॉट' कहकर दिखावे यही है भाजपा की सरकार और यही है राष्ट्र भक्तों की सरकार, अब हम गुलामी की बात नहीं करते हैं, लोकतंत्र में अनुशासन की बात करते हैं। लखनऊ में नाइट सफारी पार्क मंजूर किया गया है यह उत्तर प्रदेश का पहला पार्क होगा और आज हमने मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि आगरा में पर्यटन की बहुत सम्भावनाएं हैं और नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं और यह भी विकास पुरुष है तो मेरी आज आगरा में भी नाइट सफारी पार्क बनवाने का निवेदन है। विद्युत शवदाह गृह आगरा में सिकन्दरा के निकट संचालित है।

बल्केश्वर आवास विकास कॉलोनी, पोइया घाट के श्मशान घाट पर भी विद्युत शवदाह गृह बनवाने का सुझाव है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, समाजवाद से ही खुशहाली आती हं और समाजवाद से ही सम्पन्नता आती हैं। समाजवाद से समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर वर्ग के लोग अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को न्याय, हक, अधिकार तथा सम्मान दिलाने का काम होता हैं। जब यह देश

गुलाम था तो इस देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ और जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद 2 साल 5 महीने 11 दिन में देश का संविधान लिखा गया और देश के संविधान में आप पढ़ लीजिएगा संविधान की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि भारत के लोग एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरेपक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनायेंगे और समाजवाद की कल्पना महात्मा गांधी, डा0 भीमराव अम्बेडकर, डा0 लोहिया, लोक नायक जय प्रकाश नरायण, आचार्य नरेन्द्र देव और मा0 मुलायम सिंह ने करने का काम किया था। आज जो लोग संविधान के विरोधी हैं, जो लोग गरीब को उसका हक न मिले और न्याय न मिले वह लोग यह चाहते हैं कि देश में पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो जाये। हम चाहते हैं अमीरी और गरीबी के बीच का अन्तर दस गुना से अधिक न होने पाये। हम लोग यह चाहते हैं कि अगर अम्बानी की सम्पत्ति 50 हजार करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ हो गयी उसी अनुपात में एक गरीब की भी आय बढ़नी चाहिए। अमीरी और गरीबी के बीच में इतना अन्तर न हो और मान्यवर यह जो बजट पेश हुआ है तो इस बजट में कहीं पर भी गरीब की झुग्गी- झोपड़ी है और गरीबों की मलिन बस्तियों में सुविधाएं देने की बात नहीं की गई है और जो लोग नाले किनारे पर रहते है उनके विकास के लिए कहीं कोई बात नहीं कही गयीं है। मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में छोड़िए जहां मुख्य मंत्री का आवास है और उनके आवास के पास जो चौराहा है उसको पार करके जो पार्क रोड विधायक आवास के बीच में नाला है और उस नाले पर अगर आप घूम लेंगे तो हम जान जायेंगे कि जो आप बात कहते हैं वह सच है। नाले के किनारे गरीब बेबस लाचार लोग रहते हैं वहां पर विकास का कोई काम नहीं है। मुख्य मंत्री आवास से 50 मीटर दूरी पर जो लोग रहते हैं वह नाला खुला हुआ हैं। और उसको ढकने का कार्य करें।

यह नाला बरसात के महीने में भर जाता है। घर के अन्दर पानी भरता है। लखनऊ शहर के अन्दर जो नाले हैं जब बरसात होती है तो वह नाले भर जाते हैं और उन नालों का पानी घरों में आ जाता हैं । मान्यवर, यह हालत लखनऊ शहर में हैं। आप कह रहे है कि पूरे प्रदेश में हमने विकास किया और सड़कें बना दीं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ जहां पर इन्वेस्टर्स आ रहे थे केवल वहीं पर सड़कें बनीं। विधान सभा के चारों ओर सड़क बनी हुई थी, लेकिन बनी हुई सड़क को दोबारा बना दिया गया। माननीया अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि एक दिन केवल दस मिनट का समय निकालकर बापू भवन से आगे निकलिये और मेडिकल कालेज तिराहे तक जाकर देखिये कि सड़क में कितने गड्ढे हैं आप पायेंगे कि पूरी सड़क में गड्ढ़े हैं जिसके कारण उस सड़क पर रोज गाड़ियाँ पलटती हैं और दुर्घटनायें होती हैं और लोगों को चोटें आती हैं। लखनऊ में जो मुख्य रास्ता है, आप बापू भवन से जाइये कैसरबाग चौराहा, बस स्टैण्ड चौराहा, सिटी स्टेशन और मेडिकल कालेज तो वहां की सड़कें इतनी खराब हालत में हैं कि वहां चलना मुश्किल है। ऐसे ही पूरे लखनऊ शहर के अन्दर सड़कें टूटी पड़ी हैं और नाले भरे हुये हैं जिनकी सफाई का

कोई इंतजाम नहीं है। आज से छह-सात साल पहले जितने सफाई कर्मचारी थे उनमें कहीं कोई बढ़ोत्तरी करने का काम नहीं किया गया है। सफाई कर्मियों को आज हत्था ठेला भी नहीं मिल रहा है और वह मजबूर होकर डलिया को सिर पर रखकर कूड़ा फेंकने के लिए मजबूर हैं। हालत यह है कि पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पीने के पानी के लिए टंकियां लगवा रहे हैं। जहां पर टंकिया लग रही हैं उन मोहल्लों में भी वाटर टैक्स की नोटिस आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पर तो जल संस्थान का नल ही नहीं है, तो हम वाटर टैक्स क्यों दें। टंकी से पानी पीने वाले व्यक्ति के पास भी वाटर टैक्स का बिल जा रहा है। गरीब लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं तो नगर निगम नोटिस देकर उनके मकान को नीलाम करने का काम कर रहा है। लखनऊ शहर के अन्दर नगर निगम को भंग कर दिया और प्रशासक को नियुक्त कर दिया गया जिसके बाद नगर निगम के पार्षद काम नहीं करा पा रहे हैं। प्रशासक कहीं कोई काम कर नहीं रहा है। ठेकेदार को पेमेण्ट नहीं मिल रहा है और नगर निगम घाटे में चल रहा है। पूरे प्रदेश के बहुत बुरे हालात हैं जिसे हम सब जानते हैं। हम लोगों की सरकार में गोमती नदी से हजारों ट्रक मलवा निकालकर नदी साफ कराई गई थी, लेकिन छह साल में गोमती नदी में कहीं कोई सफाई का काम नहीं हुआ है और इस दौरान नगर विकास विभाग ने इसकी सफाई कराने का काम नहीं किया है। हैदर कैनाल नाला को ढकवा दीजिये और उस पर सड़क बनवा दीजिये जिससे ट्रैफिक की समस्या दूर हो जायेगी। नगर निगम की जो गौशालायें हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है और वहां बड़ी संख्या में रोज गायें मर रही है तो गौशालाओं की जांच कराकर गायों की रक्षा की जाये, एवं दोषी और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाये। माननीया अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री अभिजीत सिंह 'सांगा'-**

माननीया अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बजट में नगर विकास विभाग के लिए 25347 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि इस बजट में महाकुम्भ 2025 प्रयागराज में जो आयोजित होना है उसके लिए 2500 करोड़ का प्राविधान किया गया है। सड़क सुधार हेतु 500 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अमृत 2.0 के लिए 5616 करोड़ का प्राविधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सत्ताइस सौ सात करोड़ का प्राविधान किया गया है। केंद्रीय स्मार्ट सिटी के लिए 1568 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राज्य स्मार्ट सिटी के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

245 करोड़ का प्राविधान किया गया है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए 4900 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना के लिए 607 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कान्हा गौशाला के लिए 170 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अधिष्ठाता महोदय, जिन प्राविधानों की मैं चर्चा कर रहा हूँ विभिन्न मदों की मैं चर्चा कर रहा हूँ निश्चित रूप से जब बिग बजट प्रस्तुत होता है कोई मेनोफेस्टो बनता है तो उसके पीछे कोई न कोई विचार होता है। अभी हम लोगों ने मा0 मंत्री जी का वक्तव्य सुना है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट के पीछे रामराज्य का विचार है। इसमें सबका साथ सबका विकास का विचार है। इस वक्तव्य के पीछे दीनदयाल जी के अन्त्योदय का विचार है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट है यह सर्व समावेशी बजट है। आज जो विपक्ष के साथी जो आलोचना कर रहे हैं जो इनका विचार है जिस विचार को यह लोग मानते हैं उसी के अनुरूप यह लोग बजट की आलोचना करने का काम कर रहे हैं। हमारा विचार है सबका साथ, सबका विकास, इनका विचार है अपनों का साथ अपनों का विकास। हमारा विचार है रामराज्य का विचार, इनका विचार है परिवारवाद का विचार । मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जब इनकी सरकारें होती थीं और शौचालय आते थे गाँव में जाते थे, फिर गाँव में जब वह बनते थे तो फिर अपनों के बीच में यह लोग बांटने का काम करते थे। जो इनके समर्थक होते थे उनको यह शौचालय बांटने का काम करते थे। आवास आते थे यह अपने समर्थकों को आवास बांटने का काम करते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि अपनों के साथ अपनों के विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब बिजली की आपूर्ति होती थी तो उसमें भी भेद-भाव होता था। केवल कन्नौज, इटावा, सैफई, मैनपुरी को 24 घण्टे बिजली देने का काम करते थे। आज हमारे प्रदेश में हर नगरीय क्षेत्र को 24 घण्टे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज काशी के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी हैं। आज काशी को 24 घण्टे बिजली मिल रही है तो हमारे कानपुर को भी 24 घण्टे बिजली देने का काम यह सरकार कर रही है। गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं अगर वहाँ 24 घण्टे बिजली मिल रही है तो आज गाजियाबाद को भी 24 घण्टे बिजली देने का काम यह सरकार कर रही है। यह अन्तर है। मैंने नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष का विचार सुना। इस पूरे बजट के सत्र में जातिगत जनगणना की बहुत चर्चायें हम लोगों ने सुनीं। मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूँ। मैं केवल दो पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की बोलना चाहता हूँ। मैं अपने नेता सदन के लिए बोलना चाहता हूँ। पाते हैं सम्मान तपोबल से भू-तल पर सूर का मतलब वीर बहादुर। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोलना चाहता हूँ पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर। और नेता प्रतिपक्ष के लिए कहना चाहता हूँ कि जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर । बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजें थपथपायी गयीं)

***श्री आशु मलिक-**

मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नगर विकास विभाग ने वर्ष 2023-24 हेतु परिव्यय को चुकाने के लिए जो मांग की है उस राशि को घटाकर एक रुपया करने की मांग करता हूँ। उद्देश्य विभागीय नीतियों की आलोचना करना एवं सुझाव देना है। जो बजट वर्ष 2022-23 का सदन में पिछले वर्ष प्रस्तुत हुआ था, वह आज तक पूरा खर्च नहीं हो पाया है। बजट नहीं खर्च करने के कारणों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को दण्डित किये जाने पर विचार होना चाहिए। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों की बंदरबॉट हो रही है। नगर में कहीं भी स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है। मान्यवर, सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर एन0जी0टी0 का खुला उल्लघंन किया गया है। वहां पर व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। धूल एवं मिट्टी के कारण तरह-तरह की दमा जैसी बीमारियों से वहां के दुकानदार ग्रसित हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों के हाल बेहाल हैं, उनकी स्थिति बद से बदत्तर होती जा रही है। अल्पविकसित और मलिन बस्तियों का कोई भी पुरसाहाल नहीं है। डूडा के कार्य भी बहुत सन्तोष देने वाले नहीं है। शहरी गरीबों को जो वास्तव में पात्रता की परिधि में हैं, उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाइयां हो रही हैं। शहरीकरण के कारण नगरीय क्षेत्रों में आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है। शहरी गरीबों को सस्ते मूल्य पर आवास दिलाने की आवश्यकता है, उन्हें प्लाट आसान मासिक किस्तों पर देने का प्राविधान होना चाहिए। नगरों की सफाई और मार्ग प्रकाश की व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। मुख्य मार्ग की सड़कें और गलियां बदहाल हैं, जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। बरसात के दिनों में जलभराव से लोग त्रस्त रहते हैं। सरकार की बेसहारा पशु आश्रय जैसी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। नगरों में आवारा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने सदन में बताया कि हमने इतने नये नगर निकाय बनाये हैं, नगर निकायों को विस्तारित किया है, किन्तु इस बात की चिन्ता कौन करेगा कि पहले जिन गांवों को नगर निकायों में शामिल किया गया था, वहां के नागरिकों को जो अनुमन्य सुविधाएं हैं, जो उन्हें दिया जाना चाहिए था, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इससे वंचित क्यों रखा गया है। उन्हें उनका हक कब मिलेगा ? मेरी विधान सभा क्षेत्रमें 32 गांव हैं जिनके लिए मैं कई बार इस सदन में अलग-अलग नियमों के तहत प्रश्न भी लगा चुका हूँ, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार द्वारा विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया। वर्ष 2000 में भी कई गांवों को नगर में शामिल किया गया था पहले जहां ग्राम पंचायतें भली-भांति काम कर रही थीं, उनका अस्तित्व मिटा दिया गया। खेद का विषय है कि नव विस्तारित सीमा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लोग इस समय न घर के हैं, न घाट के। ग्रामीण के रूप में मिलनी वाली सुविधाएं छीन ली गयीं और शहरों वाली सुविधाएं दे नहीं रहे हैं। यह सभी लोग गृह कर एवं सीवर कर दे रहें हैं किन्तु इन्हें जिन नगरीय सुविधाओं की दरकार है, उन पर सरकार का ध्यान नहीं है। जनपद सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत 32 ग्राम पंचायतों को नगर निगम में सम्मिलित किया गया। मानकमऊ एकता कालोनी, दानिश कालोनी, इनाम कालोनी, हबीबगढ़, काजीपुरा, रसूलपुर सहित...

श्री आशु मलिक-

अन्य कॉलोनियों को नगर निगम द्वारा ग्राम पंचायत का आस्तित्व समाप्त करके नगर निगम में सम्मिलित कर दिया गया है किन्तु वे विकास की धारा से कटे हुए हैं। ये 32 गांव और कॉलोनी जहां नालों में गंदगी होने के कारण लोग गम्भीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं।पानी की निकासी और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। जांच करायी जाए तो हेपेटाइटिस-सी जैसी गम्भीर समस्या से पीड़ित की संख्या यहां मिल जाएगी। इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ग्राम शैड्यूल के अनुसार मिल रही है, अलग से फीडर बनाने का बहाना बनाया जाता है। मान्यवर, हाकिमपुर में बिजली घर है, उसके पास के जिन गांवों को शहरी क्षेत्र से जोड़ा गया वहां के लोगों को हाकिमपुर बिजली घर से आपूर्ति की जा सकती है किन्तु...

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, पांच मिनट हो गये हैं, आधे मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री आशु मालिक-

सड़कें नहीं बनी हैं, थोड़ी सी बरसात होने पर जलभराव हो जाता है। मान्यवर, विकास कार्य को लेकर भेद-भाव नहीं होना चाहिए। एक तरफ सबका साथ,सबका विकास की बात करते है, दूसरी तरफ दलित और अल्पसंख्यक की आबादी अधिक होने के कारण सहारनपुर के साथ भेद-भाव हो रहा है। मान्यवर, नगर विकास की जो मूल अवधारणा है उस पर काम होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आवास के बिना हम शहर को शहर कैसे कहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

जी, थैंक्यू।

श्री आशु मलिक-

मैं मांग करता हूं कि सहारनपुर नगर क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्राम पंचायतों एवं कॉलोनियों में समस्त नगरीय सुविधाएं तत्काल दी जाएं। मान्यवर, मैं अपनी इन्हीं बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए नगर विकास विभाग की धनराशि पर कटौती करने की अपनी मांग पर बल देता हूं।

श्री राम रतन कुशवाहा-

महोदया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, तीन दिन से अपनी बात कहने के लिए सदन में उपस्थित था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। उसके लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं सबसे पहले नगर विकास मंत्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत बन रहे हैं, उसी तरह से 200 नगर पालिका परिषद् और 500 हमारी नगर पंचायतें सबमें विकास का काम चल रहा है। मैं जब शुरू में वर्ष 2017 में चुनाव जीतकर आया था तो प्रबोधन के समय मुझे अपोजिशन के लोगों से बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन सदन में आते ही न जाने क्या हो जाता है कि उस तरफ बैठते ही, हां की भाषा न में निकलने लगती है। सब कुछ सरकार अच्छा करती है लेकिन हमें तो न करना है कि सरकार ठीक नहीं कर रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि नगर विकास के माध्यम से साफ पानी, प्रकाश की व्यवस्था, सड़क, सीवर एवं सफाई, कूड़ा हटाने आदि की व्यवस्था निरन्तर ठीक ढंग से हो रही है और आज ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग नगर की ओर भाग रहे थे उस ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। मैं बुंदेलखण्ड के अन्तिम छोर पर रहने वाले जिले ललितपुर की सदर सीट से विधायक हूं और दूसरी बार जनता ने मुझसे जन-सेवा कराते हुए एक लाख सात हजार से अधिक वोटों से जीताकर इस सदन में भेजने का काम किया है और आज प्रदेश में टाप 10 पर जो विधायक हैं उनमें मैं 8वें नंबर पर आता हूं, इसलिए मैं इस सदन को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इतने अधिक मतों से भेजकर अपनी सेवा करने का मुझे फिर से मौका दिया है। एक शेर के साथ अपनी बात और कहना चाहूंगा

कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं,
मुश्किल हैं बागवां में, अब तक कई कांटें पुराने हैं।

मैं इसी के साथ सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं आदरणीय वित्त मंत्री श्री खन्ना जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बुंदेलखण्ड की पावन धरती को निखारने हेतु विशेष योजना के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की है। बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ डिफेंस कॉरीडोर परियोजना हेतु साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और साथ ही बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे से झांसी के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे की घोषणा इस बजट में की गयी है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास से बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के किनारे 2 औद्योगिक विकास संकुल भी बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

(इस समय 08 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बुन्देलखण्ड में निराश्रित गो-वंश अन्ना पशुओं के लिए नगर विकास की ओर से कान्हा गौ-आश्रय स्थल बनाये जाने की व्यवस्था प्रत्येक जिले की प्रत्येक नगर पालिका में हमारी सरकार द्वारा की गयी है। पर्यटन के क्षेत्र में भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में करकरावल का जल प्रपात जो हमारे सहरिया आदिवासी, अनुसूचित जनजाति लोगों का तीर्थ स्थान है। जैसे हमारे

सनातन धर्म को मानने वाले लोग गंगा में अस्थियाँ विसर्जन करने जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे सहरिया जनजाति के लोग इस करकरावल जल प्रपात में जा करके अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करने का काम करते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए भी यह सरकार वचनबद्ध है और किसान सम्मान निधि की योजना में वर्ष 2022-23 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजने का काम किया है। हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, दोनों के माध्यम से यह प्रदेश विकास के निरन्तर नए आयाम रच रहा है। मान्यवर, इस समय मैं पूरी एशिया में कह सकता हूँ कि सर्वाधिक बाँधों का निर्माण ललितपुर जिले में है। यहाँ पर सिंचाई मंत्री जी भी मौजूद हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि पानी के लिए जैसे केन और बेतवा नदी का लिंक हुआ है, ठीक उसी तरह हमारे बाँधों को एक दूसरे से आपस में जोड़ने का प्रबन्ध कर देंगे तो निश्चित रूप में हमारे जिले में कभी पानी की समस्या नहीं होगी। मान्यवर, मैं जिस कार्य क्षेत्र से आता हूँ, सरकार ने वहाँ की निराश्रित विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए कॉर्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया है। अधिष्ठाता जी, अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि

''कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मजधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर भी दिखा देंगे सबको,
कि इन हालातों में भी आता है, दरिया करना पार हमें।''

श्री अध्यक्ष-

पाण्डेय जी, कल बोलिएगा, कल तो आपकी रुचि के डिपार्टमेण्ट हैं, कृषि है, जल शक्ति है। आज नगर विकास पर आप क्या बोलेंगे ? फिर भी पाण्डेय जी बोलना चाहेंगे तो मैं उनको मना नहीं करूँगा।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बहुत ज्यादा भाषण न करके अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपका नगर पंचायत बनाने का जो मानक है, इसके मानक क्या हैं ? कल तो आपने उसमें देखा था लेकिन हमारे यहाँ जो इटवा और बिस्कोहर 02 नगर पंचायतें बनायी हैं, मान्यवर, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि मुख्यालय के अगल-बगल के गाँव छोड़कर 09 कि0 मी0 आगे जा करके उन गाँवों को उसमें जोड़ दिया जाए और चलिए तो एक गाँव यहाँ है, फिर दो गाँव छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद तीसरा गाँव ले लिया जाए, पीछे के गाँव छोड़ दिए जायें। इधर बिस्कोहर की हालत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यही है। अब हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन इसका मुख्य कारण यह रहा है कि ऐसा सोच कर नहीं बनाना चाहिए। जिन गाँवों में अल्पसंख्यक आबादी है, उसको तो आपने छोड़ दिया और दूर के 10 कि0मी0 गाँव को, दूसरी आबादी को उससे जोड़ दिया। नगर पंचायत इतनी लम्बी हो गयी है कि आपके लिए भी कठिन है। आपने 70-70 व्यक्ति एक नगर पंचायत में सफाई के लिए रखा है, कोई एक गाँव में जाता नहीं है, न गाँव का कोई काम होता है, प्रधानी भी चली गयी और नगर पंचायत से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपने इनको जोड़ा है तो बीच के गाँवों को भी जोड़ लीजिए। अब इटवा से बिस्कोहर 16 कि0 मी0 है, 16 कि0 मी0 सड़क पर बना हुआ है नगर पंचायत और एक गाँव दोनों गाँवों के बीच में है, उस गाँव को उसमें नहीं जोड़ा गया है। उसका एक कम्पैक्ट एरिया होना चाहिए। मैंने इसके बारे में पत्र भी लिखा, नक्शा बनाकर भी दिया, पिछली सरकार में भी दिया, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाया। मेरा इतना आपसे कहना है आप इसको दिखवा लें, आप तो हमारे प्रभारी मंत्री भी है आप दिखवा लीजिए और जो गांव उसमें जोड़ने लायक अवशेष हैं उसको उसमें जुड़वा लीजिए जिससे वह कम्पैक्ट एरिया हो जाए। अगर इस नजरिए से आप बनाएंगे कि हम इसमें चुनाव जीतेंगे तब इस गांव को जोड़ेंगे अगर हम नहीं चुनाव जीतेंगे तो इस गांव को नहीं जोड़ेंगे तो आपके बनाने का क्या मतलब है, कोई औचित्य नहीं है। यह नगर पंचायत है और यह फिर गांव है, फिर यह नगर पंचायत है, फिर इधर नगर पंचायत है यही आपसे एक अनुरोध था मैं भाषण नहीं दे रहा, क्योंकि मैं इस पर बहुत बार कटमोशन कर चुका, इस सदन में लंबे समय से कि नगर विकास पर कोई विभाग बचा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इस पर संज्ञान ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि की मांग घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अर्न्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20586,54,10,000 रुपये (बीस हजार पाँच सौ छियासी करोड़ चौवन लाख दस हजार रुपए) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अर्न्तगत सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि की मांग में से घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25347,10,57000 रुपये (पच्चीस हजार तीन सौ सैंतालीस करोड़ दस लाख सत्तावन हजार रुपए) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

अब हम याचिकाएँ लेंगे।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल (अनुपस्थित), श्रीमती आशा मौर्या उपस्थित (उपस्थित), श्रीमती इन्द्राणी देवी (अनुपस्थित), श्रीमती गीता शास्त्री (उपस्थित), श्रीमती सरिता भदौरिया (उपस्थित), श्रीमती सरोज सोनकर (उपस्थित), श्रीमती सैय्यदा खातून (उपस्थित), इं0 बृजेश कठेरिया (उपस्थित), श्री सचिन यादव (उपस्थित), डा0 एम0पी0आर्य (उपस्थित), डा0 डी0सी0 वर्मा (उपस्थित), डा0 मनोज कुमार प्रजापति (उपस्थित), डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा (अनुपस्थित), डा0 रागिनी (उपस्थित), श्री अमित सिंह चौहान (उपस्थित), श्री अजय सिंह (उपस्थित), श्री अनिल प्रधान (अनुपस्थित), श्री अभय सिंह (उपस्थित), श्री अरमान खान (उपस्थित), श्री कविन्द्र चौधरी (उपस्थित), श्री कैलाश नाथ शुक्ल (उपस्थित), श्री गणेश चौहान (उपस्थित), श्री गुरू प्रसाद मौर्या (उपस्थित), श्री गुलाम मोहम्मद (अनुपस्थित), श्री गौरव कुमार रावत (उपस्थित), श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) (उपस्थित), श्री चन्द्रपाल सिंह (अनुपस्थित), श्री बाबूलाल (उपस्थित), श्री जय प्रकाश अंचल (उपस्थित), श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद (उपस्थित), श्री जवाहर लाल राजपूत (उपस्थित), श्री जियाउर्रहमान (उपस्थित) एवं श्री जियाउद्दीन (उपस्थित) ।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर में विकास खण्ड चित्तौरा, ग्राम पंचायत बहादुर चक में गोविन्दापुर मोहरना सम्पर्क मार्ग से माफी ग्राम होकर बहादुर चक सम्पर्क मार्ग तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम कुमार चौधरी एवं अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ †

श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर के महमूदाबाद अन्तर्गत सी0एच0सी0 अस्पताल को 60 बेड का करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद सीतापुर के महमूदाबाद अन्तर्गत सेमरी सूत मिल के सामने से रमनगरा देवरिया होते हुए बिलौली तक लगभग 4.00 किमी0 मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रवेश प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के मोहल्ला-इंदौरा में स्थित पार्क एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन प्रसाद बारी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

4-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में सामूहिक वैवाहिक स्थल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिन्गा के ब्लाक हरिहरपुर अन्तर्गत ग्राम खरगौरा पक्की रोड से ग्राम भवनियापुर तक लम्बई लगभग 300 मी0 आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित दो याचिकाएँ †

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत लीलाधर उर्फ बरचनपुर गाँव के पश्चिम नाले पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

2-जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत मऊआइमा घीनपुर के मार्ग के किमी0 10 पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री निसार अली व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित चार याचिकाएँ†

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद इटावा, विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत यमुना नदी के घाट पर विद्युत शवदाह गृह निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चौहान एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

2-जनपद इटावा, विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत ग्राम लोहिया खुर्द, पोस्ट खेड़ाहेलू, विकास खण्ड बसरेहर में प्राइमरी स्कूल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रवीर चौहान एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

3-जनपद इटावा, विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत इकदिल को नवीन ब्लाक विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 सौरभ दीक्षित एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

4-जनपद इटावा, विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत एन0एच0-2 हाई-वे से ग्राम कांकरपुर होते हुए धर्मपुरा पुल तक भोगनीपुर नहर की पटरी रोड का (मिसिंग लिंक) नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश राजपूत एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा सुजौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 20 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ †

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र 306, डुमरियागंज के ग्राम विथरियां में राप्ती नदी के तट पर साइफन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मलिक मो0 असजद, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

2-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियागंज के ग्राम बरगदवा से सिसई कला होते हुए कोडरांव नानकार तक नाले के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अब्दुल सलाम, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियागंज के ग्राम लटिया में सरयू नहर पर बने साइफन पर नाले के निर्माण के सम्बन्ध में श्री फैजान हुसैन, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित दो याचिकाएँ †

इं0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सामान में रैचन्दा से विक्रमपुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका तथा

2-जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र-109, किशनी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बड़ेपुर के ग्राम पुवायं से सौरिख तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कठेरिया एवं अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के कस्बा पाढम मौहल्ला बस्ती में डाकखाने से लेकर कृष्ण मुरारी जी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (ल0 लगभग 90 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सलमान शेख व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के कस्बा पाढम मौहल्ला बस्ती में मधू प्रकाश राठौर जी के घर से देव कुमार माहेश्वरी जी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (ल0 लगभग 70 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के कस्बा पाढम में सलमान शेख के घर से झन्डा मैदान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (ल0 लगभग 200 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राशिद कुरैसी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम न0 गुलाबी में भुजवीर जी के घर से हरविलास जी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (ल0 लगभग

---

† छापी नहीं गयीं।

120 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम न0 गुलाबी में रामदत्त जी के घर से कुमरपाल लोधी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण (ल0 लगभग 150 मी0) करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डा0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

डा0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की निम्मलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत नवाबगंज शहरी भाग के बहोर नगला होते हुए देशनगर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम सुतईया कला से खाता नवदिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवदत्त व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम पैगा होते हुए घाटमपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली के ब्लाक नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम अमीनगर में नदी कटान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली के ब्लाक भड़पुरा के अन्तर्गत ग्राम बिजासन से आनन्दपुर माधौपुर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेन्द्र गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बकैनिया चम्पतपुर से शोभादास बाबा की मढ़ी होते हुए सहकारी समिति औंध तक नहर के किनारे होते हुए मिट्टी एवं खड़न्जे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमेन्द्र सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिम के मोहल्ला ठाकुरद्वारा में श्री रामासरे की मढ़ी के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा शीशगढ़ रोड से दिनरा मार्ग का डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली, ब्लाक फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम पंचायत उदयपुर बन्नोजान के ग्राम खतौला हुलास कुंवर में ब्रहमदेव महाराज से कौशल पाण्डेय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल पाण्डेय एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम फरीदापुर से नारा तक मिट्टी खड़न्जा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

डा0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद-हमीरपुर के वि0ख0-सुमेरपुर के ग्राम बदनपुर में राम कृपाल प्रजापति के दरवाजे से रहुनिया तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अजय साहू एवं अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

2-जनपद-हमीरपुर के वि0ख0-सुमेरपुर के ग्राम-धनपुरा में राम सजीवन के दरवाजे से होरी माता स्थान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री जयराम प्रजापति एवं अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

3-जनपद-हमीरपुर के वि0ख0-मौदहा के ग्राम-छिरका में श्री देवीदीन के दरवाजे से बड़ेदेव बाबा के स्थान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मुकेश प्रजापति एवं अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

4-जनपद-हमीरपुर के वि0ख0-सुमेरपुर के ग्राम-पौथिया में कुण्डौरा सम्पर्क मार्ग से योगिक आश्रम तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री आशीष सचान एवं अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद-हमीरपुर के वि0ख0-सुमेरपुर के ग्राम-सिकरी गाँव में बड़कू धुरिया के दरवाजे से रामकिशुन पाल के दरवाजे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप दीक्षित एवं अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)†

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम वासदेवपुर में जोगे के घर से केशव दवे मंदिर से जाते हुए भूदेव सिंह के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपति लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किन्दरपुर में सरनाम सिंह के घर से गुड्डू के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनबाज व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऊवटी में कालू खां के घर से मोती के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रूपश्री व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ऊवटी में सलीम खां के घर से तुर्रावा खां के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलीम खां व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम किशनदासपुरा में मुरारी लाल के घर से रघुवीर सिंह की दुकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में मोहल्ला-नन्दलाल का पूरा मोहल्ले से एन0एच0-31 के बगल से होते हुए मरी माई पुल आर0सी0 ड्रेन तक जल निकासी नाले के निर्माण के सम्बन्ध में श्री महमूद आलम, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम-बनकट में जमुनीपुर मार्ग पिच से शीतला प्रसाद यादव इण्टर कालेज बनकट, काटी तक पिच रोड के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजकुमार, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में सृजन महाविद्यालय गेट से चौहान बस्ती होते हुए चितांव तक पिच रोड के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामबली सरोज, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम-चितांव में इण्टर कालेज के बगल से रामचन्दर यादव के घर तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल प्रधान, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के न्याय पंचायत कौरहा में साधन सहकारी समिति के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री अखिलेश कुमार, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयी :-

1-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल, विकास खण्ड मसौधा के ग्राम सभा कोटसराय में गन्ना विकास विभाग से 18 वर्ष पूर्व बनी कोटसराय से मांझाकला सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल, विकास खण्ड मसौधा की सम्पर्क मार्ग दर्शन नगर भरतकुण्ड मार्ग से रैथुआ तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल की ब्लाक सोहावल अन्तर्गत ग्राम मंगलसी में श्री देवीदीन मौर्या के घर से इब्राहिमपुर देवली तक सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रदीप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल, विकास खण्ड मसौधा के ग्राम हरीपुर नहर से हरीपुर पश्चिम सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

5-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के ग्राम महोली को जोड़ने वाली गन्ना विकास विभाग अयोध्या से 15 वर्ष पूर्व बनी सैदपुर से हाजीपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर बहादुर तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के ब्लाक परसपुर में स्थित मनिहारीघाट पर पक्का पुल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2-जनपद गोण्डा के तहसील मुख्यालय करनैलगंज में बस स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज में स्थित मनिहारी घाट पर पक्का पुल की स्थापना के सम्बन्ध में श्री सन्दीप कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज में स्थापित विद्युत सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष सोनी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज में स्थित रामलीला मैदान का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया लाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थित में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुई :-

1-जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र सदर के वि0ख0 कर्वी के ग्राम पंचायत बारामाफी में कल्लू गुप्ता के पुलिया से प्रजापति बस्ती मेन रोड तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती उर्मिला देवी एवं अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कादरगंज में धर्मपाल यादव के घर से गढ़ीघाट सम्पर्क मार्ग (लगभग 600 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मकरीपुर से बारा तक तथा गौतम पुरवा से गढीघाट तक सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भगनपुर, मजरा-ठर्री में श्मशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र पाल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

5-जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बारा से अलमा पुरवा (लम्बाई लगभग 02 कि0 मी0) तक रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार (पूर्व प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ †

श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के ब्लाक काकोरी, सकरा मार्ग गुरूदीन खेड़ा पुलिया से चिलौली गांव की पुलिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

2-जनपद लखनऊ के ब्लाक काकोरी, बहरु दसदोऊ मोड़ सम्पर्क मार्ग से सराय अलीपुर बसरैला रोड ग्राम तिलसुवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत मॉडल सिटी कालोनी से भूहर क्रासिंग नाला तक पक्का नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यकान्त उर्फ गुड्डू एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत न्यू हैदरगंज तृतीय के ग्राम मुन्नू खेड़ा में सीवर लाइन तथा जल निकासी हेतु पक्का नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत मोहल्ला शेखपुर निकट बड़ी नीम सआदतगंज में बोल्टू के मकान से भिखारी दादा के घर तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फिरोज जहां एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत लालाबाग, ग्राम भूहर, ग्रीन-वे-पब्लिक स्कूल के पास आवासीय आबादी के बीच बने शमशान स्थल को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री आँचल गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र-171, लखनऊ (पश्चिमी) के न्यू हैदरगंज वार्ड-तृतीय के अन्तर्गत मोहल्ला-गोविन्दनगर, नरपतखेड़ा, पारा में श्री आनन्द बाजपेई के मकान से श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मकान न0-545/660 एन0के0 तक लगभग-100 मी0 सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश कुमार सिंह निवासी, जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित चार याचिकाएँ †

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज, विकास खण्ड गौर, ग्राम पंचायत शम्भूपुर महाराजगंज बेलघाट मार्ग से बैसोलिया पिच मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण (दूरी लगभग 1200 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कनौजिया, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308,कप्तानगंज, विकास खण्ड दुबौलिया कप्तानगंज महाराजगंज दुबौलिया मार्ग से नागवीर होते हुए दुबौलिया तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण (दूरी लगभग 2.00 कि0 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू वर्मा, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-308, कप्तानगंज, विकास खण्ड दुबौलिया कप्तानगंज पेंदा पंडूल घाट मार्ग से सिकटिहवा गांव तक सम्पर्क मार्ग (लगभग 1.50 कि0 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 308-कप्तानगंज, विकास खण्ड दुबौलिया कप्तानगंज पंडूल घाट बसन्तपुर बंधे से भिखरिया गांव तक सम्पर्क मार्ग (लगभग 1.00 कि0 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ †

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड हरैया सतघरवा में स्थित गिरगिटही बांध एवं उससे निकलने वाली छोटी लिंक नहर की सिल्ट सफाई एवं बांध मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर स्थित ग्राम महादेव जमुनी के ग्राम नेवासपुर जैसिंहडीह, रमनपुरवा में लगभग 25 पोल बिजली विभाग द्वारा न लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गेश यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर स्थित ग्राम बड़गौ में बिन्दूलाल मिश्रा के मुहल्ले में बिजली पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दू लाल मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री गणेश चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ †

श्री गणेश चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सन्तकबीर नगर के ब्लाक-नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम हरिहरपुर से सुबखरी बेल्डुहा, मेहनिया होते हुये खजुवा तक पिच मार्ग तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका,

2-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक-नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम कुसहवा हरदी पिच मार्ग तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरगर की याचिका,

3-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक-नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम मुडियारी से भिटिनी बन्धे तक पिच मार्ग तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तबीरनगर की याचिका तथा

4-जनपद सन्तकबीरनगर के ब्लाक-नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम हरपुर से रामुपुर चौराहे पिच मार्ग तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधाकर एवं अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका।

श्री गुरू प्रसाद मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री गुरू प्रसाद मौर्या, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के सोरांव तहसील के ग्राम गदियानी मजरा धनपारी का पूरा में इण्टरलॉकिंग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमृत लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के होलागढ़ विकास खण्ड के ग्राम गारवपुर में इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पा देवी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड श्रृंगवेरपुर के ग्राम उल्दा में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंजू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के होलागढ़ विकास खण्ड के ग्राम मजरा नदवक के पूरा पटेल बस्ती में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बुन्दल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के फाफामऊ विधान सभा क्षेत्र के गद्दोपुर केशव मार्ग, न्यू शान्तीपुरम कालोनी, फाफामऊ में पक्की सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुई :-

1-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र-सिवाल खास, विकास खण्ड-जानी के ग्राम पंचायत रावा में जहारवीर की माडी से ग्राम रावा की मुख्य सड़क तक लम्बाई लगभग 1 कि0 मी0 मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास की नगर पंचायत हर्रा में गऊशाला रोड से शमशेर राणा की ट्यूबवेल से होते हुए सरधना बरसाना मार्ग तक लगभग 1 कि0 मी0 मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर राणा एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

3-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास, विकास खण्ड रोहता की ग्राम पंचायत-रोहता में मेन रास्ते पर तालाब की सफाई/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख में ग्राम मेहन्दीपुर में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिमोहन सिंह वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

2-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक सिद्धौर में ग्राम जमलापुर में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम आधार एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

3-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख में ग्राम आलमपुर गयासपुर में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

4-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख में ग्राम मक्का का पुरवा में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका तथा

5-जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक सिद्धौर में ग्राम हाजीपुर में सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल एवं अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत ग्राम हथेरी तांबा को जाने वाला रपटा पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के उरई वि0स0 क्षेत्र में जालौन नगर में मोहल्ला हृदयशाह स्थित बाबरी को प्राचीन धरोहर व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुनीत मित्तल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के उरई नगर में डी0वी0सी0 डिग्री कालेज के पास चौराहे का सौन्दर्यीकरण एवं स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद जालौन के उरई नगर में रिनिया रेलवे फाटक से राम राजा पैलेस तक दोनों तरफ वृक्षारोपड़ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के उरई नगर में रिनिया रेलवे फाटक के पास पं0 अटल बिहारी बाजपेयी प्रवेश द्वार पर भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज पालीवाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई अंतर्गत ग्राम लैदरखेड़ा से ग्राम सतोहा तक लगभग 2.5 कि0 मी0 मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषिपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अंतर्गत राजघाट-नरौरा मार्ग पर हजारीलाल के खेत से पांच न0 बांध तक 1 कि0 मी0 मार्ग खड़न्जा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अंतर्गत गांव घुसराना गैल से गांव मऊ तक 5 कि0 मी0 मार्ग डामरीकरण द्वारा निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कलियान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर अंतर्गत ग्राम कुसहा फतेहाबाद बांधौर मार्ग से बम्बे की पटरी तुलसी गढ़ी दानपुर लिंक मार्ग तक 2 कि0 मी0 खड़न्जा या इंटरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के ब्लाक दानपुर अंतर्गत धर्मपुर रोड से बम्बे की पटरी गांव उदयपुर तक 700 मी0 मार्ग को खड़न्जा या इंटरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा के कीठम अछनेरा मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कुमर जीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा में फतेहपुर सीकरी राजवाहा से निकलने वाली मलिकपुर माइनर के आखिरी हिस्सा को नाला (डब्लू0डी0डी0) तक विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा किरावली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार (100 बेड) किये जाने के सम्बन्ध में श्री तनुज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा में मार्डन राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री अरब सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के ब्लाक-अछनेरा ग्राम साधन के मुख्य मार्ग से आबादी भाग में नगला साधन तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजीव व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत दया छपरा ढाला एन0एच0-31 से बुद्धनचक रिंग बांध तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभाशंकर वर्मा, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत मून छपरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से श्रीनगर दल छपरा स्टेशन मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशि भूषण यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत रेवती-दत्तहां मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर चौधरी, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत मून छपरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से श्रीनगर दल छपरा स्टेशन मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मृत्युंजय उपाध्याय, निवासी जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत रेवती-दत्तहां मार्ग से भिसियां पिच मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा, तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत विकास खण्ड-मरौरी, ग्राम पंडरी ठाकुरद्वारा मंदिर से मेन चौराहा शिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

2-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा, तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत विकास खण्ड-मरौरी रतनपुरी में भूमि सेन से शमशान घाट तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हेतराम एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा, तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत विकास खण्ड-मरौरी, ग्राम गिधौर से भिन्डारा बाजार तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डालचन्द्र वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा, तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत विकास खण्ड-मरौरी, रमपुरा टाह में श्याम बिहारी शर्मा के घर से ओम प्रकाश के खेत तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलसुख राम एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

5-जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र-128, बरखेड़ा, तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत विकास खण्ड-मरौरी ग्राम हुलकरी ढकिया से बहरुआ तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित दो व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ †

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद झांसी के बड़वार झील से बड़वार नहर के अलावा एक और छोटी नहर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मूरत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद झांसी के गुरसराय नगर से बेंदा/खिरिया घाट (मोंठ) सड़क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रतीक जैन व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के ब्लाक पुरवा में ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित कराये जाने के संबंध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव, ब्लाक-पुरवा, ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर में माता मण्डफी के मंदिर से मंशाखेड़ा के पास पुरवा रजबहा के पुल तक पक्की सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त कुमार लोधी एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद उन्नाव, ब्लाक-पुरवा, ग्राम पंचायत-त्रिपुरारपुर में माता मण्डफी के मंदिर का जीर्णोद्धार तथा मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ †

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुरादाबाद, विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के मूडापाण्डे में पशु चिकित्सालय का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री मो0 रफी एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद, विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के मूडापाण्डे में दौलरा से वीरपुर बरीहार मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री नाजिम एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

3-जनपद मुरादाबाद, विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी के मूडापाण्डे में दो पी0एच0सी0 केन्द्रों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन लगाये जाने के संबंध में श्री मुमताज एवं अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दो याचिकाएँ †

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम सिवानकला में मण्डी के लिये अधिग्रहीत भूमि पर मण्डी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारीक अजीज व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के खरीद-दरौली में पक्के पुल के निर्माण पर धन देकर कार्य प्रारम्भ कराये जाने एवं घाघरा नदी में हो रहे कटान जो ग्राम खरीद की तरफ तेजी से हो रहा है, यहां स्वीकृत पिलरों की सं0 5 से बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

याचिकाओं का उपस्थापन (क्रमागत)

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह (उपस्थित), श्री रविन्द्र पाल सिंह (उपस्थित), श्री त्रिभुवन दत्त (उपस्थित), श्री देवेन्द्र सिंह लोधी (अनुपस्थित), श्री पल्टूराम (उपस्थित), श्री प्रदीप कुमार चौधरी (उपस्थित), श्री प्रसन्न कुमार (उपस्थित), श्री प्रेम नारायण पाण्डेय (अनुपस्थित), श्री बम्बा लाल (अनुपस्थित), श्री बाबूराम (उपस्थित), श्री बृजेश कुमार (उपस्थित), श्री भूपेश चौबे (उपस्थित), श्री महबूब अली (अनुपस्थित), श्री महेन्द्र नाथ यादव (उपस्थित), श्री मूलचंद सिंह (उपस्थित), श्री मौ0 फहीम इरफान (उपस्थित), श्री रमेश चन्द्र मिश्र (उपस्थित), श्री रमेश जायसवाल (उपस्थित), श्री रवि शर्मा (अनुपस्थित), श्री रविदास मेहरोत्रा (उपस्थित), श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (उपस्थित), श्री राज प्रसाद उपाध्याय (उपस्थित), श्री राममणि कोल (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (उपस्थित), श्री राजेश चौधरी (उपस्थित), श्री राम अचल राजभर, (उपस्थित), श्री राम अवतार सिंह (उपस्थित), श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी (अनुपस्थित), श्री लकी यादव (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मीराज सिंह (उपस्थित), श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह (उपस्थित), श्री विजयपाल (आढ़ती) (उपस्थित), श्री विनोद चतुर्वेदी (उपस्थित), श्री विपुल दुबे (अनुपस्थित), श्री शशांक त्रिवेदी (उपस्थित), श्री श्रीकान्त कटियार (उपस्थित), श्री संग्राम सिंह (उपस्थित), श्री सन्दीप सिंह (उपस्थित), श्री समरपाल सिंह (अनुपस्थित), श्री सुरेन्द्र मैथानी (अनुपस्थित), श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया (उपस्थित), श्री रामरतन कुशवाहा (उपस्थित) एवं श्रीमती विजमा यादव (उपस्थित)।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ मा0 सदस्य जो सदन में अनुपस्थित होते हैं, वे अगले दिन आकर मुझसे कहते हैं कि हमारी हाजिरी आपको लगा देनी चाहिए तो मैं कहता हूँ कि उन मा0 सदस्यों का क्या कसूर है, जो अन्त तक बैठे रहते हैं।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित दो याचिकाएँ †

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद महाराजगंज, विधान सभा क्षेत्र पनियरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनियरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद महाराजगंज, विधान सभा क्षेत्र पनियरा में चौरी मौलागंज हसखौरी सड़क का चौड़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छर्रा में छठवीं नई तहसील सृजित कराने के सम्बन्ध में श्री लालू महाजन व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

2-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छर्रा के कस्बा अकराबाद में जर्जर सरकारी बस स्टैण्ड का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री संजीव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

3-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड गंगीरी के ग्राम गंगीरी क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती गजमोतिन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका,

4-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका तथा

5-जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत नगर पंचायत कोड़ियागंज में काली नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के अन्तर्गत ग्राम केसरपुर से ग्राम हरदिहां जलालपुर तक शून्य से लेपन/पिच कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार, निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत आमादरवेसपुर शिवतारा मुख्य मार्ग पर ग्राम नसीरपुर में सुबई राम के खेत से अमरजीत गौतम के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर कुमार निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम विमावल में अजय कुमार गौतम एडवोकेट के घर से निरंकार मौर्य के घर तक नव निर्माण सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार गौतम एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के बिडहर नरियांव मुख्य मार्ग पर मंसूरगंज दुर्गूपुर होते हुए ग्राम रायपुर बेलवा डाडी में क्षत्रिय बस्ती तक अत्यन्त जर्जर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के जहांगीरगंज बाजार से नेवारी दुराजपुर व बड़पुर होते हुए रामबाग घाट तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणविजय यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम रवानी कटीली से हायतपुरा तक ल0 लगभग 2 किमी0 नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम तिबड़ा से लुधपुरा तक लम्बाई 1800 के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम बरहना में प्रेम सिंह के मकान से सौरभ के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना, कस्बा बुगरासी, मोहल्ला पड़ियावाला में देवेन्द्र सिंह के मकान से नानकचंद के मकान तक सी0सी0/नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम बुकलाना में बम्बे की पटरी से आबादी भाग में जवाहर इण्टर कालेज का नवनिर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत स्थित सुआँव नाला के सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर साईडीह/दुल्हापुर, बल्लीपुर के पास पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर स्थित मात्र एक महिला चिकित्सालय में बेड व वार्ड की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष पाठक एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

4-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में ग्राम सभा जिगना (तेदुई) में नवनिर्मित आई0टी0आई0 कालेज में पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

5-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत स्थित भुसैलवा नाला के सफाई/खोदाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश वर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के अन्तर्गत ग्राम गिनौरा शेख में मेन रोड से ज्ञानेन्द्र की दुकान होते हुए रोहताश के घर तक लगभग 100 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर में कर्मवीर सिरोही के घर से राजवीर के घर तक लगभग 100 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिरोही व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के अन्तर्गत ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग में जयपाल सिंह के घर से इन्द्रजीत के घर तक लगभग 100 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्यान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के अन्तर्गत ग्राम फतेहगढ़ी में रज्जू के घर से जयभगवान शर्मा के घर तक लगभग 100 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखलेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के अन्तर्गत ग्राम ज्ञान लोक कालोनी में संजय नाई के घर से सतेन्द्र फौजी के घर तक लगभग 200 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद शामली के वि0ख0 कांधला में माल्हीपुर राजवाहे की पटरी का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केसर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के वि0ख0 कांधला के ग्राम-जिडाना से कांधला होते हुए मेन रोड शमशान घाट तक 500 मी0 मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कयूम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के वि0ख0 शामली के मेरठ करनाल हाई-वे से ग्राम झाल जू0नि0 हाई स्कूल तक 1500 मी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सोमपाल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के वि0ख0 कांधला के ग्राम डांगरौल-आजादपुर-सुन्नामार्ग 1100 मी0 मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुधीर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

5-जनपद शामली के वि0ख0 शामली के मेरठ-करनाल हाई-वे पर लिसाढ़ किवाना मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री बिजेन्द्र मलिक व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चंदीपुर वि0खं0 तरबगंज में विद्युत आपूर्ति हेतु

† छापी नहीं गयीं।

33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यापगत हुई।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ †

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शेरपुर खुर्द में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधे लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत माँ सन्तोषी गैस एजेन्सी चितौली से मॉखी बिरसिंहपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलकी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेथीटिकुर के मजरा चकलवंशी में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगत बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री बाबूराम पासवान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद पीलीभीत, पूरनपुर के अन्तर्गत दुधिया हाल्ट से पश्चिम से पूर्व की ओर डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

2-जनपद पीलीभीत, पूरनपुर के अन्तर्गत ग्राम लाह से रघुवीर के घर से तिलकराम के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत, पूरनपुर के अन्तर्गत कुरैया हाल्ट के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत, पूरनपुर के अन्तर्गत ग्राम अभयपुर ज0 जगतपुर से ग्राम नौगवां तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश कुशवाहा एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद पीलीभीत, तहसील-कलीनगर के ग्राम जरा बुजर्ग में जसवन्त सिंह के घर से कप्तान सिंह के सेलर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयवन्त सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान, वि0ख0-नवाबगंज के अन्तर्गत लखनऊ-कानपुर हाई-वे पर ग्राम-जगदीशपुर की मुख्य सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ऋषि सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के वि0ख0-औरास के ग्राम-सीमऊ में 60 बीघा खाली पड़ी जमीन पर धान/चावल से बनने वाले उत्पाद हेतु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन मौर्या एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव निर्वाचन क्षेत्र-मोहान के ग्राम कटरा तरौना व अदौरा के बीच बेता नदी (बेता नाला) पर पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम मौर्य एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान, तहसील-हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम-अजमतगढ़ी रोड पर नहर की पुलिया एवं ग्राम-खड़वारी सादिकपुर की नाला का मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम जी तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

5-जनपद-उन्नाव के वि0ख0-नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम-मकूर में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री भूपेश चौबे, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सोनभद्र के ब्लाक कोन अन्तर्गत ग्राम पंचायत पीपरखड़ में लोगरां पाण्डू नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद सोनभद्र के ब्लाक कोन अन्तर्गत ग्राम पंचायत कचनरवा में पनडुब्बिया नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

3-जनपद सोनभद्र के ब्लाक नगवा अन्तर्गत ग्राम माची से नगवा गाँव के मार्ग पर थाने से पहले पचान नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेश खरवार एवं अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका,

4-जनपद सोनभद्र के ब्लाक कोन अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुड़वा में छपरहिया नाला पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महिपत गौड़ एवं अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका तथा

5-जनपद सोनभद्र के ब्लाक कोन अन्तर्गत ग्राम पंचायत गिधिया में बैगइया नाला पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिकन्दर जायसवाल एवं अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा विधान सभा क्षेत्र अमरोहा में डिडौली मन्दिर से चुबका बुढ़नपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर के ग्राम-मड़वानगर में मुकेश हरिजन के घर से काली मंदिर भटोलवा तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदारनाथ चौधरी निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती के अन्तर्गत वार्ड न0-18 मिल्लतनगर बेलवाडाडी के सलीम अहमद के मकान से रियाज अहमद, के मकान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलमान अहमद निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर के अन्तर्गत भूपालपुर में विनोद के घर से गंगा राम के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर के अन्तर्गत प्रहलाद कालोनी के जायसवाल आटा चक्की से कमला प्रसाद मिश्रा के घर से बाबूराम यादव के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक यादव निवासी, जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर के अन्तर्गत परसा जागिर सम्पर्क मार्ग से त्रिलोकी नाथ सिंह के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविंद यादव निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री मूलचंद्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ†

श्री मूलचंद्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन, तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत जगम्मनपुरा से उदोतपुरा होकर छोना मानपुरा मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन, तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत ऊमरी से छोना मानपुरा घूता होकर जगम्मनपुर बहादुरपुर रोड तक विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार गौर, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन तहसील कोंच के अन्तर्गत सद्पुरा से रेंढर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन, तहसील कोंच के अन्तर्गत कैलिया सलैया मार्ग से ऊंचा व्योना राजा होकर मऊ मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद झा निवासी जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन, तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत चाकी अमखेड़ा सरावन होकर मडौरा मार्ग की विशेष मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेंद्र सिंह, निवासी जनपद जालौन की याचिका।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित चार तथा कन्नौज से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम बिचौला ढूकी से ग्राम हाजीपुर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्की यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम देवरी में हनुमान मंदिर से दिनौरा तक सड़क (लगभग 1 किमी0) बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बहादुर, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम नरसरा से ग्राम स्योंडारा मार्ग तक सड़क (लगभग 1 किमी0) बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री डालचन्द यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम थांवला से ग्राम मनकुला-स्योंडारा मार्ग तक सड़क (लगभग 1 किमी0) बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रेहान पाशा, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

5-जनपद कन्नौज के वि0स0क्षेत्र तिर्वा के अन्तर्गत ग्राम-सखौली में तिर्वा कन्नौज मार्ग स्थित प्रसिद्ध हनुमान मन्दिर के पास पक्की नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश पुत्र शिवकुमार निवासी जनपद कन्नौज की याचिका।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बटाऊबीर-मई-लेदुका शेष भाग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के संबंध में श्री शनि एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में नवसृजित थाना तेजीबाजार के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलवीर गौड़ एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में क्षेत्राधिकारी आवास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील निगम एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में भीमपुर राजबाहा के नगर पंचायत बदलापुर क्षेत्र में पड़ने वाले भाग का पक्कीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयकुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में रामनगर व बाबूगंज विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज कुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित चार याचिकाएँ †

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा लौंदा में झारखण्डी के खेत व ट्यूबवेल के नाली से रमाशंकर कनौजिया के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा गुवास में मेन रोड से काली माता मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

3-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम पंचायत हसनपुर के ग्राम मछरिया में गंगा बिन्द के मकान से पप्पू हरिजन के मकान तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम डिहल एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका तथा

4-जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा अलीनगर वार्ड नं0-16 नहर के बाएं तरफ हरिजन बस्ती से छलका तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान एवं अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं :-

1-जनपद झांसी के महानगर झांसी के अन्तर्गत वार्ड सं0-31 में उन्नाव-बाला जी मार्ग, भानी देवी गोयल इण्टर कालेज के पीछे की आबादी के समीप स्थित कच्चे नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी के महानगर झांसी के अन्तर्गत वार्ड सं0-13, बूढ़ा मार्ग में आकाश गुप्ता के मकान से शुभम शाक्य के मकान तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी के महानगर झांसी के अन्तर्गत वार्ड सं0-9, पुष्पा कान्वेन्ट स्कूल के पीछे, हंसारी में नन्दू अहिरवार के मकान से राकेश कनौजिया के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीवन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के महानगर झांसी के अन्तर्गत वार्ड सं0-13, कसाई बाबा मोहल्ला में श्री मनोहर लाल कुशवाहा के मकान तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्जन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद झांसी के महानगर झांसी के अन्तर्गत वार्ड सं0-24, सिमराहा में प्राइमरी स्कूल के सामने से डा0 निरंजन के मकान से श्री अनिल यादव (फौजी) के मकान तक विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र राय व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ †

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नगर से नई बस्ती की ओर जाने वाला नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री शीबू रज्जा एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में फूलबाग चौराहे से नजरबाग होते हुए मछली मोहाल से लाटूश रोड तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेंद्र लोधी एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

3-जनपद लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में रानीगंज तिराहे से झंडेवाला चौराहा होते हुए सराय के फाटक तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री शरद यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत नगर पालिका भरथना में मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

2-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के ब्लाक महेवा में यमुना नदी के अन्दावा घाट पर पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री चरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

3-जनपद इटावा के ग्राम पंचायत कुसना के ग्राम नगला घासी बम्बा से नगलाबाग के मध्य से होते हुए कुसना-हथनौली मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोहन बाथम व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका,

4-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के ग्राम पंचायत खितौरा में रामबाबू के घर से ग्राम पं0 पिलखुना से होते हुए अलियापुरा-पिलखुना मार्ग तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री चन्द्र मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत भरथना ऊसराहार सम्पर्क मार्ग से ग्राम डबसरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय दिवाकर एवं अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के वि0ख0 दोस्तपुर में गोसैसिंहपुर से कौशल्यापुर जाने वाली रोड पर बना मझुई नदी पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजमणि कोल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री राजमणि कोल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के कोरांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माण्डा से बरौधा मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकू द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के कोरांव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा खजुरी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बैठने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में श्री अखण्ड प्रसाद पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत ग्राम सैम्या में इण्टरलॉकिंग सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रंगी लाल मिश्रा, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली, तहसील-रुधौली के अन्तर्गत डुमरी-मझौवा कला-2 का छूटी हुई कड़ी का अवशेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली, तहसील-भानपुर जनपद-बस्ती के कुड़ी-नकहा से गुलरिया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली, तहसील-भानपुर के अन्तर्गत देईपार-भैसहवा मार्ग पर स्थित रेहार जंगल चौराहे से सूरतगढ़ मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाल चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली, तहसील-भानपुर के अन्तर्गत पिरैला-आल्हेकुइयां मार्ग से महुलिया, छितिरगांवा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका तथा

5-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-309, रुधौली, तहसील-भानपुर के अर्न्तगत गरदहिया नानकार से शोभा राम के खेत तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 हाशिम चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित दो याचिकाएँ †

श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद मथुरा के छाता-शेरगढ़-नौहझील-बाजना रोड के गड्ढे भरवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

2-जनपद मथुरा की मांट तहसील में उत्तर प्रदेश सरकार की पेयजल योजना/जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मानागढ़ी, खजपुर, आवाखेड़ा, कौलाना, नावली, औहावा, सुरीर विजऊ, सुरीर कला, बरेठ, इरोली जुन्नादार एवं जैंसवा में पानी की टंकी एवं पाइप लाइन डालकर घरों में कनेक्शन देने के सम्बन्ध में श्री विवेक चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय डल्ला निजामपुर मनबहाल पाण्डेय के खेत से ग्राम सभा मानशाहपुर दलित बस्ती तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश राव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा जोगापुर प्रधानमंत्री सड़क से सुरेश पाठक के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण

---

† छापी नहीं गयीं।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा भगवानपुर जयराम के खेत से राम सेवक के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखराम राजभर एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित शिवराजपुर पिच मार्ग से अहलादे तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दर्शन भारती एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा मुसेपुर गिरण्ट बुढ़वा बाबा स्थान से राजभर बस्ती तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल यादव एवं अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ †

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम पूरनपुर स्याना से घुघली तक 3.00 किमी0 पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्यान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम खानपुर से मझोला बिल्लौच तक 1.00 किमी0 पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम कासनपुर बिल्लौच में भगवानदास के घर से शबीर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कारीमुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम सहवाजपुर से धारूपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम नैनू नागल से सीमला तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरेन्द्र चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पाँच याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएँ व्यपगत हुईं:-

1-जनपद रायबरेली के वि0ख0 हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम अचलेश्वर सिरसा मार्ग से पठानन का पुरवा दूरी 1.50 किमी0 डामरीकरण के सम्बन्ध में श्री सलमान खान व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के वि0ख0 हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम लसोड़हई से दुलारा का पुरवा तक दूरी 1.00 किमी0 डामरीकृत रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के वि0ख0 हरचन्दपुर के अन्तर्गत ग्राम मौहारी के पुरवा से विजय सिंह के पुरवा तक दूरी 1.00 किमी0 डामरीकृत रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के वि0ख0 हरचन्दपुर के अन्तर्गत ढकिया हरचन्दपुर रोड से हनुमान मंदिर हरचन्दपुर तक दूरी 200 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौशाद व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के वि0ख0 हरचन्दपुर के अन्तर्गत हिलालगंज हरनी सम्पर्क मार्ग से लोधन का पुरवा तक ल0 लगभग 1.5 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामू लोधी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सिकरारा के अन्तर्गत लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग से चाँदपुर से सैदनपुर मौर्या बस्ती तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम वैलाना में स्थित श्मशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम नगला बड़ौदा में श्मशान घाट वाली सड़क पर इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सांवली में पंचायत घर से श्री अंतरा के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री सचिन अधाना व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम महेपा जागीर में नाली से सिद्धबाबा मन्दिर तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सुनपेड़ा में श्री गिरीराज के मकान से आमपुर हुसैनपुर के तालाब तक खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत मियांपुर से नासिया घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार जिन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

2-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत मौठीखोड़ा से मसिगवां तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

3-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत डेलखेड़ा से भानपुर बनवारी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत दिलावरनगर से प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर ओक्षवा घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हापुड़ के तहसील हापुड़ में रामलीला मैदान से लज्जापुरी की सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय भास्कर एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका तथा

2-जनपद हापुड़ के ब्लाक हापुड़ श्यामपुर से खड़खड़करी मार्ग को जाने वाली सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमित श्याम एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा में छेरीनाला से विपतपुरा पुल तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के विकास खण्ड कदौरा में कदौरा-हमीरपुर मार्ग में ग्राम उदनपुर में रोड के दोनों तरफ नाला निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय तिवारी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र जालौन के विकास खण्ड जालौन के ग्राम दहगुवा से पावई रोड मुख्य मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गुप्ता, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र जालौन के विकास खण्ड जालौन में शेखपुरा से हरीपुरा मार्ग पर रपटा का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगराम सेंगर, निवासी जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र जालौन के विकास खण्ड कदौरा में चतेला मरघट से नगवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह, निवासी जनपद जालौन की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विपुल दुबे, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में टिकेश्वरनाथ मंदिर बिरनई का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमन प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका व्यपगत हुई।

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री शशांक त्रिवेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र महोली में राम नगर एवं गुजिया के मध्य कठिना तक पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

2-जनपद-सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र महोली में शिवाधर त्रिवेदी के मकान से राजू तेली के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मनीष बाजपेयी एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

3-जनपद-सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र महोली के नरनी में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

4-जनपद-सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र महोली में नीरज मिश्रा के मकान से दामोदर त्रिवेदी के मकान तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अवधेश मिश्रा एवं अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद उन्नाव, वि0ख0 बांगरमंऊ की ग्राम पंचायत कमलापुर से हूसेपुर तक नवीन डामरीकरण का कार्य कराये जाने के संबंध में श्री हरिवंश तिवारी एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

2-जनपद उन्नाव ग्राम भिक्खनपुर गोपालपुर वि0ख0 गंजमुरादाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में श्री लालेश अस्थाना एवं अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के ग्राम जनऊपुर से नूरपुर तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के बलिया सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा पिपरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के ग्राम गड़वार-रतसर बाईपास नहर से धनौती धुरा तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के ग्राम आसन से शेरवा कला तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत विकास खण्ड-गड़वार के ग्राम पचखोरा से शेरवा कला तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यदुवेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के विकास खण्ड उरुआ के ग्राम सभा सिंगारो नहर से सोनाई दलित बस्ती में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप विश्वकर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के ग्राम उसकी में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नियाज अहमद एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के ग्राम बरहा कला से ग्राम बबुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल पटेल एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा के विकास खण्ड उरुआ के ग्राम सभा बिगहनी से छतवा मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृपाशंकर एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विधान सभा मेजा के विकास खण्ड माण्डा के ग्राम सभा बेदौली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र एवं अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात, ब्लाक जोया के ग्राम-सिहाली के सभी रास्तों का सी0सी0 रोड एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका,

2-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात, ब्लाक गजरौला के ग्राम-सिहाली जहांगीर का सी0सी0 रोड एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री असलम मियां एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका तथा

3-जनपद अमरोहा, विधान सभा क्षेत्र-40, नौगावां सादात, के ग्राम-जब्बारपुर ब्लाक अमरोहा से सिरसाजट होते हुए नौगावां सादात तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री राजवीर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विशालकाय खुले रफाका नामक नाला को ढके जाने के सम्बन्ध में श्री रवि गुप्ता एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत लेबर कालोनी निवासियों को उनके स्वामित्व का मालिकाना हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत अर्मापुर से दादा नगर इण्डस्ट्रियल एरिया को जोड़ने वाले अति व्यस्त तथा वर्षों पुराने मार्ग पर एक उपरिगामी सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुमित पावा एवं अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका।

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-तिगरी में जगमोहन त्यागी के खेत से लटर मुखिया जी के खेत तक लम्बाई लगभग 01 किमी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ त्यागी एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

2-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-खेड़ा में रझेटी मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक लम्बाई लगभग 01 किमी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री आकाश चौधरी एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

3-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-हरनाथपुरकोटा में कुटी के पास से गहल सिंह की ट्यूबवेल होते हुए राजवीर के खेत तक लम्बाई लगभग 1.2 किमी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री ज्ञान सिंह लोचव एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका,

4-जनपद हापुड़ के कस्बा गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट पर गणेश चौक से पुराने बैंक तक लम्बाई लगभग 500 मी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री दीपक गौड़ एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका तथा

5-जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-बिहुनी में कान्ति त्यागी जी के खेत से आशाराम के खेत तक लम्बाई लगभग 700 मी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री आकाश त्यागी एवं अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुईं मानी गयीं :-

1-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड जखौरा के ग्राम सिरसी में खेडर नदी पर ग्राम सिरसी में रपटा/चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश रैकवार व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के रमपुरा कठवर में खजरा नाला पर ग्राम रमपुरा कठवर में रपटा/चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

3-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड जखौरा के ग्राम छिपाई नाला पर रपटा/चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजदीप बुन्देला व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

4-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड जखौरा के ग्राम बांसी पर खेडर नदी पर रपटा/चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका तथा

5-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम मावलिन में पटैरिया नाला पर रपटा/चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में ग्राम पट्टी साड़ा पक्की सड़क से भारतीय बस्ती तक एवं कतिपय अन्य स्थानों पर इण्टरलॉकिंग निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनंत लाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01-03-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 102 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की जनपद औरैया के अन्तर्गत अछल्दा ब्लाक में कतिपय सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सन्दीप सिंह की जनपद प्रयागराज के वि0ख0 मांडा के अन्तर्गत ग्राम सभा दिघिया से वाया ढिलिया से मिश्रीपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी की जनपद गाजीपुर के गहमर बारा के पास गंगा नदी पर कतिपय मार्ग पर पैन्टून पुल बनवाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ के सरधना के गांव वटजेरा में विद्युत लाइन से आम जन को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री योगेश शुक्ला की लोक निर्माण विभाग में सड़क चौड़ीकरण के लिए वन एवं ऊर्जा विभाग से समन्वय बना कर विकास कार्यों

† छापी नहीं गयीं।

को जल्द पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है, तथा छठवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी में मनरेगा के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिये जाने के तथा पात्र व्यक्तियों को लाभ न मिलने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की जनपद एटा के कासगंज-सिकन्द्राराऊ सम्पर्क मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, तथा दूसरी सूचना श्री मूलचन्द्र निरंजन की नहर कटान से किसानों की बरबाद फसलों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम ऐमनपुर में जूनियर हाई स्कूल में बाउण्ड्रीवाल कराने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री बाबू लाल की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा में कतिपय कच्चे मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री रमेश सिंह की जनपद जौनपुर की शाहगंज वि0स0 में कतिपय बाजारों में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के बलदेव बरौली में मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा छठवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा की जनपद जालौन की जालौन नगर पालिका में एक पुलिस चौकी और बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्री अनिल सिंह, श्री हंसूराम, श्री राम अवतार सिंह सैनी, श्री मोहन वर्मा, डॉ0 अमित सिंह चौहान, श्रीमती जय देवी, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्री स्वामी ओउमवेश, श्री जाहिद बेग, श्री पंकज पटेल, श्रीमती नीलिमा कटियार, श्री बेदी, श्रीमती सरिता भदौरिया, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री अमित अग्रवाल, श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री छोटे लाल वर्मा, श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्रीमती ओममणी वर्मा, श्री राजीव गुम्बर, श्री अशोक कुमार, श्री राजीव तरारा, श्री निर्मल वर्मा, श्री मनीष रावत, श्री जय प्रताप सिंह, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री प्रसन्न कुमार, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, श्री जवाहर लाल राजपूत, ई0 सचिन यादव, श्री अखिलेश यादव, श्री राम अचल राजभर, डॉ0 एच0एन0 सिंह पटेल, श्री कमाल अख्तर, श्री अमरेश कुमार, श्री बम्बा लाल दिवाकर, श्री आशु मलिक, श्री अभय सिंह, श्री अरमान खान, श्री विकास गुप्ता, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री आशुतोष शुक्ला, डॉ0 सुरभी, श्री अनिल कुमार, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री विनोद सरोज, श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, श्री रामचन्द्र यादव, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री महबूब अली, ई0 ब्रजेश कठेरिया, श्री जै किशन साहू, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री गौरव कुमार रावत, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री संग्राम सिंह, श्री आशुतोष मौर्य, डॉ0 डी0सी0 वर्मा,

श्री दूधराम, डॉ0 नीरज बोरा, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री मुकेश चौधरी, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री अशरफ अली खॉन, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री वीरेन्द्र चौधरी, श्री मो0 हसन 'रूमी', डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राम सिंह पटेल, मो0 ताहिर खॉन, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री रमेश जायसवाल, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री जगदीश नारायण, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री पल्टूराम, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्रीमती केतकी सिंह तथा श्री प्रेम सागर पटेल।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल दिनांक 02-03-2023 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 09 बजकर 08 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 01 मार्च, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थियां

नत्थी (क)

(देखिए तारांकित प्रश्न सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 31 पर)

Uttar Pradesh

Electricity Supply Code (Eighth Amendment), 2005

No.: UPERC/Secy/Regulations/Supply Code/2016/1061

Dated: 21.09.2016

Notification

Miscellaneous

Whereas the U.P. Electricity Supply Code 2005(Fifth Amendment) was notified on 25th August, 2014, in accordance with Sections 175 and 183 of Electricity Act 2003 and all other enabling powers in this behalf;

And whereas, the licensees are facing difficulties in some of the provisions of the Electricity Supply Code 2005, and amendments thereof and have requested further for some amendments in the Electricity Supply Code.

And whereas, by reason of some of the said difficulties in the Supply Code, 2005 some addendums / substitution / deletions in the Electricity Supply Code 2005 and amendments thereof, have been made.

And whereas, as a result of the above, and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of the Supply Code 2005 and amendments thereof;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 50 of the Electricity Act and the provisions of the Supply Code 2005 and all other enabling powers in this behalf, the Uttar Pradesh State Electricity Regulatory Commission makes the following Electricity Supply Code (Eighth Amendment), 2016 namely

1. **Short title and commencement** - (1) This Code shall be called the Electricity Supply Code (Eighth Amendment), 2016.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Addition of additional proviso under 6.8 (a)(iii)

"For the purposes of electrification in undeveloped / un-electrified colonies whose distribution network has not been developed by the developer, it is provided that the Distribution Licensee shall develop the HT lines on STP and LT lines on PCC Poles as these colonies are mostly in the outskirts of the city. The LT lines shall be through ABC. On request of the 10 % plot owners of the society the licensee shall prepare an estimate and provide it to the plot owners / applicants. The licensee shall initiate the work only after 50 % of the plot owners deposit the amount @ Rs. 35/- square feet of the plot area as mentioned in the registry with the licensee against the estimate. This scheme shall only be applicable on the un-developed colonies where at least 25 % of the houses have been constructed. This scheme should be applicable to the colonies with the maximum load of 400 KW including the diversity factor of 0.6. The annual carry over charges @ 12.5 % shall be charged from the plot owners who have not deposited the amount earlier with the licensee, these carry over charges shall be evenly distributed among the remaining consumers. If the total cost of electrification of the colony is not recovered by the licensee then the remaining amount can be charged as capex in the ARR. In the initial stage if the licensee arrange some loan the interest incurred thereon shall be allowed as a pass through in Tariff.

This scheme would not be applicable for the colonies developed under the schemes of Development Authorities / Housing Boards as the charges for developing of electric network has already been included in their development charges."

(S. K. Agarwal)
Member

(Desh Deepak Verma)
Chairman

नत्थी (ख)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-32 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 61 पर)

सरकारी विभागों पर बकाये की स्थिति

धनराशि (लाख रू0 में)

क0 सं0	विभाग का नाम	बकाया	वसूली
1	खाद्य एवं रसद विभाग	23.48	
2	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0	2344.34	39.57
3	लोक निर्माण विभाग	3455.72	2.81
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	940.49	
5	राजकीय निर्माण निगम	5.61	
6	केन्द्रीयय लोक निर्माण विभाग	32.20	
7	पशुपालन विभाग	0.48	
8	सहकारी समिति	274.94	
9	कृषि विभाग	94.95	
10	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	15.97	
11	फूड कॉरपोरेशन आफ इडिया	2093.36	
12	नगर विकास विभाग	39.54	
13	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	784.32	5.00
14	ग्राम्य विकास	1152.34	5.9
15	बेसिक शिक्षा विभाग	19.70	
16	पंचायती राज	277.53	
17	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0	174.09	
18	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	255.85	0.23
19	वन विभाग	15.69	
20	यू0आर0सी0 एयरफोर्स बरेली कैन्ट बरेली	32.70	
21	आबकारी विभाग	7.81	
22	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	29.30	
23	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0	804.20	11.47
24	उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग	24.03	
25	उ0प्र0 जल निगम	73.56	
26	उ0प्र0 कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग	17.95	
27	राजकीय प्रेस इलाहाबाद	9.64	
28	बी0एस0एन0एल0	155.37	40.97
29	उ0प्र0 एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	6.27	
30	आयुध निदेशालय	109.79	
31	सीमा सुरक्षा बल	2.04	
32	रेशम निदेशालय, लखनऊ	45.00	
33	उ0प्र0 राज्य सरकार परिवहन निगम	5.00	
34	उ0प्र0 पुलिस विभाग	0.90	
35	यू0पी0 कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज फेडरेशन लि0	9.95	
36	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड	400.12	
37	उ0प्र0 प्रोसेसिंग एन्ड कन्स्ट्रशन कॉरपोरेटिव फे0लि0	7.39	
38	उ0प्र0 पिछडा वर्ग कल्याण विभाग	1.11	
39	उ0प्र0 सचिवालय	4.78	
40	उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग	7.26	
41	उ0प्र0 सार्वजनिक उद्यम विभाग	10.50	
42	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	9.15	
43	उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	9.55	
44	रेलवे विभाग	257.25	
	योग	14041.22	105.95

17/02/2023

नत्थी (ग)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-75 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 84-85 पर)

कार्यालय प्रभारी अधिकारी (वर्कशॉप)

नगर निगम, कानपुर

पत्रांक :- दिनांक :-

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक यू0ओ0एल0डी0-4278/2023 दिनांक 04.02.2023 प्रश्न क्रमांक-75 श्री अमिताभ बाजपेयी के प्रश्न की नगर निगम कानपुर में विगत पॉच वर्षो में कितनी गाड़ियॉ किस कम्पनी से किन शर्तो पर अनुबन्ध की गई है का उत्तर चाहा गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर द्वारा विगत पॉच वर्षो में 40 हल्की गाड़ियॉ मेसर्स ज्योति ट्रैवेल से अनुबन्ध पर ली गई है। अनुबन्ध की शर्तो निम्नवत् है :-

1. फर्म द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से सन्तोशजनक कार्य का प्रमाण होने एवं लॉग बुक भरी होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। कोई भी अधिकारी वाहन मुख्यालय से बाहर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं ले जायेगा। अति आवश्यक साशकीय यात्रा एवं निर्धारित दूरी से अधिक चलने आदि की स्थिति में नगर आयुक्त महोदय से लिखित पूर्व स्वीकृत की छायाप्रति सम्बन्धित अधिकारी चालक को उपलब्ध करायेगें। तदोपरान्त भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
2. चालक का वैध लाइसेन्स एवं वाहन का बीमा एवं रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, न होने की दशा में कम्पनी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
3. चालक के ड्यूटी के दौरान अथवा बाद में भी अमर्यादित आचरण एवं गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर उसे ड्यूटी से हटाकर दूसरा चालक तत्काल वाहन स्वामी को उपलब्ध कराना होगा।
4. किराये पर लगाया जाने वाला वाहन दो वर्षो से अधिक पुराना नहीं होगा। पुराना पाये जाने की स्थिति मे 10 प्रतिशत की कटौती प्रतिवर्श की दर से मासिक किराये से की जायेगी।
5. वाहन चालक सहित उपयोग हेतु ड्यूटी के अनुरूप कम से कम 15 घण्टे उपलब्ध करानी होगी। वाहन खराब होने की दशा में सूचित होने के अधिकतम् दो घण्टे के अन्दर दूसरा वैसा ही वाहन फर्म को सम्बन्धित को उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न कर पाने पर सम्बन्धित अधिकारी की शिकायत प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जुर्माने के रूप में कम से कम 02 दिवसों का किराया काटा जायेगा।
6. निविदा के साथ 01 वर्षो किराये का 02 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में न्यूनतम 05 लाख रूपया एन0एस0सी0 जो कि मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी कानपुर नगर निगम

के पक्ष में होगी, जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा में सफलीभूत फर्म को सिक्योरिटी के रूप में रूपया पॉच लाख की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 एक वर्षो हेतु नगर निगम कानपुर में जमा करनी होगी। जो मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी कानपुर नगर निगम के नाम होगी।

7. फर्म टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
8. वाहनों को अधिकतम 01 वर्षो के लिये अनुबन्धित किया जायेगा, जिसको कि आवश्यकता अनुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
9. अनुबन्धित वाहनों की संख्या लगभग 40 होगी जो टैक्सी कोटे में पंजीकृत हो एंव विभागीय कार्यो की आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
10. अनुबन्ध की अवधि में वाहन किसी अन्य व्यवसाय/अन्य (अपराधिक) गतिविधियों में पाये जाने पर फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं उच्च अधिकारियों से अनुबन्ध समाप्त करने के आदेश पर कार्यवाही की जायेगी।
11. समस्त वाहन एक ही फर्म के लिये जायेगें। वही निविदा मान्य होगी, जिसमें सभी प्रकार के मेक वाहनों की दरो का उल्लेख मेकवार होगा।
12. समस्त वाहन डीजल/पेट्रोल चलित होंगे व किसी भी दशा में सी.एन.जी/एल.पी.जी. चलित वाहन अनुमन्य नहीं होगा।
13. निविदाकर्ता को ईंधन, चालक, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, सर्विस टैक्स, बाहर जाने पर टोल टैक्स व अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा ही वहन करना होगा।
14. यह की मासिक किराये के आधार पर प्रयुक्त वाहन की लॉग बुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जाना होगा तथा आवंटित अधिकारी कि0मी0 की लॉग बुक सत्यापित की जायेगी तथा वाहनों (दूरी) का मापन मोतीझील मुख्यालय से मान्य होगा।
15. मसिक बिल की धनराशि में नियमानुसार आयकर एवं सेवाकर तथा अन्य कर काट कर भुगतान किया जायेगा।
16. किराये की दर जी.एस.टी. सहित देय होगी ।
17. कानपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित सभी शर्तो व नियम फर्म को पूर्ण रूपेण मान्य होगें।
18. कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इस शर्तो के साथ करना होगा कि यदि स्टाम्प पेपर के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में चल रहे वाद पर भविश्य में कोई निर्णय होगा है, तो निर्णय अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क फर्म को जमा करना होगा।
19. फर्म द्वारा किसी भी वाहन के प्रकार अथवा वाहन चालक के बदले जाने की स्थिति में कम से कम 02 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से कार्यालय को सूचित कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
20. किराये पर लगाया जाने वाला वाहन यदि किसी माह सम्बद्ध अधिकारी द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, तो उसका उस माह का किराया देय नही होगा।
21. विभागीय मांग पर आनकाल/निर्धारित दूरी से अधिक चलने पर वाहन विभागीय निविदा स्वीकृत दर पर उपलब्ध कराना होगा एवं ऑन कॉल की दशा में फर्म को फर्म द्वारा निविदा में अंकित न्यूनतम दर पर भुगतान होगा। न्यूनतम दर के अतिरिक्त किसी प्रकार का व्यय (नाइट ड्यूटी आदि) देय नहीं होगा।
22. लेबर एक्ट को दृश्टिगत रखते हुये निविदादाता फर्म का लेबर एक्ट, ई.पी.एफ. में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

23. फर्म का सालाना टर्न ओवर कम से कम तीन करोड़ रूपया से कम नहीं होनी चाहिए।
24. फर्म को प्रति मेकवार दी गई दरें मय चालक/ईंधन सहित देय होंगें। जो कि एक वर्श तक/निविदा समाप्ति होने तक प्रभावी होगें तथा कोई भी ईंधन आदि में बढ़ोत्तरी देय नही होगी।
25. विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कानपुर नगर होगा।

प्रभारी अधिकारी (वर्कशॉप)
नगर निगम कानपुर

नत्थी (घ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-92 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 92-93 पर)

नगर निगम कानपुर

उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (विनियमन) अधिनियम 2000(वर्श 2018 में संशोधित) के तहत निर्गत अधिनियम अधिसूचना संख्या 1056/नौ–7–18–29(लखनऊ)/2018 दिनांक 15.07.2018 के कम में की गई कार्यवाही का विवरण

➢ नगर निगम प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक के अभियान के अन्तर्गत 15 जुलाई 2018 से 15 फरवरी 2023 तक की गई कार्यवाही का विवरण :–

कम सं0	दिनांक	जब्त की गई प्रतिबन्धित पालीथीन	प्रतिबन्धित में किया गया जुर्माना (रूपया)	प्लास्टिक निस्तारण से आय (रूपया)
1	2	3	4	5
1	दिनांक 15.07.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	24,748.545 कि0ग्रा0	8,45,800.00	-
2	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक	7728.115 कि0ग्रा0	33,17,400.00	-
3	दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक	32,601.930 कि0ग्रा0	11,73,600.00	-
4	दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक	14,835.500 कि0ग्रा0	6,65,000.00	3,75,000.00
5	दिनांक 01.04.2022 से 15.02.2023 तक	1,39,620.250 कि0ग्रा0	42,25,730.00	13,75,000.00
	कुल योग	2,19,534.340 कि0ग्रा0	1,02,27,530.00	17,50,000.00

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम कानपुर

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, कानपुर

नत्थी (ङ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-185 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 145-146 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2023 के 2–बुधवार के निर्धारित श्री अतुल प्रधान जी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–185 की अनुपूरक सूचना।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना, में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 26.08.2022 तक निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य एवं गढढामुक्ति के कार्यों को पूर्ण कराया गया है :–

क्र0 सं0	योजना का विवरण	मार्गो का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृति का दिनांक	माह 02/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	माह 08/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	अवशेष लम्बाई (किमी0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चौडीकरण/सुदृढीकरण	जनपद मेरठ में कंकरखेडा पावलीखुर्द मुल्हैडा बपारसी मार्ग (अ0जि0मा0) के चै0 1.500 से 19.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	17.500	25-03-2021	0.000	17.500	0.000
2		जनपद मेरठ में दादरी से सकौती होते हुये कपसाड होते हुये गंग नहर तक मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4.900	07-01-2022	0.000	1.000	3.900
		योग	**22.400**		**0.000**	**18.500**	**3.900**

क्र0 सं0	योजना का विवरण	मार्गो का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृति का दिनांक	माह 02/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	माह 08/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	अवशेष लम्बाई (किमी0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बसावट का निर्माण	——————————शून्य आख्या——————————					

क्र0 सं0	योजना का विवरण	मार्गो का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृति का दिनांक	माह 02/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	माह 08/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	अवशेष लम्बाई (किमी0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवीनीकरण	गडीना ब्लॉक मवाना में गडीना से फलावदा मार्ग कि0मी0 1(500)	0.500	15-02-2021	0.500	0.000	0.000
2	नवीनीकरण	बहजादका सम्पर्क मार्ग कि0मी0 1(800)	0.800	15-02-2021	0.800	0.000	0.000
3	नवीनीकरण	फलावदा गंगसोना से गदनपुरा मार्ग कि0मी0 1,2(500)	1.500	15-02-2021	1.500	0.000	0.000
4	नवीनीकरण	पिलौना सम्पर्क मार्ग।	0.400	25-03-2022	0.000	0.400	0.000
5	नवीनीकरण	मिलबाईपास से अटौरा मार्ग।	4.000	25-03-2022	0.000	1.600	2.400
6	विशेष मरम्मत	फलावदा गंगसोना मार्ग से नेडू होते हुये वापस मुख्य मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	21-10-2021	0.000	1.000	0.000
7	विशेष मरम्मत	देदूपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.300	21-10-2021	0.000	0.300	0.000
8	विशेष मरम्मत	तखावली से रहावती मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.800	21-10-2021	0.000	1.800	0.000
9	विशेष मरम्मत	मवाना मार्ग के कि0मी0 08 से गडीना मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.450	29-11-2021	1.450	0.000	0.000
10	विशेष मरम्मत	सकौती फलावदा मार्ग के कि0मी0 15 से बुनियादपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	2.200	29-11-2021	2.200	0.000	0.000
11	विशेष मरम्मत	निलोहा से अक्खेपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.800	29-11-2021	1.800	0.000	0.000
12	विशेष मरम्मत	फलावदा से मन्दवाडी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.700	29-11-2021	1.700	0.000	0.000
13	विशेष मरम्मत	देदूपुर से खाता तालाब मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	08-12-2021	0.000	4.000	0.000
14	विशेष मरम्मत	देदूपुर स्कूल से खालिदपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.250	08-12-2021	0.000	0.250	0.000
15	विशेष मरम्मत	गंगसोना बाईपास मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.600	08-12-2021	0.000	0.600	0.000
16	विशेष मरम्मत	मवाना फलावदा से सकौती मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	08-12-2021	0.000	1.000	0.000
17	विशेष मरम्मत	मवाना फलवदा से खाला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.500	17-12-2021	0.000	1.500	0.000

18	विशेष मरम्मत	सकौती फलावदा वाया साधु नंगली मार्ग पर सी0सी0 एवं नाली द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य।	0.650	30-11-2021	0.000	0.650	0.000
19	विशेष मरम्मत	सरधना से मंढियाई मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.500	07-12-2021	0.000	0.000	0.500
20	विशेष मरम्मत	झिटकरी से अक्खेपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	07-12-2021	0.000	0.600	2.400
21	विशेष मरम्मत	पाली से भामौरी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	07-12-2021	0.000	0.600	2.400
22	विशेष मरम्मत	दौलतपुर से गंगनहर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	07-12-2021	0.000	0.900	0.100
23	विशेष मरम्मत	कुशावली से भामौरी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	07-12-2021	0.000	0.500	2.000
24	विशेष मरम्मत	महल सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	07-12-2021	0.000	0.800	1.200
25	विशेष मरम्मत	दौराला मसूरी (अ0जि0मा0) के लावड़ आबादी भाग में सी0सी0 द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य।	0.150	08-12-2021	0.000	0.150	0.000
26	विशेष मरम्मत	कृषि विश्वविद्यालय से पबरसा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.400	08-12-2021	0.000	0.000	1.400
27	विशेष मरम्मत	कुशावली से अटैरना पुल तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.900	08-12-2021	0.000	0.500	1.400
28	विशेष मरम्मत	लावड़ जलालपुर उलखपुर सैनी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	7.950	07-01-2022	0.000	0.500	7.450
		योग	**48.850**		**9.950**	**17.650**	**21.250**

क्र0 सं0	योजना का विवरण	मार्गो का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृति का दिनांक	माह 02/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	माह 08/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	अवशेष लम्बाई (किमी0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवनिर्माण	सावित्री सोनी विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज नागोरी से तखावली तक मार्ग के निर्माण का कार्य।	2.700	24-03-2021	0.810	1.620	0.270
2	नवनिर्माण	गुडम्ब से बातनौर मंदिर तक नव निर्माण का कार्य।	1.500	07-01-2022	0.00	0.570	0.930
3	नवनिर्माण	गुडम्ब बातनौर मार्ग से सकौती फलावदा मार्ग तक नव निर्माण का कार्य।	0.700	07-01-2022	0.00	0.252	0.448
4	नवनिर्माण	फलावदा बुनिदयापुर मार्ग से मंदवाडी भट्ठा होते हुये कैलावडा (मेरठ सीमा तक) नव निर्माण का कार्य।	2.400	07-01-2022	0.00	0.144	2.256

5	नवनिर्माण	जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौ0 चरण सिंह कांवड मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नवनिर्माण का कार्य।	25.000	23-12-2020	0.000	0.000	25.000
6	नवनिर्माण	नंगाला मुखत्यापुर मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	0.860	07-01-2022	0.000	0.000	0.860
		योग	**33.160**		**0.810**	**2.586**	**29.764**

क्र0 सं0	योजना का विवरण	मार्गो का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृति का दिनांक	माह 02/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	माह 08/22 तक पूर्ण लम्बाई (किमी0 में)	अवशेष लम्बाई (किमी0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गढढामुक्ति	चौ0 चरण सिंह अपर गंगा नहर की बायी ओर पटरी मार्ग	18.000		0.000	6.000	0.000
2		दौराला बरनावा मार्ग।	15.000		0.000	15.000	0.000
		योग	**33.000**		**0.000**	**21.000**	**0.000**